खण्ड-511, अंक-08
बुधवार, 07 फाल्गुन, शक संवत् 1941
(26 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड-511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2020

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
जातिवार जनगणना कराये जाने व पिछडा वर्ग का कॉलम जोड़े जाने की मांग...			7-9
प्रश्नोत्तर	...	...	10-116
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शाकिर अली के निधन पर शोकोद्गार	...	...	116-117
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	117-118
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	...	...	118
आय-व्ययक पर साधारण चर्चा 05 दिन के स्थान पर 03 दिन ही कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	118-120
जनगणना में पिछडे वर्ग के कॉलम को जोड़े जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न, विकास निधि 02 करोड़ से बढ़ाकर 05 करोड़ रुपये किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	120-125
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	125-127
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जेवर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		127
जनपद वाराणसी मे ग्राम तेवर में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लालजी पहलवान हिन्द केशरी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	128
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		128
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम-गनगोला में जिला सहकारी संघ बदायूं में निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		128-129
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत आयुष्मान योजना में सर्वे कराकर छूटे हुए जरूरतमन्द लोगों को सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भूता में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार करके चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	130
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद बलिया में स्थित जिला जेल को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद सहारनपुर के नगर मुख्यालय के पुराने शहर की सीवर व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131-132
जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत टौंस नदी पर निर्मित पुल के दोनों एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ रोड पुराने कमेले की रिक्त जगह पर स्वीकृत हास्पिटल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत दीदारगंज-सरायमीर मार्ग से हैदराबाद ग्राम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
जनपद जौनपुर के नगर पालिका मुंगरा-बादशाहपुर में कटरा मोहल्ले में कमासिन ड्रेन नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा की ग्राम पंचायत पुलन्दर में गौ-शाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसी दास प्रेरणा स्थलीय रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य में उत्तर वार्ड, पूर्व वार्ड में कतिपय कार्यों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असोहा से ग्राम खरगीखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद लखनऊ के यूपीपीसीएल, गोमतीनगर के सी0जी0एम0 श्री गोपाल मिश्रा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	136-137
श्री प्रभाष कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	137-138
श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	138
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	138
श्रीमती साधना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	139
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	139
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	140-141
श्री छत्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	141-142
श्री ओमकार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	142
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित सात याचिकाएँ, जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चार याचिकाएँ तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) ...	142-144
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	144-175
विधायकों की सैलरी, भत्तों व विधायक निधि को बढ़ाये जाने की मांग ...	175-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों की सूची को समीक्षोपरान्त नवीनीकृत किया जाना	180-181
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित चार याचिकाएँ तथा जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	181-182
श्री प्रतीक भूषण, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	182-183
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	183-184
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	184
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	184-185
श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	185
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)... ...	185
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	185
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)... ...	185
श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	186
श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	186
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	186-187
श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	187

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ व जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	187-188
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	188
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	189
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	189-190
श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	190
श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	190
श्री मसूद अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	190
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	190-191
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	191
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	192
श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	192
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित नौ व जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	192-193
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	193-194
श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	194-195

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 अनीता लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	195
श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	195-196
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	196
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	196-197
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	198
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	198-199
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	199
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	199-208
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	208-213
बजट चर्चा के दौरान अधिकारियों की दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	213
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) ...	213-251
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	251-252
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	252-255
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भगवन्तनगर क्षेत्र के कस्बा बीघापुर में 100 शैय्या के अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	256-257
जनपद लखनऊ स्थित टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	257-259

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नगर पालिका में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेश चौबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	259-260
स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	260-261
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में अधूरे निर्मित विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	261-262
जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	262
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में डलमऊ पम्प कैनाल में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य ...	263-264
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	264
उत्तर प्रदेश में विमुक्त घुमन्तू जनजातियों के विकास हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार डेविड द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	264-266
नत्थियाँ	267-281

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-316

1-अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
2-अजय कुमार, डॉ0	इलाहाबाद
3-अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
4-अजीत सिंह पाल, श्री	कानपुर देहात
5-अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद
6-अदिति सिंह, सुश्री	रायबरेली
7-अनिल कुमार मौर्य, डा0	सोनभद्र
8-अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
9-अनिल पाराशर, श्री	अलीगढ़
10-अनिल राजभर, श्री	वाराणसी
11-अनिल सिंह, श्री	उन्नाव
12-अनीता, श्रीमती	अम्बेडकरनगर
13-अनीता लोधी राजपूत, डा0	बुलन्दशहर
14-अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच
15-अनुराग सिंह, श्री	मिर्जापुर
16-अनूप प्रधान, श्री	अलीगढ़
17-अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर
18-अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री	प्रतापगढ़
19-अमन मणि त्रिपाठी, श्री	महाराजगंज
20-अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
21-अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
22-अरुण कुमार, डॉ0	बरेली
23-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0)	वाराणसी
24-अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	खीरी
25-अविनाश त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
26-असलम अली, श्री	हापुड़
27-आजाद अरिमर्दन, श्री	आजमगढ़
28-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री	बलिया
29-आनन्द शुक्ला, श्री	चित्रकूट
30-आर0के0 वर्मा, डॉ0	प्रतापगढ़
31-आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़
32-आलमबदी, श्री	आजमगढ़
33-आशीष सिंह पटेल ''आशू'',श्री	हरदोई
34-आशुतोष उपाध्याय, श्री	देवरिया
35-आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री	लखनऊ
36-इकबाल महमूद, श्री	सम्भल
37-इकराम कुरैशी, हाजी	मुरादाबाद
38-इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री	फैजाबाद
39-इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
40-उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
41-उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
42-उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
43-उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
44-ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
45-ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
46-कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
47-कमलेश शुक्ल, श्री	देवरिया
48-करण सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
49-कल्पनाथ पासवान, श्री	आजमगढ़
50-काली प्रसाद, श्री	देवरिया

51-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
52-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
53-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
54-केसर सिंह, श्री बरेली
55-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
56-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
57-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
58-गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
59-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
60-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
61-गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
62-गौरी शंकर, श्री जालौन
63-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
64-चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
65-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
66-छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
67-जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
68-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
69-जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
70-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
71-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
72-जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
73-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
74-जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
75-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
76-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
77-डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
78-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
79-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
80-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
81-तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
82-त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
83-दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
84-दल बहादुर, श्री रायबरेली
85-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
86-दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
87-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
88-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
89-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
90-देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
91-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
92-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
93-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
94-देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
95-धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
96-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
97-धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
98-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
99-धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
100-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
101-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
102-नईम उल हसन, श्री बिजनौर
103-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
104-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
105-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
106-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
107-नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
108-नवाब जान, श्री मुरादाबाद
109-नाहिद हसन, श्री शामली
110-नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
111-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात

112-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
113-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
114-नील रतन सिंह पटेल नीलू, श्री वाराणसी
115-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
116-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
117-पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
118-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
119-पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
120-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
121-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
122-प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
123-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
124-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
125-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
126-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
127-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
128-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
129-फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
130-बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
131-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
132-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
133-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
134-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
135-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
136-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
137-बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
138-बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
139-बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
140-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
141-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
142-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
143-ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
144-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
145-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
146-मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
147-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
148-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
149-मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
150-मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
151-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
152-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
153-महबूब अली, श्री अमरोहा
154-महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
155-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
156-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
157-महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
158-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
159-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
160-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
161-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
162-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
163-मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
164-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
165-मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
166-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
167-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
168-योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
169-योगेश धामा, श्री बागपत
170-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई

171-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
172-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
173-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
174-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
175-रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
176-रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
177-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
178-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
179-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
180-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
181-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
182-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
183-राकेश सिंह, श्री रायबरेली
184-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
185-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
186-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
187-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
188-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
189-राजबाला, श्रीमती रामपुर
190-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
191-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
192-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
193-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
194-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
195-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
196-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
197-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
198-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
199-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
200-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
201-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
202-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
203-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
204-राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
205-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
206-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
207-रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
208-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
209-रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
210-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
211-लाखन सिंह, श्री औरैया
212-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
213-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
214-लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
215-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
216-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
217-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
218-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
219-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
220-विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
221-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
222-विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
223-विजय मिश्र, श्री भदोही
224-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
225-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
226-विनय शाक्य, श्री औरैया
227-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
228-विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
229-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
230-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर

231-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
232-विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
233-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
234-वीरेन्द्र, श्री एटा
235-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
236-शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
237-शशांक वर्मा, श्री खीरी
238-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
239-शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
240-शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
241-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
242-शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
243-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
244-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
245-शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
246-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
247-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
248-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
249-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
250-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
251-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
252-श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
253-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
254-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
255-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
256-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
257-संजय, श्री बुलन्दशहर
258-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
259-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
260-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
261-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
262-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
263-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
264-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
265-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
266-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
267-सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
268-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
269-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
270-सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
271-सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
272-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
273-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
274-साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
275-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
276-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
277-सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
278-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
279-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
280-सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
281-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
282-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
283-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
284-सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
285-सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
286-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
287-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
288-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
289-सुरेश कुमार, श्री शामली
290-सुरेश कुमार, श्री अमेठी
291-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
292-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
293-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ

294-सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	306-स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
295-सुरेश राही, श्री	सीतापुर	307-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
296-सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	308-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
297-सुशान्त सिंह, कुं0	बिजनौर	309-हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
298-सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	310-हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
299-सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर	311-हरीराम, श्री	सोनभद्र
300-सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया	312-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
301-सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर	313-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
302-सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	314-हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
303-सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर	315-हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
304-सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	316-हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
305-सौरभ सिंह, श्री	खीरी		

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

जातिवार जनगणना कराये जाने व पिछड़ा वर्ग का कॉलम जोड़े जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, देश में जनगणना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिवार जनगणना की बात करती रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नकाल में न बोलिये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम जातिवार जनगणना करवायेंगे, लेकिन यह दुख की बात है कि लगातार कहने के बावजूद भी सरकार जातिवार जनगणना नहीं करा रही है और पिछड़े वर्ग का कॉलम ही खत्म कर दिया है कि अब इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिये, उसके बाद आपको सुन लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जातिवार गणना करवा लें। इस विधान सभा से एक प्रस्ताव पास करके भेजा जाए कि जातिवार जनगणना हो और पिछड़ा वर्ग का कॉलम जोड़ा जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी है।

श्री अध्यक्ष-

जनगणना का उत्तर प्रदेश सरकार से तो कोई मतलब है नहीं। आपकी यह बात नियम विरुद्ध है। आपकी बात नियम विरुद्ध है। आपकी बात नियमों में नहीं आती है। आप प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

आपने उनको अन्दर आने के लिये क्या पहले नहीं बताया ? (हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जातिवार जनगणना हो। जातिवार जनगणना का यहां से प्रस्ताव पास हो।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जातिवार जनगणना हो। हमेशा हुई है, लेकिन इस बार क्यों नहीं हुई ?

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार वेल से नारेबाजी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह तैयारी कितने बजे हुयी। (हंसी) अब आप लोग अपने स्थानों पर लौट जाईये। आप लोग आज बेमन से नारा लगा रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 1865 से 1872 के बीच देश के सभी राज्यों में जातिवार जनगणना करायी गयी। उसके बाद 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 व 1941 में जातिवार जनगणना हुयी थी। वर्ष 1951 की जनगणना के लिये तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जातिवार जनगणना की सहमति दी थी, किन्तु 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस सरकार ने जनगणना फार्म में जाति का कालम हटा दिया। 1961 व 1971 में भी जातिवार जनगणना नहीं हुयी। 1981 में जातिवार जनगणना का कालम जोड़ा गया, लेकिन पुनः उसे हटा दिया गया। जनता तथा समाजवादियों की मांग पर 2011 की जनगणना जातिवार करायी गयी, किन्तु कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संसद में तथा विधान मण्डलों में जातिवार जनगणना की बात उठायी है। लोक सभा व राज्य सभा तथा राज्यों के विधान मण्डलों में भाजपा सरकार के मंत्रीगण द्वारा जनता से जातिवार जनगणना का वादा किया जाता रहा है। समय-समय पर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को संविधान प्रदत्त आरक्षण में जातिवार आरक्षण देने की बात भाजपा सरकार द्वारा की जाती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा कोई किसी के हक पर अतिक्रमण न कर पाये इसलिये सभी जातियों की जनगणना की बात संसद से जनता तक लगातार की जाती रही है।

(इस मध्य सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर भी अपने दल के सदस्यों के साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझे नहीं मालूम कि यह लोग क्यों छुट्टी चाहते हैं। आज बुधवार का दिन है। यह छुट्टी क्यों चाहते हैं ? यह ऐसा इश्यू उठाना चाहते हैं कि जिससे मजबूर होकर आपको हाउस स्थगित करना पड़े। इनके पास कोई काम तो है नहीं। जो इश्यू

इस विधान सभा के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है उसको उठाकर यह लोग क्या कहना चाहते हैं ? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का सम्मान करती है, करती थी और करती रहेगी, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है। यह लोग घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थानों पर वापस चलिये। यह विषय विधान सभा की परिधि में नहीं आता है। आप लोग वापस जाईये। देखिये, मा0 ओम प्रकाश राजभर जी अपनी जगह खड़े हैं वह यहां वेल में नहीं आये। आप लोग ओम प्रकाश जी का अनुसरण करिये।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से लगातार नारेबाजी करते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 35 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 05 मिनट पर 35 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 40 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा हमारे लोग वापस आ गये, आपके सम्मान में लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि देश के लिए, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 60 प्रतिशत इस देश में पिछड़े हैं, पिछड़ों की इतनी अनदेखी क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

क्या सवालों के पहले इसको सुनना है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 60 प्रतिशत इस देश में पिछड़े हैं, पिछड़ों की इतनी अनदेखी क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, प्रश्नोत्तर के पहले नहीं।

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

अल्पसूचित तारांकित

लखनऊ के के0जी0एम0सी0 व पी0जी0आई0 हास्पिटलों में वेंटिलेटर की संख्या दोगुनी करने व समस्त चिकित्सा केन्द्रों में वेंटिलेटर लगाये जाने विषयक

****1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय -**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर स्थित के0जी0एम0सी0 एवं पी0जी0आई0 हास्पिटलों में वेंटिलेटर की कमी के कारण मरीजों की होने वाली मृत्यु को रोकने के दृष्टिगत उक्त अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या दोगनी किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में 193 वेंटिलेटर तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कुल 205 वेंटिलेटर क्रियाशील हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत के0जी0एम0यू0 में 50 वेंटिलेटर क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा एस0जी0पी0जी0आई0 में भी 55 अतिरिक्त वेंटिलेटर क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण आज प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां यह मानव जीवन और मानव संवेदनाओं से जुड़ा है वहीं प्रदेश के उन गरीब, कमजोर और आर्थिक संसाधनों से कमजोर लोगों से भी जुड़ा है। आज प्रायः यह समस्या आ रही है कि जब नाजुक स्थिति में कोई मरीज चाहे वह पी0जी0आई0 जाये, चाहे के0जी0एम0सी0 जाये, उसे वेन्टिलेटर नहीं मिल पा रहा है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि उस गरीब आदमी को प्राइवेट हास्पिटलों में जाना पड़ता है और वहीं से उसका शोषण शुरू हो जाता है। प्राइवेट हास्पिटलों में कहीं 25 हजार, कहीं 30 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेन्टिलेटर का लिया जा रहा है और जो मरीज यह पैसा नहीं दे पा रहा है, वह वेन्टिलेटर नहीं पा रहा है और उसकी मृत्यु हो जा रही है। मेरा एकदम स्पष्ट प्रश्न था माननीय मंत्री जी से कि जो उत्तर प्रदेश के हास्पिटलों में पी0जी0आई0 और के0जी0एम0सी0 में वेन्टिलेटर्स की कमी है उस कमी को देखते हुए और उनकी मौतों को रोकने के लिए क्या सरकार उसको दो गुना करेगी। एक यह सूचना भी है और मेरी जानकारी भी है कि पी0जी0आई0 में माह जनवरी में 1458 मरीजों को वेन्टिलेटर नहीं मिल पाया वह वहां से वापस किये गये। 2267 लोगों को माह जनवरी में के0जी0एम0सी0 में

वेन्टिलेटर नहीं मिला, उनको वापस किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वेन्टिलेटरों की कम संख्या को देखते हुए इसे दो गुनी अर्थात के0जी0एम0सी0 में 193 की जगह 386 और पी0जी0आई0 में 205 की जगह पर 410 वेन्टिलेटर आवश्यकता को देखते हुए करेगी, एक प्रश्न ? दूसरा है कि क्या सरकार के पास इसके आंकड़े हैं कि वेन्टिलेटर न मिल पाने के कारण पी0जी0आई0 और के0जी0एम0सी0 में गये मरीज जिन्हें वेन्टिलेटर नहीं मिला, उनकी मृत्यु की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

आपके मूल सवाल में तो यह बात है नहीं। आपका मूल सवाल तो इस बात पर था कि आप कितने वेन्टिलेटर लगाने जा रहे हैं, दो गुना करने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यही पूछ रहे हैं कि क्या दो गुना करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने उत्तर तो दिया, उन्होंने संख्या बताई कि इतने कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वेन्टिलेटर का एम0सी0आई0 के हिसाब से एक मानक है और वह मानक यह है कि 20 वेन्टिलेटर 100 बेड पर होने चाहिए जो इस समय हमारे पास व्यवस्था है, वह व्यवस्था पर्याप्त है लेकिन जितनी मांग है उसके अनुरूप नहीं है, यह सही है। मांग ज्यादा है। पी0जी0आई0 में हमारी यह कोशिश है कि हम उसमें बेड बढ़ायें और हम लगातार इस कोशिश में हैं कि जो ट्रामा सेन्टर के 60 बेड हैं उसमें बढ़ा दें और 30 इमरजेन्सी के बेड बढ़ा दें इसके लिए लगातार जो नये डायरेक्टर को एप्वाइन्ट किया गया वे मिलने आये थे। मैने उनसे केवल एक ही बात कही और जब मैं उधर बैठता था तो कई बार सी0एम0एस0 को बुलाकर आपके चैम्बर में जब आपके पूर्वाधिकारी माननीय माता प्रसाद जी थे, उन्होंने स्वयं इस बात को संज्ञान में लिया था और बेड बढ़ाने के लिए कोशिश की थी कि किसी तरीके से बेड बढ़ जायें और हमने अब भी पहली शर्त नये निदेशक से यही रखी कि हम आपको अच्छा डायरेक्टर तभी मानेंगे जब आप पी0जी0आई0 में बेड बढ़ाने की पुरकश व्यवस्था कर देंगे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें ई0एम0ओ0 की व्यवस्था कर दें तो हम कम से कम 60 बेड से लेकर 200 बेड कर देंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम कर देंगे। जब चतुर्वेदी जी थे तो हमने उनसे बात की और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी से बात की और जिस दिन विभाग परिवर्तन हुआ उस दिन भी हमने कहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े पी0जी0आई0 में बेड बढ़ाइये क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि पी0जी0आई0 एक इतनी अच्छी और रेपुटेटेड संस्था होने के बावजूद वहां से मरीज को वापस लौटना पड़ा। जिस दिन से

यह संस्थान बना है उस दिन से सभी ने इसका स्टैण्डर्ड मेनटेन करने में बहुत सहयोग दिया है। सभी का बहुत सहयोग रहा। इस संस्थान में और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए यह जरूरी है कि वहां से मरीज खाली ना जाये और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से मरीज वापस ना जाये, लेकिन यह भी सही है कि डाक्टर्स की संख्या ओवरनाइट नहीं बढ़ाई जा सकती है। खासतौर से पी0जी0आई0 जैसी संस्था के लिए तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। लोग वर्षों से इस बात की आशंका जता रहे थे कि आगे चलकर डाक्टर्स की संख्या का टोटा पड़ेगा और इसके लिए हमारी सरकार में आठ नये मेडिकल कालेज बन गये हैं और 13 मेडिकल कालेज नये स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2016 में जो मेडिकल कालेज सेंशन हुये थे उसमें एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई प्रारम्भ कर दी है और 700 सीटों पर एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी है। एक दिन में डाक्टर नहीं बन सकता है और खासतौर से पी0जी0आई0 के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूरी है। इस प्रकार वहां की असली समस्या बेड बढ़ाने की है ओर हम पूरी तरीके से इसके लिए प्रयत्नशील हैं और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि पी0जी0आई0 में किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी बेड बढ़ा दें और जहां तक आपने वेन्टिलेटर खरीदने की बात कही है तो हमने पहले ही इस सवाल का उत्तर अपने जवाब में दे दिया है कि इसे खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। आज भी हमारी फोन पर सी0एम0एस0 और डायरेक्टर से बात हुई है कि जितनी जल्दी हो सके यह प्रक्रिया पूरी कर दें। के0जी0एम0सी0 ने कहा कि हम जून तक कर पायेंगे और इन्होंने कहा कि दो महीने लगेंगे। पैसा दे दिया गया है उसकी कोई समस्या नहीं है। उपकरण के लिए अलग से पैसा दिया जाता है और सेलरी के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। इस बार भी बजट में एक अच्छा खासा अमाउण्ट इसके लिए रखा गया है। हालांकि 550 करोड़ रुपये तो केवल सेलरी का ही है। कुल मिलाकर हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेड को बढ़ा दें। जहां तक दोगुना करने का सवाल है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक वेन्टिलेटर बढ़ाते हैं तो 146 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। यह कह देना तो बहुत आसान है लेकिन इसको जमीन पर उतारना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। हमारी कोशिश, नीयत और मंशा इस दिशा में है और हम सक्रियता से इस बात के लिए लगे हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम करेंगे। हम इस बात के लिए माननीय सदस्य और उनके माध्यम से पूरी सदन को आश्वस्त करते हैं कि यह जो आपकी चिंता है वह जल्दी से जल्दी दूर हो जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पी0जी0आई0 में 50 और के0जी0एम0सी0 में 55 की बात की है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम प्रयास करेंगे कि यह दो महीने में आ जाये। हम चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त कर देंगे कि दो महीने में यह वेन्टिलेटर की संख्या बढ़ जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि प्रक्रिया चल रही है। इससे ज्यादा और अच्छा उत्तर नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि बेड भी बढ़ जायेंगे। पूरा उत्तर आ गया है और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी अनुपूरक प्रश्न अथवा उत्तर की अब आवश्यकता है। मनोज जी कृपया आप बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल वेन्टिलेटर बढ़ाने से सुविधा नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

वह तो खुद कह रहे हैं कि बेड भी बढ़ाने हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल करना चाहता हूँ उसके लिए एनेस्थीसिया का डाक्टर होना चाहिये जिसकी बड़ी कमी है। वेन्टिलेटर संचालित तभी होगा जब एनेस्थीसिया का डाक्टर होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एम0बी0बी0एस0 का कोर्स रिकग्नाइज्ड हो गया है, उन मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 की कक्षाएं जल्दी शुरू करने का काम करेंगे ? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे और जब तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे तब तक आप हजारों वेन्टिलेटर्स खरीद लीजिए काम नहीं नहीं चलेगा इसलिए उस पद को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में लोक सेवा आयोग से अप वान्ट निकलती है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की कमी रहती है तथा वह पूरा होता ही नहीं है। जब डॉक्टर्स पूरे नहीं होंगे तो वेन्टिलेटर्स कहां से चल पायेंगे ? हर मेडिकल कॉलेज में वेन्टिलेटर्स हैं। अम्बेडकरनगर में है, आजमगढ़ में है, हर जगह हैं और वह संचालित इसलिए नहीं हैं, क्योंकि वहां एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी वेन्टिलेटर्स की व्यवस्था करके और साथ-साथ स्टॉफ की व्यवस्था करके उसको संचालित करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसकी प्रकिया चल रही है। इसमें लगभग पौने दो सौ के करीब सीटें बढ़ा दी गयी हैं और तीन सौ सीटें प्रक्रिया में हैं। यह जल्दी से जल्दी होने जा रहा है।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 28-01-2020 तक विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु प्रदूषण किये जाने की घटनायें सरकार के संज्ञान में आयी हैं तथा कितनी ऐसी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बढ़ते हुये वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जी हां।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत वर्ष 2018 से 28.01.2020 के मध्य कुल 847 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस, 2155 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध बन्दी आदेश निर्गत किये गये तथा 308 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये गये।

जी हां।

प्रदेश के 15 प्रमुख प्रदूषणकारी शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गजरौला, नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, अनपरा, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजनायें निर्मित कर क्रियान्वित कर दी गई हैं। उक्त कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाना निर्धारित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आच्छादित होने वाले 08 शहरों यथा गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली तथा प्रदेश के 05 प्रमुख शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, तथा मुरादाबाद में वायु

प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रिस्पांस कार्य योजना लागू है, जिसका नियमित अनुश्रवण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपको ढेर सारा वाणी से, हृदय से और नाभि से भी धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो दस शहर हैं उसमें छः शहर उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें कोई योजना आज तक धरातल पर नहीं आई है, जिससे बचाव हो सके। सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि कब तक जिंदगी काटोगे, सिगरेट, बीड़ी और सिगार से कुछ दिन तो काटो यू0पी0 और एन0सी0आर0 से। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूं कि कार्य योजना तो निर्मित की गई, जिसके लिए हम आपको ढेर सारी सलामी देते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी विवरण नहीं है। अगर मा0 मंत्री जी विवरण बता देंगे तो हम ढेर सारा साधुवाद मंत्री जी को करेंगे। अगर विवरण बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

पूरे प्रदेश में एक ही योजना है या अलग-अलग योजना है और तीसरी खास तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानिटरिंग स्टेशन जो दिल्ली की तर्ज पर हैं क्या उसे लगवाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी और एक एक्ट केन्द्र सरकार ने जो एन0सी0पी0 योजना जो शुरू किया है क्या उत्तर प्रदेश में भी सरकार उसे लागू करेगी या नहीं करेगी ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 सदस्य इस हाउस के बहुत ज्यादा सीनियर और अनुभवी हैं। उनका जो सवाल है कि जो देश के 06 शहरों का जिक किया, प्रदूषित है। जो डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट 2016 में आयी थी। उसका आपने हवाला दिया है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जो 2016 में जिन शहरों की बात आपने कही है जो प्रदूषित थे उसी डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट 2018 में जब आयी, मैं आपको वह रिपोर्ट दे दूंगा। उसमें ही 2016 और 2018 में जो कमी है वह लगभग 30 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की कमी है। वह डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर है। लेकिन इसके बावजूद जो सी0पी0सी0बी0 जो अतिप्रदूषित शहर हैं। जो उनका आंकड़ा सर्वे में आया, उन्होंने तो कुछ शहरों का लिया है, केवल 06 शहर में 2016 में, 2018 में कुछ शहर उसमें चार ही रह गये। लेकिन सी0पी0सी0बी0 ने जो सर्वे किया है उसमें देश के शहरों में 15 को हमने लिया है। जो अति प्रदूषित शहर हैं। और उसके लिए हमने तमाम

कार्ययोजनायें बनायी हैं। और मैंने उत्तर में भी बताया। उसकी सुनवायी की जाती है। अगर कहीं मा0 सदस्य को इस तरह का कोई संज्ञान में है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और इस तरह के लिए मैटिंग सिस्टम के लिए मैनुअल और आटोमेटिक सिस्टम को भी हमने लखनऊ में भी 10 जगह किया है। पूरे प्रदेश में 33 जगह पर है। इसके बाद भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे देश में, प्रदेश में इस बात को लेकर चिंता है। पूरे हाउस को चिंता है उस चिंता को कम करने के लिए पूरे तरीके से सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मंत्री जी आपसे मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से केवल इतना आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया उसके निर्देशों के क्रम में एन0सी0आर0 में एंटी संयोग टावर के डायरेक्शन हैं। क्या मथुरा को उसमें शामिल करने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी। बस इतना आग्रह है।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इस पर सी0पी0सी0बी0 और आई0आई0टी0, बम्बई ने मिलकर जो सुझाव दिया उसको पूरे देश में एक स्थान पर दिल्ली में कनाट प्लेस में लगाने का उन्होंने सुझाव दिया है। इसके बाद अगर इसका रेडियस कुछ मात्रा में कम होता है तो निश्चित रूप से उसको एन0सी0आर0 में भी लागू करने का प्रयास करेंगे।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। बहुत गंभीर विषय है। हम लोग तथा हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रदूषित वातावरण में जीने के लिए मजबूर हैं। जितनी तरह-तरह की बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसे में आपने नवम्बर से लेकर दिसम्बर जनवरी में जब किसान अपने धान की फसल काटता है। तो उसके पास जो पराली बचती है उस पर रोक लगाने का काम दिल्ली सरकार ने, प्रदेश सरकार ने भी किया था। और यह कहा था कि अगर कोई किसान पराली जलाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। तो मैं मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की कार्रवाई उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ भी की जायेगी जो इसके मानक के विपरीत प्रदूषण कर रही हैं। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 की जायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न के पहले पैराग्राफ में ही उत्तर दिया हुआ है कि अनेक औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है और कार्रवाई की जा रही है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, एफ0आई0आर0 की कार्रवाई नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले भाग के उत्तर को पढ़िये। उसमें लिखा है कि अभियोजनात्मक कार्रवाई। इसका मतलब क्या हुआ ?

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं तथा अपशिष्ट पदार्थों की प्रति इकाई उत्सर्जन मानक क्या है तथा क्या इन इकाइयों द्वारा इस मानक का पालन किया जा रहा है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, आज ही पेपर में दिया गया है कि स्विटजरलैण्ड की एक संस्था ने सर्वे निकाला है और मुझे खुशी है कि उन्होंने 4-5 शहरों का नाम लिया है उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया गया है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक 20 फीसदी की कमी है। इसका मतलब है कि इस दिशा में जो वायु प्रदूषण में उत्सर्जन हो रहा है और इस प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और आगे भी इसी गंभीरता से काम करती रहेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के प्रमुख प्रदूषणकारी शहर हैं जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, रायबरेली इत्यादि शहरों का उल्लेख किया है।

श्री अध्यक्ष-

शहर प्रदूषणकारी नहीं है, प्रदूषण से युक्त है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, ठीक है, लेकिन यही एक बड़ी समस्या है। जनपद रायबरेली में शहर के बीचों-बीच कूड़े की रिसाइकिलिंग करके खाद बनाये जाने के लिए एक संयंत्र वर्ष 2005 में स्वीकृत हुआ था और जगह भी चिन्हित की गयी थी, लेकिन वह संयंत्र वर्ष 2011 में लगाया। वह संयंत्र वर्ष 2013 से बन्द पड़ा हुआ है और वहां पर लगभग 05 लाख मैट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है। बिजली का कनेक्शन भी कटा हुआ है, एन0जी0टी0 के चेयरमैन आये थे और उन्होंने आपत्ति जताई कि इस संयंत्र को चलाया जाए या तो इस संयंत्र को शहर की आबादी से बाहर किया जाए। प्रदूषण विभाग ने रिपोर्ट दी है कि इससे संक्रामक बीमारी हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एन0जी0टी0 की

रिपोर्ट और उससे बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए मा0 मंत्री जी उस कूड़े संयंत्र को शहर की आबादी से बाहर ले जाने पर विचार करेंगे ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, मा0 सदस्य का जो सवाल है वह अनुपूरक है और इस सवाल का मूल प्रश्न से ताल-मेल नहीं है। लेकिन फिर भी मा0 सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कार्यवाही को आगे बढ़ायेंगे।

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

गैरकानूनी कैसिनो को लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवा राज्य की भांति प्रदेश में भी गैरकानूनी जुआ रैकेटों को रोकने और भारी मात्रा में पर्यटन और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हेतु कैसिनो के लाइसेंस आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

कैसिनो एक निश्चित प्रकार के जुआ की सुविधा है। कैसिनो को लाइसेंस दिये जाने से प्रदेश में जुआ, सट्टा एवं लाटरी जैसी गतिविधियों को रोकना विधिक रूप से सम्भव नहीं हो पायेगा तथा इनको बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक एवं नैतिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत गोरखपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए हवाई यात्रा शुरू की है और मेरे जिले के कम-से-कम हजार लोग बधाई दे चुके हैं कि अब गोरखपुर तक फ्लाईट हो गयी है। अब हम गोरखपुर जाकर सुनौली बार्डर पार करके टाइगर रिजार्ट, नेपाल में जुआ खेलेंगे। कहने का मतलब है कि बिहार में एल्कोहल को बैन कर दिया गया है लेकिन मुझे ऐसा कोई बिहारी नहीं मिला जिसने एल्कोहल को पीना कम कर दिया हो। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कैसिनो लास वेगस है और उस लास वेगस के क्षेत्र में कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं है क्योंकि कैसिनों के माध्यम से इतना रेवन्यू आता है, वहां पर जो दो जिले हैं जहां पर कैसिनों है, मेरा कहने का मतलब यह है..

श्री अध्यक्ष-

आप कहिए मत, सवाल करिए।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मेरा सवाल यह है कि जो चीज इल-लीगल है, जिसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं, इन वजह से स्थिति अन-कंट्रोल्ड है, मैं आपको बताऊं कि जब मैं विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब मैच्स चलते थे....

श्री अध्यक्ष-

विदेश का यहां से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

तो कहा जाता था की बैट करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। अब क्या होता है कि जब आई0पी0एल0 का मैच होता है तो आप कोई भी समान लेने जाइए तो नजर टी0वी0 पर और एक हाथ से फोन पर है...

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, आपके पास सवाल नहीं है, उत्तर आ चुका है। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

***2-श्री लालजी वर्मा-**

[मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

बुंदेलखण्ड में गन्ना की उपज के अनुसार चीनी मिलों की स्थापना कराये जाने विषयक

***3-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों की भाँति बुन्देलखण्ड में भी गन्ना की पर्याप्त उपज के दृष्टिगत चीनी मिलों की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

गन्ने की खेती नगण्य होने के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने की खेती नगण्य होने के कारण चीनी मिल की स्थापना किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वास्तव में बुंदेलखण्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ एवं अविकसित रहा है, इसलिए वहां के लोग

बुंदेलखण्ड के विकास की मांग करते रहे क्योंकि पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार द्वारा चीनी मिलें लगाई जाती रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

जवाहर लाल जी, आप चीनी मिल के बारे में पूछिये।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय मंत्री जी, गन्ना और चीनी मिल लगाने के लिए क्या मानक है ? क्या गन्ना उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना बना रही है ? अगर वास्तव में गन्ना पैदावार वहां पर हो रहा है तो कब तक वहां पर चीनी मिल लगाने की योजना बनाएंगे क्योंकि किसान की आय को दुगुना करने का मा0 प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। आज ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से फसलों का नुकसान होता है, ऐसी फसलों को उगाने के लिए क्या गन्ना मंत्री जी प्रोत्साहन देंगे ?

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मा0 सदस्य को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने की तरफ विचार किया और मैं अभिनन्दन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बंद तमाम चीनी मिलों को चलाने का काम किया। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) जहां तक उन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी नीति है जिससे गन्ना किसान अधिक प्रोत्साहित हो सकता है ? तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत-सारी नीतियां है, चूंकि उन्होंने मिल संचालन की बात कही है, पिछले 25 सालों से उत्तर प्रदेश में एक भी खांडसारी उद्योग का लाइसेंस जारी नहीं हुआ था, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके निर्देश पर एक साल के अंदर हमने 108 नये खांडसारी उद्योगों का लाइसेंस जारी किया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) जहां लगता है कि मिल की क्षमता के लायक गन्ना नहीं है, मतलब पांच हजार टी0सी0डी0 की मिल की स्थापना करनी होती है तो पचास हजार कुण्टल गन्ना रोजाना चाहिए होता है, अगर ढाई हजार की भी करें तो पच्चीस हजार कुण्टल गन्ना रोजाना चाहिए। जहां ऐसा क्षेत्र है, जहां गन्ने का किसान गन्ने की खेती करना चाहता है, प्रोत्साहन चाहता है तो खांडसारी उद्योग को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारा प्रयास है और मा0 प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक किसान की आय को दुगुना किया जाये और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इस सपने को पंख लगाने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ है।*

---

* नोट :- नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, एक मिनट बैठ जाइए।

प्रदेश में पौधा तैयार करने के लिए वन विभाग के पास उपलब्ध भूमि व तैयार किये गये पौधों का विवरण

***4-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पौधा तैयार करने के लिए कितनी भूमि वन विभाग के पास उपलब्ध है तथा उसमें कितने पौधों तैयार किये जा सकते हैं ? क्या सरकार की उपलब्ध भूमि के सापेक्ष पौधा तैयार करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में पौध तैयार करने हेतु वन विभाग के पास वर्तमान में 1,491 पौध शालाओं में 1715 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिस पर लगभग 33.00 करोड़ पौधे तैयार किये जा सकते हैं।

प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौध तैयार किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सदस्य की संस्तुति पर 5 करोड़ रु0 की सड़क निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धन आवंटित किये जाने विषयक

***5-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा सदस्य की संस्तुति पर 05 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु धन आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं। आवश्यकतानुसार सड़क का निर्माण कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के वन विभाग की कृषि योग्य भूमि को कृषकों को आवंटित करने की नीति विषयक

***6-श्री नाहिद हसन-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग की नागरिक बसावटों के नजदीक स्थित कृषि योग्य भूमि को स्थानीय सीमांत कृषकों को कृषि कार्य हेतु आवंटित करने की सरकार की क्या नीति है ?

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में उपरोक्त श्रेणी की कुल कितने हेक्टेयर भूमि स्थित है तथा कुल कितने हेक्टेयर कृषि कार्य हेतु कृषकों को आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना किसानों का मूल भुगतान समय से कराने तथा मिल मालिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के ब्यौरे सदन के पटल पर रखे जाने सम्बन्धी

***7-हाजी इरफान सोलंकी, श्री राकेश प्रताप सिंह तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को बीते गन्ना पेराई सत्र 2018-19 व चालू पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ना मूल्य का निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर 31 दिसम्बर 2019 तक उक्त मिल मालिकों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकियों एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाहियों का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

पेराई सत्र 2018-19 में गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के कारण, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक, प्रदेश की चीनी मिलों के विरुद्ध दर्ज करायी गई प्राथमिकियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	नाम चीनी मिल/जनपद	मुकदमा दर्ज कराने का दिनांक	अधिनियम जिसके अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया
1	2	3	4
1	शामली जिला शामली	22.01.2019	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2	सिम्भावली जिला हापुड़	04.01.2019 एवं 21.09.2019 (02 प्राथमिकी)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860
3	मोदीनगर जिला गाजियाबाद	22.09.2019	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860

4	बृजनाथपुर जिला हापुड़	04-01-2019	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5	अगवानपुर जिला मुरादाबाद	07-03-2019	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
6	बेलवाड़ा जिला मुरादाबाद	12-04-2019	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
7	बिलाई जिला बिजनौर	13-06-2019	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
8	बिसौली जिला बदायूं	06-03-2019 एवं 23-08-2019 (02 प्राथमिकी)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एंव भारतीय दण्ड संहिता, 1860
9	चिलवरिया जिला बहराइच	24-01-2019	भारतीय दण्ड संहिता, 1860

उपर्युक्त के अतिरिक्त चीनी मिल बिसौली-बदायूँ के विरुद्ध पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु दिनांक 15-11-2019 को वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया है।

वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 अभी चल रहा है तथा गन्ना मूल्य भुगतान प्रक्रियागत है। इस सत्र में चीनी मिलों के विरुद्ध अभी कोई प्राथमिकी की कार्यवाही नहीं की गई है, परन्तु चीनी मिलों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु दिनांक 04-02-2020 को नोटिसें निर्गत की गई हैं।

उपर्युक्तानुसार।

क्षेत्रों में केबिल, पाइप या सीवर आदि डालने हेतु खोदी गयी सड़कों को चिन्हित कर शीघ्र ठीक कराने सम्बन्धी

***8-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केबिल, पाइप या सीवर आदि डालने हेतु खोदी गयी सड़कों को चिन्हित कर उन्हें निश्चित अवधि में सरकार ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

जी हाँ।

पाइप लाइन/सीवर लाइन डालते समय खोदी गयी सड़कों को ठीक कराने का कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था/फर्म की होती है। लाइन डालने के उपरान्त सड़क को प्रथम चरण में अस्थायी रूप से बनाया जाता है, लाइन की टेस्टिंग होने के उपरान्त स्थायी रूप से पी0डब्ल्यू0डी0 के मानक के अनुसार ठीक कर दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश एवं जनपद प्रयागराज के नव विकसित शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों एवं महानगरों में विकसित हो रही आवासीय तथा व्यावसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद प्रयागराज की आवासीय एवं व्यवसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.11.5 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.11.5 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं शीर्षक के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

''जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भू-खण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।'' प्रयागराज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 120 आवासीय, समूह आवास एवं व्यवसायिक भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार निर्मित एवं क्रियाशील है। प्रश्न नहीं उठता।

पेराई सत्र 2019-20 में गन्ने का मूल्य 450 रु0 प्रति कुंतल करने व बकाया मूल्य का भुगतान कराये जाने विषयक

***10-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र 2019-20 के लिए गन्ने के मूल्य में कितने रुपये की बढ़ोत्तरी की है ? क्या सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य 450/- रुपये प्रति कुंतल प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में आने वाली लागत तथा चीनी मिलों की चीनी उत्पादन लागत, चीनी आदि उत्पादों के बाजार मूल्य तथा चीनी मिलों व गन्ना कृषकों के पक्ष

को सुनते हुए सुसंगत पहलुओं पर विचार कर कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2018-19 में घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य को यथावत रखते हुए, वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 के लिए विज्ञप्ति संख्याः 09/2019/2274/46-3-19-3(48)/98-99 दिनांक 07-12-2019 द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य घोषित किया जा चुका है, जो निम्नवत है :-

अगेती प्रजाति	रु0 325.00 प्रति कुन्तल
सामान्य प्रजाति	रु0 315.00 प्रति कुन्तल
अनुपयुक्त प्रजाति	रु0 310.00 प्रति कुन्तल

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

दिनांक 24-02-2020 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2018-19 में संचालित कुल 119 चीनी मिलों में से निगम क्षेत्र की 03, सहकारी क्षेत्र की 24 तथा निजी क्षेत्र की 83 चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तथा निजी क्षेत्र की 09 चीनी मिलों पर आंशिक गन्ना मूल्य (रु0 452.42 करोड़) अवशेष है। उक्त 09 बकायेदार चीनी मिलों में से 05 चीनी मिलों यथा-बिसौली, पलियाकलां, मोदीनगर, सिम्भावली एवं बुलन्दशहर पर अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है।

वर्तमान में पेराई सत्र 2019-20 अभी चल रहा है। इस सत्र के अन्तर्गत, दिनांक 24-02-2020 तक की स्थिति के अनुसार, प्रदेश की चीनी मिलों पर सूचना की तिथि को, कुल देय हुए गन्ना मूल्य (14 दिन पूर्व) रु0 18,375.48 करोड़ के सापेक्ष रु0 10,422.69 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 56.72 प्रतिशत है। इस पेराई सत्र में देय गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु चीनी मिलों को दिनांक 04-02-2020 को नोटिसें निर्गत की गई हैं। राज्य सरकार गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कार्य योजना विषयक

***11-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना लागू की गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि बीते अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर माह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े महानगरों में वायु जल एवं ध्वनि प्रदूषण मानक से काफी

ज्यादा व खतरनाक स्तर पर पहुँच गया था ? यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

प्रदेश के 15 प्रमुख प्रदूषणकारी शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गजरौला, नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, अनपरा, मुरादाबाद, बरेली तथा रायबरेली हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्य योजनाओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जा चुका है। उक्त कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की 12 नदियों यथा गंगा, रामगंगा, गोमती, हिण्डन, काली पूर्वी, वरुणा, यमुना, बेतवा, घाघरा, राप्ती, साई एवं सरयू नदी में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषित नदी खण्ड चिन्हित किये गये हैं। उक्त नदी खण्डों के पुनर्जीवन हेतु अन्तर्विभागीय कार्य-योजनायें निर्मित कर क्रियान्वित कर दी गयी हैं। इन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित रीवर रिजूवेनेशन समिति द्वारा किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

शीतकाल में प्रदेश की राजधानी समेत बड़े महानगरों में वायु प्रदूषण में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, जिसका मुख्य कारण तापमान एवं वायु की गति में कमी तथा स्थानीय कारकों के साथ-साथ निकटवर्ती राज्यों पंजाब व हरियाणा में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण का उत्तरी पश्चिमी हवाओं द्वारा राज्य में आना है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये गये अनुश्रवण में प्रदेश के महानगरों में जल एवं ध्वनि प्रदूषण में विगत शीतकाल (अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2019) में अत्यधिक वृद्धि नहीं पायी गयी है।

प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्य योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पालीथीन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को बंद करने विषयक

***12-श्री विजय मिश्र-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को सरकार पूर्णतया बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की कोई इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)-2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टम्बलर के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 17 से दिसम्बर, 19 तक जिला सड़क मार्गों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण व मरम्मतीकरण कराये जाने व फोरलेन बनाने सम्बन्धी विवरण

***13-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक किन-किन जिला सड़क मार्गों का चौड़ीकरण, सुन्दरीकरण व गड्ढामुक्त कराने के साथ ही फोरलेन सड़क बनायी जा चुकी है, तथा कितनी शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर सूचीवार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि में अन्य जिला मार्ग तथा प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी के कुल 34 कार्यों के फोरलेन निर्माण हेतु स्वीकृतियाँ निर्गत की गयीं हैं। वर्तमान समय में 17 कार्य पूर्ण हैं व शेष 17 कार्य प्रगति में हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0 क्षेत्र बेहट में ग्राम दयालपुर तह0 बेहट में आवारा कुत्तों के काटने से दो मासूमों की मृत्यु के दृष्टिगत बचाव हेतु ठोस नीति बनाने के सम्बन्ध में

***14-श्री नरेश सैनी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम दयालपुर, तहसील बेहट में आवारा कुत्ते के काटने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आवारा कुत्तों से बचाव हेतु सरकार कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

ग्राम दयालपुर में दो बच्चों की मौत कुत्तों के काटने से हुई है या किसी अन्य जानवर के काटने से हुई है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामवासियों द्वारा यह आशंका जताई गई की दोनों बच्चों की मौत कुत्तों के काटने से हुई है। जिसको दष्टिगत रखते हुए उपजिलाधिकारी बेहट के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा सभी आवारा कुत्तों को पकड़वाकर दूर जंगलों में छोड़ा गया है तथा लगभग 01 माह तक पी0ए0सी0 पुलिस बल द्वारा ग्राम में कैम्प लगाकर अभियान भी चलाया गया।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-691/2009 एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया बनाम पीपुल्स फार एलिमिनेशन आफ स्ट्रे ट्रवल्स व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-03-2016 के अनुपालन में एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) रूल्स 2001 के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि के प्रबन्धन, रेबीज उन्मूलन एवं मानव कुत्तों में संघर्ष आदि में कमी लाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135(1)/9-8-2018-89ज/2017 दिनांक 14 मई, 2018 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त मानव-कुत्तों में संघर्ष तथा कुत्तों की आक्रामकता में कमी लाने के उद्देश्य से निराश्रित श्वानों के बंध्याकरण हेतु एनिमल बर्थ कन्ट्रोल योजनान्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में से रुपये 10.00 करोड़ की राज्य स्तरीय निधि का गठन शासनादेश संख्या 849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा किया गया है।

उ0प्र0 के प्रत्येक जिले में लैण्ड यूज रेजीडेंशियल प्लान का पालन कराये जाने व जनपद सहारनपुर में मास्टर प्लान रिवाइज करने विषयक

***15-श्री मसूद अख्तर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर सहित प्रदेश में लैण्ड यूज प्लान के विरुद्ध विकसित हो रही अवैध कालोनियों को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लैण्ड यूज रेजीडेंशियल प्लान का कड़ाई से पालन सरकार करायेगी ? क्या सरकार जनपद सहारनपुर में मास्टर प्लान रिवाइज करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश में लैण्ड यूज प्लान के विरुद्ध विकसित हो रही अवैध कालोनियों को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में सहारनपुर महायोजना, 2021 प्रभावी है। भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत जी0आई0एस. आधारित महायोजना

तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के 60 नगरों को चयनित किया गया है, जिसमें सहारनपुर नगर भी सम्मिलित है तथा जिसके पुनरीक्षण का कार्य सहारनपुर महायोजना, 2031 के लिए भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत संपादित किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त करने के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने विषयक

***16-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं के तहत सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है एवं उक्त लक्ष्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने हेतु वर्ष 2019-20 में समस्त विभागों का कुल लक्ष्य 58299 कि0मी0 रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 55272 कि0मी0 मार्ग गड्ढामुक्त किये जा चुके हैं। (अब तक 95 प्रतिशत लम्बाई में मार्गों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है)

मार्गों पर गड्ढों के बनने एवं इनकी मरम्मत कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

उपर्युक्तानुसार।

मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों में वेंटीलेटर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

***17-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में वेंटीलेटर स्थापित किये जाने के क्या मानक है ? क्या सरकार बताएगी कि निर्धारित मानक में प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा तथा राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में एम0सी0आई0 मानकों का पालन किया जाता है। एम0सी0आई0 मानक के अनुसार 100 एम0बी0बी0एस0 यू0जी0 सीट पर 20 बेड के आई0सी0यू0 के साथ 20 वेंटीलेटर्स तथा इमरजेन्सी में 20 बेड के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात् 10 वेंटीलेटर्स के मानक निर्धारित हैं।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा एक टर्शियरी केयर संस्थान है और निर्धारित मानकों के अनुसार संस्थान में आई0सी0यू0 बेड की संख्या कुल बेडों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकती है।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में एम0सी0आई0 मानकानुसार उपलब्ध वेंटीलेटर्स की स्थिति निम्नवत है :-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 250 एम0बी0बी0एस0 सीटों के सापेक्ष 193 वेंटीलेटर्स।

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 200 एम0बी0बी0एस0 सीटों के सापेक्ष 65 वेंटीलेटर्स।

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 200 एम0बी0बी0एस0 सीटों के सापेक्ष 89 वेंटीलेटर्स।

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में 100 एम0बी0बी0एस0 सीटों (प्रथम वर्ष) के सापेक्ष 10 वेंटीलेटर्स।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं हैं।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 205, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में 20, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में 02 तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में 18 वेंटीलेटर्स क्रियाशील हैं।

संस्थानों की आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधन के दृष्टिगत वेंटीलेटर्स उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश की बचत दर को बढ़ाने के सम्बन्ध में

***18-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बचत की वर्तमान औसत दर क्या है और उसमे उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है ? क्या सरकार उत्तर प्रदेश की बचत दर बढ़ाने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में देश की सकल बचत, जी0डी0पी0 का 30.5 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश में 'अल्प बचत' की कुल जमा धनराशि रुपये 6,74,856.46 करोड़ है जिसमें

उत्तर प्रदेश का अंश रुपये 79,183.85 करोड़ है। देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है।

प्रदेश की अल्प बचत में निवेश को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनायी गयी है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1-वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में रु0 6,000 करोड़ शुद्ध जमा का लक्ष्य रखा गया है।

2-जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के लिये जनपद, तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर बैठकों, गोष्ठी आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करके धन जमा कराने के लिए प्रेरित किया जाता है।

3-निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में लोक भविष्य निधि खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि लोकप्रिय योजनाओं में आयकर में छूट की योजना सहायक होती है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर आयकर की पुस्तिका, पेम्फलेट, फोल्डर्स आदि का मुद्रण कराकर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाये जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र लगाये गये तथा उनमें से कितने सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि घनी आबादी में लगे उक्त संयंत्रों के प्रदूषण से उन क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे संयंत्रों को आबादी से बाहर लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ। प्रदेश में 24 नगर निकायों (13 नगर पालिका परिषद, 11 नगर निगम) में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मोड पर विगत वर्षों में लगाये गये हैं, जिनमें से 12 संयंत्र अस्थायी रूप से संयंत्र ऑपरेटर से आर्बिट्रेशन/विवाद के कारण सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर-मुजफ्फरनगर टोल रोड पर टोल शुल्क को कम करने विषयक

1-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर टोल रोड पर वसूला जाने वाला टोल शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों पर वसूले जाने वाले टोल शुल्क के सापेक्ष कितना अधिक है ? क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर वसूले जाने वाले अधिक टोल शुल्क कम करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (दरों का अवधारण एवं पथकर का संग्रहण) नियमावली, 2011 के अनुसार उपशा द्वारा टोल शुल्क की वसूली की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पथकर नीति के अनुसार फोर लेन मार्गों के लिए 01 अप्रैल, 2019 से वर्ष 2019-20 हेतु टोल शुल्क की आधार दरें निम्नवत हैं :-

वाहन का प्रकार	01 अप्रैल 2019 से उपशा की आधार दरें (2019-20)	01 अप्रैल 2019 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधार दरें (2019-20)
	फीस दर प्रति कि0मी0 (रु0)	
कार, जीप, वैन या हल्के वाहन, थ्री व्हीलर या गैर कृषि उत्पाद ले जा रहे ट्राली युक्त ट्रैक्टर मोटर यान	1.044	1.1558
हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.566	1.8671
बस या ट्रक	3.131	3.9120
हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या मल्टी एक्सल वेहिकल तीन से छः एक्सल	5.219	6.1348
ओवर साइज वेहिकल (सात या अधिक एक्सल)	6.263	7.4684

उक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में उपशा द्वारा वसूले जा रहे टोल शुल्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल शुल्क की तुलना में कम हैं।

जनपद मऊ की वि0स0 क्षेत्र घोसी के बरलाई मोड़ से धवरिया साथ तक आजमगढ़ मऊ को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने विषयक

2-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र की बरलाई मोड़ से धवरिया साथ तक की सड़क जो आजमगढ़ मऊ की मुख्य सड़क से जुड़ती है पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण व उच्चीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित मार्ग की लम्बाई 7.03 कि0मी0 है जिसमें 2 मार्ग सम्मिलित हैं जिनका विवरण निम्नवत हैं :-

1-बरलाई मोड़ से पुराघाट तक का मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 4.430 कि0मी0 है लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है, मार्ग का विगत नवीनीकरण नवम्बर, 2016 में हुआ है। मार्ग के इस भाग में पैच मरम्मत का कार्य दिसम्बर, 2019 में कराया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

2-पुराघाट से धवरियासाथ तक 2.60 कि0मी0 लम्बाई का अन्य जिला श्रेणी मार्ग है, जिसकी लेपित सतह 3.75 मीटर है उक्त भाग का नवीनीकरण 11/2019 में कराया गया है। वर्तमान में मार्ग की सतह यातायात हेतु सुगम है।

ग्रामीण श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। मार्ग के द्वितीय भाग पर यातायात घनत्व 3500 पी0सी0यू0 है जो 6000 पी0सी0यू0 से कम होने के कारण 7.00 मीटर चौड़ीकरण के मानकों से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के ग्लोबल मेडिकल कालेज के मानक अधूरे होने के कारण नीट के माध्यम से प्रवेश पाये अभ्यर्थियों का स्थानान्तरण दूसरे मेडिकल कालेज में कराने विषयक

3-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्लोबल मेडिकल कालेज में मानक न पूरे होने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि नीट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाये अभ्यर्थियों का स्थानान्तरण किसी दूसरे मेडिकल कालेज में किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये किसी दूसरे मेडिकल कालेज में प्रवेश दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्य सरकार द्वारा मानक पूर्ण न होने के कारण संस्था को राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया है।

संस्था के वैध प्रवेशित छात्रों का समायोजन निजी क्षेत्र के अन्य मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2016 के अन्तर्गत रिक्त सीटों के सापेक्ष किए जाने हेतु छात्रों से विकल्प प्राप्त कर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, नई दिल्ली को तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमति हेतु दिनांक 03.02.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.02.2020 के अनुसार शासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित छात्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री असलम अली-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित मड़ियांव थाने से केशव नगर पुलिस चौकी मोड़ तक मार्ग के नाला निर्माण के विषयक

5-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित मड़ियांव थाने से केशव नगर पुलिस चौकी मोड़ तक के मार्ग पर वर्षा के दिनों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त सड़क के किनारे नाले का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग की लगभग 2.50 कि0मी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के दाऊदनगर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने सम्बन्धी

6-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित फैजुल्लागंज-द्वितीय वार्ड के दाऊदनगर में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या पैमाइश कराकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ

ग्राम दाऊदनगर की नगर निगम में निहित ग्राम समाज की कुल भूमि 9.129 हे0 के सापेक्ष 0.662 हे0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया। अवैध कब्जों की बेदखली हेतु कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के शीतगृह वाटिका के सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक

7-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज स्थित शीतगृह वाटिका के अधूरे सौन्दर्यीकरण कार्य को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसी योजना का भाग नहीं है, ऐसी स्थिति में लोकहित के कार्य अवस्थापना विकास निधि में प्रस्तावित किये जाते हैं।

उक्त कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित किया गया था। स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि शासन द्वारा माह जुलाई, 2017 से अवमुक्त न हो पाने के कारण कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। अतः उपलब्ध संसाधनों में आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर अवस्थापना मद से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य निष्पादित कराया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अन्तरण मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कोई बजट व्यवस्था नहीं की गयी है। अतः उक्त मद से उपर्युक्त वांछित धनराशि अवमुक्त किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया से लाल पुल तक बने बन्धा मार्ग के चौड़ीकरण के विषयक

8-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से सीतापुर रोड स्थित पुरनिया से लाल पुल तक बने बन्धा मार्ग पर भारी वाहन एवं अन्य वाहनों का दबाव रहता है तथा आये दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सर्विस रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

लखनऊ से सीतापुर मार्ग पर स्थित पुरनिया से लाल पुल तक बना बंधा मार्ग मूल रूप से सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। अतः इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद लखनऊ में आवासीय भू-खण्ड का व्यावसायिक उपयोग हेतु नियम बनाये जाने विषयक

9-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आवासीय भू-खण्ड का व्यावसायिक उपयोग किये जाने हेतु नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या नियमों में संशोधन करते हुए वर्ष 2016 के पूर्व बने ऐसे आवासीय भू-खण्ड जहां सड़क 24 मीटर या उससे अधिक है, का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-457/आठ-3-16-127 विविध/11 दिनांक 08.07.2016 निर्गत की गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की पूर्व में नियोजित कालोनियों में आवासीय भू-खण्डों पर जहां सड़क 24.00 मीटर या उससे अधिक है, को व्यावसायिक किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाने एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही करते हुए अनुज्ञा से संबंधित आवेदन

पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान उक्त अधिसूचना दिनांक 08.07.2016 में है। उपरोक्तानुसार।

वेतन आयोग शासनादेश दिनांक 14.06.2012 की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के प्रस्तर 12 के अनुपालन में की गई कार्यवाही विषयक

10-श्री लाल जी वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग के शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-288/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 14 जून, 2012 जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (वित्त लेखा परीक्षा-2) के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, के प्रस्तर-12 के अनुपालन में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन सम्बन्धी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-288/दस-54(एम)/ 2008 टी0सी0 दिनांक 14 जून, 2012 के प्रस्तर-12, में की गयी संस्तुतियों के अनुपालन में वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-आडिट-2018/दस-2012 350(1)/12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के ग्रामीण क्षेत्रों बसखारी, मलिकपुर व मखदूम नगर को ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नगरीय क्षेत्र के 17 वार्डों के नाम इंट्री कराने विषयक

11-श्री लाल जी वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को सम्बोधित अधिशाषी अधिकारी, अशरफपुर किछौछा नगर अम्बेडकर नगर का पत्र-117/न0पं0कि0/2019-20, दिनांक 07.08.2019, जो कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के विस्तारित क्षेत्र में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों बसखारी, मलिकपुर एवं मखदूम नगर को ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नगरीय क्षेत्र के 17 वार्डों का नाम इन्ट्री कराने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी, हां।

अधिशासी अधिकारी, के पत्र के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकरनगर ने पत्र संख्या-409/ स0क0/वृ0पें0/2019-20, दिनांक 22.08.2019 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में सम्मिलित राजस्व ग्राम मलिकपुर, बसखारी व मखदूमनगर को समाज कल्याण की समस्त योजनाओं के वेबसाइट पर सम्मिलित कराने अथवा जनपद स्तर पर सम्मिलित करने का आप्शन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तद्क्रम में समाज कल्याण विभाग, लखनऊ द्वारा sspy-up.gov.in वेबसाइट पर नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के वार्डों के नाम संशोधित विवरण के अनुसार प्रदर्शित करा दिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में किसान सहकारी चीनी मिल में भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

12-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 12.9.17 जो किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहाँपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के जाँच के सम्बन्ध मे है, उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या जिसे आपके कार्यालय पत्रांक सं0 430 दिनांक 12.9.17 द्वारा प्रमुख सचिव गन्ना को प्रेषित कर जाँच के आदेश दिये गये है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 12.09.2017 प्राप्त न होकर पत्र दिनांक 05.09.2019 प्राप्त हुआ है।

कार्यालय के पत्रांक सं0 430 दिनांक 17.09.2019 द्वारा प्रमुख सचिव गन्ना को प्रेषित कर जांच के आदेश दिये गये हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहाँपुर की जांच में चीनी मिल तिलहर को प्रेसमड के विक्रय में कोई वित्तीय हानि नहीं पायी गयी। कृषकों के मध्य प्रेसमड वितरण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0 स0 क्षे0 बेहट के अकबरपुर के पहले बूढ़ी यमुना नदी पर आवागमन हेतु पुल निर्माण के सम्बन्ध में

13-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में अकबरपुर के पहले बूढ़ी यमुना नदी पर पुल न होने से बेहट में रायपुर से अकबरपुर

डूडूमाजरा, लादीबास आदि स्थानों हेतु आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बूढ़ी यमुना नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल से लगभग 1.50 किमी0 दूरी पर अपस्ट्रीम में गंदेवड़ रायपुर हथनीकुण्ड बैराज मार्ग तथा डाउनस्ट्रीम में लगभग 4 किमी0 की दूरी पर पठेड-नानौली से लतीफपुर भूड मार्ग पर पूर्व में ही बूढ़ी यमुना नदी पर पुल निर्मित है। प्रश्नगत सेतु स्थल से अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम में 10 किमी0 के अन्दर पुल निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना में सिटी बस चलाये जाने विषयक

14-श्री मसूद अख्तर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना में चयनित शहर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद सहारनपुर में सिटी बस का संचालन शुरू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना के विवरण

15-श्री मसूद अखतर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी योजना सरकार चला रहीं है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर क्रिटिकली/

सीरियसली औद्योगिक समूहों एवं नान अटेनमेन्ट सिटीज को चिन्हित किया जाता है। जनपद सहारनपुर उक्त में आच्छादित नहीं है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद सहारनपुर में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में औसत PM 10-175.98 माइक्रोग्राम/घन मी0, SO2-16.69 माइक्रोग्राम/घन मी0 एवं NO2- 27.66 माइक्रोग्राम/घन मी0 पाया गया था, जोकि वर्ष 2019 में घटकर औसत PM10- 171.46 माइक्रोग्राम/घन मी0, SO2- 15.92 माइक्रोग्राम/घन मी0 एवं NO2- 23.45 माइक्रोग्राम/घन मी0 पाया गया, जिससे क्षेत्र की वायु गुणता में सुधार परिलक्षित होता है। जनपद सहारनपुर में हिण्डन नदी प्रवाहित होती है, जोकि क्रिटिकली पॉलयूटेड रीवर स्ट्रेच के अन्तर्गत चिन्हित है। हिण्डन नदी के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुमोदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर क्रियान्वित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित रीवर रिजुवेनेशन कमेटी द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली में सरकार द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि से स्वीकृति मार्ग भानपुर सामुदायिक केन्द्र होते हुए कोटिया हरिजन टोला, भर टोला, से असनहरा मार्ग तक, बड़ौगी बार्डर से हलुआ का डीह से बनगंवा होते हुए गोबरहिया का हरिजन पुरवा मार्ग बनटीकरा से पेलनी हरजन टोला तक का मार्ग धनाभाव के कारण अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सड़क निधि से स्वीकृत मार्गों के लिए धन उपलब्ध कराकर मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों का विवरण निम्नवत है :-

1-भानपुर सामुदायिक केन्द्र होते हुए कोटिया हरिजन टोला सम्पर्क मार्ग प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है।

2-भरटोला से असनहरा मार्ग बड़ौगी बार्डर से हलुआ का डीह से बनगवां होते हुए गोबरहिया का हरिजन पुरवा सम्पर्क मार्ग प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है।

3-बनटिकरा से पेलनी हरिजन टोला मार्ग-मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है।

क्र0सं0-1 व 2 पर अंकित मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के पाण्डेय बाजार पुरानी बस्ती से डुमरियागंज जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

17-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत पाण्डेय बाजार पुरानी बस्ती से डुमरियागंज जाने वाले मार्ग नगरपालिका सीमा से हाईवे ब्रिज तक अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को जिला पंचायत से अधिग्रहण कर लो0नि0वि0 को स्थानान्तरित कर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग एक शहरी आन्तरिक मार्ग है जिसका स्वामित्व जिला पंचायत बस्ती का होने के कारण लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

18-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[03 सोमवार के अता0 प्र0 सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के लो0नि0वि0 द्वारा स्थापित निरीक्षण भवन सोनहा के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित निरीक्षण भवन, सोनहा में किचन व कक्ष की स्थिति अत्यन्त खराब है, रात्रि निवास में तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती के सोनहा में स्थापित निरीक्षण भवन में दो अतिरिक्त कक्ष एवं किचन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। सोनहा निरीक्षण भवन के दोनों कक्ष एवं किचन की स्थिति संतोषजनक है।

दो अतिरिक्त कक्ष व किचन निर्माण हेतु आगणन गठित किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के कतिपय व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता के बावजूद वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रुधौली बाजार में स्थित नजूल की भूमि में आश्रय योजना के तहत आवास निर्माण कराकर वंचित लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद बस्ती के नगर पंचायत, रुधौली बाजार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार (बी0एल0सी0) के अन्तर्गत कुल पात्र पाये गये 1208 लाभार्थियों के सापेक्ष 1059 लाभार्थियों को प्रथम किश्त, 891 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त व 370 लाभार्थियों को तृतीय किश्त की धनराशि निर्गत की गई है। बी0एल0 सी0 (नया) के अन्तर्गत 107 लाभार्थियों व बी0एल0सी0 (विस्तार) के अन्तर्गत 110 लाभार्थियों का डी0पी0आर0 स्वीकृत हुआ है तथा बी0एल0सी0 (नया) के अन्तर्गत 440 पात्र लाभार्थियों व बी0एल0सी0 (विस्तार) के अन्तर्गत 138 पात्र लाभार्थियों का डी0पी0आर0 तैयार कर जांच की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इसके बावजूद कोई पात्र व्यक्ति वंचित रह जाता है तो उसे शीघ्र चिन्हित कर योजना का लाभ दिया जायेगा।

नगर पंचायत, रुधौली बाजार में आश्रय योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु काम्प्रेहेंसिव रिस्पांस एक्शन प्लान सदन के पटल पर रखने विषयक

21-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के प्रथम बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के क्रम में क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु काम्प्रेहेंसिव रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार 16 विभागों हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्लान का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

जी हाँ।

पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रेहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एअर पॉल्यूशन तैयार कर लागू किया गया है।

इस कार्य योजना के अन्तर्गत कुल 16 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा परिवेशीय वायु में पी0एम0 10 की मात्रा के स्तर के आधार पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार 34 कार्यवाही के बिन्दु निर्धारित हैं :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्रदूषण के विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	परिवहन विभाग (04 बिंदु)	1-शहरों में भारी वाहनों की इन्ट्री का प्रतिबन्ध। 2-आड-इवन प्रणाली लागू करना। 3-भारत स्टेज-4 वाहनों का संचालन। 4-सी0एन0जी0/बैट्री चालित वाहनों के संचालन हेतु प्रोत्साहन आदि।
2	ट्रैफिक विभाग (गृह विभाग) (03 बिंदु)	1-शहरों में भारी वाहनों की इन्ट्री का प्रतिबन्ध। 2-आड-इवन प्रणाली लागू करना। 3-वाहनों का निर्बाध संचालन।
3	नगर विकास विभाग (05 बिंदु)	1-निर्माण कार्यों को रोकना। 2-सड़कों की खुदाई को रोकना। 3-सड़कों की साफ-सफाई कराना। 4-जल का छिड़काव। 5-नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाने से रोकना।
4	राजकीय निर्माण विभाग (02 बिंदु)	1-भवन निर्माण कार्यों को रोकना। 2-सड़कों का निर्माण रोकना।
5	खनन विभाग (01 बिंदु)	1-खनन कार्यों को रोका जाना।
6	जिला प्रशासन (04 बिंदु)	1-विभिन्न विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण रोकने हेतु कार्यवाही का स्वतः मानीटरिंग। 2-भट्ठों का संचालन रोकना। 3-हाट मिक्स प्लांट का संचालन रोकना। 4-डी0जी0 सेट संचालन रोकना।
7	फायर सेफ्टी विभाग (01 बिंदु)	1-सड़कों पर जल छिड़काव।

8	शिक्षा विभाग (01 बिंदु)	1-अधिक प्रदूषण की स्थिति में स्कूलों का बन्द करना।
9	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (01 बिंदु)	1-वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की नियमित जाँच कराते हुए दोषी इकाइयों पर कार्यवाही।
10	नेशनल हाई-वे अथारिटी आफ इण्डिया (01 बिंदु)	1-विटुमिन गर्म करने तथा सड़कों की खुदाई को रोकना।
11	आवास विकास परिषद (02 बिंदु)	1-भवन निर्माण कार्य रोकना। 2-सड़कों का निर्माण कार्य रोकना।
12	उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (01 बिंदु)	1-डी0जी0 सेट संचालन रोकना।
13	कृषि विभाग (01 बिंदु)	1-पराली/भूसा को जलाने से रोकना।
14	खाद्य एवं रसद विभाग (01 बिंदु)	1-लकड़ी एवं कोयला जलाने से रोकना।
15	सी0एन0जी0 आपूर्तिकर्ता कम्पनियां (01 बिंदु)	1-निर्बाध रूप से वाहनों हेतु सी0एन0जी0 आपूर्ति करना।
16	इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक डेवलपमेन्ट विभाग (05 बिंदु)	1-निर्माण कार्य रोकना। 2-सड़कों की खुदाई को रोकना। 3-सड़कों की साफ-सफाई। 4-सड़कों पर जल का छिड़काव। 5-नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाने से रोकना।

कुल कार्य बिंदु-34

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय विभागों द्वारा बिना विभागीय परीक्षा लेखाकार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पद पर की गई पदोन्नतियों के कारण उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण हेतु विभागीय परीक्षा का प्राविधान करने विषयक

22-श्री संजय गर्ग-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के विभिन्न विभागों में लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के लेखा कर्मियों के लिए सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर तथा लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा प्रथम का प्राविधान वित्त विभाग द्वारा किया गया था जो दिनांक 10-10-2011 से समाप्त कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त समयावधि में कतिपय विभागों द्वारा

बिना विभागीय परीक्षा के लेखाकार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नतियां की गयी तथा कतिपय विभागों द्वारा अपने कर्मिकों की विभागीय परीक्षा न हो पाने के कारण पदोन्नति नहीं की गयी जिसके कारण लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में विसंगतियां हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु पुनः विभागीय परीक्षा का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

कतिपय विभागाध्यक्षों द्वारा दिनांक 24-09-2001 से 10-10-2011 के मध्य शासनादेशों में प्रतिपादित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना पदोन्नति की कार्यवाही की गयी जिसके कारण विसगतियां उत्पन्न हुई। राज्य सरकार द्वारा पुनः विभागीय परीक्षा का प्राविधान किया जाना विचाराधीन नहीं है।

आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में अवैध चट्टे हटाने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

23-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जानवरों के अवैध चट्टे हटाने हेतु कानपुर नगर निगम सीमा के बाहर कैटिल कालोनियों के निर्माण के पश्चात भी कानपुर नगर निगम जोन-1 के वार्ड संख्या 89, चेक संख्या 76 में मकान नं0 76/228, 76/228ए एवं 76/241 के अतिरिक्त अन्य अवैध डेरी भी संचालित हैं तथा सब्जी मण्डी कुलीबाजार गुलियाना, थाना बादशाहीनाका, कानपुर नगर के चट्टे नहीं हटाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सराकर उपरोक्त चट्टे हटवाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत जोन-1 के वार्ड संख्या 89, चेक संख्या 76 में मकान नं 76/228, 76/241, 76/184 सब्जी मण्डी, कुलीबाजार गुलियाना, थाना बादशाही, नाका, कानपुर में संचालित चट्टों को पूर्व में ही दिनांक 17-10-2019 को कार्यवाही कर हटाया गया है।

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित अवैध चट्टा संचालकों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हमीरपुर रोड पर कैटिल कालोनी आंवटित की गयी है तथा पूर्व में विस्थापित

कराया गया है, किन्तु कुछ चट्टा संचालक वापस आकर चट्टा संचालित कर रहे हैं, उनका चिन्हांकन कर पुनः विस्थापित कराये जाने हेतु अभियान चलाकर विस्थापित कराया जायेगा।

चट्टों का पुनः विस्थापन अभियान संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् कैराना जनपद शामली में वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में अधिशासी अधिकारियों द्वारा काटे गये चेक व धनराशि का विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

24-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् कैराना जनपद शामली में वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020 तक दिनांक 22-01-2020 तक कुल कितने कार्य हेतु किस-किस अधिशासी अधिकारी द्वारा चेक काटे गए हैं ?

क्या सरकार उक्त कार्य का विवरण, अधिशासी अधिकारी का नाम व जारी किए गए चेक व उसकी धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद शामली द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में दिनांक 22-01-2020 तक कराये गये कार्यों एवं अधिशासी अधिकारी का नाम तथा काटे गये चेकों का विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड जोन 7 के मटियारी-देवा रोड स्थित राजनगर कालोनी कंचनपुर में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक

25-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन 7 के अन्तर्गत मटियारी-देवा रोड (एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे) स्थित राजनगर कालोनी कंचनपुर में अर्द्ध निर्मित/जर्जर सड़क व नाली का निर्माण सरकार पूर्ण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

राजनगर कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसायटीज द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कालोनी है, जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अनियोजित रूप से बसायी गयी कालोनी में किसी भी प्रकार का विकास कार्य कराये जाने का प्राथमिक दायित्व नगर निगम का नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में होने के दृष्टिगत जनहित में समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा नगर पालिका परिषद् कोसीकलां के सीमा विस्तार किये जाने सम्बन्धी

26-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगर पालिका परिषद् कोसीकलां के सीमा वृद्धि सम्बन्धी जिलाधिकारी, मथुरा का संस्तुति सहित प्रस्ताव सं0 1103/तेईस बी/एल0 बी0 सी0/2019 दिनांक 30 दिसम्बर 2019 शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में ग्राम सभा कोसी देहात तथा ग्राम सभा अजीजपुर को नगर पालिका कोसीकलां में शामिल करते हुये सीमा विस्तार सम्बन्धी अधिसूचना जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा की छाता चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने विषयक

27-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी उद्योग-2 के अर्द्ध शा0 प0 सं0 2629/46-2-19 -ए-क्यू-2 (8)/2019, दिनांक 16 जनवरी 2020 में उल्लिखित गन्ना विकास कार्यक्रम के अनुरूप जनपद मथुरा की छाता चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रम सरकार प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

क्षेत्र में गन्ना विकास की सम्भावनाओं का परीक्षण के सम्बन्ध में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर तथा मथुरा जिला के गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि मथुरा जिले में जल की विशिष्ट प्रकृति होने के कारण क्षेत्र में गन्ना

उत्पादन चुनौतीपूर्ण होगा। छाता चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना उत्पादन तथा गन्ना आपूर्ति में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज हुई है। क्षेत्र के गन्ना कृषकों से संवाद की स्थिति में पाया गया कि कृषकों का रुझान गन्ने की फसल से अन्य फसलों की तरफ हुआ है, फिर भी वर्ष 2020-21 के लिए गन्ना बीज वितरण एवं अन्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रु0 1,89,600/- की धनराशि गन्ना विकास कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के पिलखुवा स्थित जी0 एस0 मेडिकल कालेज में मेडिकल पैकेज से अधिक धनराशि वसूलने व उनसे बदतमीजी करने की जांच कराने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

28-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ में पिलखवा स्थित जी0एस0 मेडिकल कॉलेज में कम उपचार पैकेज के नाम पर मरीजों को भर्ती कर मेडिकल पैकेज से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्था के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच की कार्यवाही नहीं की गयी है।

जनपद गाजियाबाद के परगना डासना ग्राम डासना भू घड़ी बंबे पर स्थित एक्स0 के0 एल0 यू0 चमड़ा फैक्ट्री द्वारा फैलाये गये प्रदूषण की जांच

29-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के परगना डासना के ग्राम डासना देहात भू घड़ी बंबे पर स्थित एक्स के0एल0यू0 चमड़ा फैक्ट्री के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है तथा फैक्ट्री में से निकलने वाला गंदा पानी व केमिकल से आबादी क्षेत्र में गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चमड़ा फैक्ट्री की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के परगना डासना क्षेत्रान्तर्गत एक्स के0एल0यू0 के नाम से कोई चमड़ा फैक्ट्री स्थित नहीं है। ग्राम भूरगढ़ी, परगना डासना में मैसर्स एक्सक्लूसिव लैदर, ग्राम-भूरगढ़ी, डासना, गाजियाबाद नाम से टैनरी उद्योग स्थापित है। उद्योग द्वारा रॉ स्किन एवं केमिकल का प्रयोग कर सेमी फिनिश लैदर 2800 पीस/दिन की उत्पादन क्षमता है। उद्योग दिनांक 20-12-2018 से कार्यरत नहीं है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 11-02-2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बन्द है तथा औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं हो रहा था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 20-11-2019 के अनुसार उक्त क्षेत्र में गम्भीर बीमारियों की जाँच हेतु स्वास्थ्य कैम्प लगाये गये तथा उक्त कैम्प में कोई गम्भीर बीमारी का रोगी नहीं मिला।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात भूडे घड़ी बंबा पर स्थित चमड़ा फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से बढ़ते बीमारी के प्रकोप के दृष्टिगत फैक्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

30-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात भूडे घड़ी बंबा पर स्थित त्रियश चमड़ा फैक्ट्री के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है तथा फैक्ट्री में से निकलने वाला गंदा पानी से आबादी का शुद्ध पानी दूषित हो रहा है एवं चमड़ा फैक्ट्री में से निकलने वाले केमिकल से आसपास की आबादी में बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम भूरगढ़ी, परगना डासना में मैसर्स त्रियश इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0, ग्राम-भूरगढ़ी, डासना, गाजियाबाद नाम से टैनरी उद्योग स्थापित है। इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है

तथा उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को डासना ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है।

दिनांक 04-12-2019 को इकाई के निरीक्षण के दौरान औद्योगिक उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में विभिन्न प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। दिनांक 05-02-2020 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा भूरगढ़ी डासना क्षेत्र के भूगर्भ जल के नमूने एकत्रित किये गये हैं, जो कि मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। उद्योग मैसर्स त्रियश इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत वैध सहमति प्राप्त है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 20-11-2019 के अनुसार उक्त क्षेत्र में गम्भीर बीमारियों की जांच हेतु स्वास्थ्य कैम्प लगाये गये तथा उक्त कैम्प में कोई गम्भीर बीमारी का रोगी नहीं मिला।

जनपद प्रयागराज वि0स0क्षे0 सोरांव के क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मतीकरण विषयक

31-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ऐसे मार्ग जिनका स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने के कारण मरम्मत नहीं हो सकी है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जी नहीं, लोक निर्माण विभाग केवल अपने स्वामित्व के मार्गों की मरम्मत करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की त0 महमूदाबाद-रेउसा मार्ग पर नुरपुर के समीप शारदा सहायक पुल के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

32-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा मार्ग पर नुरपुर के समीप शारदा सहायक पुल पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हाँ तो क्या सरकार जाम की समस्या के निराकरण हेतु पुल का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु का निर्माण शारदा सहायक नहर पर जल शक्ति विभाग द्वारा कराया गया है। इस सम्बन्ध में सिंचाई, जल संसाधन विभाग द्वारा ''इरीगेशन मैन्यूअल आर्डर के प्रस्तर-248 11 ख (11) में विहित व्यवस्था'' के आलोक में दिये गये परामर्श के दृष्टिगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सेतु निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में विभिन्न मार्गों के उच्चीकरण व चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में

33-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में महमूदाबाद-भगौली मार्ग, महमूदाबाद-पैतेपुर-बेलेहरा मार्ग, देबियापुर-पोखरपुर मार्ग, गोडैचा सदरपुर-बिसवां मार्ग, तथा पैतेपुर-चांदपुर बाजार मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक के दृष्टिगत उपरोक्त मार्गों का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

महमूदाबाद-भगौली मार्ग (लम्बाई 4.20 किमी0) का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने हेतु लागत रु0 6399.69 लाख की स्वीकृति सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

महमूदाबाद-पैतेपुर-बेलहरा मार्ग एवं गोडैचा-सदरपुर-बिसवां मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कार्य हेतु अनुमानित लागत क्रमशः रु0 2209.00 लाख एवं रु0 5072.191 लाख आंकलित है। उक्त कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

देवियापुर-पोखरा कला मार्ग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 02 लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक 6000 से कम होने के कारण उक्त मार्ग चौड़ीकरण हेतु अर्ह नहीं है एवं पैंतेपुर से चाँदपुर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का होने के कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामों में दो स्थानों पर डामर मार्ग बनाए जाने सम्बन्धी

34-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी अन्तर्गत ग्राम थांवला से ग्राम मनुकूला व रायपुर होते हुए ग्राम बीरमपुर तक तथा ग्राम

शाहपुर से मरघट होते हुए ग्राम हमज़ापुर के पास करसरा तक स्थान चिन्हित कर नवीन डामर मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम थांवला, मनकुला, रायपुर, बीरमपुर, शाहपुर एवं ग्राम हमजापुर पूर्व से ही एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

35-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 694/भजपा/वि0म0द0/2018 दिनांक 19-12-2018 जो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त/मरम्मत कराये जाने के संबन्ध में है, पर आपके आदेश संख्या आई0जी0आर0एस0 18143180241523 दिनांक 26-12-2018 के क्रम में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 विधायक श्री दलवीर सिंह, विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) द्वारा जनपद अलीगढ़ में निर्मित एन0एच091 गभाना मार्केट से ग्राम रामपुर होते हुये सोमना रेलवे स्टेशन मार्ग एवं मांट ब्रांच फीडर सोमना-खैर मार्ग से ग्राम भीमपुर मार्ग को मरम्मत कराये जाने हेतु पत्रांक 694/भजपा/वि0म0द0/2018 दिनांक 19-12-2018 के माध्यम से अनुरोध किया गया था।

उक्त सन्दर्भित मार्गों का निर्माण कार्य पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से कराया गया था। सड़कों की मरम्मत हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित नगरीय अवस्थापना निधि सक्षम स्तर है। नगरीय अवस्थापना निधि में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर उपरोक्त कार्य निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर बस स्टाप से सोहास तक जर्जर मार्ग की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक

36-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर बस स्टाफ से सोहास जाने वाली सड़क जर्जर हो जाने के कारण वर्तमान समय में आवागमन लायक नहीं

है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/लेपन कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण है तथा मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर वि0स0क्षे0 रामकोला के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में चीनी मिल/शुगर काम्प्लेक्स की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

37-श्री रामानन्द बौद्ध-

क्या चीनी मिलें एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र-रामकोला के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में चीनी मिल अथवा शुगर काम्प्लेक्स के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-11-2018 उनके कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157180227873 पर दर्ज शिकायत के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें लक्ष्मीगंज बाजार में चीनी मिल या शुगर काम्प्लेक्स लगवाये जाने की मांग की गयी है।

जिला कुशीनगर जनपद के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 5 चीनी मिलें क्रमशः खड्डा, रामकोला (पी0), कप्तानगंज, सेवरही तथा हाटा संचालित है। जिनकी पेराई क्षमता क्रमशः 1600, 6500, 6000, 6000 तथा 8000 टी0सी0डी0 है तथा वर्तमान में कृषकों द्वारा इन्हीं चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की जा रही है। जिला कुशीनगर में उपलब्ध पेराई योग्य गन्ने के सापेक्ष वर्तमान में पर्याप्त चीनी मिलें संचालित हैं तथा नई चीनी मिल/शुगर काम्प्लेक्स स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक बुलन्दशहर की प्रबन्ध कमेटी के नियम विरुद्ध संचालकों का आमेलन विषयक पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

38-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6, नम्बर-574565, दिनांक 03-07-2019 जो कि जिला सहकारी बैंक बुलन्दशहर की प्रबन्ध कमेटी के नियम विरुद्ध संचालकों का आमेलन विषयक है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी)-

जी हाँ।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जाँच सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, बुलन्दशहर द्वारा करायी गयी। जाँच में आमेलन हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं0 2222/2019 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2019 के क्रम में दिनांक 05-02-2019 की बैठक का एजेण्डा दिनांक 23-01-2019 को निकाला गया है। जिसकी प्रति सभी सम्बन्धित संचालक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई है। आमेलन की कार्यवाही विधि सम्मत पाये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं नियमावली, 1968 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी में हुई रिक्ति को आमेलन द्वारा भरे जाने का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा उक्त आमेलन नियमानुसार किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त आमेलन से क्षुब्ध पक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या-4225/एमबी/2020 योजित की गई थी। मा0 न्यायालय ने आमेलन की कार्यवाही नियम संगत पाये जाने पर आमेलन के विरुद्ध दाखिल उक्त याचिका को अपने आदेश दिनांक 13-02-2020 द्वारा खारिज कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण में अवर एवं सहायक अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत की सूचना व इनके वेतन के भुगतान की सूचना विषयक

39-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर में अवर एवं सहायक अभियन्ताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके सापेक्ष कुल कितने अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि स्वीकृत पदों से अधिक अभियन्ता नियुक्त/कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो इनके वेतन आदि का भुगतान बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा क्यों वहन किया जा रहा है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर में अवर अभियन्ता के 13 पद तथा सहायक अभियन्ता के 04 पद अर्थात् कुल 17 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 16 अवर अभियन्ता तथा 01 सहायक अभियन्ता अर्थात् कुल 17 अभियन्ता कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद वि0स0क्षे0 बिलारी में ग्राम बेहटा सरथल से मड़वा तक तथा बरौली रुस्तमपुर से चिड़िया भवन तक मार्ग का डामरीकरण विषयक

40-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेहटासरथल से ग्राम नवेनी उदैया होते हुए ग्राम मंडवा तक तथा ग्राम बरौली रुस्तमपुर से ग्राम चिड़िया भवन मार्ग तक नवीन डामर मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत ग्राम बहेटा सरथल, नवेनी उदया, मण्डवा, बरौली रुस्तमपुर एवं ग्राम चिड़िया भवन पूर्व से ही एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियाँ, वि0ख0 जखनियाँ में डाक बंगले का निर्माण कराने विषयक

41-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जखनियाँ के आस-पास डाक बगलों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

भूमि उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियाँ, वि0ख0 जखनियाँ बाजार के पास रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने विषयक

42-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के विकास खण्ड जखनियां बाजार के समीप रेलवे क्रासिंग पर प्रतिदिन लगने वाले ट्रैफिक जाम के दृष्टिगत उक्त क्रांसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में सम्पार सं0-51बी की टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण उक्त आर0ओ0बी0 रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है, जिसके कारण रेलवे द्वारा उक्त आर0ओ0बी0 पर अपनी सहभागिता नहीं की जायेगी। अतः उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियाँ के अन्तर्गत मनिहारी से जखनियाँ तक मार्ग को गड्ढामुक्त कराने विषयक

43-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के अन्तर्गत मनिहारी से जखनियाँ होते हुए फद्दुपर तक मार्ग लम्बाई 22.575 किलोमीटर का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य 03-03-2017 को पूर्ण किया गया है तथा मार्ग 5 वर्ष की अनुरक्षण अवधि में है, वर्तमान में गड्ढे में तब्दील है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ, वर्तमान में मार्ग अनुरक्षण अवधि के तृतीय वर्ष में है। चैनेज 11.00 से चैनेज 16.00 तक आबादी वाले भाग में विभाग द्वारा निर्मित नाली को स्थानीय लोगों द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण मार्ग पर पानी भरने से पैच/पॉटहोल्स सृजित हो गये थे। अब उक्त नाली को चालू करवा दिया गया है तथा मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग की सड़कों का चौड़ीकरण कराने विषयक

44-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग की सड़कों का चौड़ीकरण कर राजमार्गों की तरह बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में पड़ने वाली अन्य विभागों की सड़कों को भी लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण कराकर राजमार्गों की तरह विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मथुरा/अलीगढ़ में ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई (संकीर्ण आबादी भाग को छोड़कर) में 5.50 मी0 में चौड़ीकरण हेतु आंकलित लागत रु0 22323.39 लाख है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मथुरा वि0स0क्षे0 मांट की नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराये जाने विषयक

45-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट की नगर निकायों में समन्वित रूप से अवस्थापन सुविधाओं के कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत निकायों के चयन के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली नागर निकायों को सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। इस क्रम में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर पंचायत फरह, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर पंचायत नन्दगाँव एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पंचायत गोकुल का चयन उक्त योजनान्तर्गत किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत का चयन निर्धारित मानक के अनुरूप जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त होने पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ मालुपुर रिंग रोड, दुबग्गा कानपुर बाईपास लखनऊ में निर्मल ढाबा से एल0एम0 लान तक मार्ग का निर्माण कराने विषयक

46-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर के मालुपुर रिंग रोड, दुबग्गा कानपुर बाई-पास लखनऊ में निर्मल ढाबा से एल0एम0 लॉन तक रोड गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर/सोसाइटी द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कलोनी है, जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास, मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। प्रश्नगत कालोनियों में विकास कार्य कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सोसाइटी/कालोनाईजर का होता है। चूंकि प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम की सीमा में है, को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में नगर निगम द्वारा समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत स्थल पर नाली व सड़क निर्माण पर लगभग रु0 70.00 लाख का व्यय होना सम्भावित है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर प्रश्नगत कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र कटरा में कराये गये वृक्षारोपण की सूची उपलब्ध कराने विषयक

47-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-09-2019 जो जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में वर्ष 2019-20 में कराये गये वृक्षारोपण की स्थलवार सूची भेजने तथा जाँच कराने के सम्बन्ध मे हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी तिलहर रेन्ज जनपद शाहजहाँपुर के कार्यालय में दिनांक 26-09-2019 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 26-09-2019 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलहर रेंज, शाहजहाँपुर को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्रश्नगत पत्र के क्रम में कटरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कराये गये वृक्षारोपणों की सूची वन क्षेत्राधिकारी, तिलहर के पत्रांक-74/29-1, दिनांक 11-09-2019 द्वारा मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र कटरा, जनपद शाहजहाँपुर को उपलब्ध करा दी गई है। इसकी जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, तिलहर द्वारा कर ली गई है। जांच के दौरान वृक्षारोपण मानक के अनुरूप पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के वि0स0क्षे0 कालपी के वि0ख0 कदौरा के इकौना से निधानन डेरा के मध्य पुल निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में

48-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जपनद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा के इकौना से निधानन डेरा के मध्य पुल निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन में लम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत पुल की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन वि0स0क्षे0 कालपी ग्राम सभा कुठौंद की आबादी अधिक होने को सरकार नगर पंचायत घोषित करने विषयक

49-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी की ग्राम सभा कुठौंद की आबादी लगभग 16000 (सोलह हजार) से अधिक है, को सरकार नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14 दिनांक 06-10-2016 के मानक 2 (1) अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान

जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए और मानक 2 (2) के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए। जनपद जालौन के ग्राम पंचायत कुठौंद (कुठौंद) की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार मात्र 9559 है एवं 30 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त होने के कारण नगर पंचायत गठन हेतु मानक पूर्ण नहीं करती है।

जनपद जालौन के नगर कालपी में मुख्य बाजार मार्ग में सी0सी0 मार्ग बनवाने विषयक

50-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के नगर कालपी में मुख्य बाजार का मार्ग लम्बाई लगभग एक कि0मी0 ध्वस्त है तथा दुकानों के सामने पानी भरा रहने से ग्राहक व दुकनदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पानी निकासी की व्यवस्था तथा सी0सी0 मार्ग बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

उक्त ध्वस्त सड़क पर निर्माण हेतु पालिका को प्राप्त 14वां वित्त की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त वर्ष 2017-18 के द्वारा पालिका कार्यालय से 100 मीटर बायीं ओर व 100 मीटर दायीं ओर सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण हेतु रु0 134.14 लाख का टेण्डर किया जा चुका है। कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

आगामी 03 माह में 200 मीटर निर्माण कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा। शेष कार्य धनराशि प्राप्त होने पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0क्षे0 ऊँचाहार के वि0ख0 रोहनियाँ ग्राम पंचायत इरौरा के बअऊपुर में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

51-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियाँ के ग्राम पंचायत इरौरा के वअऊपुर में कोई पक्का रास्ता नहीं होने के कारण गाँव के लोगों को आवागमन में परेशानी के दृष्टिगत बअऊपुर को रानीगंज होते हुए 700 मीटर सड़क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड-रोहनियाँ के ग्राम पंचायत 'इरौरा के बअऊपुर' के स्थान पर 'इटौरा के बछऊपुर' है। बछऊपुर ग्राम की वर्ष

2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 71 है। 250 से कम आबादी के ग्रामों/मजरों को जोड़ने की वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में कुत्तों के लिए नसबन्दी केन्द्र खोले जाने विषयक

52-डॉ0 मन्जू शिवाच-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर शहर में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर पालिका में कुत्तों की नसबन्दी केन्द्र खोलने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1468/नौ-8-18-89ज/2017 टीसी दिनांक 14 मई, 2018 द्वारा समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश को नगर निकायों में एनिमल वर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) सेन्टर की स्थापना किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में प्रदेश की समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में भी एनिमल वर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) सेन्टर की स्थापना किये जाने की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में सिखेड़ा रोड के नाले के पक्का किये जाने के सम्बन्ध में

53-डॉ0 मन्जू शिवाच-

क्या नगर विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर में सिखेड़ा रोड के नाले को सरकार पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद-गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद् मोदीनगर में सिखेड़ा रोड के नाले को पक्का कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वि0स0क्षे0 रुधौली में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मार्गों के विशेष मरम्मत हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

54-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विशेष मरम्मत हेतु कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं सुधार हेतु कार्यालय मुख्य अभियन्ता बस्ती क्षेत्र लो0नि0वि0 बस्ती के द्वारा दिनांक 13/12/2019

पत्रांकः 6985/106/ब0क्षे0/19 द्वारा आगणन शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्गों के विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्न में वर्णित पत्र द्वारा 21 मार्गों के आगणन विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत प्राप्त हुये थे, जिसमें से सात मार्गों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। शेष मार्गों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वि0स0क्षे0 रुधौली में 5000 आबादी को शुद्ध पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक में की गयी मरम्मत की अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में

55-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र सल्टौआ के ग्राम गोरखर में वर्ष 2010-11 में निर्मित ओवरहेड टैंक की ट्रायल के दौरान से ही जल रिसाव की मरम्मत न करने तथा उक्त टैंक कनेक्शन न देने के कारण उक्त क्षेत्र की आबादी पेयजल सुविधा से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त ओवरहेड वाटर टैंक का मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत गोरखर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 01 नग नलकूप, शिरोपरि जलाशय (300 कि0ली0 क्षमता/18 मी0 स्टेजिंग)-01 नग वितरण प्रणाली 16.814 कि0मी0, पम्प हाउस-01 नग, स्टाफ क्वार्टर- 01 नग एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य माह मार्च- 2019 में पूर्ण कर लिया गया है। माह जनवरी-2019 में विद्युत संयोजन होने के उपरान्त टैंक के परीक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक के इनलेट व आउटलेट पाइप के ज्वाइंट में एक स्थान पर लीकेज था, जिसे फर्म द्वारा ठीक करा दिया गया है। योजनान्तर्गत 02 ग्राम पंचायतें (गोरखर एवं हसनापुर) सम्मिलित हैं। योजना में 07 राजस्व ग्राम-गोरखर, हसनापुर, रेहार जंगल, धौरापारा, सिकन्दरपुर, रमुवापुर एवं दरहिया बुजुर्ग सम्मिलित हैं। अद्यतन योजना के अन्तर्गत 02 राजस्व ग्रामों-गोरखर एवं रेहार जंगल में पूर्ण रूप से तथा 01 ग्राम सिकन्दरपुर में आंशिक रूप से 300 नग गृह संयोजन के माध्यम से

पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शेष ग्रामों में पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत अवशेष 100 नग गृह संयोजनों का कार्य माह मार्च, 2020 तक पूर्ण करते हुए योजना के समस्त ग्रामों को लाभाविन्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली ब्लाक रामनगर के आर0के0वी0आई0 अनुदान न मिल पाने के कारण सदस्यों को खाद्य, बीज आदि अनुदान के सम्बन्ध में

56-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर के साधन सहकारी समिति लि0 दरियापुर में आर0के0वी0आई0 अनुदान न मिल पाने के कारण सदस्यों को खाद्य, बीज आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हितों को देखते हुए साधन सहकारी समिति दरियापुर को आर0के0वी0आई0 अनुदान दिलाने हेतु स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मुकुट बिहारी-

साधन सहकारी समिति लि0 दरियापुर के सदस्यों को विकास खण्ड रामनगर के ही अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 मोहम्मदनगर से सम्बद्ध कर खाद, बीज की सुविधा दी जा रही है।

वर्तमान में आर0के0वी0वाई0 योजना के अन्तर्गत समितियों को खाद, बीज व्यवसाय हेतु अनुदान योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में मार्गों का स्वामित्व स्पष्ट कर संबंधित विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक

57-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ऐसे मार्ग जिनका स्वामित्व स्पष्ट न होने के कारण मरम्मत नहीं हो सकी है, की मरम्मत लोक निर्माण विभाग से सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, लोक निर्माण विभाग केवल अपने स्वामित्व के मार्गों की मरम्मत करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ फैजुल्लागंज में अमृत योजना के तहत पेयजल योजना हेतु प्रस्ताव पर विचार किये जाने विषयक

58-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज अमृत योजना अन्तर्गत पेयजल कि सुविधा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ। लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज-प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ वार्ड में बालागंज जलकल से पेयजल आपूर्ति के कार्य का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 127.60 करोड़ उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम में अभिषेकपुरम आदि मोहल्ले की जल निकासी हेतु 60 फिटा रोड पर नाली निर्माण विषयक

59-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम् में अभिषेकपुरम मोहल्ले की जल निकासी के लिए साठ फिटा रोड पर नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

लखनऊ नगर के जानकीपुरम् में अभिषेकपुरम मोहल्ले की जल निकासी के लिए साठ फिटा रोड पर नाली का निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में अलीगंज इंजीनियरिंग कालेज से आई0 आई0 एम0 तक मेट्रो रेल की योजना का विवरण दिये जाने विषयक

60-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में अलीगंज इंजीनियरिंग कालेज होते हुए आई0आई0एम0 तक मेट्रो रेल की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर के अन्य क्षेत्रों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से एक टेक्नो फिजिबिलिटी अध्ययन कराया गया है। इस टेक्नोफिजिबिलिटी अध्ययन में आई0आई0एम0 से अलीगंज इंजीनियरिंग कालेज होते हुए राजाजीपुरम तक 21.58 कि0मी0 लम्बा मेट्रो रेल कॉरिडोर का भाग सम्मिलित है।

लखनऊ के घैला में अमृत योजना के अन्तर्गत एस0टी0पी0 का निर्माण कराये जाने विषयक

61-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के घैला क्षेत्र में अमृत योजना के अन्तर्गत एस0टी0पी0 का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

लखनऊ नगर की गोमती प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना (फेज-II) अनु0 लागत रु0 557.12 करोड़ का प्राक्कलन नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु भारत सरकार को प्रेषित है। योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त एस0टी0पी0 का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के निराला नगर के पटेल पार्क को योग पार्क हेतु विकसित किये जाने विषयक

62-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ मे लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित निराला नगर के पटेल पार्क को योग पार्क के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-10-2019 एवं 7-11-2019 उन्हें प्रप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं। यद्यपि जनपद लखनऊ के निराला नगर स्थित पटेल पार्क के बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत, रंगाई-पुताई व पाथ-वे का निर्माण कार्य अमृत योजना के अन्तर्गत सम्पादित करा दिया गया है। पार्क में सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत देवरिया में साकेत नगर/कृष्णा नगर में सोनू नाऊ के सैलून से शम्भू नाथ मिश्रा के घर तक जर्जर मार्ग का निर्माण विषयक

63-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की नगर पंचायत देवरिया के साकेत नगर/(कृष्णानगर) में सोनू नाऊ के सैलून से शम्भू नाथ मिश्रा के घर तक का मार्ग लगभग 175 मी0 जर्जर होने के कारण आमजन को आवागमन मे असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अनुमानित आगणन रु0 13,11,360.00 का तैयार कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत शीघ्र ही निविदा की कार्यवाही कराकर निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निकायों में स्थित मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जाने विषयक

64-श्री नाहिद हसन-

क्या नगरीय रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निकायों में स्थित मलिन बस्तियों के सुधार हेतु सरकार के पास क्या योजना है तथा चालू वित्तीय वर्ष में मलिन बस्तियों के सुधार हेतु कुल कितना बजट जारी कर किस प्रकार के कार्य कराए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका परिषद कैराना कि नगर पंचायत झिंझाना तथा ऊन की मलिन बस्तियों में नाली, खड़ंजा व अन्य विकास कार्य किस तिथि तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

प्रदेश के नगर निकायों में स्थित मलिन बस्तियों में 'मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना' के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में सुधार कार्य कराया जाना प्राविधानित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मलिन बस्तियों के सुधार हेतु रु0 148.34 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके द्वारा इंटरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण इत्यादि के कार्य कराये जा रहे हैं।

जनपद-शामली की न0पं0, झिंझाना तथा ऊन की मलिन बस्तियों में नाली इंटरलॉकिंग व अन्य विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-20) में शासन में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों पर नियुक्ति तथा सभी मंडल मुख्यालयों पर प्रदूषण प्रयोगशाला/जांच केन्द्र खोलने सम्बन्धी

65-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा सभी मंडल मुख्यालयों पर प्रदूषण प्रयोगशाला सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत सृजित पदों पर नियुक्ति बोर्ड की प्रख्यापित ''उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995'' में निहित प्राविधानों के अनुरूप की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बिजनौर, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, अलीगढ़, उन्नाव में 22 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जिनके माध्यम से सभी मण्डलों में अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा मेडिकल कालेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में नवजात शिशुओं/बच्चों के ऑपरेशन हेतु पीडियाट्रिक एनेस्थेटिक की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में।

66-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एनेस्थेटिक न होने के कारण पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अन्तर्गत नवजात शिशुओं/बच्चों के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आगरा मेडिकल कॉलेज मे पीडियाट्रिक एनेस्थेटिक की नियुक्ति कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में वर्तमान में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग अलग से स्थापित नहीं है। डा0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, सहआचार्य, सामान्य सर्जरी एम0सी0एच0

(पीडियाट्रिक सर्जरी) डिग्रीधारक हैं, जिनके द्वारा सामान्य सर्जरी के साथ ही साथ पीडियाट्रिक सर्जरी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड में सरस्वतीपुरम और साठ फिटा रोड पर चोक सीवर लाइनों का स्थाई समाधान करने के सम्बन्ध में

67-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम प्रथम वार्ड में सरस्वतीपुरम और साठ फिटा रोड पर डाली गई सीवर लाइन चोक है ? यदि हाँ, तो क्या सीवर लाइनों के चोक हो रही समस्या का स्थाई समाधान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

जानकीपुरम प्रथम वार्ड में सरस्वतीपुरम और साठ फिटा रोड पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा ट्रंक सीवर लाइन डाली गयी थी, जो साठ फिटा रोड पर सीवर लाइन से जुड़ा है। ट्रंक सीवर लाइन का एलाइनमेन्ट ठीक न होने के कारण सीवर लाइन चोक की समस्या होती है, जिसके स्थाई समाधान हेतु एलाइनमेन्ट ठीक किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ निराला नगर स्थित पटेल पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

68-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के निराला नगर अन्तर्गत स्थित पटेल पार्क का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

जनपद लखनऊ के निराला नगर अन्तर्गत स्थित पटेल पार्क में बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत व रंगाई-पुताई का कार्य, पाथ-वे का निर्माण कार्य सम्पादित करा दिया गया है। पार्क में सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम में सीवर लाइनों को कुर्सी रोड की मेन रोड से जोड़े जाने विषयक

69-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम में जल निगम द्वारा बिछाई गई सीवर लाइनों को कुर्सी रोड की मेन रोड से सरकार जुड़वायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

वर्तमान में जानकीपुरम का सीवर एल0डी0ए0 द्वारा डाली गयी सीवर लाइन से जोड़ा गया है, जिसे कुर्सी रोड पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी 700 मि0मी0 व्यास की सीवर लाइन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। जानकीपुरम की सीवर लाइन को कुर्सी रोड की मेन रोड पर पड़ी सीवर लाइन से दिनांक 30-05-2020 तक जुड़वाया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज पुरनिया चौराहा पर अतिक्रमण को हटाये जाने विषयक

70-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज पुरनिया चौराहा पर अवैध अतिक्रमण से लोगों को परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल से समय-समय पर अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में स्थल से अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ वि0स0क्षे0 के प्रगति विहार फैजुल्लागंज में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने विषयक

71-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के प्रगति विहार फैजुल्लागंज में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी लखनऊ से जांच कराकर अवैध कब्जे की दशा में नियमानुसार अवैध कब्जे की भूमि को मुक्त कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

72-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[दिनांक 24-02-2020 को अता0प्र0सं0-69 द्वारा उत्तरित]

73-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[03 सोमवार के अता0प्र0सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियाँ के विकास खण्ड मनिहारी में मरदानपुर मोहम्मदपुर के बीच मगई नदी पर सेतु व मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

74-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के विकास खण्ड मनिहारी में मरदानपुर मोहम्मदपुर के मध्य मगई नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया के विकास खण्ड मनिहारी में मरदानपुर लक्ष्मन एवं मुहम्मदपुर के बीच मगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु लागत रु0 742.86 लाख आंकलित है तथा आगणन गठन की प्रक्रिया में है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियां वि0ख0 मनिहारी में उकरांव सादात-उदन्ती नदी पर निर्मित सेतु पर पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

75-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के विकास खण्ड मनिहारी में उकराँव सादात उदन्ती नदी पर निर्मित सेतु पर पहुँच मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी में उकरावं सादात उदन्ती नदी पर सेतु निर्माण हेतु ही स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में लागत रु0 87.34 लाख निर्गत की गयी थी जिसके सापेक्ष लघु सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये सेतु के दोनों तरफ 50-50 मी0 लम्बाई में कच्चे पहुँच मार्ग का निर्माण कर यातायात चालू किया गया है। लेपित पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु रु0 58.60 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियां वि0ख0 मनिहारी में कुरुन्दशीपुर से टड़ियांव खड़हरी नदी पर निर्मित सेतु निर्माण विषयक

76-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जपनद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के विकास खण्ड मनिहारी में कुरुन्दशीपुर तड़ियाव खड़हरी नदी पर निर्मित सेतु पर पहुँच मार्ग निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जपनद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के विकास खण्ड मनिहारी में कुरुन्दशीपुर तड़ियाव खड़हरी नदी पर सेतु निर्माण हेतु स्वीकृति वर्ष 2008-09 में दी गयी जिसके सापेक्ष लघु सेतु का निर्माण करते हुये सेतु के दोनों तरफ 50-50 मी0 लम्बाई में कच्चे पहुँच मार्ग का निर्माण कर यातायात चालू कर लिया गया है। लेपित पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु रु0 60.20 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जखनियां के अन्तर्गत जंगीपुर-बहरियाबाद मार्ग में छूटे हुए लगभग 6 कि0मी0 का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

77-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के अन्तर्गत जंगीपुर-बहरियाबाद मार्ग के छूटे हुए 6 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु आंकलित लागत रु0 850.00 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सहारनपुर, वि0स0क्षे0 बेहट के अन्तर्गत ग्राम कुंडी खेड़ा चांणचक में फतेहपुर पेलो मार्ग में सोलानी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक

78-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बेहट जनपद सहारनपुर के ग्राम कुंडी खेड़ा चांणचक में फतेहपुर पेलो मार्ग पर सोलानी नदी पर पुल निर्माण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु के डाउन स्ट्रीम में 4.0 कि0मी0 की दूरी पर सुन्दरपुर कुरडीखेड़ा मार्ग पर सोलानी नदी पर पक्का सेतु निर्मित है।

अपस्ट्रीम में कोई सेतु निर्मित नहीं है। प्रश्नगत सेतु स्थल से अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम में 10 कि0मी0 के अन्दर पुल निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर वि0स0क्षे0 बेहट के ग्राम हुसैनपुर मलकपुर तक जाने वाली सड़क के पुनःनिर्माण के सम्बन्ध में

79-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम हुसैनपुर मलकपुर जाने वाली सड़क नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग पर 187.84 मी0 लम्बाई का सेतु निर्माणाधीन है। सेतु की शाहपुर गाँव की ओर 300.00 मी0 लम्बाई तथा शहाबुद्दीन गाँव की ओर 100.00 मी0 लम्बाई में पहुँच मार्ग का कार्य किया जाना है। शाहपुर गांव की ओर नदी के बहाव से कटे पहुँच मार्ग के अन्तर्गत 300.00 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट के बादशाही बाग से खारा पावर हाउस मार्ग में गजरा नदी पर पुल निर्माण विषयक

80-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग से खारा पावर हाऊस तक जाने वाली सड़क पर गजरा नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल पर 150.73 मी0 लम्बाई के सेतु का पहुँच मार्ग सहित लागत रु0 1031.32 लाख का प्रारम्भिक आगणन गठित किया गया है। प्रश्नगत सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर वि0स0क्षे0 बेहट में तब्बरकपुर उर्फ उसण्ड से टोडरपुर व सुंदरपुर से मिर्जापुर मार्ग में हिन्डन नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

81-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में तब्बरकपुर उर्फ उसण्ड से टोडरपुर तथा सुन्दरपुर से मिर्जापुर मार्ग में हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

(1) तब्बरकपुर उर्फ उसण्ड से टोडरपुर मार्ग पर प्रस्तावित सेतु स्थल से 5 कि0मी0 अपस्ट्रीम में बेहट-सहारनपुर मार्ग पर तथा 10 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में रावणपुर-बहादरा मार्ग पर गांगरो नदी पर पक्का सेतु निर्मित है। तब्बरकपुर उर्फ उसण्ड से टोडरपुर मार्ग पर हिण्डन नदी नहीं पड़ती है।

प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में 10.00 कि0मी0 के अन्दर पूर्व से सेतु निर्मित होने के फलस्वपरूप नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

(2) सुन्दरपुर से मिर्जापुर मार्ग पर पड़ने वाली हिण्डन/चाचाराव नदी पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड खीरी में वर्ष 2016-2020 तक हुए टेण्डरों की जांच के सम्बन्ध में

82-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड खीरी जनपद के प्रखण्डों में वर्ष 2016 से दिनांक 24-1-2020 तक बिना टेण्डर का कार्य किन फर्मों/ठेकेदारों को कितनी धनराशि का भुगतान वर्षवार किया गया है ? क्या इसकी जाँच कराकर फर्मों के विरुद्ध एवं मनमानी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य -

जनपद लखीमपुर खीरी के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2016 से दिनांक 24-01-2020 तक स्वीकृत समस्त कार्यों का सम्पादन नियमानुसार निविदा (टेण्डर) प्राप्त कर ही कराया गया है। बिना निविदा आमंत्रित कर कोई भी कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

83-श्री पारसनाथ यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सहा0 निदेशक, किसान गन्ना संस्थान, शाहजहांपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

84-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0आर0एस0 संख्या 18150190080222 जो सहायक निदेशक किसान गन्ना संस्थान शाहजहाँपुर को जनपद शाहजहाँपुर में स्थानान्तरण नीति के विपरीत करीब 10 वर्षों से कार्यरत होने पर स्थानान्तरण विषयक है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

हां।

गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र शाहजहाँपुर में एक मात्र तकनीकी अधिकारी श्री प्रवीण कुमार, सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार

द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लक्ष्य पूर्ति किये जाने के कारण गत वर्ष विभाग में कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

गन्ना शोध परिषद् में वैज्ञानिकों की भर्ती में की गयी अनियमितता की जांच पर कार्रवाई विषयक

85-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 250338 दिनांक 08-04-2019 जो जनपद शाहजहाँपुर के वर्ष 2015 मे हुई वैज्ञानिकों की भर्तियों में अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त की जाँच मण्डलायुक्त सहारनपुर ने दिनांक 9-03-18 में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद में की गयी वैज्ञानिकों की भर्ती में प्रभारी निदेशक को प्रथम दृष्टता दोषी पाया गया है ? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

हां।

मण्डलायुक्त सहारनपुर की जांच आख्या दिनांक 09-03-2018 में तत्कालीन प्रभारी निदेशक, डा0 बी0एल0 शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके आधार पर श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्तुत करते हुए जांच करायी गयी। जांच आख्या में श्री शर्मा को दोषी पाया गया। उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद सेवा नियमावली के नियम 18-2 के अन्तर्गत दण्ड पर निर्णय हेतु जांच आख्या को गवर्निंग बॉडी उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद को सन्दर्भित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली के नगर पंचायत रुधौली बाजार में पं0 दीन दयाल योजनान्तर्गत बरात घर व एल0डी0 रोड पर महादेव सिंह मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण विषयक

86-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की नगर पंचायत रुधौली बाजार में पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत बारात घर व एल0डी0 रोड पर महादेव सिंह मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुधौली के पत्रांक संख्या-113 दिनांक 10-09-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में एल0डी0 रोड पर महादेव सिंह मार्ग पर शिव मन्दिर 400 मी0 तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण हेतु पत्रांक 353 न0प0रूधौ0ब0/निर्माण अनुभाग-19-20 दिनांक 26-09-2019 को

विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-9 के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत रुधौली में नागरिकों के शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम को सम्पन्न कराने हेतु बरात घर व नागरिकों के आवगमन हेतु महादेव सिंह मार्ग पर सी0सी0रोड निर्माण की प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत स्थानीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण की धनराशि समुचित आगणन एवं उक्त मद में बजट की उपलब्धता पर स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 में धनराशि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के वार्डों में सोलर लाइट लगाये जाने विषयक

87-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रमुख स्थानों पर प्रकाश बिन्दु हेतु सोलर लाइट के सरकार लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रमुख स्थानों पर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत प्रकाश बिन्दु हेतु सोलर लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-181/नौ-8-19-03एस0(बजट)/2018 दिनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा धनराशि रु0 67.02 लाख एवं शासनादेश संख्या-21/नौ-8-20- 04एस0 (बजट)/2018 दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा धनराशि रु0 155.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

जनपद लखनऊ के मड़ियांव से आई0आई0एम0 तिराहा तक नगरीय सीमा के मुख्य मार्ग तक प्रकाश व्यवस्था कराये जाने विषयक

88-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मड़ियांव से आई0आई0एम0 तिराहा तक नगरीय सीमा में मुख्य मार्ग पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नगर निगम द्वारा अब तक नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

जनपद लखनऊ के मड़ियाव से आई0आई0एम0 तिराहा तक मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। इसका स्वामित्व नगर निगम का नहीं है। अतः नगर निगम द्वारा उक्त मार्ग पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था का कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयन सम्बन्धी विवरण दिये जाने हेतु

89-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जनपद बागपत में कितनी नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयनित किया गया है तथा प्रस्तावित विकास कार्यों के सापेक्ष उनमें कौन कौन से विकास कार्य किये गए हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुयी तथा कितनी धनराशी के विकास कार्य हो चुके हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत कुल 03 नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयनित किया गया है।

नगर पंचायत, अग्रवाल मण्डी, टटीरी को शासनादेश संख्या-585/नौ-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/19, दिनांक 18-02-2019 द्वारा 300.00 लाख के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रुपये 150.00 लाख स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित विकास कार्य कराये गये हैं :-

1-डूडा कालोनी से श्री रतिराम के मकान तक 1000 मी0 लम्बाई में प्रकाश व्यवस्था का कार्य-रु0 25.70 लाख।

2-वार्ड नं0-9 में श्री यामीन के मकान से श्री प्रहलाद के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 40.49 लाख।

3-वार्ड नं0-9 में श्री प्रहलाद के मकान से पैरामाउण्ट स्कूल तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 70.18 लाख।

4-बागपत मेरठ रोड से कब्रिस्तान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 07.81 लाख।

5-श्रीराम कालोनी में श्री गिरिवर के मकान से श्री संजय के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 20.76 लाख।

6-श्रीराम कालोनी में श्री मनोज तेड़ा के मकान से श्री सुभाष के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 18.82 लाख।

7-श्रीराम कालोनी में समाधि रोड से बिल्डर हाउस तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 81.81 लाख।

8-श्रीराम कालोनी में बिल्डर से मोदी के मकान तक व श्री सुरेन्द्र से रामसिंह व संतराम से श्री भंवर सिंह से भारदवाज के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 20.63 लाख।

9-श्रीराम कालोनी में मेरठ रोड से श्री नवीन के मकान तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य-रु0 18.47 लाख।

10-बागपत मेरठ मेनरोड क्रासिंग से 1500 मी0 लम्बाई तक पोल व लाइट का कार्य लेफ्ट साइड-रु0 37.97 लाख।

11-बागपत मेरठ मेन रोड क्रासिंग से 1500 मी0 लम्बाई तक पोल व लाइट का कार्य राइट साइड 37.97 लाख।

नगर पंचायत, छपरौली

शासनादेश संख्या-586/नौ-8-2019-10डी0डी0यू0(बजट)/19, दिनांक 18-02-2019 द्वारा 299.25 लाख के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 149.62 लाख स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित विकास कार्य कराये गये हैं :-

1-कस्बा छपरौली में तिलवाड़ा रोड पर स्थित आर्य समाज प्रांगण में युवा विकास हेतु क्रीड़ा हाल, योगा पार्क व सामुदायिक कार्य-रु0 65.36 लाख।

2-कस्बा छपरौली में विभिन्न स्थानों पर 15 नग नये वाटर कूलर मय फिटिंग कम्प्लीट सहित अधिष्ठापन का कार्य-रु0 40.73 लाख।

3-कस्बा छपरौली में तिलवाड़ा रोड पर 25 मी0 ऊंची एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाइटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य-रु0 9.91 लाख।

4-कस्बा छपरौली में रठौड़ा रोड पर 25 मी0 ऊँची एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाइटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य-रु0 9.91 लाख।

5-कस्बा छपरौली में बदरख रोड पर श्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के सामने पर 25 मी0 ऊँची एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाइटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य-रु0 9.91 लाख।

6-कस्बा छपरौली में थाने के सामने मुख्य मार्ग पर आधुनिक यात्री शेड का निर्माण कार्य-रु0 7.23 लाख।

नगर पंचायत, अमी नगर सराय

शासनादेश संख्या-115/नौ-8-2020-02डी0डी0यू0(बजट)/19, दिनांक 09-01-2020 द्वारा 300.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रुपये 150.00 लाख स्वीकृत की गयी है।

जनपद बागपत में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर मूल्य के साथ ब्याज प्रदान किये जाने विषयक

90-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में 14 दिन से अधिक की देरी करने पर नियमानुसार गन्ना सीजन वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में गन्ना मूल्य के अतिरिक्त ब्याज की धनराशि भी किसानों को दी गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जिला बागपत में सहकारी क्षेत्र की 02 चीनी मिलें यथा-बागपत व रमाला तथा निजी क्षेत्र की 01 चीनी मिल मलकपुर संचालित है। उक्त चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में गन्ना किसानों को ब्याज के मद में कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(3) में ब्याज के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित है। तत्क्रम में गन्ना मूल्य विलम्बित करने पर चीनी मिलों को गन्ना समितियों की ओर से समय-समय पर ब्याज के बिल प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर गन्ना मूल्य का भुगतान अत्यन्त विलम्बित करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध ब्याज सहित देयता निर्धारित करते हुए वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किये जाते हैं।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से आच्छादित व्यक्तियों का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

91-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का सुविधा (लाभ) किस श्रेणी के लोगो को प्रदान किया जाता है

तथा उसका मानक क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कितने लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ उनके नाम व पते क्या हैं तथा कितने लोगो के आवेदन किन कारणों से लंबित हैं ? क्या सरकार लंबित आवेदनों का निराकरण कराते हुये उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा (लाभ) इस योजना के निर्धारित मानक के अनुसार पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को दिया गया है।

इस योजना का मानक निम्नवत् है :-

ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय रु0 3.00 लाख हो।

(क) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिये। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियां शामिल होंगी।

(ख) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे व्यस्क पुरूष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जायेगा। उक्त व्यस्क पुरुष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होगें।

(ग) विवाहित दम्पत्ति के प्रकरण में पति-पत्नी दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस योजना की गाइडलाइन में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।

लाभार्थी योजना के चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिये पात्र होगा।

नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिये।

जिन लाभार्थियों के पास पक्का मकान अथवा अर्धपक्का मकान है जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमीटर तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बीनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है।

(क) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9 वर्ग मीटर जोड़ा जायेगा, जिसमें एन0बी0सी0 मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और शौचालय बनाया जायेगा।

6.पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होने आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 2128 लाभार्थियों का चयन किया गया है। 1547 लाभार्थियों को प्रथम किश्त, 898 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त एवं 310 लाभार्थियों को तृतीय किश्त प्रेषित कर योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। शेष पात्र/वंचित लाभार्थियों के आवेदनों के सम्बन्ध में सर्वे का कार्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

जी हां, उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 प्रथम सत्र, 2017 के प्रथम बुधवार अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की जानकीपुरम कालोनी के सेक्टर एच का हस्तान्तरण नगर निगम को करने के सम्बन्ध में

92-श्री सुखदेव राजभर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के पहले बुधवार को निर्धारित श्री मो0 असलम राइनी एडवोकेट, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अता0प्र0सं0-45 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की जानकीपुरम कालोनी के सेक्टर-एच का हस्तानान्तरण नगर निगम को कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो हस्तानान्तरण करने के पूर्व क्या-क्या एवं कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार हस्तानान्तरण से सम्बन्धित समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पूर्ण रूप से विकसित जानकीपुरम योजना स्थित सेक्टर-एच को आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 05-10-2017 के कार्यवृत्त के अनुसार नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के क्रम में सेक्टर-एच के अन्तर्गत विभिन्न भागों में क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों, नालियों एवं पार्कों के सुधार का कार्य कराये जाने के उपरान्त, कराये गये कार्यों को मानचित्र पर दर्शाते हुए नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 579/अ0अ0-5/सचिव/2018, दिनांक 17-11-2018 आवश्यक रख-रखाव की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी-'क' आगे पृष्ठ सं0-267-272 पर)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के यमुना नदी पर मांट बाबूगढ़ पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक

93-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के यमुना नदी पर मांट बाबूगढ़ पैण्टून पुल के स्थान पर एक पक्का पुल सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के यमुना नदी के सुरीर औहावा स्यारहा पर बने पैण्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक

94-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के यमुना नदी के सुरीर औहावा स्यारहा पर बने पैण्टून पुल के स्थान पर एक पक्का पुल सरकार बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में वि0स0क्षे0 सोरांव में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में जर्जर सड़कों की मरम्मती में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

95-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव से वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में नव निर्मित सड़कों/विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कराये गये निर्माण में अनियमितता कर मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कराये गये सड़कों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय कमेटी से जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 लालगंज अन्तर्गत ज्यूली-देवगांव, मेहनाजपुर औड़िहार प्रमुख जिला सड़क मार्ग को फोरलेन करने के सम्बन्ध में

96-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ज्यूली- देवगाँव, मेहनाजपुर ओड़िहार प्रमुख जिला सड़क मार्ग को फोरलेन बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 4 लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम होने के कारण उक्त मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

कार्यालय वित्त व लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा प्रयागराज से स्थानान्तरित लेखाकार को कार्यालय जिला निरीक्षक कौशाम्बी से कार्यमुक्त किये जाने विषयक

97-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखाकार कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रयागराज को जिला निरीक्षक कौशाम्बी के रिक्त पद पर आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1255/5859/स्था0/लेखा/2019, दि0 29-06-2019 द्वारा स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित को कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

जी, हां।

सम्बन्धित लेखाकार को वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रयागराज के कार्यालय आदेश दिनांक 04-0-.2020 द्वारा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी में कार्यभार ग्रहण

करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 05-02-2020 को कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आदेश का अनुपालन करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

98-श्री मो0 फईम-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ, नगर पंचायत मोहनलालगंज में नई जेल रोड पर बनी रेलवे क्रासिंग पर जाम से निजात हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण के सम्बन्ध में

99-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर (एडवोकेट)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नवगठित नगर पंचायत मोहनलालगंज में नई जेल रोड पर रेलवे क्रांसिंग पर फाटक बन्द होने की दशा पर घटों जाम लगा रहता है, तथा नई जेल रोड की साइड पट्टी व सड़क खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार जेल रोड क्रांसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण व सड़क पट्टी आदि की मरम्मत पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग (प्र0जि0मा0, 89 सी) के लोक निर्माण विभाग की सीमा तक के मार्ग की दशा संतोषजनक है। मात्र रेलवे का भाग वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

प्रश्नगत सम्पार संख्या 188 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित न होने के कारण रेलवे द्वारा अपनी सहभागिता नहीं की जायेगी। अतः उक्त आर0ओ0बी0 का निर्माण किया जाना सम्प्रति प्रस्तावित नहीं है।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज सहित प्रदेश के नानकनेक्टिंग समस्त गांवों को पक्की सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

100-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर (एडवोकेट)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के गांवो में सरकार द्वारा नानकनेक्टिंग वाले गांवों को अभियान चलाकर उन गांवो को सड़क मार्ग (डामरीकरण) जोड़ने का कार्य किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अभियान के अन्तर्गत मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम हीरामनखेड़ा, रानीखेड़ा मनोहरापुर, बरियारखेज जमोरिया, मरूई सहित अनेक गांवों में कोई पक्की सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांवों में पक्की सड़क का निर्माण

न करवाने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही कर वहां सड़क निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के प्रदेश के समस्त ग्रामों को सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

मोहनलालगंज क्षेत्र में मार्गों का विवरण निम्नवत है :-

(1) हीरामनखेड़ा मार्ग तथा मनोहरापुर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 24-02-2020 द्वारा निर्गत कर दी गयी है।

(2) रानीखेड़ा ग्राम मोहनलाल गंज मौरावां मार्ग के कि0मी0-3 से जुड़ा है तथा मरूई ग्राम बिजनौर सिसेण्डी मार्ग के कि0मी0-11 से निकलने वाले मरूई सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(3) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सूची में बरियार खेड़ा का उल्लेख नहीं है।

(4) जमोरिया ग्राम की आबादी 250 से कम है। 250 से कम आबादी के ग्रामों/मजरों को जोड़ने की वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के जंघई रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्रासिंग पर जाम के कारण फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक

101-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जंघई रेलवे स्टेशन के बगल में रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन जाम लगने के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर में जंघई मछली शहर जिला मार्ग पर उत्तर रेलवे के सम्पार सं0 51बी की टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण उक्त आर0ओ0बी0 रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है, जिसके कारण रेलवे द्वारा उक्त सेतु पर अपनी सहभागिता नहीं की जायेगी। अतः उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पर्यावरण सम्बन्धी निर्देश उल्लंघन के मामले में औद्योगिक इकाई संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी विषयक

102-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-09-2019 से 31-12-2019 के मध्य पर्यावरण सम्बन्धी निर्देश उल्लंघन के मामले में औद्योगिक इकाइयों के कितने संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ? उक्त अवधि में किसानों के विरुद्ध कृषि अवशेष जलाने के कितने मामले दर्ज कराए गए हैं ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण सम्बन्धी उल्लंघन के मामले में औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का प्राविधान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित नहीं है। अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन मामलों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है।

फसल अवशेष/कृषि अपशिष्ट के जलाये जाने के सम्बन्ध में कुल 5686 मामले प्रकाश में आये। जाँचोपरान्त जिला प्रशासन द्वारा किसानों के विरुद्ध कृषि अवशेष जलाने के 2165 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

जनपद आजमगढ़ के विलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड 32 के उत्तरी पटरी पर 03 कि0मी0 मार्ग को पिच रोड का निर्माण विषयक

103-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड 32 के उत्तरी पटरी पर इस्माइलपुर गोरिया पुल से मसीरपुर तक के 03 किलोमीटर मार्ग को पिच रोड सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग नहर की पटरी पर स्थित है, जो सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में डूडा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के अन्तर्गत दिये गये आवासों का विवरण

104-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में डूडा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कितने लाभार्थियों के आवेदन के सापेक्ष में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिये गये है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद-फिरोजाबाद में डूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत योजना के घटक 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार' के अधीन 07 नगर निकायों में कुल 40877 आवेदकों के आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अद्यतन कुल 24754 आवेदकों को आवास निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवशेष आवेदकों के प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है।

जी हां, उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अलीगंज स्थित कपूरथला में पार्किंग का निर्माण कराये जाने विषयक

105-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज स्थित कपूरथला में पार्किंग की सुविधा न होने से लोगों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अलीगंज की समस्त योजना नगर निगम, लखनऊ को दिनांक 28-04-2008 में हस्तगत कर दी गई है। कपूरथला स्थित सेक्टर-एफ, अलीगंज आवासीय योजना के पार्क में पूर्व में भूमिगत पार्किंग सह पार्क के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की 153वीं बैठक दिनांक 28-02-2015 में स्वीकृति हेतु रखा गया। बोर्ड द्वारा स्थल का विस्तृत सर्वे, एप्रोच रोड आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन करते हुए क्षेत्र के निवासियों से सुनवाई कर संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। इस क्रम में दिनांक 29-04-2015 को गठित समिति द्वारा स्थानीय निवासियों

को आमंत्रित करते हुए बैठक की गई। उक्त बैठक में स्थानीय आवंटियों द्वारा कपूरथला आवासीय कल्याण समिति सेक्टर-एफ, अलीगंज के माध्यम से लिखित रूप से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई। वर्तमान में नगर निगम द्वारा पार्क का सौन्दर्यीकरण करा दिया गया है, जिसका उपयोग जनसामान्य के द्वारा किया जा रहा है।

नियोजित पार्क में पार्किंग के प्रस्ताव पर स्थानीय आवंटियों की अनापत्ति आवश्यक है। अतः कपूरथला आवासीय कल्याण समिति की आपत्ति प्राप्त होने पर उक्त प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त कपूरथला क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण किए जाने हेतु अन्य कोई स्थान चिन्हित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

106-डा0 आर0के0 वर्मा-

[01 गुरुवार के अता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों की भांति समान शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट दिये जाने विषयक

107-श्री ओम प्रकाश राजभर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के बराबर पिछड़ी जातियों का भी शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट दिनांक 18-02-2020 को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न बजट प्रस्तावित है :-

सामान्य	**(धनराशि रु0 लाख में)**
योजना	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि**
1) पूर्व दशम छात्रवृत्ति	2500.00
(2) दशमोत्तर छात्रवृत्ति	50000.00
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
योजना	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि**
(1) पूर्व दशम छात्रवृत्ति (केंद्रांश-50/ राज्यांश-50)	4000.00
(2) पूर्व दशम छात्रवृत्ति	13500.00
	योग- 17500.00

(3) दशमोत्तर छात्रवृत्ति शत प्रतिशत केन्द्रांश	20000.00
(4) दशमोत्तर छात्रवृत्ति	100000.00
	योग- 120000.00

प्रश्न नहीं उठता।

हापुड़ बाबूगढ़ से बी0बी0 नगर ज0 बुलंदशहर में उल्लिखित मार्गों को चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक

108-श्री विजय पाल (आढ़ती)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ बाबूगढ़ से बी0बी0 नगर जनपद-बुलन्दशहर में पड़ने वाला 8 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का पूर्व में साढ़े 5 मीटर चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु हापुड़ के अन्तर्गत पड़ने वाले 9 किलोमीटर मार्ग केवल साढ़े 3 मीटर चौड़ा है जिसका भी जनहित में साढ़े 5 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके प्रारम्भ के 09 कि0मी0 लम्बाई का भाग जनपद हापुड़ में तथा शेष 7.00 कि0मी0 लम्बाई का भाग जनपद बुलन्दशहर में पड़ता है। जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कराया गया है तथा जनपद हापुड़ में पड़ने वाले भाग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 5655 तथा सी0वी0पी0डी0 386 है, जिसके अनुसार उक्त भाग का 5.50 मी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु रु0 1418.20 लाख की लागत आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हापुड़ के राज्य मार्ग हापुड़ से ग्राम दोमयी, घनौरा आदि मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक

109-श्री विजय पाल (आढ़ती)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-622/2020, दिनांक 27-01-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है, जोकि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत राज्य मार्ग हापुड़ से ग्राम दोमयी, धनौरा, बझीलपुर, खड़खड़ी, मुरादपुर, असरा, निजामसर आदि मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य -

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु आंकलित लागत रु0 1601.63 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 तिलहर अन्तर्गत ग्राम पुरायूँ से हुसैनापुर तक मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

110-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम पुरायूँ से ग्राम हुसैनापुर तक कच्चे गड्ढा युक्त ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम पुरायूँ (पुरायँ) एवं ग्राम हुसैनापुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 तिलहर अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर से अजीजपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

111-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर से ग्राम अजीजपुर डामर रोड तक कच्चे गड्ढा युक्त मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर एवं ग्राम अजीजपुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 तिलहर के ग्राम संतोषपुर से ईश्वरा तक मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

112-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम सन्तोषपुर मार्ग से ग्राम ईश्वरा तक कच्चे गड्ढा युक्त मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम सन्तोषपुर एवं ग्राम ईश्वरा पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 सिधौली अन्तर्गत ग्राम रखिया खुर्द से ग्राम पचदियुरा तक मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

113-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम रखिया खुर्द मार्ग से ग्राम पचदियुरा तक कच्चे गड्ढा युक्त मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी। यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत रखिया खुर्द सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.45 कि0मी0 की स्वीकृति शासनादेश संख्या-111/2019/आ0-134(1)/23-9-2019-03डी0डी0/2019, दिनांक 18-11-2019 द्वारा प्रदान की गयी है। कार्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पचदियुरा पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है, अतः ग्राम रखिया खुर्द एवं ग्राम पचदियुरा को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 तिलहर अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया से बख्तियारपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

114-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया से नहर पटरी पर ग्राम बख्तियारपुर से डामर रोड तक कच्चे गड्ढा युक्त ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया एवं ग्राम बख्तियारपुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

के0जी0एम0यू0, लखनऊ में रिक्त पदों के विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

115-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कुल कितने विभाग हैं तथा उन विभागों में शासन द्वारा किस-किस श्रेणी के पद सृजित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रत्येक फैकल्टी (विभाग) में कितने पद किस सेवा वर्ग में वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में 66 शैक्षणिक विभाग विद्यमान हैं, जिसमें एक विभाग (स्पोर्टस मेडिसिन विभाग) भारत सरकार द्वारा केवल 05 वर्षों तक के लिए ही स्वीकृत है। उक्त के अतिरिक्त के0जी0एम0यू0 लखनऊ में कालेज ऑफ नर्सिंग, विभिन्न छात्रावास, निर्माण विभाग, वित्त विभाग, प्रशासनिक कार्यालय आदि कतिपय अन्य यूनिट भी संचालित है। उक्त विभागों/यूनिटों में यथावश्यकता समूह-क, समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ श्रेणी के पद सृजित हैं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के प्रत्येक फैकल्टी (विभाग) में सेवा वर्ग के अनुसार रिक्त पदों का विवरण संलग्नक-1 में उल्लिखित है।†

---

† (देखिये नत्थी-'ख' आगे पृष्ठ सं0-273-276 पर)

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

के0जी0एम0यू0, लखनऊ में अनु0 जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग के भरे व रिक्त पदों की विभागवार सूचना उपलब्ध कराने विषयक

116-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी सेवारत हैं तथा उनकी सेवाएं किन-किन विभागों में हैं ? क्या सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के रिक्त पदों की विभागावार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

के0जी0एम0यू0 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के क्रमशः 837, 02 तथा 815 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनकी सेवायें संलग्नक-1 में उल्लिखित 66 शैक्षणिक विभागों, कालेज ऑफ नर्सिंग के अतिरिक्त कतिपय अन्य यूनिटों में हैं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण वर्तमान में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2019/3118, दिनांक-14 नवम्बर, 2019 द्वारा पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुये देवनागरी लिपि के अ, आ से ज्ञ तक के क्रम में विभागों को रखते हुये किया जा रहा है। अतः उक्त के क्रम में शैक्षणिक पदों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों का विभागवार विवरण संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।†

के0जी0एम0यू0 के गैर शैक्षणिक संवर्ग के आरक्षित श्रेणी की विभागवार रिक्तियों के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में गैर शैक्षणिक संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 की प्रथम परिनियमावली-2011 की धारा-41(थ)16.15(2) के प्राविधानों के अनुसार उक्त परिनियमावली के प्रभावी होने के दिनांक 29 जुलाई, 2011 से के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों (अर्थात चिकित्सा संकाय/दंत संकाय के समस्त कर्मचारियों को उनके संवर्ग में) एकल संवर्ग मानते हुए उनकी एकल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन अन्तिम रूप से किया गया है। इसके पश्चात कर्मचारियों को विभागों की आवश्यकतानुसार तैनाती की जाती है।

---

† (देखिये नत्थी-'ग' आगे पृष्ठ सं0-277-280 पर)

ऐसी स्थिति मे गैर शैक्षणिक संवर्ग मे विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्तियों का विभागवार उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम झांसी में खाली प्लाट/भू-खण्ड को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

117-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम झांसी में नगर निगम की भूमि व नजूल वाली भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नजूल/नगर निगम की भूमि को दबंगो से कब्जा मुक्त करायेगी तथा अवैध कब्जा करने वाले दबंगों के विरुद्ध एंटी भू-माफिया के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

झांसी नगर निगम की 785.18 एकड़ (317.936 हेक्टेयर) की पैमाइश कराकर भूमि के चारो ओर आर0सी0सी0 पिलर व लोहे के बोर्ड लगा कर सुरक्षित किया गया है। अवैध कब्जों में निहित भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। नगर निगम/नजूल भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध 07 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। नजूल भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध बेदखली हेतु पी0पी0 ऐक्ट (THE PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS ACT, 1971) के अन्तर्गत 76 वाद नगर मजिस्ट्रेट झांसी के न्यायालय में दायर किये गये हैं, जो लम्बित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गुरसराय कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने विषयक

118-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरसराय कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर अपूर्ण पुल/निर्माणाधीन पुल को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

सेतु के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के राया में जयपुर-पीलीभीत मार्ग पर बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक

119-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्ष में मथुरा वृदावन में होने जा रहे कुम्भ की तैयारियों के दृष्टिगत जयपुर पीलीभीत मार्ग पर जनपद मथुरा के राया कस्बा में बाईपास का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मथुरा में राया नगर क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट रोड 33 अब राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-530बी के रूप में नोटिफाइड हो चुका है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के डी0पी0आर0 का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सीकॉन जीआईएस ड्रिविन डिजाइन कन्सल्टेंसी, बैंगलोर से कराया जा रहा था जिसे सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया था। भू-अर्जन कमेटी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा भूमि अर्जन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके पश्चात् डीपीआर के कार्य को पुनः आरम्भ करने के निर्देश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिए जा चुके हैं उक्त परियोजना में राया कस्बा में एक बाई-पास प्रस्तावित है। बाई-पास का कार्य भू-अर्जन के पश्चात निविदा आमंत्रित कराने के उपरान्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव के नगला अकोस पंचायत में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

120-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक बल्देव में नगला अकोस पंचायत तथा आस-पास के ग्रामीणों को यमुना पार आगरा जाने के लिए यमुना के ऊपर पुल न होने के कारण परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो जनहित में नगला अकोस को यमुना पर पुल निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु स्थल से 12.50 कि0मी0 अपस्ट्रीम में बल्देव-बरौली-कैलाश मार्ग से नेरा मार्ग (ग्रा0मा0) के कि0मी0 2 में यमुना नदी पर सेतु निर्मित है एवं लगभग 7 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में यमुना नदी पर कंजौली घाट सेतु निर्मित है।

जनपद मथुरा के नगला अकोस आदि गांववासियों को आगरा जाने हेतु उक्त दोनों पूर्व निर्मित सेतु उपलब्ध है।

प्रस्तावित स्थल के डाउन स्ट्रीम में 10 कि0मी0 से कम दूरी पर सेतु निर्मित है। अतः नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 ठेकमा में कतिपय सड़क मार्गों का निर्माण व मरम्मत कराये जाने विषयक

121-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम सकरामऊ में पश्चिम व अनुसूचित बस्ती गांगी नदी से जौनपुर सरहद तक व मुड़हर बाजार से आमानगंज होते हुए आजमगढ़- वाराणसी तक एवं ग्राम-महुआरी पंचायत भवन से ग्राम फेरी तक तथा ग्राम बैरीडीह में सोसायटी भवन से डा0 साहिल के घर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो, क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम-सकरामऊ में पश्चिम अनुसूचित बस्ती, गांगी नदी से जौनपुर सरहद तक मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में है। प्रश्नगत मार्ग को वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुये निविदा आंमत्रित की जा चुकी है।

मुड़हर बाजार से अमानगंज होते हुए आजमगढ़-वाराणसी मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष मार्ग पर मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराकर मार्ग पर यातायात सुलभ कराया जा चुका है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

ग्राम महुआरी पंचायत भवन से ग्राम फेटी के बीच में कोई मार्ग स्थित नहीं है तथा महुआरी एवं फेटी ग्राम पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। उक्त के कारण दोनों ग्रामों का आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में विभागीय नीति से आच्छादित न होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम बैरीडीह में सोसायटी भवन से डा0 साहिल के घर तक सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। उक्त मार्ग विशेष मरम्मत/नवीनीकरण मद के अन्तर्गत स्वीकृत है। कार्य को पूर्ण कराया जाना 10-03-2020 तक लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देश के समस्त नगर निकायों में नये पशु संरक्षण केन्द्र बनाने या पुराने केन्द्रों में सुधार करने विषयक

122-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में किसी निश्चित अवधि तक जरूरत के अनुसार नये पशु संरक्षण केन्द्र बनाने या पुराने केन्द्रों को सुव्यवस्थित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर 2017, द्वारा प्रदेश की नगर निकायों में आवारा एवं बेसहारा पशुओं को आश्रय दिये जाने हेतु कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश की 75 जनपदों में 262 नगर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि रुपये 394.1184 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश की नगर निकायों में निर्मित की जाने वाली कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से 500 आवारा एवं बेसहारा पशुओं को आश्रय दिये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु निकाय की मांग पर निर्धारित माडल कार्य योजना के अनुसार रुपये 165.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

जनपद बागपत नगर पालिका परिषद् बड़ौत में डूडा द्वारा विकास कार्यों हेतु व्यय धनराशि व लंबित विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने विषयक

123-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर पालिका परिषद् बड़ौत, जनपद बागपत में वर्तमान सरकार के गठन से अब तक डूडा द्वारा विकास कार्यों हेतु कितनी धनराशि सड़क/गली निर्माण कार्यों में कहाँ-कहाँ खर्च की गयी है तथा कौन कौन से सड़क/गली निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लंबित है ? क्या सरकार लंबित विकास कार्यों को पूर्ण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

वर्तमान सरकार के गठन से अब तक 'मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत' जनपद-बागपत की निकाय, नगर पालिका परिषद्, बड़ौत के मोहल्ला

आजाद नगर में अखिल पुत्र सुखपाल के मकान से भ्रमपाल पुत्र रामपाल के प्लाट तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत रु0 64.82 लाख की धनराशि से उक्त निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पालिका परिषद्, बड़ौत अल्पविकसित बस्तियों में 06 विभिन्न परियोजनाओं हेतु कुल रु0 210.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलित है। उक्त कार्यों के विवरण की सूची संलग्न है। †

उपरोक्त अंश में उत्तर दिया गया है।

वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के औगासी घाट के पुल निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक

124-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बबेरू-फतेहपुर मार्ग पर औगासी घाट का पुल विगत कई वर्षों से अधूरा पड़ा होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराकर यातायात चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जी हां, कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत सेतु को माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

125-श्री मनीष असीजा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रधानमंत्री आवास योजना में (शहरी) पात्र लाभार्थियों की पहली किस्त, दूसरी किस्त एवं तीसरी किस्त जारी करने के सम्बन्ध में

126-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में दिनांक 20 जनवरी, 2020 तक कितने पात्र लाभार्थियों की पहली किस्त, दूसरी किस्त एवं तीसरी किस्त आना शेष है ? क्या सरकार इन लम्बित किस्तों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी-'घ' आगे पृष्ठ सं0-281 पर)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद-फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत दिनांक 20-01-2020 तक कुल पात्र 28604 लाभार्थियों के सापेक्ष 7598 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 12822 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 25523 लाभार्थियों को तृतीय किस्त प्रेषित किया जाना शेष है।

जी हां, शेष लाभार्थियों को मिशन अवधि 31 मार्च, 2022 तक नियमित/क्रमिक रूप से लाभान्वित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में

127-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 को नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद एवं सिचाई एवं जल संसाधन विभाग (वर्तमान जल शक्ति विभाग) के मध्य गठित होने वाले एम0ओ0यू0 हेतु शासनादेश संख्या 173/2017/1623/17-27 सि0-4-28 (डब्ल्यू)/16, दिनांक 6-9-2017 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश के अनुपालन में एम0ओ0यू0 करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के कुछ बिन्दुओं/तथ्यों पर नगर निगम फिरोजाबाद को आपत्तियां हैं। उक्त बिन्दुओं पर विचार कर संशोधित एम0ओ0यू0 गठित कराये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 07-12-2019 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में पेयजल आपूर्ति कराये जाने विषयक

128-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजल आपूर्ति कराये जाने के क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 27-09-2019

की आहूत बैठक में मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग कानपुर, उ0प्र0 एवं नगर निगम, फिरोजाबाद के मध्य एम0ओ0यू0 कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

नगर निगम फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के कुछ बिन्दुओं/तथ्यों पर नगर निगम फिरोजाबाद को आपत्तियां हैं। उक्त बिन्दुओं पर विचार कर संशोधित एम0ओ0यू0 गठित कराये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 07-12-2019 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु जसराना नवीन शहर, फिरोजाबाद के माध्यम से 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराये जाने विषयक

129-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु जसराना नवीन शहर, फिरोजाबाद के माध्यम से 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराये जाने के क्रम में नहर से दिनांक 18-08-2018 से जलापूर्ति कराई जा रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नहर में सिल्ट जमा होने से नगर निवासियों को पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की सिल्ट सफाई एवं अनुरक्षण हेतु कोई ठोस/स्थायी व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

नहर में सिल्ट जमा होने, नहर बीच में ब्रेक होने इत्यादि कारणों से बीच-बीच में पेयजलापूर्ति प्रभावित हुई है। उक्त अवधि में नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अपने संसाधनों से पेयजल आपूर्ति की गई है।

फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना (जेड़ाझाल परियोजना) के अन्तर्गत कच्चा जल प्राप्त करने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 200 क्यूसेक नहर का निर्माण किया गया है। नहर के संचालन एवं रख-रखाव हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा नगर निगम, फिरोजाबाद के मध्य एम0ओ0यू0 प्रस्तावित है। एम0ओ0यू0 के निष्पादन के उपरान्त नहर की सिल्ट सफाई एवं अनुरक्षण हेतु ठोस/स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के वि0स0क्षे0 अजगरा में नए पिच रोड निर्माण विषयक

130-श्री कैलाश नाथ सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की विधान सभा क्षेत्र-अजगरा में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत नए पिच रोड निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-424 सी0डी0ओ0 दिनांक 16-08-2019, जो मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत पत्र दिनांक 16-08-2019 के क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग के लिए 250 से अधिक आबादी की बसावटों की योजना के अन्तर्गत आगणन गठित है, जिसे स्वीकृत करने पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है। उक्त पत्र के क्रम संख्या-2, 4, 5, 6, 7, 9 व 10 पर अंकित मार्गों की लागत रु0 50.00 लाख से कम होने के कारण तथा क्रमांक-3 पर वर्णित मार्ग पूर्व से लेपित मार्ग होने के कारण इनका निर्माण पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित न होने के कारण संभव नहीं है। क्रमांक-8 पर उल्लिखित मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में भूमि अधिग्रहण का प्राविधान न होने के कारण इसका निर्माण कार्य किया जाना प्राविधानों से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के नगर पंचायत राया के तालाबों से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में

131-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगर पंचायत राया के कुल कितने तालाबों पर अतिक्रमण किया गया है ? क्या सरकार उक्त तालाबों से अतिक्रमण हटवाकर पुनरुद्धार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर पंचायत राया के कुल 03 तालाबों पर अतिक्रमण किया गया है। उनमें से गोपालबाग स्थित तालाब से अतिक्रमण हटवाकर पुनरुद्धार किया जा रहा है। सुल्तानगंज स्थित तालाब पर चार अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध पी0पी0ऐक्ट के तहत उप जिलाधिकारी मांट के समक्ष वाद विचाराधीन है। माँट रोड स्थित किशन तलैया पर अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मथुरा के नगर पंचायत राया की सीमा विस्तार विषयक

132-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की नगर पंचायत राया में ग्राम पंचायत-नगला भीमा, भैसारा, खरवा, कोयल, थाना- अमर सिंह, गौंगा, अचस लधौर के भाग सीमा विस्तार में शामिल करके नगर पंचायत राया के सीमा विस्तार सम्बन्धी अधिसूचना जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

नगर पंचायतों की सीमा विस्तार हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-450/9-1-2015 426सा/14, दिनांक 31 जनवरी, 2015 के मापदण्डों के अनुसार सीमा विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में नगर पंचायत राया के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्ध में जिलाधिकारी मथुरा का प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद शाहजहांपुर वि0ख0 तिलहर के ग्राम कुआँडांडा रेलवे फाटक से रुजवारी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

133-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम कुआँडांडा रेलवे फाटक से ग्राम रूजवारी तक तथा ग्राम हसैनपुर कबरा से बाजपुर कुमरिया तक कच्चे गड्ढायुक्त ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी। यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

(1) ग्राम कुआँडांडा रेलवे फाटक एवं ग्राम रुजवारी पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

(2) ग्राम हसैनपुर कबरा (हुसैनपुर कबरा) एवं बाजपुर डुमरिया (बाजपुर कुमिरखा) पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में वि0ख0 निगोही के ग्राम विक्रमपुर चकौरा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

134-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम विक्रमपुर चकौरा के पश्चिम से ग्राम बरौरा तक तथा ग्राम चमरूआ से बरौरा तक कच्चे गड्ढा युक्त ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी। यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम विक्रमपुर चकौरा के पश्चिम से ग्राम बरौरा तक मण्डी परिषद का स्वामित्व है अतः लो0नि0वि0 से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ग्राम चमरूआ से बरौरा तक के मार्ग की दशा वर्तमान में संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम बाजपुर से ग्राम सैजना तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

135-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम बाजपुर कुमरिखा से ग्राम सैजना तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का सरकार डामरीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम बाजपुर कुमरिखा एवं ग्राम सैजना पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 तिलहर में ग्राम वीरमपुर से ग्राम इस्माइलपुर नवादा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

136-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत तथा ग्राम वीरमपुर से ग्राम सैजना तक ग्राम वीरमपुर से ग्राम इस्माइलपुर

नवादा तक मार्गों का सरकार डामरीकरण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम वीरमपुर एवं ग्राम सैजना तथा ग्राम वीरमपुर एवं ग्राम इस्माइलपुर नवादा पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े ग्रामों को परस्पर लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 निगोही के शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

137-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर पतराजपुर तिराहे से ग्राम भदैग-भटपुरा तक गड्ढा युक्त उबड़-खाबड़ जर्जर मार्ग का डामरीकरण सरकार करायेगी। यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग पर माह 11/2019 में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग की दशा वर्तमान में संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मंदरेपुर पश्चिम से शिवनगर चरनई तक जर्जर मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

138-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मन्दरेपुर पश्चिम से शिवनगर चरनई तक का मार्ग दूरी लगभग 01 कि0मी0 जर्जर होने के कारण लोगों की आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड विलरियागंज में मन्दुरी ग्रामीण बैंक से दुर्गा माता मन्दिर तक मार्ग निर्माण विषयक

139-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड विलरियागंज मे मन्दुरी ग्रामीण बैंक से दुर्गा माता मन्दिर तक मार्ग जर्जर हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में नेवादा से परशुरामपुर को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

140-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में नेवादा से जाने वाली मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित ग्राम नेवादा व परशुरामपुर पूर्व से ही एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद हरदोई के माधौगंज-बिलग्राम रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में

141-श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां अन्तर्गत माधौगंज-बिलग्राम रेलवे क्रासिंग और माधौगंज-बघौली क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत दोनों सम्पारों का टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण रेलवे द्वारा रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में उक्त सेतुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस कारण रेलवे द्वारा

उक्त सेतुओं पर अपनी सहभागिता नहीं की जायेगी। अतः उक्त दोनों उपरिगामी सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर वि0स0क्षे0 में टाउन एरिया को सैदपुर नगर पालिका परिषद् घोषित करने के सम्बन्ध में

142-श्री सुभाष पासी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा सैदपुर में नगर पंचायत सैदपुर को सरकार नगर पालिका परिषद् घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद् बनाने के लिए शासनादेश दिनांक 03-04-2018 के अनुसार निकाय की आबादी एक लाख से अधिक तथा जनसंख्या घनत्व 6266(प्रति वर्ग कि0मी0) का मानक निर्धारित है। नगर पंचायत, सैदपुर की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 24438 है तथा जनसंख्या घनत्व का मानक भी पूरा नहीं है। इस प्रकार नगर पंचायत-सैदपुर, नगर पालिका परिषद् की श्रेणी में आने का मानक पूरा नहीं करती है।

जनपद शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर में भर्ती की जांच के सम्बन्ध में

143-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-3-2019 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर में की गई भर्ती की जाँच सम्बन्ध में था, के क्रम मे उक्त की जाँच मण्डलायुक्त, सहारनपुर से कराने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो उक्त जाँच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

इस सम्बन्ध में पत्र 08-03-2019 प्राप्त न होकर पत्र दिनांक 08-04-2019 प्राप्त है। प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने हेतु पूर्व में ही आदेश दिनांक 03-11-2017 निर्गत किये गये थे।

मण्डलायुक्त, सहारनपुर की जांच आख्या में तत्कालीन प्रभारी निदेशक, डा0 बी0एल0 शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके आधार पर श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्तुत करते हुए जांच करायी गयी। जांच आख्या में श्री शर्मा को दोषी

पाया गया। उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् सेवा नियमावली के नियम 18-2 के अन्तर्गत दण्ड पर निर्णय हेतु जांच आख्या को गवर्निंग बॉडी उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद को सन्दर्भित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

144-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-8-2019 जो किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहाँपुर मे व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हैं ? यदि हाँ, तो क्या सही है कि दिनांक 20-8-19 को पत्रांक 397 आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव गन्ना को प्रेषित किया है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहाँपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15-08-2019 प्राप्त न होकर पत्र दिनांक 07-08-19 प्राप्त हुआ है।

हां।

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहाँपुर की जाँच में चीनी मिल तिलहर को प्रेसमड के विक्रय में कोई वित्तीय हानि नहीं पायी गयी। कृषकों के मध्य प्रेसमड वितरण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर कार्यालय द्वारा किसानों को भ्रमण कराने के सम्बन्ध में

145-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-6-2019 पत्रांक 147110 जो गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र शाहजहाँपुर कार्यालय द्वारा किसानों को भ्रमण कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 01-07-19 को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

हां।

गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 17-10-2016 से 23-10-2016 तक आयोजित अन्तः प्रदेशीय अध्ययन यात्रा में जनपद-शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, बरेली व फर्रुखाबाद के कुल 38 कृषकों को बस द्वारा मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ व सीतापुर का भ्रमण कराया गया। इस अध्ययन यात्रा में कुल अंकन रु0 89997/- व्यय हुआ।

इसी प्रकार दिनांक 12-03-2018 से 17-03-2018 तक आयोजित अन्तःप्रदेशीय अध्ययन यात्रा में जनपद शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, पीलीभीत के कुल 40 कृषकों को बस द्वारा कानपुर, लखनऊ, कुमारगंज फैजाबाद, गोण्डा-बलरामपुर, गोला का भ्रमण कराया गया। इस अध्ययन यात्रा में कुल अंकन रु0 99925/- व्यय हुआ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी गयी निविदाओं के सम्बन्ध में

146-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवा में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी निविदायें हुईं और कौन-कौन से फर्म को निविदाएं प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में नौतनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल बारह कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गईं। निविदा प्राप्त करने वाले ठेकेदार/फर्मों का विवरण निम्नवत् है :-

1-मे0 हरिशंकर कसौधन पुत्र स्व0 सत्यनारायण कसौधन, गौतमबुद्धनगर, वार्ड नं0-14, नौतनवां, महाराजगंज।

2-मे0 शिव कुमार, ग्राम व पोस्ट- नईकोट, अड्डा बाजार, नौतनवां, महाराजगंज।

3-मे0 राम सावर, ग्राम व पोस्ट- नईकोट, अड्डा बाजार, नौतनवां, महाराजगंज।

4-मे0 राम सावर, ग्राम व पोस्ट- नईकोट, अड्डा बाजार, नौतनवां, महाराजगंज।

5-मे0 विजेश नारायण त्रिपाठी, ग्राम हथियहवा, टोला रामगढ़, करमहवां, महाराजगंज।

6-मो0 अनीस, सुबाष नगर वार्ड नं0-19, नगर परिषद्, नौतनवां, महाराजगंज।

7-मे0 हरिनन्दन उपाध्याय, ग्राम परसौनी कला, नई कोट, नौतनवां, महाराजगंज।

8-मे0 हरिनन्दन उपाध्याय, ग्राम परसौनी कला, नई कोट, नौतनवां, महाराजगंज।

9-मे0 हरिशंकर कसौधन पुत्र स्व0 सत्यनारायण कसौधन, गौतमबुद्धनगर, वार्ड नं0-14, नौतनवां, महाराजगंज।

10-मे0 रेशमी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री दसगुना गुप्ता, गनेशपुर पोस्ट करमहवां, नौतनवां, महाराजगंज।

11-मे0 आशुतोष कुमार दूबे, ग्राम भखरा भगवानपुर, जनपद - गोरखपुर।

12-मे0 राम सावर, ग्राम व पोस्ट- नईकोट, अड्डा बाजार, नौतनवां, महाराजगंज।

उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत विवरण का उल्लेख कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

147-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती के गन्ना किसानों के शुगर मिल व वाल्टरगंज शुगर मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में।

148-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अठदमा शुगर मिल तथा वाल्टरगंज शुगर मिल पर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 22-02-2020 तक की स्थिति के अनुसार, पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि0 अठदमा-रुधौली द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2019-20 अभी चल रहा है एवं चीनी मिल रुधौली द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है। गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु चीनी मिल को दिनांक 04-02-2020 को नोटिस निर्गत की गई है।

जिला बस्ती में स्थित गोविन्द शुगर मिल्स लि, वाल्टरगंज गत पेराई सत्र 2018-19 से बन्द चल रही है। दिनांक 22-02-2020 तक की स्थिति के अनुसार जिला बस्ती में स्थित गोविन्द शुगर मिल्स लि0 वाल्टरगंज पर पूर्व पेराई सत्र 2106-17 का रु0 22.29 करोड़ एवं पेराई सत्र 2017-18 का रु0 19.65 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। चीनी मिल पर उक्त सत्रों के बकाये गन्ना मूल्य की वसूली हेतु क्रमशः दिनांक 07-02-2018 एवं 14-12-2018 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके है, जिसके अनुक्रम में वसूली की कार्यवाही जिला प्रशासन के स्तर से की जा रही है। राज्य सरकार गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वि0स0क्षे0 रुधौली त0 रुधौली बांसखोर कला से इड़वाकला तक जाने वाले मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

149-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की तहसील रुधौली के अन्तर्गत बांसखोर कला से डड़वाकला तक जाने वाले मार्ग जिगना, रानीपुर, हटवा, सिसवारी खुर्द, बभनी मिश्र, कथकपुरवा आदि गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर स्वीकृति के बाद ईंट गिट्टी आदि डाल कर छोड़ दिया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार बांसखोर कला से डड़वाकला तक जाने वाले उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति में है।

जी हां।

निर्माण कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हजरतगंज से इंदिरानगर तथा खुर्रमनगर जाने हेतु गोमती बैराज पुल के बगल में एक पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

150-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित गोमती बैराज पर ट्रैफिक वन-वे कर दिये जाने के कारण हजरतगंज से इन्दिरानगर तथा खुर्रमनगर जाने वाले लोगों को 1090 चौराहे पर हमेशा जाम से जूझना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार हजरतगंज से इन्दिरानगर तथा खुर्रमनगर जाने हेतु गोमती बैराज पुल के बगल में एक पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर सामान्यतः जाम की समस्या नहीं रहती है, अपितु कभी-कभी यातायात अधिक बढ़ने पर ही कुछ समय के लिये जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रश्नगत मार्ग पर गोमती बैराज पुल से अपस्ट्रीम में लगभग 1350 मीटर की दूरी पर एक 4 लेन का सेतु तथा डाउन स्ट्रीम में क्रमशः लगभग 200 मीटर एवं 400 मीटर दूरी पर 8-लेन सेतु एवं 2-लेन सेतु पूर्व से उपलब्ध हैं जो वर्तमान यातायात की दृष्टि से पर्याप्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मानक नगर के केसरी खेड़ा वार्ड, सूर्य नगर में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

151-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मानक नगर में केसरी खेड़ी वार्ड, सूर्य नगर (हनुमान मंदिर के पीछे) में लगभग 50 मीटर नाली एवं आर0सी0सी0 सड़क के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी मा0 नगर विकास मंत्री के आदेश संख्या-सामा0 3569/मं0सं0का0न0वि0/2018, दिनांक 26-07-2018 नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ।

प्रश्नगत सड़क 40 मीटर लम्बाई में है, जिस पर इंटरलाकिंग लगाने एवं नाली के निर्माण कार्य पर रु0 3.17 लाख का व्ययभार सम्भावित है। प्रश्नगत कार्य 03 माह में करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज वि0स0क्षे0 सोरांव में सोरांव-कल्याणपुर मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण में गड़बड़ी की जांच के सम्बन्ध में

152-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में सोरांव-कल्याणपुर मार्ग की कि0मी0-12(हरखपुर से मदारी) वाया जालालपुर, मऊ-आइमा होते हुए ईदगाह तीन बन्ती (पी0बी0एम0) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार नहीं कराये गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण कार्य की जाँच टी0ए0सी0 से करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 के मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के सोरांव में फाफामऊ से कलंदरपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण में अनियमितता की जांच विषयक

153-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में फाफामऊ हनुमानगंज मार्ग (थरवई) से पड़िला बैजनाथ मन्दिर नहर पटरी से बड़नपुर पान की पुलियाँ कुरगाँव होते हुए कलन्दरपुर (एस0पी0एच0) मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण में मानक के विपरीत गुणवत्ता विहीन कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य की जाँच टी0ए0सी0 से करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 के मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज वि0स0क्षे0 सोरांव में मऊआइमा से मोहन तक सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में

154-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरावं में मऊआइमा से मोहन का पूरा तक सड़क के निर्माण/मरम्मत में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता कर घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या सरकार सड़क निर्माण में कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नांकित मार्ग में कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा मार्ग निर्माण में गुणवत्तापरक सामग्री का ही प्रयोग किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम सोमना में स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जीकृत कराये जाने विषयक

155-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 278/भाजपा/वि0म0द0/2019 दिनांक 25-11 2019 जो ग्राम सोमना पर रेलवे उपरिगामी पुल पर लगी स्ट्रीट लाइटों का ऊर्जीकरण एवं सरकारी धन का अपव्यय सम्बन्धी है, पर मुख्य मंत्री आदेश संख्या आई0जी0आर0एस0 18157190125468 दिनांक 28-11-2019 के क्रम में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जाकृत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद अलीगढ़ में रेल उपरिगामी सेतु सम्पार सं0 119बी, खैर सोमना मार्ग पर सेतु निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने के पश्चात् समस्त प्रकाश व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु ग्राम प्रधान, सोमना को हस्तगत कर दिया गया है। अतः स्ट्रीट लाइट को ऊर्जीकृत करने की कार्यवाही विद्युत विभाग/ग्राम प्रधान द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

प्रदेश में बंद किये जाने वाले निगमों का विवरण विषयक

156-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने निगमों को बन्द किया जा रहा है तथा इन निगमों की वर्ष 2016 से 2019 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण क्या है ? सरकार बतायेगी कि इन बन्द किये गये निगमों का कार्य किससे करायेगी तथा कर्मचारियों को कहां समायोजित करेगी ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर प्रदेश के किसी भी निगम को बन्द किये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत विषयक

157-श्री मानवेन्द्र सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज क्षेत्र में काफी हाउस के सामने स्थित इलाहाबाद बैंक से भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल तक का फुटपाथ

क्षतिग्रस्त होने के कारण पैदल यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फुटपाथ की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निकाण्ड से प्रभावित गरीब/पीड़ितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में

158-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निकाण्डों में सब कुछ गवां देने वाले गरीबों/पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या सहायता राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गरीब/पीड़ित नागरिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहारनपुर सिटी में लकड़ी उद्योग की आरा मशीनों के कारखानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने विषयक

159-श्री मसूद अखतर-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के सहारनपुर सिटी में संचालित उद्योग व आरा मशीनों से शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरा मशीनों के कारखानों को शहर के बाहर शिफ्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

जनपद सहारनपुर के सहारनपुर सिटी में कुल 43 वैध आरा मशीनें स्थापित हैं। इन आरा मशीनों के संचालन से शहरवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में कोई लिखित या मौखिक शिकायत शहरवासियों द्वारा वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

के0जी0एम0यू0, लखनऊ के लारी कार्डियोलाजी विभाग में आपरेशन वाले मरीजों से सर्जिकल सामान व दवाओं, आपरेशन टीम के चिकित्सकों हेतु गाउन (एप्रेन) के शुल्क के सम्बन्ध में

160-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0 लखनऊ के लारी कार्डियोलाजी विभाग में आपरेशन वाले मरीजों से सर्जिकल सामान एवं दवाओं के साथ ही आपरेशन टीम के चिकित्सकों के गाउन (एप्रेन) को शुल्क जमा करने अथवा बाहर से मंगवाये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न जन आरोग्य योजनाओं जैसे-आयुष्मान योजना, सी0एम0/पी0एम0 एवं असाध्य रोगों के अन्तर्गत आच्छादित निःशुल्क श्रेणी के मरीजों से सर्जिकल सामान एवं दवाओं के साथ ऑपरेशन टीम के चिकित्सकों के गाऊन (एप्रेन) के शुल्क न तो जमा कराये जातें है और न ही बाहर से मंगाये जाते हैं। परन्तु उक्त योजनाओं के अतिरिक्त ऑपरेशन वाले भर्ती मरीजों जिन्हें सशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है, से केवल एंजियोग्राफी में लगने वाले कन्ज्यूमेबिल सामान जैसे स्टॅन्ट, गुब्बारे, वायर, आदि के साथ-साथ गाऊन (एप्रैन) भी बाहर से मंगाये जाते है या उनका शुल्क जमा कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

161-श्री विजय मिश्रा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद झांसी के जल संस्थान गुरसराय में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैण्ड पम्प मकैनिक के भुगतान के सम्बन्ध में

162-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के जल संस्थान गुरसराय में दैनिक वेतन/नकद वेतन पर कितने हैण्ड पम्प मकैनिक कार्यरत एवं मजदूरी पर है ? क्या यह सही है कि सितम्बर, 2018 से उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं मजदूरों को कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हाँ। जल संस्थान, झाँसी द्वारा केवल जनपद की नगरीय निकायों में स्थापित हैण्डपम्प के सामान्य रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। जल संस्थान द्वारा नगर

पालिका परिषद गुरसरांय क्षेत्र में हैण्डपम्प व पाइप लाइन के मरम्मत कार्य हेतु 03 श्रमिक कार्यदायी संस्था के माध्यम से रखे गये थे।

जी नहीं, उन्हें माह सितम्बर, 2019 तक का भुगतान किया जा चुका है। माह नवम्बर, 2019 से हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा प्रति हैण्डपम्प की दर से किया जा रहा है तथा कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक भी कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये जाते है तथा उन सभी श्रमिकों को कार्यदायी संस्था द्वारा माह जनवरी, 2020 तक का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली वि0ख0 रुधौली के जर्जर कथकपुरवा केशवापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

163-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रुधौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को स्थानान्तरित कथकपुरवा केशवापुर मार्ग जर्जर होने से आवागमन में राहगीरों, छात्र-छात्राओं को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग केशवापुर से कथकपुरवा में दो मार्ग सम्मिलित हैं :-

1-केशवापुर हटवा से गोटवा मार्ग-प्रश्नगत मार्ग विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है। मार्च 2020 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2-गोटवा से कथकपुरवा मार्ग-प्रश्नगत मार्ग में आबादी भाग को छोड़कर शेष भाग गड्ढामुक्त है। आबादी भाग में कहीं-कहीं पैच हो गये है। मार्ग के उक्त भाग की मरम्मत मार्च, 2020 तक किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शाकिर अली के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस आदरणीय सदन को एक शोक-सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शाकिर अली का 23 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। वे देवरिया में जन्मे थे। वह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1993, 2002 और 2012 में इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे। हम सब अपने पुराने साथी को खोकर शोकग्रस्त हैं, व्यथित हैं। इस आदरणीय सदन का सदस्य रहकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समाज जीवन में हस्तक्षेप करना, समाज के लिए काम करना, ऐसे उदाहरण दुर्लभ होते हैं। हम सब उनके निधन पर शोकग्रस्त हैं, दुःखी हैं और इस सदन की शोक-संवेदनाएं, मैं उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में मोक्ष मिले, मुक्ति मिले और उनका स्मरण हम लोगों के बीच बना रहे। आइये, उनकी स्मृति में हम 02 मिनट का मौन रखते हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आपका एक दूसरा नोटिस है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वह अलग है, यह प्रश्नों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, प्रश्नों पर व्यवस्था का प्रश्न कहां होता है ? अगर कोई त्रुटि है तो संशोधन करा लेते।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठता है। मेरा एक तारांकित प्रश्न 02 नम्बर पर लगा था। हमने इसमें पूछा था कि-'क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु सेवा-प्रदाताओं से संविदा के माध्यम से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्टाफ नर्स की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अवनि सेवा-प्रदाता कम्पनी द्वारा स्टाफ नर्स के पद पर 21 हजार रुपया वेतन तथा अन्य सेवा-प्रदाताओं द्वारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्टाफ नर्स के पद पर 11 हजार वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत कर्मियों को समान वेतन भुगतान करायेगी ?' मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जो कार्यरत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, जो काम इस समय चल रहा है, उसमें 21 हजार और 11 हजार का जो अन्तर है, क्या उसको समान करेगी ? यह आज की कार्य-सूची में 02 नम्बर पर है। लेकिन इसको मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया गया है। मान्यवर, न्यायालय में दोनों में डिफरेन्स का मामला विचाराधीन नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन यह है कि संविदा पर न रखे जायें या रखे जायें। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लिख कर भिजवा दीजिए, हम देख लेंगे।

आपकी जो दूसरी नोटिस है, क्या उस पर नहीं बोलेंगे ?

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आय-व्ययक पर साधारण चर्चा 05 दिन के स्थान पर 03 दिन ही कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, हमारी जो नियमावली है, इस नियमावली के नियम-187 को आप देखने का काम करें। उसके पहले है कि विधान सभा में महामहिम आय-व्ययक प्रस्तुत करायेंगे और उस आय-व्ययक पर दो तरह की चर्चा होगी। एक-साधारण चर्चा और दूसरी अनुदान मांगों पर चर्चा। तो मान्यवर, मेरा आज केवल साधारण चर्चा के सम्बन्ध में प्रस्ताव है और मैं इसमें चाहता हूं कि आपकी इसमें व्यवस्था आ जाए, आप व्यवस्था देने का काम करें। मान्यवर, नियम-187(1) में है कि 'आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी।' मान्यवर, इस तरह से 05 दिन की चर्चा का इसमें उल्लेख है और इस पर सदन में जो चर्चा हो रही है, उसका तीसरा दिन है। पांच दिन की जगह पर 03 दिन में ही उस चर्चा को माननीय मंत्री जी खत्म कराना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 05 दिन तो चर्चा होनी चाहिए। अनुदान की मांगों पर, मान्यवर, जब से यह 04 बार का सदन चला है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहला अवसर है कि लगातार चार बार की बैठकों में आय-व्यय के अनुदान मांगों पर अवश्य एक-एक मांग पर कटौती चार के चारों बार प्रस्तुत नहीं हुई। एक बार का दृष्टांत तो हो सकता है, दो बार का दृष्टांत ऐसा हो सकता है, लेकिन लगातार चार बार से अनुदान मांगों की अलग से कटौती नहीं हो रही है, उसी तरह से सामान्य चर्चा में कभी-कभी विषम परिस्थितियां होती हैं, पांच दिन न सही। ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है सदन सही से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस पर पांच दिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा होनी आवश्यक है। जिसे कि सभी मा0 सदस्य अपनी बात रख सकें, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर पांच दिन की चर्चा हो, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्मा जी जब इधर बैठते थे तब यह नियमावली की जो किताब थी, वह पता नहीं सहारनपुर चली गई थी या अम्बेडकरनगर हमें नहीं मालूम, पर उस समय किताब खो गई थी, लेकिन जब यह उधर बैठते हैं तो पता नहीं यह चाभी कहां से आ जाती है और किताब मिल भी जाती है। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश का यह संज्ञान लिया नहीं जाता, लेकिन यहां अगर आपकी आज्ञा हो, हम एक बात पर कोट करना चाहेंगे। मान्यवर अनुमति है ? अभी मुझे पांच दिन की चर्चा याद आ गई, जिस समय पांच दिन को घटाकर चार दिन की गई थी, उस समय मा0 वर्मा जी सशरीर पूरे होश-हवास के साथ वहां पर उपस्थित थे। आपकी पार्टी की तरफ से आपका अधिकृत प्रतिनिधि था और उन्होंने इस बात पर सहमति दी। मान्यवर, जिस पर कल का नेता अधिकृत करे और वह सहमति दे और बाद में उसको नकारे। यह पहली बार परंपरा देख रहा हूं। मान्यवर, मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हं, दूसरी बात मान्यवर, हमने एक जगह पढ़ था कि, जिनके अपने महल शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यह जो बैठे हैं यह वर्ष 2009 की कार्यवाही देख लें, 2009 में केवल 13 दिन हाउस चला है। आप लोगों ने इतिहास बनाया है तेरह दिन में। मान्यवर, रूलिंग अगर बो दी जाती है, जो हमको सूट करे। वर्ष 2009 की कार्यवाही देख लें, पूरे हिंदुस्तान में छपा है कि तेरह दिन सत्र चला है, यह इतिहास बनाया है, ऐसा-वैसा इतिहास नहीं बनाया, एक ही दिन में खड़े होकर हमने अलग-अलग अनुदान की मांगे प्रस्तुत की दो घंटे में और इन्होंने एक साल में पूरा बही खाता निकालकर एक साथ बजट को पास करके पैसा ले लिया। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो मान्यवर, फिर लोग एक उम्र तक सियासतें साथी से बेखबर, अपना ही लहू पीते रहे अपने जाम से। मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना है कि अभी सवेरे-सवेरे आज यहां मैं आया और मैं समझ रहा था कि शायद प्रश्नकाल परवान चढ़ गया और आप लोग फौरन बेल पर आ गए और वजह क्या है ? सामान्यतः मान्यवर जो इस विधान सभा के कार्य क्षेत्र में नही है, वह भी उठाए पड़े हैं। उसका भी कोई मतलब नहीं है, ये जानते हैं कि यहां पर उससे किसी प्रकार का कोई भला नहीं होने वाला। हम यह समझ नहीं पाए कि जब ये सदन चलाना नहीं चाहते तो यहां पर सवेरे-सवेरे आ गए। मान्यवर, 11 बजे से लेकर 11 बजकर 40 मिनट तक, 11.50 तक इन्होंने सदन को बाधित किया। मान्यवर, लेकिन अब सवाल यह है कि जब इनका अपना मौका पड़ता है, तब इनके खरीदने के बांट दूसरे हैं और बेचने के दूसरे हैं। इसलिए जब-जब इनका मौका पड़ता है तो सारी चीजें जस्टिफाइड हैं और इनके पास उसके लिए तमाम प्रकार के कारण भी हैं और जब हमारा मौका पड़ता है तब ये हरी किताब फौरन निकालकर दिखाते

हैं। मान्यवर, नियम-300 में नहीं आता इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लें कि यह नियम-300 में क्यों आता है ? आप नियम-300 को पढ़ लें, यह उसका पूरी तरह से पालन कर रहा है। दूसरी बात मा0 मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने सदन नहीं चलाया तो हमने वहां शेखी भी नहीं बघारी कि आप एक-एक बिन्दु पर चर्चा कराइए, हम पूरी चर्चा कराने को तैयार हैं। 90 दिन से भी ज्यादा सदन चलाने को तैयार हैं। यह शेखी तो हमने नहीं बघारी थी। आप तो शेखी भी बघारते हैं और सदन भी नहीं चलाते। इसलिए कम से कम दोनों में से एक काम तो करिए क्योंकि हमने तो शेखी नहीं बघारी थी कि हम 90 दिन से भी ज्यादा सदन चलाना चाहते हैं। आप तो रोज अपने भाषण में कहते हैं कि हम 90 दिन सदन चलाते हैं। मेरा आपसे मतलब नेता सदन से है। उसके बाद भी आप सदन चलाना नहीं चाहते। मान्यवर, इस प्रकार दोनों में अन्तर हुआ। हमने कभी नहीं कहा कि हम चलाना चाहते हैं। आपने तो कहा कि हम 90 दिन से भी ज्यादा सदन चलाना चाहते हैं। आपको एक-एक बिन्दु पर जितनी भी बहस करनी है, हम उतना चलाना चाहते हैं तो फिर आप क्यों भाग रहे हो ? आप क्यों भागना चाहते हो, आप क्यों 28 तारीख को सदन बन्द करना चाहते हो ? आप क्यों बन्द करना चाहते हो ? आप 05 साल की किसी एक सरकार का ऐसा एक भी दृष्टान्त बताइए। पूरे 04 साल लगातार का कोई एक सत्र बताइए कि जब 04 साल लगातार अनुदान मांगों पर अलग-अलग कटौतियां न हुई हों, चर्चा न हुई हो। आप ऐसा एक दृष्टान्त बताइए कि जब लगातार चार साल ऐसा हुआ हो। आप तो उससे भी ज्यादा भाग रहे हो। आप तो पूर्ण बहुमत 325 की संख्या के साथ आए थे और उसके बाद भी आप सदन से भागना चाहते हैं। कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं। इसलिए दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। या तो आप कहिए कि हम सदन नहीं चलाना चाहते हैं या फिर आप यह कहिए कि हम सदन चलाना चाहते हैं तो फिर सदन चलाइए, आपको कौन रोक रहा है ? मान्यवर, यह नियम-300 में पूरी तरह से खरा उतर रहा है। आप नियम-300 देख लीजिए, यह पूरी तरह से खरा उतर रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

जनगणना में पिछड़े वर्ग के कॉलम को जोड़े जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जिस मुद्दे पर आज वेल में मा0 सदस्यगण आए। वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा की परिधि से बाहर है। मैं इससे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहमत हूं कि यह विधान सभा की परिधि से बाहर हो सकता है, पर यह प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इच्छा शक्ति हो और हम सब भी उस पर सहमति देंगे। आपको इस पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजना चाहिए कि इसमें पिछड़े वर्ग का एक कॉलम जो छूट गया है, उसको जोड़ दें। इस पर हम सारे सदस्य सहमत हैं। इसलिए आपको एक प्रस्ताव भेजना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रथम सूची की प्रविष्टि-69 में जनगणना शुद्ध रूप से केन्द्र का विषय है। इस विधान सभा की विधायी क्षमता, इस विधान सभा की विधायी क्षमता के अन्तर्गत ही हम किसी विषय पर यहां चर्चा करते हैं और यह विधायी क्षमता भी संविधान की 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट में है। यह आदरणीय सदन उन्हीं-उन्हीं विषयों पर चर्चा कर सकता है जो संविधान निर्माताओं ने इस आदरणीय सदन को सौंपे हैं। इसलिए यह विषय यहां की विधायी क्षमता में नहीं है तो यहां पर विचार योग्य भी नहीं है। जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है तो आप लोगों द्वारा इस विषय को नियम-56 में और जिसे आप लोग नियम-311 कहते हैं, बाधा डालने वाला नियम जिसमें सदन प्रायः प्रातः काल बाधित होता है, उस नियम के अन्तर्गत इस विषय को उठाने की कोशिश की जा रही थी। जब कोई भी बात आपकी तरफ से आती है तो हम उस पर सरकार से उत्तर लेते हैं। हम सरकार को कहते हैं कि सरकार इस पर उत्तर दे। इसलिए जिस विषय की पत्रावली ही सरकार के पास नहीं है, जनगणना तो भारत सरकार करा रही है। इस विषय की कोई जानकारी ही उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को हम उन्हीं-उन्हीं विषयों पर यहां खड़ा कर सकते हैं, रेस्पांसिबिल/जवाबदेह बना सकते हैं जो विषय संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को सौंपे हैं। इसलिए वह विषय तो मैं निरस्त करता हूं।

(कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इसी विषय पर बोलेंगे ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से व्यवधान)

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा सक्षम है कि वह सुझाव तो भेज सकती है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केन्द्र को प्रस्ताव तो भेजा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों ने प्रस्ताव कहां किया, आप तो बाधा डाल रहे थे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, हम बाधा नहीं डाल रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई नियमित प्रस्ताव नहीं किया है। प्रस्ताव और संकल्प का नियम अलग है। आप नियम-311 के तहत आये थे और आप लोग किसी नियम में भी नहीं आये चूंकि हमने अनुमति दे दी है या ये कहें कि हमारी सदाशयता है कि सब को सुन लेते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी का किसी भी संगत नियम में इस प्रकार की कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। वेल में आकर दबाव बनाकर कोई काम करना ठीक नहीं है।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग वेल में नहीं आये थे।

श्री अध्यक्ष-

हम कहां कह रहे हैं कि आप आये थे।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से एक सुझाव के रूप में तो उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र को भेज सकती है आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हमारे माध्यम से नहीं भेज सकती है। वह तो नियमानुसार है।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माध्यम से तो भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह बात जितना आप कहना चाहते थे उतनी आ गई है। सवेरे भी आ गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्देश दिया है तीन जजों की पीठ ने भी निर्देश दिया है कि जो पिछड़ी जातियों की जनसंख्या है....

श्री अध्यक्ष-

आप मनोज जी बैठिये मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आप कृपया बैठिये। इसका सर्वोच्च न्यायालय से क्या सम्बन्ध है आप हमारे प्रश्न के उत्तर में बताइये। जो बात मैंने कही

है कि केन्द्रीय सूची में जनगणना का विषय आता है उत्तर प्रदेश सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें जवाबदेह नहीं है। सरकार जिन-जिन विषयों पर जवाबदेह है वही-वही विषय हम उठाते हैं और उन्हीं विषयों पर प्रश्न करते हैं बात खत्म हो गई। क्या सर्वोच्च न्यायालय यह कहेगा कि सेन्ट्रल लिस्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार काम करने लगे या राजस्थान सरकार काम करने लगे या मध्य प्रदेश सरकार काम करने लगे संविधान निर्माताओं ने सम्यक विचारोपरान्त लम्बी बहस के बाद सूची बनाई थी और वे तीन सूचियां हैं आप सब भिज्ञ जन हैं, इसे जानते हैं। अभी मा0 खन्ना जी संकेत कर रहे थे आपको कि जो आपको पसंद होता है वही आप कहते हैं। अब ये मामला हो गया।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-103 में हम प्रस्ताव कर सकते हैं कि मान्यवर, यह सदन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि जनगणना में पिछड़े वर्गों की या जातिगत जनगणना अलग-अलग करा ली जाये। यह प्रस्ताव नियम-103 में यहां लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कब दिया ?

श्री लाल जी वर्मा-

हम प्रस्ताव रख रहे हैं, मान्यवर आप इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आप बातचीत के दौरान प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

इसी पर आप चर्चा करा लीजिये। आपकी अनुमति से हमने प्रस्ताव रख दिया है।

श्री अध्यक्ष-

किसी विषय पर जब बात चल रही है, उसी बीच में उस विषय को रोककर क्या कभी प्रस्ताव आया है। आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, हम तो छोटे आदमी हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो गई तब प्रस्ताव रख दिया है।

श्री अध्यक्ष-

हमारी सहमति है कि आगे विषय और चलें तो मा0 वर्मा जी मैं आपका प्रस्ताव अग्राह्य करता हूं आपका पूरा विषय आ गया है और आपने जो कहना था कह लिया है। अगला नितिन अग्रवाल जी का है। नितिन जी, डेढ़-दो मिनट में अपनी बात कहिये।

विकास निधि 02 करोड़ से बढ़ाकर 05 करोड़ रुपये किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, आपने तीन मिनट का समय दिया था। मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय को उठाने का मौका दिया। यह विषय कोई मेरा ही नहीं है यह विषय यहां पर जितने भी मा0 सदस्य बैठे हैं उनसे सम्बन्धित है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या से भी सम्बन्धित है। मा0 अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि चाहे आप जनसंख्या के आधार पर ले लीजिये तथा चाहे आप पूरे देश की विधान सभाओं में कितने विधायक हैं, वह भी आंकड़ा ले लीजिये तब भी सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश की विधान सभा है जनसंख्या के आधार पर भी और विधायकों की संख्या के आधार पर भी। हरेक माननीय सदस्य जो यहां पर आया है अमूमन उनके विधान सभा की जनसंख्या करीब 6 लाख के आस-पास है अर्थात् वह 6 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में देखा जाये तो क्षेत्र के जनता की अपेक्षा विधायक से ज्यादा होती है अपितु सांसद के, क्योंकि विधायक जनता से सीधे जुड़ा हुआ होता है। अगर उत्तर प्रदेश से छोटे प्रदेश भी ले लीजिए उन प्रदेशों के विधायकों की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि है वह उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा है। अगर मैं कुछ राज्यों का उल्लेख करूं तो दिल्ली जैसा प्रदेश जो कि बहुत छोटा प्रदेश है वहां जानकारी में आया है कि विधायक निधि/विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को 4 करोड़ से 10 करोड़ फिक्स करा दिया गया है। तमिलनाडु में 3 करोड़ है। उत्तराखण्ड जैसे छोटे स्टेट में करीब 5 करोड़ की निधि है। छोटे-छोटे स्टेटों में जब उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्षेत्र विकास निधि हो रही है, तो हम लोग तो इतने बड़े स्टेट के विधायक हैं और इतनी जनसंख्या का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझता हूं कि यहां बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इससे सहमत होंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश में यही विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर कम से कम 5 करोड़ रुपये कर दिया जाये, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके क्योंकि जनता हमसे पूछती है। हालांकि सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोगों को विधान सभा क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ मिलती है वह काफी नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय नेता सदन का दिल तो बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि जब वह संसद में सदस्य थे तो उन्होंने भी सिफारिश की थी कि विकास निधि ज्यादा होनी चाहिए। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां पर हैं और उनका दिल भी बहुत बड़ा है, तो जब नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों ही बड़े दिल के नेता हमारे बीच में हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम आज आप प्रस्ताव कर दीजिए अगर निधि 5 करोड़ रुपये हो गयी तो आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव करा दीजिए और सरकार आश्वासन दे दे कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपना बजट भाषण देंगे तो उसमें घोषणा कर देंगे कि प्रत्येक विधायक के विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी जाती है जिससे हम लोग समुचित विकास कर सकें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप आज आश्वासन दे दीजिए कम से कम हम लोगों को भी लगेगा कि आप बड़े दिल के नेता है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिए, आपका विषय आ गया।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और आप यहां के आए हुए सभी सदस्यों का सम्मान करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय नियम-300 में नहीं आता, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप वाली सूचना संगत नहीं है और सुने जाने योग्य नहीं है। आप तो विद्वान अधिवक्ता भी है लेकिन यह सूचना किसी भी तरह से नियम-300 में नहीं आती है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सदन में दो माननीय मंत्रियों का छुट्टा जानवरों पर अलग-अलग बयान आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

वह हमने पहले ही मना कर दिया है और वह इसमें नहीं आता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

एक माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वह जानवर छुट्टा हैं लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। एक माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में न छुट्टा जानवर है, न ही इससे कोई नुकसान हो रहा है। यह दोनों ही कार्यवाही के पार्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे प्रदेश में एक अलग संवैधानिक परिस्थिति पैदा हो गयी है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

आज दिनांक 26-02-2020 को कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 22 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जेवर रोड पर बाईपास का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना, श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लालजी पहलवान हिन्द केशरी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना, श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भैया' की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम-गनगोला में जिला सहकारी संघ बदायूँ निष्प्रयोज्य पड़ी भंमि पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पांचवी सूचना, श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत आयुष्मान योजना में सर्वे कराकर छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को सम्मिलित कराये जाने के संबंध में है। छठी सूचना, डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना, श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार करके चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना, श्री राजेश कुमार सिंह 'चुन्नू' की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। नौवीं सूचना, श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में स्थित जिला जेल को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना, श्री सोवरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के अन्तर्गत कतिपय संपर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना, श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के नगर मुख्यालय के पुराने शहर की सीवर व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना, श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत टौंस नदी पर निर्मित पुल के दोनों एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना, श्री रफीक अन्सारी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ रोड पुराने कमेले की रिक्त जगह पर स्वीकृत हास्पिटल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पंद्रहवीं सूचना, श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत दीदारगंज सरायमीर मार्ग से हैदराबाद ग्राम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना, श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के नगर पालिका मुंगरा-बादशाहपुर में कटरा मोहल्ले में कमासिन ड्रेन नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना, श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा की ग्राम पंचायत पुलन्दर में गौशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध

में है। अट्ठारहवीं सूचना, श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसी दास प्रेरणा स्थलयी रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना, श्री राम कृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य में उत्तर वार्ड, पूर्व वार्ड में कतिपय कार्यों का भुगतान किये जाने के संबंध में है। बीसवीं सूचना, श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अर्न्तगत ग्राम पंचायत असोहा से ग्राम खरगीखेड़ा तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना, श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बाइसवीं सूचना, श्री अमनमणि त्रिपाठी की जनपद लखनऊ के उ0प्र0 प्रोजेक्ट का0लि0 गोमती नगर के सी0जी0एम0 श्री गोपाल मिश्रा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में है। निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी- श्री नितिन अग्रवाल, श्री प्रेम नारायन पाण्डेय, श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री नरेश सैनी, श्री संजय सिंह गंगवार, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सुभाष पासी, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया, श्री आजाद अरिमर्दन, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री असलम अली, श्रीमती जयदेवी, श्रीमती राजबाला, श्री रोशन लाल वर्मा, श्रीमती निर्मला संखवार। यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जेवर रोड पर बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर के खुर्जा में कैलाश हास्पिटल के समीप जी0टी0 रोड से जेवर रोड को बाईपास न होने से यहां के यात्रियों को काफी घूमकर आना पड़ता है और सारा ट्रेफिक शहर से होकर गुजरता है और शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इस बाईपास के बन जाने से अलीगढ़ की तरफ से जेवर जाने वाले एवं जेवर से बुलन्दशहर या अलीगढ़ आने वालों के लिए काफी सुविधा होगी और जाम की स्थिति से भी बचा जा सकेगा। जनहित में इस बाईपास का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लाल जी पहलवान हिन्द केशरी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर (बरैछा) वि0ख0 हरहुआ में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लाल जी पहलवान हिन्द केशरी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर (बरैछा) वि0ख0 हरहुआ में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लाल जी पहलवान हिन्द केशरी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की बहुत कमी है। जिससे क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। यातायात हेतु कोई मार्ग सुलभ नहीं हैं। लोग अपने गन्तव्य तक जाने के लिए कई-कई घंटे पहले घर से निकलते हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में तालौड़ से पट्टी कुम्हर्रा, सिमिरिया से शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग, बरनाया से बड़ा बेलमा तक, जेरा से बरनायां तक, सुजानपुरा से रमपुरा, सिया से परसवा, चन्दार से सोराई, अम्मरगढ़ से बकुवां, बजीता से शाहजहांपुर, हरदुआ से बिलाटी एवं पुछी से गरौठा मऊरानीपुर मुख्य मार्ग तक सड़कों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम-गनगोला मे जिला सहकारी संघ बदायूं में निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया'-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 117-दातागंज जनपद बदायूं के ग्राम-गनगोला में जिला सहकारी संघ बदायूं निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर स्टेडियम निर्माण की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वीकृति की अनुमति जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि पूरी विधान सभा क्षेत्र में युवाओं के शारीरिक विकास के लिए कोई स्टेडियम नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम-गनगोला में जिला सहकारी संघ बदायूं निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर स्टेडियम निर्माण किये जाने हेत कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत आयुष्मान योजना में सर्वे कराकर छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा उन्नाव के अन्तर्गत आयुष्मान योजना से गरीब जरूरतमंद लोग वंचित रह गए हैं। आयुष्मान योजना में लापरवाही के कारण जरूरतमंद लोग पात्रता सूची से वंचित रह गए हैं। वहीं एक ही घर के कई सदस्यों को एवं मृत लोगों को भी सूची में सम्मलित किया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार की अतिमहत्पूर्ण योजना में लापरवाही बरते जाने के कारण जन आक्रोश व्याप्त। उक्त योजना में पारदर्शिता को लेकर पुनः सर्वे कराकर छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को सम्मिलित करने हेतु शासन एवं सरकार से अनुरोध किया गया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता के ग्राम सिमरा बहोर नगला में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना जनहित/छात्रहित में अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस विकास खण्ड में पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग की जनसंख्या अत्यधिक है। उक्त ग्राम में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम समाज की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम सिमरा बहोर नगला में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार करके चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-मुजफ्फरनगर की मेरी विधान सभा क्षेत्र-बुढ़ाना के ग्राम गढ़ी नोआबाद, ब्लॉक शाहपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अत्यन्त जर्जर एवं गिराऊ स्थिति में है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण वर्ष 1989 में प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1997 में यह बिल्डिंग बनकर स्वास्थ्य विभाग को हैण्डओवर हुआ। इस 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में तत्समय लगभग 71 लाख रुपये का व्यय आया परन्तु तब से लेकर आज तक इस चिकित्सालय में किसी चिकित्सक अथवा सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई और न ही यह चिकित्सालय अभी तक संचालित हो सका। जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार करके चिकित्सक एवं सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति कर चिकित्सीय सेवाएं संचालित कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार सिंह 'चुन्नू'-

[महोदय, जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत विकास खण्ड छजलैट में ग्राम नवादा से महेन्द्री सिकन्दरपुर तक महमूदपुर राजवाहा पर बनी सड़क की हालत अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को कृषि उपज की मण्डी तक ले जाने व आगमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जनहित में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण अतिआवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया में स्थित जिला जेल को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया के शहरी क्षेत्र में जिला जेल स्थित है जिसमें वर्तमान मे 339 कैदियों के रहने की व्यवस्था है पर आलम यह है कि इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जेल में हर समय 850 से 900 कैदियों को रखा जा रहा है जबकि इस जेल में न तो इतने कैदियों के रहने की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था है और न ही अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था है।

अभी पिछले साल इस जेल में बरसात के समय में कैदियों को अन्य जिलों की जेलों में शिफ्ट किया गया था और आलम यह था कि वर्षा जलभराव के कारण इस पूरी जेल में इतना पानी भर गया कि यहां के समस्त कैदियों को प्रशासन द्वारा अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ की जेलों में शिफ्ट करना पड़ा जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अगर इस जेल को बलिया जनपद के शहरी क्षेत्र से स्थानान्तरित कर अन्य जगह बनाया जायेगा तो इस जेल की जमीन से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा उसी रेवेन्यू से नई जगह पर अधिक क्षमता की जेल तो बनेगी ही साथ ही बचत भी होगी।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया स्थित जिला जेल को शहरी क्षेत्र से बाहर कहीं अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोबरन सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र करहल जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत नं0 छेड़ी राजस्व ग्राम जवापुर विकास खण्ड मैनपुरी की आबादी लगभग 1000 है उक्त ग्राम सम्पर्क मार्ग विहीन है। दन्नाहार से नं0 छेड़ी मार्ग की लम्बाई लगभग 1.500 किमी0 तथा राजस्व ग्राम गढ़िया (खजुरारा) विकास खण्ड करहल की आबादी लगभग 750 है जो सम्पर्क मार्ग विहीन है। बांसक सैफई राजवाहा से सम्पर्क मार्ग की दूरी लगभग 500 मीटर है। यह दोनों सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। उक्त सम्पर्क मार्ग न बनने से स्थानीय लोगों में काफी रोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के नगर मुख्यालय के पुराने शहर की सीवर व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के नगर मुख्यालय के पुराने शहर के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगभग सभी क्षेत्रों जैसे दीनानाथ बाजार, रानी बाजार, मौ0 चौन्ताला, बड़तला यादगार, अरबी मदरसा मोरगंज बाजार, रामानन्दी बाजार, मौहल्ला संगियान, छत्ता जम्बूदास, मौहल्ल्ला मुफ्ती, हिन्दुस्तानियान, कम्बोह कटहरा, मौहल्ला मिश्रान, रामलीला भवन, अग्रवाल धर्मशाला आदि क्षेत्रों की पूरी सीवर व्यवस्था पिछले बीस से भी अधिक वर्षों से पूरी तरह ध्वस्त है। सभी सीवर लाईन्स व मेनहोल्स पूरी तरह अवरुद्ध हैं। सीवर होल्स के उपरी किनारों को तोड़कर किनारों में बहने वाली नालियों से बाईपास कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों का मानव मल सड़क किनारें की नालियों से होकर अन्ततः पांवधोई नदी में जाकर गिरता है।

सफाई विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी इस गम्भीर समस्या से अवगत हैं फिर भी अवरुद्ध सीवर लाईन्स को चालू करने के लिये या बदलवाने के लिये कोई भी कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा इस दिशा में नहीं किया गया। हद तो यह है कि निकासी लाईनों के 100 प्रतिशत बन्द होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों में इन्हीं क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर नयी सहायक सीवर लाईन्स सहारनपुर नगर निगम द्वारा बिछायी जा रही हैं जो अपने आप में चैम्बर बन गयी है। इन क्षेत्रों की सीवर लाईन्स का IPS या STP से सम्पर्क ना हो पाने के कारण समस्त मानव मल उन्हीं में जमा हो रहा है या फिर नालों में जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य देने तथा जनपद सहारनपुर के नगर मुख्यालय के पुराने शहर की सीवर व्यवस्था में अपेक्षित सुधार कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दो वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में एक हजार इंजेक्शन (वैक्सीन) भेजे गए थे, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में खत्म हो गये जिसके कारण मरीजों को भटकना पड़ रहा है। इस वैक्सीन के दो टीके नौ से 14 वर्ष की किशोरियों को पांच माह के दौरान लगने होते हैं। अक्टूबर 2019 में वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण जिन किशोरियों को जून, जुलाई, अगस्त में पहला इंजेक्शन लगा था, उनको दूसरा इंजेक्शन न लगने से पहली डोज भी बेकार हो गई है और जिन किशोरियों की मियाद अभी शेष है वे क्लीनिक के चक्कर काट रही हैं। इस टीके की कीमत दो हजार रुपये से भी अधिक है और यह टीका लगभग पांच हजार रुपये में होता है, जिसके कारण गरीब परिवार की किशोरियाँ इस वैक्सीन से वंचित रह जाती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्याओं के निदान की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत टौंस नदी पर निर्मित पुल दोनों पुल के एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टौंस नदी में बाढ़ के कारण ग्राम शिवराजपुर को जोड़ने वाले पुल के दोनों किनारों की एप्रोच रोड बाढ़ के पानी के बाहव के कारण बह गयी। ग्रामवासियों का उधर से आना-जाना प्रभावित है।

जनहित में आपसे निवेदन करना है कि एप्रोच रोड को लेपन स्तर तक जल्द से जल्द ठीक कराने का कष्ट करें, इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आभारी रहेगी।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ रोड पुराने कमेले की रिक्त जगह पर स्वीकृत हास्पिटल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अर्न्तगत सूचना

श्री रफीक अन्सारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड पुराने कमेले के रिक्त जगह पर 50 बेड का हास्पिटल वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ था। प्रदेश सरकार द्वारा 3.50 करोड़ रुपया भी इसी वर्ष कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को दे दिये गये। परन्तु आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी हास्पिटल का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि इस कार्य को जनहित में तत्काल कराये जाने की आवश्यकता है। तथा कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत दीदारगंज सरांयमीर मार्ग से हैदराबाद ग्राम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-हैदराबाद के वि0ख0-मार्टिनगंज तहसील-मार्टिनगंज में दीदारगंज सरांयमीर मार्ग से हैदराबाद ग्राम से नहर तक (ल0 लगभग 2 कि0 मी0) जर्जर मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का पिच मार्ग निर्माण न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग को पिच मार्ग बनवाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।

जनपद जौनपुर के नगर पालिका मुंगराबादशाहपुर में कटरा मोहल्ले में कमासिन ड्रेन नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुषमा पटेल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

अवगत कराना चाहती हूँ कि जौनपुर जनपद में न0पा0 मुंगराबादशाहपुर में कटरा मोहल्ले में आवागमन हेतु निर्मित कमासिन ड्रेन (नाले) पर बनी पुलिया टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है इस कारण स्थानीय निवासयों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त कमासिन ड्रेन (नाले) पर पुलिया के पुनः निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा की ग्राम पंचायत पुलन्दर में गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कटियार-

[महोदय, जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा की ग्राम पंचायत पुलन्दर में एक गौशाला का निर्माण अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आसपास क्षेत्र में आवारा जानवरों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे उनकी आय व जीवन स्तर निम्न स्तर पर जा रहा है, जिसका उनके परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। इस ग्राम पंचायत में काफी जमीन ग्राम सभा की है, जिसमें गौशाला का निर्माण हो सकता है, और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मदद से गौशाला भी संचालित हो सकती है।

अतः लोकमहत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ, जिससे गौशाला का निर्माण हो सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसीदास प्रेरणा स्थलीय रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र 252 मंझनपुर के ग्राम महेवाघाट स्थित महाकवि तुलसीदास की प्रेरणा स्थली रत्नावली धाम स्थित है। जनहित में महाकवि तुलसीदास प्रेरणा स्थली रत्नावली धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं पर्यटन मंत्री से इस सदन से आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य में उत्तर वार्ड पूर्व वार्ड में कतिपय कार्यों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामकृष्ण भार्गव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य में उत्तर वार्ड, पूर्व वार्ड में सहारा बैंक से रामस्वरूप बाल्मीकि तक मरम्मत कार्य का मूल्य 11,42,000 तथा नगर मिश्रिख मोहल्ला सीताकुण्ड-3 मिश्रिख डा0 बंगाली के मकान से नईम खां के मकान से सलीम के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य का मूल्य 2,34,000 तथा पूरब वार्ड में ललिता देवी मन्दिर पूरब गेट से राधे मालाकार के मकान से रबड़ मोउ इण्टरलाकिंग कार्य रोड के दोनों तरफ 6,15,000 तथा धर्मशाला चौराहे से स्टेशन रोड तक मरम्मत कार्य का भुगतान 5,85,000 तथा धर्मशाला चौराहे से स्टेशन रोड पर मरम्मत का कार्य 5,85,000 तथा सी0एच0सी0 मिश्रिख यात्री प्रतीक्षालय के मरम्मत कार्य का भुगतान 20,000 अभी तक नहीं हुआ है। उक्त कार्य मेसर्स अम्बरीश कुमार दीक्षित द्वारा कराये गये है तथा उक्त कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में कई बार अधिशासी अधिकारी से शिकायत की गई परन्तु अधिशासी अधिकारी को सुविधा शुल्क न दिये जाने के कारण अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त के सम्बन्ध में मेसर्स अम्ब्रीश कुमार द्वारा आई0जी0आर0एस0 पर भी शिकायत की गई परन्तु भुगतान नहीं हो सका। उक्त कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण करा दिये गये थे तथा वर्ष 2017 से अभी तक भुगतान नहीं कराया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में जांच किये जाने एवं उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असोहा ग्राम खरगीखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ में ग्राम पंचायत ओसाहा से होकर तिलेण्डा हलोर मार्ग से ग्राम खरगीखेड़ा से नवाजी खेड़ा पुरबिया फिर कैरावं होते हुये उक्त 5 कि0मी0 मार्ग कच्चा होने के कारण लगभग 15 हजार की आबादी के लोगों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः आग्रह है कि जनहित में उक्त मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम बेगमपुर चायमल, कालाखेड़ी, किरतपुर, धर्मशानंगली आदि गांव के लोगों को बिजनौर एवं कोतवाली जाने के लिए नगीना होकर जाना पड़ता है, जबकि बेगमपुर चायमल-नरैनी मार्ग लम्बाई लगभग 0.5 किमी0 एवं गांगन नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण होने के बाद उक्त गांव के लोगों को बिजनौर कोतवाली आने जाने में बहुत सुविधा हो जायेगी। इसलिए बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण होना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांगन नदी पर पुल एवं सड़क बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के यू0पी0पी0सी0एल0, गोमतीनगर के सी0जी0एम0 श्री गोपाल मिश्रा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में श्री गोपाल मिश्रा जो UPPCL लखनऊ में सी0जी0एम0 के पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा पूर्व में कराये गये विकास कार्यों में आवंटित धनराशि का ठेकेदार के साथ मिल कर बंदर बाट किया गया और सी0जी0एम0 के पद पर तैनात होकर उत्तर प्रदेश में जनहित एवं लोक कल्याण के लिए आवंटित की जा रही धनराशि को बिना कार्य कराए ठेकेदार के साथ मिलकर बंदर-बाट किया जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद लखनऊ में तैनात सी0जी0एम0 पर दण्डनीय कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले कार्य-स्थगन ले लें चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर में हो नहीं पायेगा, मैं थोड़ा ले-डाउन वाला एजेण्डा पूरा कर लूं।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ग्राम अल्लीपुर में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से गोण्डा तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा तिवारी से सगवां वगदर ग्रान्ट सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वाशदेव मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेवादा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याराम व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

4-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तुरकौली उजागपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नरायन व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

5-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तालागंज ग्रान्ट सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(इसी समय 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

---

† छापी नहीं गयीं।

6-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खम्हरिया-छपिया सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामानन्द बौद्ध-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम सिरसिया, विकास खण्ड मोतीचक में अधिग्रहीत जमीन पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में श्री नौरंग सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री महबूब अली-

1-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में ग्राम सरकड़ी अजीज कामेश के मकान से खाता चौराहे तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामेश व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा के ग्राम हुसैनपुर निकट मालीखेड़ा में जोया सम्भल रोड से ज्यारत के पास होते हुए ग्राम हुसैनपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिहान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में ग्राम रजबपुर शकरपुर मार्ग से बागड़पुर तक 2.70 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इंतजार व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

4-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा के ग्राम अकबरपुर पटट्ी में प्राथमिक विद्यालय में मो0 कुरैशी में रिंग रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेमपाल सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर पट्टी, जनपद अमरोहा व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

5-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद अमरोहा में जोया अमरोहा मार्ग से जोई सम्पर्क मार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवास अली व अन्य निवासी जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती साधना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्रीमती साधना सिंह-

1-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत बंबुरी विकास खण्ड के सृजनता के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सेठ निवासी बबूरी जनपद चन्दौली व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नगर पंचायत चन्दौली को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमनाथ अग्रहरि निवासी नगर पंचायत चन्दौली, जनपद चन्दौली व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री लाल जी वर्मा-

1-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत अशरफपुर बरवाँ फत्तेपुर जैनपुर मार्ग का अवशेष जर्जर सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 900 मी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सालिक राम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय भीटी से डिहवा व तिनपेड़वा से बाबू का पूरा तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गुप्ता निवासी ग्राम भीटी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3-माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत फत्तेपुर बेलाबाग मो0 सलीम एवं राम प्रताप के आवास से जलालपुर चाँदपुर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करता हूं, तथा

4-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत नकटहा माइनर की पुलिया से कुर्मी डीह तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरजीत गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दस याचिकाएं†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक बिथरी चैनपुर, तहसील बरेली के ग्राम एहलादपुर में मुन्नालाल के मकान से श्यामलाल कश्यप के मकान तक सी0सी0 रोड बनाने के संबंध में श्री मुन्नालाल निवासी ग्राम एहलादपुर जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक-भौजीपुरा, तहसील बरेली के मिलककलारा की शमशान भूमि से पडरीखालसा तक पक्की सड़क बनाने के संबंध में श्री इन्साराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक बिथरी चैनपुर, तहसील बरेली के बड़े बाई-पास से नवदिया इलाका सिंघाई होते हुये रिठौरा अभयपुर मार्ग तक पक्की सड़क बनाने के संबंध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

4-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक शेरगढ़, तहसील बहेड़ी के भदरक गांव की पुलिया से पखुरनी तक पक्की सड़क बनाने के संबंध में श्री रामचन्द्र गंगवार निवासी ग्राम भदरक, जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

5-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक-शेरगढ़, तहसील बहेड़ी के गुनहा गौंटिया बाजार से ग्राम खाता तक पक्की सड़क बनाने के संबंध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

6-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत अब्दुल्लापुर माफी के पास नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री द्वारिका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

7-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग से मोहनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री भगवान दास व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

8-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के मोहम्मदपुर गौटिया के पास किच्छा नदी पर पत्थरों की ठोकरें लगाये जाने के संबंध में श्री राम चरन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

9-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बल्लाकोठा से ठिरिया ठकुरान तक पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री मनोहर लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

10-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग से बिलवा होते हुये अटा का स्थान तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री लेखराज कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं†

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के ग्राम उदरा से भोजपुर तक पक्की सड़क व 2 पुलिया बनाने के संबंध में श्री शंकर लाल पुत्र श्री रूकम सिंह निवासी ग्राम उदरा, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली में गांव शिव नगरिया नहर की पुलिया से खुजरीखेड़ा तक रोड बनवाने के संबंध में श्री चन्द्रसेन गंगवार, निवासी ग्राम-शिव नगरिया, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली में ग्राम गुरसौली से नहर पर होते हुये ग्राम डुडा शुमाली की पक्की रोड के संबंध में श्री देवेश कुमार पुत्र श्री उमेश कुमार, निवासी गुरसौली, विकास खण्ड व तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

4-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली में ग्राम रहपुरा गनमीत से दौलत राम के घर से शमशान भूमि तक पक्की रोड बनाये जाने के संबंध में श्री सोम पाल पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी रहपुरा गनीमत, विकास खण्ड दमखोदा, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

5-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, जनपद बरेली के ग्राम बंजरिया, विकास खण्ड व तहसील बहेड़ी में मेन रोड से काली माता मंदिर तक रोड बनाये जाने के संबंध में श्री घनश्याम दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद बरेली में जाकि सराय से अहरो-रूद्रपुर रोड को पक्का रोड करने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

7-जनपद बरेली के ग्राम पिपरा में मेन रोड से शमशान भूमि तक पक्का रोड या खड़न्जा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

8-जनपद बरेली के ग्राम झाले से शमशान भूमि के नीचे वगइया पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

9-जनपद बरेली में रूड़की विकास खण्ड व तहसील बहेड़ी के ग्राम भमसेन मार्ग पर पक्का रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री ओमकार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओमकार सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बदायूँ सम्भल में सदियों से बहती चली आ रही महाबा नदी को जनहित में पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लताफत हुसैन प्रधान निवासी पंचायत जरैठा, विकास खण्ड दहगवां, जनपद बदायूँ व अन्य की याचिका उपस्थित उपस्थित करता हूं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित सात याचिकाएं, जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चार याचिकाएं तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से

1-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की ब्लाक मोंठ की कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराजा राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

2-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की ब्लाक गुरसराय में सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डिस्कू पटेल निवासी गुरसराय, ब्लाक गुरसराय, जनपद झांसी व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सिरायू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री शशांक खरे व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

4-जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर को पुनः पुरवा तहसील से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप विक्रम निवासी ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर, तहसील बीघापुर भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं।

5-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय नगर के आस-पास वेयर हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू चौहान व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

6-जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सिरायू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री रजत खरे व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

7-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छपार को थाना समथर से थाना शाहजहांपुर में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री भारत राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

8-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धसान नदी पर स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्री कमलेश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

9-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र की गुरसराय मुख्य नहर में रीमॉडलिंग कच्चे/पक्के कार्यों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

10-जनपद झांसी की बेतवा नदी पर खिरिया घाट में रपटा के स्थान पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजा कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

11-जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में खलिहान, चकरोड सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम समाज की भंमि से अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री देव कुमार लोधी व अन्य निवासीगण उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

12-जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सिरायू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल खरे व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

13-जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सिरायू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र खरे व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

14-जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज की ग्राम पंचायत गोकुलपुर के ग्राम देवी जगदीशपुर के जूनियर हाई स्कूल से ग्राम पैंथर तक पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(इस मध्य 01 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुएं)

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि इस माननीय सदन में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने 18 फरवरी को वर्ष 2020-2021 का उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया था और पिछले तीन दिनों से इस माननीय सदन में इस बजट पर चर्चा आगे बढ़ी है। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस पर पूरी गम्भीरता से चर्चा की और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जो सरकार का विजन है, जो सरकार की कार्य-योजना है, सरकार की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं। मैं देख रहा था कि नेता प्रतिपक्ष समेत इस पूरे बजट पर अब तक 49 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। एक अच्छा और समृद्ध सम्वाद का माध्यम है यह चर्चा। क्योंकि बजट के माध्यम से सभी माननीय सदस्यगण न केवल अपने विधान सभा क्षेत्रों के बारे में अपितु जिस जनपद से जुड़े होते हैं उस जनपद के बारे में और प्रदेश के समग्र विकास के बारे में जो शासन की कार्य-योजनाएं हैं उन सबको आगे बढ़ाने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव भी देते हैं। निसन्देह कहा जा सकता है कि जो बजट इस सदन में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह विकास को गति प्रदान करने वाला, प्रदेश की युवा ऊर्जा के कौशल सम्वर्धन और उनके लिये रोजगार का सृजन करने वाला, एक अत्यन्त संतुलित और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने वाला एक बजट है। मैं इसके लिये वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं (मेजों की थपथपाहट) जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इस बजट के दायरे को यहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं भारत की प्राचीन उस विरासत और परम्परा का मार्गदर्शन भी है। मैं देखता हूं 2015-2016 में प्रदेश का बजट 3,02,687.32 करोड़ रुपये का था और आज हम लोग कुल 5 वर्ष के दौरान ही एक नेक नीयति के कारण प्रदेश के इस बजट के दायरे को 5,12,860.72 करोड़ रुपये तक पहुंचा करके लेकर गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह सरकारों का विजन है, सरकार की सोच है एक सकारात्मक सोच, विकास की एक सकारात्मक सोच। माननीय अध्यक्ष

जी, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने, बुनियादी ढांचागत विकास और औद्योगिक निवेश के साथ-साथ समग्र विकास की उन परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कार्य प्रारम्भ हुए हैं, उसका परिणाम है कि हम लोगों को हर एक क्षेत्र में, प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान नयापन देखने को मिला है, लोगों के मन में विश्वास जाग्रत हुआ है। सही मायने में उत्तर प्रदेश का यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनकर के देखने को मिला है। इसके पीछे रामचरितमानस का भाव भी स्पष्ट दिखता है कि ''जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना''। पिछली सरकारें विपत्ति का कारण थीं, क्योंकि वहां पर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सोच नहीं थी, एक नकारात्मकता थी, एक संकीर्णता थी, एक स्वार्थ था। स्वाभाविक रूप से जहां स्वार्थ होगा वहां परमार्थ नहीं हो पायेगा, संकीर्णता होगी तो विराटता नहीं आ पायेगी और एक संकुचित दायरे में कैद करके पिछली सरकारों ने प्रदेश को रख दिया था, उसका दुष्परिणाम प्रदेश को भुगतना पड़ा था। 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश और बजट केवल 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ में भी अगर हम विभागीय आवंटन की स्थिति देखेंगे तो बहुत कम राशि मिल पाती थी, इसीलिए सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे, किसान बदहाल था, नौजवान परेशान था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उस एक नयी प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो चुका है जहां पर समाज के प्रत्येक तबके के नागरिकों को ध्यान में रखकर के शासन ने अपनी योजनायें बनायी हैं। कोई तबका आज के दिन यह नहीं कह सकता कि जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर उसके साथ कोई भेद-भाव हुआ हो, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रारम्भ ही सबका साथ और सबके विकास के साथ किया है और उसके माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित करने की रणनीति के तहत सरकार ने कार्य किये हैं। हर एक बार के बजट की अपनी एक थीम लाइन है। उसको लेकर के हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया है और मुझे इस अवसर पर अन्त्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन पुरोधा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति होगा। मुझे लगता है कि यही सरकार की इस कार्य योजना का और इस बजट का आधार भी बना है। आप याद करिये जब हमने 2017-18 में पहला बजट प्रस्तुत किया था तो वह बजट हम लोगों ने प्रदेश के अपने किसानों को समर्पित किया था और बजट को इसी सदन में प्रस्तुत करते हुए तब भी हम लोगों ने कहा था कि ''हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किन्तु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार''। किसानों को समर्पित करते हुए। मैं खन्ना जी की तरह शेरो शायरी नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा कि कुछ कवितायें तो आपको बता ही दूं, जिससे आसानी से समझ में आ जाये। मैं खन्ना जी की तहर शेरो-शायरी नहीं जानता लेकिन मैंने कहा कि कुछ कविताएं तो आपको बता ही दूं। जिससे आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि बहुत दिनों से जो

मन की जकड़न है वह इसी से खुल पाएगी। किसानों को समर्पित करते हुए और किसानों को समर्पित करने के लिए हम लोगों ने उस समय जो व्यवस्था की थी हर व्यक्ति जानता है कि जब हम लोग आए थे तो खजाना खाली था सेवेन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना था 14 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि की भी व्यवस्था करनी थी इससे पहले 12-15 साल सरकारें जिस तरह से चली थीं उस अंदाजे को देखकर उत्तर प्रदेश का परसेप्सन पूरे देश के अन्दर खराब हो चुका था किसान बदहाल था आत्महत्या कर रहा था जब विपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रगण किसानों की चर्चा करते हैं तो मुझे कभी-कभी उन पर हंसी आती है। यह लगता है कि इनके पुराने समय की कारगुजारियां इनके मन-मस्तिष्क में होंगी जो कभी-कभी उनके मुंह से निकलती हैं क्योंकि सच को कभी न कभी निकलना है। जब यह बोलते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है किसान बदहाल है मुझे लगता है कि वास्तविक स्थिति से वह वंचित हैं। इसीलिए पहला ही निर्णय सरकार ने लिया था और वह निर्णय लिया था सरकार ने प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों के एक लाख तक के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया था। देश के अन्दर विभिन्न राज्य सरकारों ने कर्जमाफी की योजना लागू की है सबसे अधिक किसान उत्तर प्रदेश में है सबसे पारदर्शी तरीके से सबसे व्यवस्थित तरीके से किसी प्रदेश के किसानों के लिए ऋणमाफी की योजना सफलतम रूप से सम्पन्न हुई है तो उत्तर प्रदेश की योजना लागू हुई है इसमें किसान भी लाभान्वित हुआ है साथ ही साथ देश के अन्दर किसानों के मन में जो उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्सन खराब था वह चेंज हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में हर एक किसान खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की जो रणनीति है उस दिशा में हम सफलतापूर्वक प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। किसानों की कर्जमाफी के साथ ही अनेक उन योजनाओं को प्रदेश के अन्दर लागू किया गया है चाहे वह किसानों के लिए प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना हो चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या फिर समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को मिल सके इस दृष्टि से जो कदम उठाए गए प्रक्योरमेंट की नीति उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोग लेकर आए 2017-18 में मुझे याद है 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और पहली अप्रैल से हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर तीन हजार केन्द्रों में गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित करके गेहूं की प्रक्रिया को आढ़तियों से मुक्त करके सीधे किसानों से खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था। पहले ही वर्ष में लगभग 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया गया था और यह हर एक व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय था कि क्या यह उत्तर प्रदेश में संभव है। हमने किया। वर्षों से लम्बित सिंचाई की परियोजनाओं को सरकार ने पूरा किया वर्तमान में भी हमारी योजनाएं चल रही हैं पहले चरण में बाण सागर का था अर्जुन सहायक का था अन्य तमाम परियोजनाएं थीं छोटी-बड़ी परियोजनाओं को पहले चरण में पहले वर्ष मे पूरा करने का कार्य किया दूसरे चरण में सरयू नहर का है मध्य गंगा का है अर्जुन सहायक का है लगभग एक दर्जन बड़ी परियोजनाएं हमारे

समय में पूरी हो रही हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त में पूरा होने के बाद जब योजनाएं सम्पन्न होंगी उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेएयर से अधिक क्षेत्र को सिंचन की सुविधा उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त होगी यह कार्य पहले ही हो सकता था। पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इसलिये हमारी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर के पहला बजट किसान को और देश के जवान को समर्पित किया था, क्योंकि वह जवान जिसके कारण देश सुरक्षित है, वह जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए स्वयं जब वह जागता है तब देश आराम की नींद सोता है। चाहे वह देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला हमारा मिलिट्री का जवान हो, पैरा मिलिट्री के जवान हो, चाहे हमारा पुलिस का जवान हो, इन सबकी सक्रियता और सचेतता के कारण हम लोग देश के अन्दर भी सुरक्षित महसूस करते हैं और देश की बाह्य सीमाओं के सुरक्षित होने से हम लोगों को सुरक्षा का एक महौल मिलता है। पहला बजट हम लोगों ने इन सबको समर्पित किया था और उस बजट के माध्यम से उनके लिये उस प्रकार की योजनाएं हैं। शहीद परिवारों के बारे में सरकार की योजनाएं हैं। 2017 से पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि पहली अप्रैल, 2017 के बाद से हमारे प्रदेश का कोई भी जवान चाहे प्रदेश के अन्दर वह पुलिस का जवान हो, उसको सरकार पहले से सुविधा देती थी, लेकिन उसको मिलने वाली जो धनराशि थी, अगर वह शहीद होता है या किसी घटना-दुर्घटना में सेवा के दौरान घायल होता है तो शासन के स्तर पर उसके लिये सहायता की इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं थी जिससे वह निर्भीकतापूर्वक, निःसंकोच होकर के अपनी सेवा प्रदेश की जनता को दे सके। कहीं न कहीं उसके मन में एक संकोच होता था कि मैं अगर किसी अपराधी से, किसी आतंकवादी से मुठभेड़ करते हुए घायल हो गया, गम्भीर रूप से घायल हो गया अथवा मुझे लम्बे समय तक कोमा में जाना पड़ गया तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा, इसके लिये कोई योजना नहीं थी। सरकार ने उनको मिलने वाली कम्पन्शेसन की राशि को दोगुना किया। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मिलिट्री, पैरा मिलिट्री को जवान जो देश की सीमा की सुरक्षा करने या देश की आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद से, उग्रवाद से, नक्सलवाद से लड़ता हुआ शहीद होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली मुआवजे की राशि को हमनें दोगुना भी किया और यह व्यवस्था की कि उस जवान के परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां नौकरी देगी (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी0ए0सी0 की क्षमता को बढ़ाया। पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हमनें 01 लाख 37 हजार से अधिक पुलिस और पी0ए0सी0 की सफलतापूर्वक भर्ती करने में सफलता प्राप्त की है और उनके लिये हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, उनकी ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना किया है। सात जगह ऐसी थीं जहां पर पुलिस लाइन ही नहीं थीं, पहले जिले बन गये, लेकिन पुलिस लाइन हीं नहीं थीं। हमनें वहां पर उनके लिये पुलिस लाइन बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उनके लिये बैरक बनाये, उनको आवासीय सुविधाएं दी हैं। यह प्रदेश

कहां जा रहा था, क्या कर रहे थे ? उस पुलिस के जवान के लिये हम लोगों ने यह व्यवस्था की है। 'जय जवान और जय किसान' के लिये हमारा 2017-18 का पहला बजट समर्पित था और उस बजट को उस रूप में प्रस्तुत करते हुए इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए आज पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अपनी पुलिस एण्ड फारेन्सिक यूनिवर्सिटी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बजट में इसका प्रावधान कर चुकी है, वर्तमान बजट में इसका प्रावधान कर चुकी है और हर एक रेंज स्तर पर एक साईबर तथा एक फारेन्सिक लैब की स्थापना, साईबर थाने की स्थापना होगी, इस प्रक्रिया को भी सरकार आगे बढ़ा चुकी है। साथ-साथ प्रदेश के अन्दर प्रदेश के उन सभी क्षेत्रों के बारे में खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, याद करिये जब हम लोगों ने कहा था कि प्रदेश के अन्दर हम गड्ढामुक्त सड़के देंगे तो लोग हंसते थे कि अरे, यह कैसे होगा। एक लाख बीस हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़के ऐसी हैं जो गड्ढों में बदल चुकी हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी आदत थी, विपक्ष की आदत थी, पिछली सरकारों की आदत थी कि उनको गड्ढे ज्यादा प्यारे होते थे, लेकिन हमने गड्ढामुक्ति का जो अभियान चलाया आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अन्दर सड़कें देखने लायक बन गयी हैं। अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय जो हमारी कनेक्टिविटी है उन सबको फोर लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्यवाही हमने प्रारम्भ की है। हर जिला मुख्यालय को हम फोर लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। यह सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ हर तहसील मुख्यालय को हर ब्लाक मुख्यालय को हम इनके साथ जोड़ेंगे ग्रामीण सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। पी0डब्लू0डी0 नोडल विभाग सड़क का है लेकिन बहुत सारी सड़कें सिंचाई विभाग की थीं, गन्ना विभाग की थीं, मण्डी की थीं। 20-20 वर्षों से इन सड़कों पर कोई काम ही नहीं हुआ था लेकिन बिना किसी संकोच के कौन विधायक है, कौन सांसद है इसकी चिन्ता किए बगैर हर एक जगह इन सड़कों को गड्ढामुक्त करके या उनको नवीनीकरण करने का काम प्रदेश के अन्दर सफलतापूर्वक किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई जान देने का कार्य किया था। यह प्रदेश का पहला बजट 2017-18 में हमारी सरकार का था। महोदय दूसरा बजट हम लोगों ने समर्पित किया प्रदेश के बुनियादी ढांचागत विकास और प्रदेश के औद्योगिक निवेश और साथ-साथ प्रदेश की शिक्षा और चिकित्सा को ध्यान में रखकर किया गया। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके हमने यहां पर कार्य किया और बजट भी उसी को ध्यान में रख करके हमने कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। बुनियादी ढांचागत विकास के आभाव में आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने के मित्रों को यह बुरा लगता है कि जब हम इनकी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की कहानी को इस समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब ये लोग उधर से बोलते हैं तो उनको देखकर लगता है कि जैसे ये सत्यवादी हरिश्चन्द्र के नए अवतार के रूप मे प्रस्तुत हो चुके हैं और यह लोग जो सदन में बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन उसका उससे कोई भी किसी भी प्रकार का

समन्वय नहीं होता है। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेन्ट पर इसी बात को लेकर फोकस किया गया है, क्योंकि पहले मैं जब किसान और जवान उत्तर प्रदेश की आधारशिला है किसान उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने के लिए उसका आधार बन सकता है। हमने पहले चरण में उसके मन में विश्वास भरा क्योंकि किसान इस धरती पर सोना उगाने का काम करता है और जवान सुरक्षा का एक वातावरण बनाता है। इन दोनों के समन्वय से हमने जो वातावरण चेन्ज किया, अब उसके लिए उस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस-वे, इण्टर स्टेट कनेक्टीविटी, मैट्रो, एयर कनेक्टीविटी। 20 वर्षों से सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी कि जेवर में एयरपोर्ट बनना है या नहीं बनना है ? हमने कहा अब इसमें न शब्द तो होगा ही नहीं, हम लोग इसको बनायेंगे और हर हाल में बनायेंगे। आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नाम का और यह एयरपोर्ट 2023 में जब फंक्शन में आएगा तो 2023 से लेकर के आगामी मात्र 30 वर्ष के दौरान ही एक लाख करोड़ से अधिक का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को देगा। यानी सरकार ने अपनी योजनाओं को इस रूप में बनाया है कि हम प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी देखेंगे और जेवर वह क्षेत्र है। हमारे जेवर के माननीय विधायक या नोएडा से जुड़े हुए हमारे जो जनप्रतिनिधिगण थे बुलन्दशहर और अलीगढ़ से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण थे ये अक्सर कहते थे कि क्या होगा ? हमने कहा देखिए वहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। याद करिए जेवर वही क्षेत्र है जहां पर आप लोगों की सरकार के समय भट्टा पारसोल की घटना घटित होती है। जहां पर तमाम ऐसी वारदातें घटित होती रही हैं जो पूरी मानवता के लिए अत्यन्त शर्मनाक हैं, लेकिन आज हमारी सरकार ने विकास का एक विजन दिया है, और मैं अभिनन्दन करूँगा जेवर क्षेत्र के उन सभी किसानों को, मैं गया था एक बार मैंने जनप्रतिनिधियों के साथ उन किसानों के साथ सीधे संवाद किया था और मैंने उनके सामने इसी बात को कहा कि देखा हम आपको उतना मुआवजा देंगे जो वास्तव में एक बार तय हो जायेगा आप एक हाथ से मुआवजा लीजिए और दूसरे हाथ से जमीन की रजिस्ट्री कर दीजिए, और पहली बार हुआ कि जब किसान अपनी भूमि को सरकार को सौपने के लिए अपने दस्तावेजों के साथ मुख्य मंत्री आवास पर आते हैं और जेवर के सभी किसानों ने इस बात को सौंपा कि हम लोग यह जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए देना चाहते हैं। सरकार ने कम्पनसेशन दिया है हमने जमीन अपनी दी है और हम चाहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहां बने। यह सरकार की सोच है। पहले क्यों नहीं होता था क्योंकि नियत खराब थी। किसान का मुआवजा कुछ और ही लोग हड़प जाते थे वह बेचारा देखते रह जाता था। आज ऐसा नहीं है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट है। इससे विश्वास जना और पहले ही 21-22 फरवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टरस् समिट 5 लाख करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 के साथ सम्पन्न हुआ। लोग मानते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में इतना भी निवेश आएगा। और आज भी लोग कहते हैं कि क्या हुआ ? जब जमीन पे जाओगे तब दिखायी देगा

कि क्या हुआ है। कार्यालयों में बैठ करके, सरकारी बगलों में बैठ करके सब दिखायी नहीं देता है। इसके लिए जमीन पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सरकार आने के बाद से लेकर के अब तक ढाई लाख करोड़ से अधिक का निवेश हम लोगों ने निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अन्दर करवाया है, और प्रदेश में इसके माध्यम से 33 लाख से अधिक यूथ को स्वरोजगार के साथ, रोजगार के साथ और नौकरियों के साथ भी जोड़ा है। प्रदेश के अन्दर सफलता पूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। एक विश्वास जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी पर व्यक्त किया था उसको इसके माध्यम से यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। 24 जनवरी, 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का नोटिफिकेशन जारी होता है लेकिन हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं लेकिन जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश की स्थापना दिवस को नहीं मनाते हैं। हमारी सरकार ने पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी के प्रस्ताव पर सहर्ष अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी, 2018 को पहली बार 68 वर्षों के बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है और स्थापना दिवस में जिस उत्तर प्रदेश की इनकम 1947 में जब यह देश आजाद होता है इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। वह उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय औसत से नीचे क्यों आया ? यानी आज उत्तर प्रदेश की आय कितनी विसंगति उसमें पैदा हुई अगर हम पूरे प्रदेश का एवरेज लें तो राष्ट्रीय औसत से आधी पिछले दो वर्ष के दौरान थोड़ा बढ़ा है आधे से कुछ ज्यादा हो गया है लेकिन 1950, 1947 में क्या स्थिति थी ? और लगातार यह डिटोरेट क्यों होता गया ? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में ? सब कुछ तो था। लेकिन प्रति व्यक्ति आय यहां लगातार घटती गयी। लोगों की इनकम घटती गयी, पलायन होता गया। हम केवल लोगों को उलझाते गये, झूठे नारों में उलझाते गये और झूठे नारों में उलझा-उलझा कर के हम लोगों ने पूरे प्रदेश को इतना खराब कर दिया कि दंगे, लूट-पाट, पेशेवर अपराधियों को सरकारी बंगलों में बुलाकर के सम्मानित करना यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन गयी थी, कोई निवेशक आना नहीं चाहता था। हमने तस्वीर बदली है उस मिथक को तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा है। प्रदेश में निवेश सुरक्षित होगा तो देखते-देखते देश और दुनिया भर के निवेशक यहां आने को तत्पर रहेंगे। अभी आपने डिफेन्स एक्स्पो देखा होगा। दुनिया के 70 देशों के रक्षा मंत्री और डिफेन्स चीफ लखनऊ आए थे और उन्होंने कहा कि कितना चेन्ज हो गया है। यह चेन्ज यह प्रसेप्शन बोलने से नहीं यह दिखना चाहिए। वास्तविक धरातल पर भी दिखना चाहिए और यह चीजें निवेश के माध्यम से हो सकती हैं। पहले स्थापना दिवस में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया था यहां की प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज से अधिक ले जाने में मदद की थी वह था प्रदेश का एम0एस0एम0ई0 सेक्टर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम। हमने इसके लिए एक यूनीक योजना चलाई है और उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद। मैं अभी आऊंगा कि इसके क्या परिणाम हुए, इस पर भी मैं आऊंगा लेकिन उसको भी बढ़ावा दिया। हम लोगों ने इसके साथ ही शिक्षा पर

फोकस किया। बेसिक शिक्षा परिषद इस सदन में बैठे जितने हमारे सदस्य हैं, हो सकता है आपमें से बहुत सारे लोग कैम्ब्रिज और हारवर्ड में पढ़े होंगे लेकिन हममें से ज्यादातर लोग प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़े हैं। आप लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। जानने के लिए कहीं भी जायेंगे, टैक्नालॉजी के लिए हर व्यक्ति जाता है। मैं स्वयं बोलता हूं अपने सदस्यों से और मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी से मैं इस बात का अनुरोध करने वाला हूं कि हमारे सदस्यों के डेलिगेशन को दुनिया के अन्दर अलग-अलग क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए टैक्नालाजी के लिए। मैंने अपने एम0एस0एम0ई0 मिनिस्टर से कहा है कि आप तैयार करिये दुनिया के अन्दर अब एक समय आया है उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के मन में विश्वास जगा है लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं। दुनिया के अन्दर ट्रेड के लिए टैक्नालाजी के लिए और टूरिज्म के लिए हम दुनिया से बहुत कुछ आदान-प्रदान कर सकते हैं। अपने लाखों यूथ को वहां भेज सकते हैं और वहां से बहुत कुछ आदान-प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ होगा। हमारे पास कहीं चावल है, उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह अलग-अलग प्रकार का चावल है, गुड़ भी हमारे पास मौजूद है, दलहन हमारे पास है, आम हमारे पास है, आलू हमारे पास है कौन सा फल बागवानी का हो साग भाजी का हो या फिर खाद्यान्न का हो, क्या चीज नहीं है हमारे पास, हम इसको भेज सकते हैं। मोटा चावल आप अफ्रीकन देशों में भेजिये, बासमती गल्फ में और यूरोप में बहुत डिमान्ड है। अभी मैं चन्दौली गया था उन्होंने ब्लैक राइस वहां पर ले कर आयें हैं बड़े क्षेत्रफल में उसका उत्पादन शुरू किया, 300 रुपये प्रति किलो डिमान्ड है दुनिया में। हम उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बना सकते हैं। इण्टरनेशनल राइस इन्स्टीट्यूट हम लोगों ने काशी में खुलवाया है। मनीला की मदद से वह इन्स्टीट्यूट काम करना प्रारम्भ किया है। मुजफ्फरनगर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गुड़ की 118 वैराइटी बनाकर अपने आपको दिखा दिया कि हां हम भी अपने यहां कुछ पैदा कर सकते हैं। लोग कहते थे कि गोरखपुर में केवल टेराकोटा है, हमने कहा कि टेराकोटा बहुत लम्बी छलांग मारेगा। अभी आपको जो दिखता है न टेराकोटा आने वाले समय में गोरखपुर का टेराकोटा हर घर में गणेश-लक्ष्मी को पहुंचाने का काम करेगा। क्यों हम चीन से लेकर आयेंगे ? यहीं बनेगा। जब दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने 2017 में किया था 51 हजार दीप जलाने थे मुझे पूरे प्रदेश से दीप इकट्ठा करने पड़े थे और पिछले वर्ष जब हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया 5 लाख 51 हजार दीप जलाये थे और सभी दीप अयोध्या में बने थे। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति। क्यों हम चीन से मंगायेंगे ? अब मंगायेंगे तो उसके साथ कोरोना वायरस भी आयेगा। इसलिए बच के रहियेगा लेकिन हम लोग तो उस विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। दुनिया में कहां अच्छी टैक्नालाजी है हमें अगर उपयोगी है जो यहां की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, यहां की यूथ को ज्यादा इम्प्लाइमेन्ट दे सकता है हम इसको जोड़ेंगे। टूरिज्म, दुनिया का कौन ऐसा हिन्दू होगा, कौन ऐसा बौद्ध होगा जो उत्तर प्रदेश के अन्दर न आना चाहता होगा। कौन ऐसा पर्यटक होगा जो इको टूरिज्म और हैरिटेज टूरिज्म के

लिए उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता होगा। क्या नहीं है आपके पास। हम दुनिया से उनको यहां आमंत्रित करें। अलग-अलग देशों में डेलीगेशन भेजे जाने चाहिये, इण्डियन डायस्पोरा के साथ हम बैठें, बातचीत करें, संवाद करें, आमंत्रित करें। इससे लाखों यूथ को एक साथ इस क्षेत्र में नया कार्य मिलेगा और एक नया स्टार्ट अप स्थापित करने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार ने इसकी भूमिका वर्ष 2018 में बनाई है और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे समय में कुम्भ का आयोजन हुआ था और लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु कुम्भ में आते हैं। इस बार यहां आने वाला हर व्यक्ति इस बात को कह गया कि वाह क्या कुम्भ है। यह है हमारी कार्य करने की पद्धति लेकिन जो व्यक्ति वर्ष 2013 में आया होगा वह उस समय गाली देकर जरूर गया होगा। यह अंतर है कि कृत्य आपके थे और गाली उत्तर प्रदेश खा रहा था लेकिन इस बार कार्य हमारे और वाह-वाही पूरा उत्तर प्रदेश ले रहा था। यह है कार्य पद्धति में अंतर। इस कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुये हैं। वर्ष 2018 में दूसरे बजट में इसको फोकस करते हुए हम लोगो ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बेसिक शिक्षा परिषद के 158000 विद्यालयों की बहुत खराब स्थिति थी। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी थी और साथ-साथ बुनियादी सुविधायें भी नहीं थी। वहां पर ना पेयजल की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था, ना वहां पर बैठने की व्यवस्था, ना वहां पर कोई कनेक्टिविटी थी। वहां बच्चों की यूनीफार्म इस प्रकार की थी कि बच्चे नंगे पैर जाते थे, ना बैग, ना बुक, ना स्वेटर और भीषण सर्दी में गरीब बच्चा ठण्ड से मरता था। आपने जाति-पाति के नाम पर बांटने के सिवाय और क्या किया है। वह गरीब बच्चा जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ता है क्या वह इस प्रदेश का बच्चा नहीं था। क्या उसकी कोई जाति नहीं थी। आप उसको दो अच्छी यूनीफार्म दे दिये होते, उसके पैरों में जूते नहीं थे, वह नंगे पैर स्कूल क्यों जायेगा। उसको पैरो में पहनने के लिए जूते-मोजे दिये जाने चाहिये। सर्दी में भीषण ठण्ड से गरीब का बच्चा क्यों मरेगा, उसको भी स्वेटर मिलना चाहिये था, लेकिन आप वह नहीं दे पाये क्योंकि आपकी सोच ही नहीं थी क्योंकि आपको भय लगता था कि गरीब का बच्चा अगर उठ जायेगा तो आपका सिंहासन डोलने लग जायेगा। यह है आपकी कथा। अरे कथा कहां से प्रारम्भ होती है। माननीय अध्यक्ष जी, तीन भाई थे और तीनों ने भगवान की बड़ी आराधना की। एक ने कहा कि मुझे शक्ति मिल जाये, दूसरे ने कहा मुझे भक्ति मिल जाये, तीसरे ने कहा कि मुझे सत्ता मिल जाये। सत्ता का प्रतीक इन्द्रासन था तो बेचारा इन्द्रासन बोलने की बजाय निद्रासन बोल गया तो निद्रासन में पहुंचा ही दिया जनता ने। माननीय अध्यक्ष जी, यह यहां पर होता था। हम विकास की बात करेंगे वह जाति की बात करेंगे। हम बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे, वह जाति की बात करेंगे। हम लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे, वह जाति की बात करेंगे। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते हैं तो वह जाति की बात करते हैं। हमने कहा 'सबका साथ और सबका विकास', हमने कोई भेद किया क्या किसी के साथ ? कोई नहीं कह सकता। यह सोचिये कि वर्ष 2011

की सेन्सस सूची हमने नहीं बनाई है तब ना केन्द्र में बीजेपी थी और ना प्रदेश में बीजेपी थी लेकिन हमने कहा कि उस सूची के अनुसार देंगे लेकिन जो बचेंगे उनको भी देंगे। किसी को वंचित नहीं रखेंगे। कार्य करने के लिए संवेदनशीलता चाहिये, कार्य करने के लिए विजन चाहिये। जो आप में नहीं था। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से, शिक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के 158000 विद्यालयों में से 120000 विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। फ्लोरिंग बन चुकी है। टॉयलेट बन चुके हैं। लाइट का कनेक्शन दिया जा चुका है। पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है और वहां पर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था बहुत सारी जगहों पर हो चुकी है। फर्नीचर की व्यवस्था भी बहुतायत में हो चुकी है। हमने एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप जाइए न, और मैं आप में से सभी माननीय सदस्यों से चाहंगा कि हमारा विजन होना चाहिए। सत्ता में एक दिन कम से कम एक दिन किसी एक प्राथमिक विद्यालय में जाकर उन बच्चों के साथ कुछ समय गुजारें और उनको हम कुछ बताएं क्योंकि वह बच्चा उपेक्षित नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो स्कूल जाने से वंचित रह जाए। आखिर वह प्रदेश का बच्चा है। प्रदेश का बालक है। उस बालक और बालिका के मन में यह भाव दिखना चाहिए कि आज कोई हमारे पास आया तो है, कोई पूछ तो रहा है ? उसके मन एक विश्वास जगना चाहिए और इस विश्वास को एक करोड़ अस्सी लाख बच्चों को यह सुविधा प्रदेश की सरकार आज के दिन दिला रही है और निरंतर दिलाएगी भी। वर्ष 2018 में स्वास्थ्य को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा था। हमारे कार्य पहले से प्रारम्भ हो चुके थे। इंसेफेलाइटिस स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाने के बाद हमारी जो कार्य योजना आगे बढ़ी थी आज यह उसी का परिणाम है। तीस जनपद जहां पर इंसेफेलाइटिस कम या ज्यादा मात्रा में थी। इंसेफेलाइटिस हर वर्ष हजारों बच्चों को लील जाती थी। पिछली सरकारों को फुरसत ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि इंसेफेलाइटिस भी कोई बीमारी है। जिनकी फाइव स्टार की प्रवर्ती हो चुकी थी वह लोग गरीब की पीड़ा को क्या सुनेंगे ? उन्हें किसी गरीब की, किसी दलित की पीड़ा से मतलब ही क्या था ? क्योंकि जब वह बीमार होता था तो उसकी वाइस नहीं होती थी। आपने इसके बारे में उसकी पीड़ा को नहीं सुना। चालीस वर्षों से बच्चे मर रहे थे। 38 जनपदों में मर रहे थे। कुशीनगर से लेकर के और आप इधर आ जाइए लखीमपुर खीरी से लेकर के सहारनपुर तक। यह पूरी तराई की बेल्ट इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थी। कोई संवेदना नहीं थी क्योंकि आपके नारे थे। वे नारे जो केवल लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। आज भी तो आप यही कर रहे हैं। आज भी तो आप इन सब चीजों से सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं कि कुछ तो सुधार हो। एक बार ठोकर लगी है। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है कि वह बार-बार ठोकर नहीं खाता है। एक बार ठोकर खाकर संभल जाता है या फिर दूसरे को देखकर संभल जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि बार-बार ठोकर खाना बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। उन लोगों के

साथ किस प्रकार की स्थिति है कि आज भी जो वह कर रहे हैं, कहीं सी0ए0ए0 के नाम पर, कहीं एन0पी0आर0 के नाम पर और एन0आर0सी0 के नाम पर प्रदेश में और देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप समाज की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इस कृत्य के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। देश के संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। देश की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई संवेदना गरीब के लिए नहीं है, आखिर वह गरीब तो किसी जाति का होगा तब आपकी जाति कहां गयी थी ? तब आप क्या कर रहे थे ? ऐसा ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। इंसेफेलाइटिस से मरने वाले जो बच्चे थे वह 40 वर्षों से मर रहे थे। इसमें 90 फीसद बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से थे। कोई नहीं बोलता था। जब मैं सांसद था तब भी मैं ही बोलता था और मुख्य मंत्री बनने के बाद भी मैं ही बोल रहा हूं। तब भी आप हमें ही कहते हैं, हमारी पार्टी को कहते हैं। हम गरीब विरोधी हैं। हम फालाना विरोधी हैं। तब भी आप यही आरोप लगाते हैं। इंसेफेलाइटिस विगत वर्ष तक हम लोग 56 फीसदी कम कर चुके हैं और मौत के आंकड़ों को 81 फीसदी नीचे ला दिये हैं। और जो प्रोग्राम चल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि पहली मार्च से संचारी रोग नियंत्रण का इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू, काला जार इन सबके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है और इसमें इंसेफेलाइटिस के खिलाफ वेक्सीनेशन को भी एक नये प्रोग्राम के रूप में जोड़ा गया है। और मैं चाहंगा, पहली मार्च को रविवार है। हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यह कार्यक्रम चलेंगे और आप सब उसमें भागीदार बनें। अभी पिछले 16 फरवरी को फाइलेरिया के खिलाफ अभियान का शुभारम्भ हुआ। हमें चलाना चाहिए। जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक हम इस प्रकार के रोगों को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। हम सबका दायित्व है कि हम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ इस अभियान का हिस्सा बनें। कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब, कोई भी पीड़ित इससे मौत का शिकार न बने। सरकार की योजना उस तक पहुंचायें। टीबी मुक्त भारत के इस अभियान में हम भी सहभागी बनेंगे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहां पर ए0एल0एस0 देने की बात हो रही थी। मुझे याद है जब सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मंत्री बने। 10-12-15 दिन के अंदर ही वह फाइल लेकर आये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमें कुछ कार्डियेक वेन देना चाहती है। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने मना कर दिया हम क्या करें। मैंने कहा कि नहीं, आप तुरन्त भारत सरकार में जाइये और यह स्वयं वहां गये और एक साथ एक महीने के अंदर 150 कार्डियेक एम्बुलेंस यहां लेकर आ गये। जो वेल इक्युप्ट थी। जिसमें मानीटर भी है, वेंटिलेटर भी है हर प्रकार की सुविधायें हैं और आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में दो-दो कार्डियेक एम्बुलेंस हम लोगों ने दी है। ए0एल0एस0 दी हैं। हर जनपद में पहले चरण में दे चुके हैं। और दूसरे चरण में भी 100 और दी हैं जिसमें चार बड़े जनपदों में और छोटे जनपदों में तीन-तीन हैं। यह सिस्टम कैसे

कार्य करता है। एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक में भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, जल संसाधन है, वित्तीय समावेशन है, स्किल डेवलपमेंट है इन सभी क्षेत्रों में भी बेहतर कार्य होना चाहिए। पूरे देश के अंदर टांप की रेंकिंग में उत्तर प्रदेश चल रहा है। यह ऐसे ही नहीं हुआ। इसके लिए प्रयास करने पड़े हैं यह चीजें तब आयी हैं। स्वास्थ्य के लिए 108, 102 के रिस्पांस टाइम को कम करने का कार्य किया गया है। नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन शिकायत नहीं आती थी। रोज शिकायत, रोज कुछ न कुछ होता था। आज वह तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कालेजेस के क्षेत्र में गोरखपुर, रायबरेली एम्स का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और एम्स में ओ0पी0डी0 भी दोनों जगह प्रारम्भ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कालेज की एक श्रंखला बिछी है। हमने तो पालिसी तैयार करने के लिए कहा है कि जो हमारे 16 जिले बचे हैं इन 16 जनपदों में भी आगामी एक वर्ष के दौरान एक पालिसी बनाइये, वहां पर भी पी0पी0पी0 मोड में एक मेडिकल कालेज बन जाये जिससे विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हम हर जनपद में उपलब्ध करा सकें। हमने तो भेद-भाव नहीं किया। बिजली यहां आयेगी यहां नहीं आयेगी। बलदेव सिंह औलख हमारे मंत्री आये, कहा कि रामपुर में बिजली आयेगी कि नहीं आयेगी। मैंने कहा कि जैसे पहले आती थी वैसे ही आयेगी। वहां बिजली जा रही है और वहां तो बिजली बहुत चमक रही है। बहुत तेजी से चमक रही है। बहुत अच्छे ढंग से चमक रही है। जब बिजली चमकती है। मान्यवर, यह फालतू वायरस नहीं पैदा होते हैं, कोरोना वायरस गंदगी में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही पैदा होते हैं और हम उसी को दूर कर रहे हैं। उस प्रकार की सभी चीजों की एक साथ सफाई करने का अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शौचालय देने के साथ-साथ गंदगी को साफ करने का भी एक अभियान है। किसी भी रूप में गंदगी हो उसका सफाया होना चाहिए। यह उसी का हिस्सा है और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों की एक श्रंखला खड़ी की है। आखिर प्रदेश में गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं यहां पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलेगी, क्यों वह पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में जायेगा ? इतना बड़ा प्रदेश है। हम वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2016 तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज ही बना पाये थे। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच 29 मेडिकल कॉलेजेज पर एक साथ काम चल रहा है। शेष 16 मेडिकल कॉलेजेज के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कह दिया गया है कि यहां पर भी मेडिकल कालेज बनेंगे।

(इस मध्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोका-टोकी करने पर)

मान्यवर, क्या दिक्कत आ रही है, जाएं न, सुविधा है। हम लोग यहां पर भी मेदांता बना चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना आने के बाद सारे भेद समाप्त हो चुके हैं। आप जाइये, आपको पैसा दिया जा रहा है, गरीब भी मेदांता में उपचार करा सकता है, एस0जी0पी0जी0आई0 मे उपचार करा सकता है। यह कार्य सिर्फ बीजेपी करा सकती है, आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि आपको बुरा लगता था। हर एक चीज को लेकर एक गांव में डालते

थे लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमने 07 विश्वविद्यालय दिये हैं और सभी जगहों पर दिये हैं। अभी हमने सहारनपुर एवं अलीगढ़ में एक-एक विश्वविद्यालय दिया है। आप लोगों ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भुला दिया है। हमने उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ में दिया है, हमने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया है। जनपद आजमगढ़ में मा0 मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे लेकिन वह एक भी विश्वविद्यालय नहीं दे पाये। हमने एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ दिया है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रहे हैं। यह सारी चीजें बताती हैं कि आपका विकास का विजन था ही नहीं। हम प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं और स्वर्गीय मा0 अटल जी के नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में देने जा रहे हैं। आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में देने जा रहे हैं। एक नयी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मेरठ में जमीन का चयन कर रहे हैं। हर एक ओर, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं।

हाजी इकराम कुरैशी-

मान्यवर, एक यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में भी दे दीजिएगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में एक गन्ना संस्थान दिया गया है। जनपद बिजनौर में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। हर एक जगह के लिए कुछ-न-कुछ किया जा रहा है। यह सरकार के उस विजन का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास के साथ देश के सबके विश्वास को अर्जित किया है और हम उसी भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा बजट विगत वर्ष 2019-2020 में महिला सशक्तीकरण और उन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित किया था। प्रदेश के अंदर वास्तव में जिनको योजनाएं होने के बावजूद भी वंचित रखा गया था। महिला सशक्तीकरण, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इससे दो लाख साठ हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और अलग-अलग चरणों में, बालिका के जन्म लेने से लेकर किसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स तक की 15 हजार का पैकेज सरकार देने जा रही है। अगर बालिका शादी-विवाह योग्य हो गयी है। उसको मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने की कार्यवाही हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब सरकार ने पहली बार मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की थी तो सामने के मित्रों ने कहा कि यह बालिकाओं का अपमान है क्योंकि वह जब जमीन पर उतरेंगे नहीं तो उनको गरीबी दिखाई नहीं देगी। एक लाख से अधिक बालिकाओं का विवाह मुख्य मंत्री सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत हुआ है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) हर जन-प्रतिनिधि उसमें शामिल भी हुआ है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उन लोगों तक मिले यह सरकार का विजन होना चाहिए और सरकार ने उस कार्यक्रम को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। खासतौर पर, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना उसी की अगली कड़ी थी। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना,

सामूहिक विवाह योजना, स्नातक तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, प्रदेश में पुलिस बल में 20 फीसदी बालिकाओं की भर्ती अनिवार्य की जाए, तीन पी0ए0सी0 वाहिनियों का गठन किया जाये और इसी के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए भी काम प्रारम्भ हुआ है। महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन हम ही लोगों ने किया था, 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हम ही लोगों ने किया है, 74 पाक्सो कोर्ट का गठन भी सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया है और प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण करके नारी गरिमा की रक्षा इसके माध्यम करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यह महिला सशक्तीकरण के प्रति समर्पण का एक भाव है। यह कार्यक्रम उसी के हिस्से के रूप में आगे बढ़े हैं, पोषण मिशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही हुई है। यह कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है और हम लोग उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अगर मैं थोड़ी चर्चा करूं कि प्रदेश के अंदर पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन की स्थिति क्या थी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। निराश्रित महिला पेंशन 2016-17 में केवल 17 लाख 31 हजार 941 निराश्रित महिलाओं को मिल पाती थी और आज 24 लाख 75 हजार 224 निराश्रित महिलाओं को इस पेंशन की सुविधा से हमने जोड़ दिया, त्रैमासिक रूप से पैसा उनके एकाउण्ट में पहुंच जाता है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) इसी प्रकार से, दिव्यांगजन पेंशन वर्ष 2016-17 तक कुल 08 लाख 75 हजार दिव्यांग जन इसका लाभ पाते थे लेकिन आज 10 लाख 55 हजार 500 से अधिक लाभार्थी इस योजना के साथ सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, जिसमें पहले 300 रुपये पेंशन थी, हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे 500 रुपये किया है और सभी दिव्यांगजनों को इस पेंशन सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, पहले कुल 36 लाख 52 हजार लोगों को यह सुविधा मिलती थी लेकिन आज 46 लाख 96 हजार वृद्धजनों को यह पेंशन मिल रही है और इसे 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक करने का काम प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किया है। इन कल्याणकारी योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का काम भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया है। महोदय, महिला सशक्तीकरण की जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से एक सम्मान का भाव होना चाहिए और उस सम्मान के भाव को लेकर ही हम लोगों ने इस बात को समर्पित किया था, उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था,

''नारी! तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास-रजत-नग पग तल में।
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।।''

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

महिला सशक्तीकरण को समर्पित प्रदेश सरकार का यह तीसरा बजट था और चौथा बजट जो अभी 18 फरवरी को मा0 खन्ना जी ने इसी सदन में प्रस्तुत किया है वह प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है सबसे अधिक युवा हमारे देश में हैं और उसमें भी हम और सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे युवा है। सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश के हैं। उस युवा ऊर्जा, उसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम तैयार किए हैं, उसके लिए फोकस करते हैं। ध्यान तो सभी वर्गों के लिए दिया है, सभी प्रकार के विषयों को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। लेकिन युवाओं को ले करके अनेक योजनाओं को इस बजट में देने की व्यवस्था की गयी है और बजट के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, इसको भी हम लोगों ने इसके माध्यम से दिया है क्योंकि हम जानते हैं, हमारा युवा, जहां भी उसको अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा की ऐसी धाक जमायी है, लेकिन उसको सुविधाओं से वंचित किया गया, अवसरों से वंचित किया गया। नौकरी की बात आती थी, तब जाति सामने आ जाती थी। जाति के नाम पर भी लोग झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे। उस समय भी फिर परिवार की बात आ जाती थी। जाति के लोग ही लाभान्वित नहीं होते थे, बेचारा पैसा दे करके भी टुकुर-टुकुर देखता था। आज यह सब समाप्त हुआ है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 01 लाख 37 हजार भर्तियां हम लोगों ने की हैं। एक भी भर्ती में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। पारदर्शी तरीके से पूरी भर्तियां हुई हैं और यही नहीं लगभग पौने तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं को नौकरी में जगह दी है, प्रदेश के अन्दर नौकरी दी है और इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे अभी बढ़ाया जा रहा है। पहली बार दिखता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ कोई भेद-भाव नहीं हो रहा है। मुझे याद है, जो परिपाटी बन चुकी थी, आज उसको बदला है, चेन्ज किया है, उत्तर प्रदेश ने उसको बदलने का कार्य किया है। हमने नौकरी भी दी, जगह-जगह रोजगार मेले के माध्यम से प्लेसमेंट की व्यवस्था भी अपने उन यूथ के लिए किया, जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेण्ट के सेण्टर से सर्टीफिकेट प्राप्त किया है, उसके लिए हमने रोजगार मेलों का आयोजन भी किया है और साथ-साथ भारी निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार सृजन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है और हम लोग जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, अभी डिफेंस एक्सपो में, आपने देखा होगा, लोगों में क्या उत्साह था। मैंने तो आपको भी आमंत्रित किया था कि आप सब लोग भी डिफेंस एक्सपो में आइये। उसमें सभी को जाना चाहिए क्योंकि वह देश के रक्षा शौर्य का प्रदर्शन था। देश की सेना के पराक्रम का भी एक अच्छा अवसर देखने का था। लेकिन यह अवसर बाहर के लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में जानने का भी अवसर था। लेकिन साथ-साथ इसके माध्यम से निवेश, इन सम्भावनाओं को आगे बढ़ा करके रोजगार के साथ इसको जोड़ना है। ये कार्यक्रम

सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 03 वर्ष के दौरान प्रदेश के अन्दर किए हैं और इस बजट में भी हम लोगों ने इसीलिए दो स्कीम स्पेशली युवाओं को फोकस करते हुए दी हैं। एक-हमारा नौजवान कोई पॉलीटेक्निक करता है, कोई आई0टी0आई0 करता है, कोई स्किल डेवलपमेण्ट के किसी सेण्टर से किसी सर्टीफिकेट का कोर्स करता है, 600 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजेज हमारे पास हैं, डिग्री लेता है या फिर हमारे राज्य विश्वविद्यालय, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में जो छात्र डिग्री के किसी पाठ्यक्रम में, वह साइंस हो, कामर्स हो, किसी मानविकी के किसी पाठ्यक्रम से अध्ययन कर रहा है, डिग्री ले रहा है, एक समय के बाद वह अपने को हताश और निराश पाता था। आज सरकार उनके लिए योजना लेकर आयी है और उसे टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं, हर कालेजेज के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अप्रेन्टिसशिप की जो योजना है, हर नौजवान जिसका चयन होगा, उसको आगामी एक वर्ष तक पहले चरण में 2500 रुपये महीने सरकार इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करायेगी और सरकार इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को जोड़ना चाहती है। क्यों हमारा यहां का यूथ बाहर जाएगा। मैंने जो इस बारे में कहा कि हम देखें ट्रेड दुनिया के इण्डियन डायस्कोरा के साथ हमारा ट्रेड मैन/पावर के साथ भी हो सकता है। हमारे पास योग्य स्नातक हैं, हमारे पास योग्य टेक्नोक्रेट हैं, हमारे पास योग्य स्किल्ड डेवलपमेंट से निकले हुए नौजवान हैं। दुनिया के अंदर मांग है प्लम्बर की, हम यहां से सरकार के स्तर पर भेजेंगे उसको। सरकार उसके लिए मुहैया कराएगी साधन, उसके साथ चीटिंग नहीं हो पाएगी। नहीं तो क्या होता था आप लोगों के समय में, बेचारा जाता था वहां पर पलम्बर बनने के लिए, वहां बेचारे को बकरी, भेड़ चरवाया जाता था, यही होता था न ? और वह बेचारे परिवार के लोग परेशान होते थे, लोग कहते थे अरे, काम करो कुछ तो मिल गया। आज ऐसा नहीं है, चीटिंग बंद है, पूरी तरह बंद है। हमारा यह यूथ जाएगा प्रदेश के बाहर स्थान पर, दुनिया के अंदर, देश के अंदर जहां कहीं होगा, हम उसको उसके लिए पारंगत करेंगे। इसके लिए इंटर्नसिप की स्कीम हम लोग लेकर के आए हैं, और यह स्कीम प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर लागू होती है, और दूसरा युवा हब, युवा उद्यमिता विकास की दृष्टि से, वह सेण्टर हमारे खुलने जा रहे हैं। युवा हब के रूप में और हर जनपद में हम खोलने जा रहे हैं। 12 सौ करोड़ रुपये केवल इस कार्य के लिए है। यह 12 सौ करोड़ का मतलब आप लाखों यूथ को इसके माध्यम से रोजगार और सेल्फ इम्प्लायमेण्ट के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए यूथ को फोकस करते हुए कहा, हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान को भी इसके साथ जोड़ा था। टेक्नालॉजी और उसके साथ ही उसको मार्केटिंग की व्यवस्था देना यह चीजें उन युवाओं के लिए और इसीलिए हम लोगों ने कहा था, युवाओं को समर्पित इस बजट को हम लोगों ने इसी बात को लेकर के कहा था कि नए युग का सर्जन युवकों, तुम्हारे हाथ में है, समुचा जग युवा पीढ़ी, तुम्हारे साथ में है। प्रबल फौलाद सच मानों तुम्हारे दांत में है, नए युग का सर्जन, युवकों तुम्हारे हाथ में है।

सफलता तो तुम्हारी बात में, जज्बात में है, नए युग का सर्जन युवकों, तुम्हारे हाथ में है। यह है अपने यूथ को समर्पित हमारा बजट। महोदय, बजट की अपनी थीम जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित किया है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हं, अब हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे इंजीनियरिंग कालेज, हमारे पॉलीटेक्निक, हमारे आई0टी0आई0, हमारे मेडिकल कालेज यह केवल शासन की योजनाओं को लेने के माध्यम नहीं बनेंगे, बल्कि समाज को देने के माध्यम बनेंगे। समाज ने उनको अवसर दिया, यह समाज को देंगे, और इस दृष्टि से इनकी उपयोगिता को उस रूप में जोड़ने कि कार्यवाही को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने युवाओं के लिए इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों ने इस बजट को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया, और इस दृष्टि से बजट के दायरे को हमें बढ़ाना था, उसके लिए प्रदेश के अंदर हमने अपने लिए आय के श्रोत बढ़ाए, अगर मैं आय के श्रोत में आऊं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्या कर रहे थे आप लोग ? जब मैं यह आंकड़े आपको दे रहा हूं नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अगले दिन फिर एक पोथा लेकर आना बताने के लिए कि नहीं हमारे समय में यह नहीं होता था। कैसे-कैसे चोरी होती थी, कैसे-कैसे आप लोग प्रदेश की जनता को उनकी विकास योजनाओं से वंचित करते थे। महोदय, अगर मैं देखं तो जी0एस0टी0 हमारी सरकार आने के बाद लागू हुआ, लेकिन जी0एस0टी0 के पहले वैट था और जी0एस0टी0 से पहले वैट के दौरान प्रदेश का जो राजस्व था, वह कुल 51 हजार करोड़ के आस-पास था, यानि उसमें कोई बढ़ोत्तरी आप लोग नहीं कर पाए थे और उस राशि से आप बहुत कुछ आगे बढ़ा भी नहीं सकते थे, वह 51882 करोड़ रुपये था। महोदय आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जी0एस0टी0 आज के दिन इस वित्तीय वर्ष में 76000 करोड़ रुपये को पार करेगा और अगले वर्ष के लिए इस बजट में हमने जो लक्ष्य रखा है, वह 91000 करोड़ रुपये का रखा है। टैक्स पेयर का पैसा शासन के खाते में ही आना चाहिए और जब यह पैसा रहेगा तब ही योजनाएं बनेंगी। इस दृष्टि से स्टैम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2016-17 में कुल 11564 करोड़ रुपये मिलता था और इस समय 19179 करोड़ रुपये मिल रहा है। आबकारी विभाग, आबकारी पॉलिसी लागू होने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी लेकिन हम लोगों ने लागू की। इनके समय में इन्होंने इसके कुल राजस्व का लक्ष्य 14273 करोड़ रुपये रखा था और इस समय हमारे पास जो पैसा आ रहा है, वह 31517 करोड़ रुपये आ रहा है। आखिर यह बीच का पैसा कहां जा रहा था ? वाहन एवं यात्री कर वर्ष 2016-17 तक 5148 करोड़ रुपये था और हमारे समय में 7863 करोड़ रुपये आ रहा है। यह पैसा भी कहां जाता था ? विद्युत कर और शुल्क वर्ष 2016-17 तक 1555 करोड़ रुपये था, इस समय इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास 3130 करोड़ रुपये आ रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

विद्युत की दर भी तो बढ़ी है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, दाम नहीं बढ़े हैं। वर्मा जी आप इतने सीनियर हैं, कभी-कभी सच भी बोल लिया करिए। खनन में वर्ष 2016-17 में 1548 करोड़ रुपये थे और वर्ष 2019-20 में यही लक्ष्य 4400 करोड़ रुपये का रखा गया है। महोदय यह है तस्वीर और यह तस्वीर तब है, जब हमने चारों बजट में कोई टैक्स पब्लिक पर नहीं लगाया है। कोई टैक्स नहीं लगाया है, जनता पर कोई भार नहीं डाला है। हां चोरी जरूर रोकी है, यह सरकार का दायित्व है। हम लोगों ने चोरी रोकी है, बहुत मजबूती के साथ रोकी है और तब ही हम लोग 05 लाख 12 हजार 860.72 करोड़ रुपये का बजट इस सदन में प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। महोदय अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने बजट में वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया है। एफ0आर0बी0एम0 की जो 03 प्रतिशत की सीमा है उसके अन्दर ही हमारा बजट है, यह 2.97 प्रतिशत है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर हर एक स्तर पर कहीं भी चाहे प्रदेश के विकास का हो, बुनियादी सुविधाओं का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, किसी भी सेक्टर की किसी भी योजना में कटौती नहीं की। बल्कि उस सब में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की है और इसी बढ़ोतरी का परिणाम है कि आज भारत की आर्थिक स्थिति में भी उसका बहुत असर पड़ा है। अब एक नये विजन के साथ नया उत्तर प्रदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है तो उसमें नये भारत का यह नया उत्तर प्रदेश है और इस नये उत्तर प्रदेश का यह नया बजट 05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सीमा को पार करते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग अगर इसमें सबसे बड़ी बात देखें तो आपके समय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जो मैं पहले बोल रहा था। 1947 से 50 के बीच में ये नेशनल एवरेज से थोड़ा सा अधिक था। उसके आधे से अधिक आपके समय में हो गया था अब आधे से ज्यादा हमने इसको बढ़ाया है वह आपके समय में 42267/- रुपये था और इस समय यह 64330/- रुपये प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की बढ़ी है (मेजों की थपथपाहट)। ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है ये तस्वीर आपके सामने आनी बहुत आवश्यक है। वर्ष 2016-17 में जो राष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि दर थी वह 8 फीसदी थी जिसमें उत्तर प्रदेश का निर्यात 3.8 प्रतिशत था नोट करिये मेरे आंकड़ों को उस समय उत्तर प्रदेश का निर्यात 3.8 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में हम लोग आये थे तो इसको बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत तक लेकर गये। यह राष्ट्रीय औसत 5.7 प्रतिशत था और उत्तर प्रदेश का 5.6 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 में जब ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' अपना पूरा रूप ले चुका था तब यह 18 फीसदी बढ़ा था और आज की डेट में यह 28.2 प्रतिशत है जो कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यह देश के अंदर यह 28.2 फीसदी है। फाइनेन्सियल इन्क्लूजन में स्वरोजगार सृजन करने में, आर्थिक स्वावलम्बन में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया बूम देने में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वित्तीय समावेशन जिसे आप कह सकते हैं। इसमें प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है पहले 16264 बैकों की कुल शाखायें थीं और आज 18869 बैंक की

शाखायें पूरे प्रदेश के अंदर हैं। आपके समय में 8 करोड़ 62 लाख बैंक के खाते थे। हमारे समय में ये संख्या 16 लाख 36 हजार हो चुकी है। एवरेज हर परिवार में एक दो परिवार के सदस्यों और कहीं तीन सदस्यों के बैंक एकाउण्ट खुल चुके हैं यानि डी0बी0टी0 के माध्यम से हम उसको पैसा दे सकते हैं। आज यह चीजें यह इसके माध्यम से देखा जा सकता है इसको हम इसके माध्यम से बता सकते हैं। यह है वह परिवर्तन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। अब इस सबके बावजूद भी आप प्रश्न करते हैं प्रदेश के बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं यानि किस रूप में प्रदेश के अंदर यह सब कार्य हुये हैं। यह एक सामान्य स्थिति नहीं है हरेक का प्रयास है, सामूहिक प्रयास है इसको हम किसी संकीर्णता के दायरे में नहीं लेकर जा रहे हैं लेकिन महोदय इस बजट में हरेक विभाग के लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है और खास तौर पर आप देखेंगे कि अभी इस बजट में हमने बुन्देलखण्ड के लोगों के लिए ये किया है अभी 29 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे। बुन्देलखण्ड सदैव उपेक्षित था, पूर्वांचल सदैव उपेक्षित था। मध्य का यह क्षेत्र उपेक्षित रहता था। अब कहीं कोई उपेक्षित नहीं रहेगा। हम तो सबको साथ लेकर चले हैं। सबको सुरक्षा दे रहे हैं आज कोई यह नहीं कह सकता। इस तरह की घटनायें घटित नहीं हो सकती हैं कि जबरन किसी बालिका को कार में बिठाकर लेकर चले गये, अपहरण कर दिया। उन अपहरणकर्ताओं को मालूम है किसी बालिका को लेकर जायेगा तो उसके बाद उसका क्या हाल होने जा रहे हैं और ये चीजें आज नहीं हो सकतीं है। सुरक्षा के वातावरण के साथ एक विश्वास जगा है। एक विश्वास जगाने का कार्य हुआ है प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक नया माहौल देने का कार्य हुआ है। जहां आवश्यकता पड़ रही है हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम लोग पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ-साथ, हरेक व्यक्ति तक सुरक्षा पहुंचाएंगे। सुरक्षा सबको देंगे लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। किसी का तुष्टिकरण नहीं सुरक्षा सबको। सारे पर्व-त्यौहार लोग अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार मनायें लेकिन एक दूसरे के पर्व और त्यौहारों में व्यवधान डालोगे तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा (मेजों की थपथपाहट)। हम लोगों ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज एक नया परसेप्शन उत्तर प्रदेश का जगा है। बड़े से बड़े आयोजन को हम संपन्न कर सकते हैं। वह कांवड़ यात्रा हो या फिर दीपोत्सव का उत्सव, रंगोत्सव हो या देव दीपावली, प्रयागराज कुम्भ हो या फिर उन सभी पर्व और त्योहारों को जिनको आप लोगों ने बंद करवा दिया था यानि थानों में जन्माष्टमी नहीं मनेगी, कांवड़ यात्रा नहीं जाने देंगे, डी0जे0 नहीं बजने देंगे।

(विपक्ष के सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। आपके समय में कोर्ट का आदेश था, हमारे समय में क्यों नहीं लागू हो पाया। कोर्ट का आदेश तो हमने लागू कराया है। कोर्ट ने कहा है कि डी0जे0 बजाने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई आदेश नहीं था लेकिन

आपका मनमानापन था क्योंकि आपको हिन्दू आस्था के साथ खिलवाड़ करना था, चिढ़ाना था क्योंकि जो कांवड़ भक्त थे उनकी ड्रेस से आपको चिढ़ थी लेकिन हमने सम्मान दिया है। हमने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, आप देखेंगे और यह एक उदाहरण है कि 25 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुम्भ में आए थे और 25 करोड़ श्रद्धालुओं में, एक ठेले वाला भी यह नहीं कह सकता कि किसी श्रद्धालु ने किसी ठेले वाले से जबरन एक मूंगफली का दाना भी ले लिया हो, कोई नहीं बोल सकता। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कांवड़ यात्री निकलते हैं और एक भी कांवड़ यात्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उसने किसी के साथ जबरन किया हो। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में साढ़े 5 लाख श्रद्धालु आए थे और पर्यटक भी आए थे परंतु कोई नहीं कह सकता। लाखों की संख्या में रंगोत्सव के कार्यक्रम में बरसाना में श्रद्धालु आते हैं, एक भी आरोप न महिला सुरक्षा से संबंधित है और न ही किसी व्यापारी, किसी आम नागरिक से, किसी भी जाति, मत और मज़हब को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। देव दीपावली काशी में होती है जहां 25 लाख श्रद्धालु आते हैं परंतु कोई शिकायत नहीं है। पूरे श्रद्धाभाव के साथ लोग आते हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी माघ मेला प्रयागराज में हुआ जिसमें ढाई से 3 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कहीं कोई तिनका नहीं हिल रहा है लेकिन कुछ लोग हैं कि 12-15 लोग जाएंगे और हाथों में तलवार लेकर जो दिखेगा, ऐसे मारेंगे-ऐसे मारेंगे और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए, उम्मीद करते हैं कि हम शांति से उनकी आरती उतारें ? यह नहीं हो सकता। कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। कानून सबको सुरक्षा देगा लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट हम किसी को नहीं देंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम सुरक्षा का वातावरण प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। महोदय, इसीलिए हमें इस बारे में आपसे स्पष्ट करना है। प्रदेश के अंदर जो एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है, उस बेहतर वातावरण को ही आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का परिणाम है कि प्रत्येक दिशा में प्रदेश का परसेप्शन तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास जगा है। मैं इस बात को कह सकता हूं चूंकि मैं एक मुख्य मंत्री हूं लेकिन आज से 3 वर्ष पहले प्रदेश के बारे में परसेप्शन क्या था, आपके बारे में लोग क्या सोचते थे, आज आप देश के अंदर कहीं भी जाएंगे तो आप चाहे सत्ताधारी दल के हों, विपक्ष के हों, केवल उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हों, इस नाम से ही आपको पूरे देश के अंदर सम्मान मिलना प्रारम्भ होगा। यह प्रदेश का परसेप्शन है। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उस धारणा का यह बजट है। यह बजट केवल सरकार का नहीं है, प्रदेश की उस धारणा का बजट है जिसको चेन्ज करने के लिए प्रयास शुरू से प्रारम्भ हुए हैं। आप चाहे सत्तापक्ष के हों, विपक्ष के हों सबका योगदान हो, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप असहमति के लिए बैठाए गए हैं तो आपको असहमति व्यक्त करनी ही करनी है, भगवान करे हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आप वहां रहें। लेकिन ये सहमति के जो स्वर हैं, वह हमने आगे बढ़ाने प्रारम्भ किये हैं।

सी0ए0ए0 के मुद्दे पर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम धरना-प्रदर्शन नहीं करने देंगे। हमने कहा भाई आप शान्तिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे दीजिये लेकिन आगजनी करेंगे तो प्रापर्टी से वसूली भी करेंगे क्योंकि ये मेरे घर की प्रापर्टी नहीं है।

(विपक्ष द्वारा टोका-टाकी और घोर व्यवधान के मध्य)

श्री इकबाल महमूद-

आप सबके मुख्य मंत्री हैं, आप केवल भाजपा के मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, तो कोई बात कहने की बीच में परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आप बैठें-आप बैठें, आपको अनुमति नहीं है। आप कृपया बैठें। आप लोग शान्त रहिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हमने इसी बात को कहा। हमने कहा सबको स्वतंत्रता है, सरकार संवाद बनाने पर विश्वास करती है। संवाद की भाषा में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक अधिकार किसी के सरकार लेने नहीं जा रही है। हर व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर सकता है लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में आगजनी करने की छूट सरकार नहीं देगी। तोड़-फोड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी और जिसने किया है, उससे वसूली भी करेगी। आप काहे परेशान हो रहे हैं।

(विपक्ष द्वारा टोका-टाकी और घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहिये। आप बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। आप बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप कृपया बैठें। आप क्या यहां भी विचार प्रकट नहीं करने देंगे। नेता सदन को नहीं बोलने देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है ? आपका जब नम्बर आया नेता विरोधी दल बोले तो कोई नहीं बोला। आप लोग बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता। यह तरीका ठीक नहीं है। आप शान्त रहिये। बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं। बिल्कुल गलत बात है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, हमने इसी चीज को लेकर कहा है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून को ले करके इतना बवाल क्यों ? मैं यही तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप लोग जो समर्थक बैठे हुए हैं उनसे मैं यहीं पूछना चाहता हूं कि आखिर देश की छवि को खराब करके आप क्या

प्राप्त करना चाहते हैं ? आखिर देश की छवि को खराब करके आप पाना क्या चाहते हैं ? देश की छवि में आगजनी करके, तोड़-फोड़ करके, निर्दोष लोगों को निशाना बना करके आखिर आप इसके माध्यम से साबित क्या करना चाहते हैं ? देखिये, एक बात को नोट कर लें, आप किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, ये कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है-कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गये होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलायेंगे तो ये नहीं हो पायेगा, कभी नहीं हो पायेगा। हम सुरक्षा सबको देंगे लेकिन अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि तोड़-फोड़ करके, आगजनी करके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट-पाट करके वह किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका हो तो उस गलतफहमी का हम बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए सी0ए0ए0 के नाम पर विरोध प्रदर्शन अनावश्यक है। ये नागरिकता देने का कानून है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कह चुके हैं कि किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने वाली है। ये नागरिकता का कानून 1955 में कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था, इसमें केवल एक संशोधन किया है 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की समय-सीमा कर दी है और उस सबके बावजूद वह बनायेंगे ठीक और हम बना देंगे तो बुरा। कोई जगह नहीं मिली तो इसी के नाम पर भ्रम पैदा करो। जगह-जगह अव्यवस्था पैदा करके जिस प्रशासनिक मशीनरी को डेवलपमेंट के कार्य के साथ जुड़ना चाहिये था आज आप लोग जबरदस्ती केवल कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उसकी ऊर्जा को दूसरी तरफ डायवर्ट कर रहे हैं और प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं और देश की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब देश दुनिया की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है और तब विपक्ष का इस प्रकार का रवैया अत्यन्त ही गैर जिम्मेदारानापूर्ण है, बहुत गैर जिम्मेदारानापूर्ण है। (मेजों की थपथपाहट) एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये इसे शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता है। इसीलिये मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि हम लोग गलतफहमी पैदा करना बन्द करें। हम सही तथ्यों को रखना प्रारम्भ करें। विरोध हम आमंत्रित करेंगे और सदन से अच्छा विरोध आप कहां दर्ज कर सकते हैं। इस सदन से बड़ा कौन मंच हो सकता है लेकिन सदन में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, रोज वेल में आना चाहेंगे, रोज एक ही मुद्दे को उठाना चाहेंगे और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह चीजें नहीं हो सकतीं। हम लोग आपका पूरा सम्मान करेंगे, पूरी तरह सम्मान देंगे, लेकिन प्रदेश के अन्दर 23 करोड़ जनता की सुरक्षा यह हमारा दायित्व है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ0 संग्राम यादव-

बिहार विधान सभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में वह हर कानून लागू होगा जो भारत की संसद जिस कानून को बनायेगी। (मेजों की थपथपाहट) भारत की सम्प्रभुता

के प्रति हमारा पहला दायित्व है। नेशन फर्स्ट, हम उस बात को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिये कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं, देश पहला होता है और देश में योग्य नेतृत्व है और उनके सानिध्य में पूरी व्यवस्था भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने की ओर अग्रसर है हम सब उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम लोग केन्द्र सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिये, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये, भारत को दुनिया की एक महा ताकत के रूप में स्थापित करने के लिये जो कार्य योजना बनाई गयी है हम उसको प्रदेश में भी लागू करेंगे और इसके लिये प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन भी करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने फोकस सेक्टर की जो अलग-अलग पालिसी बनाई है इसमें निवेश आ रहा है और इसमें सरकार की तरफ से जो इन्सेंटिव्स देने थे, उस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने तेजी से किया है। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि पालिसी किसी भी समय में बनी होगी पिछली सरकारों के समय में भी अगर कोई एम0ओ0यू0 हुआ है तो सरकार उसका पालन करेगी, उसको लागू करेगी। हम उसको भी लागू कर रहे हैं। एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं नये सिरे से हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है एयर कनेक्टिविटी, यानि देश का पहला स्वदेशी विमान हम उत्तर प्रदेश में उड़ाने जा रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) एच0ए0एल0 की मदद से। यह स्वदेशी विमान उत्तर प्रदेश में 19 सीटर विमान है अब तक एयरफोर्स और कोस्टगार्ड इसका इस्तेमाल करती थी अब उत्तर प्रदेश इसका इस्तेमाल करेगी अपनी यात्री सेवाओं की अभिवृद्धि के लिये। हम जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को, मुरादाबाद भी उससे जुड़ेगा, आप चिन्ता मत करिये। (मेजों की थपथपाहट)

(सत्ता पक्ष की ओर से अब तो ताली बजा दो की आवाजें)

नहीं-नहीं, असल में कुछ लोग ताली बजाने के पहले इधर-उधर देखते हैं कि कहीं बजा लें और कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरा देख ले और फिर शाम को वहां पर लाइन हाजिर न होना पड़े। इसलिये हम लोग हर जगह इसको जोड़ने जा रहे हैं। अब तक जो विमान फोर्स में इस्तेमाल हो रहा था वह विमान अब हमारी यात्री सेवाओं के लिये इस्तेमाल होगा। सस्ता किराया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा (मेजों की थपथपाहट)। उत्तर प्रदेश में स्वेदशी विमान के माध्यम से यह साकार हो चुका है, उड़ान योजना में साकार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला स्वदेशी विमान हमारी दो सिटीज को कनेक्ट करे, वाराणसी-लखनऊ को, गोरखपुर-लखनऊ को, लखनऊ-मुरादाबाद को, लखनऊ-आगरा को, लखनऊ-मेरठ को, लखनऊ-हिंडन को, झांसी को, प्रयागराज को जोड़े, उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा, इस बजट में हम लोगों ने अयोध्या के लिए भी एक बड़े एयरपोर्ट के निर्माण

की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है, एक इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि आखिर हमारे लिए आस्था के साथ-साथ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेन्टर अयोध्या बनने जा रहा है। अयोध्या की कनेक्टिविटी देश और दुनिया से हो, इंडोनेशिया को देखिये, आपको कुछ तो सीखना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश राम को अपना पूर्वज मानता है। क्या हो गया है, हम इस देश में रोटी खायें, इस देश में रहें और श्री राम से दुराव करें यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। मुझे याद है दीपोत्सव का आयोजन पहली बार जब अयोध्या में हुआ था तो हमारी इच्छा थी कि भाई दुनिया में राम की संस्कृति कहां-कहां है, वहां के कलाकारों को बुलाओ। संस्कृति विभाग ने बुलाया था, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहां बैठे हैं इन्होंने इंडोनेशिया के कलाकारों को बुलाया। इंडोनेशिया के कलाकार जब यहां आये थे तो वह मुझसे मिलने के लिए आये थे, अयोध्या में उनका मंचन मैंने देखा, बहुत अच्छा मंचन था। यहां पर वह मुख्य मंत्री आवास में मुझसे मिलने के लिए आये, जब मैंने नाम पूछा तो सभी नाम मुस्लिम नाम थे। जो राम बना था वह भी मुस्लिम, जो हनुमान बना था वह भी मुस्लिम, जो सीता बनी थी वह भी मुस्लिम, तो मैंने कहा कि भाई यहां तो राम के नाम पर बहुत सारे लोगों को करेंट लगता है, आप मुस्लिम होने के बावजूद राम को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब, राम हमारे पूर्वज थे, हमने उपासना विधि बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। मैं आपसे कहूंगा कि क्या आप लोग बोल पायेंगे। स्वागत करना चाहिए, स्वागत कीजिये।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)

अरे! आप भारत की बात कीजिये, आबूधाबी की बात मत कीजिये, आप भारत के नागरिक हैं।

श्री इकबाल महमूद (बैठे हुए)-

आप हम लोगों को क्या दे रहे हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

हमने तो पांच एकड़ जमीन दे दी है अयोध्या में। याद करना, एक बात बताऊं आपको, आपको भारत के इतिहास को देखना चाहिए। केरल में पहली मस्जिद एक हिन्दू राजा ने बनाई थी।

श्री इकबाल महमूद (बैठे हुए)-

आपने क्या दिया ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अरे भाई, मैं वहीं आ रहा हूं। हम उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए है, किसी जाति और मजहब के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए मुझे कार्य करना है, इसके लिए इस टीम को काम करना है और 23 करोड़

जनता के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, जाति और मजहब के लिए नहीं और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं।

श्री इकबाल महमूद (बैठे हुए)-

23 करोड़ में क्या मुस्लिम नहीं हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, इस दिशा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, अयोध्या भी उसी का पार्ट बन रहा है और मैं इसीलिए कहना चाहंगा कि यह प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर और बलिया लिंक-वे, एक-एक करके पूरे प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है 2024 तक देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यू0एस0 डालर इकोनॉमी बनाना, यू0पी0 भी 1 ट्रिलियन यू0एस0 डालर की उस इकोनॉमी को अचीव कर सके इसके लिए कार्य योजना को हम लोगों ने अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ाया है। महोदय, अभी हम लोगों ने नगर निकायों की तमाम ग्राम पंचायतों को, जो नगर निकाय बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी थीं, उनको हमने नगर निकाय के साथ जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, यानी नगरीय विकास के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाना है।

महोदय, जहां पर बिजली नहीं थी, एक करोड़ बीस लाख लोग ऐसे थे जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं था, आप क्या कर रहे थे कि वहां तक विद्युतीकरण नहीं पहुंच पाया। आप कैसे कार्य कर रहे थे, बिजली देने में भेदभाव कर रहे थे। कहते थे कि हमने इतना पावर जनरेट कर दिया है। अगर ये सभी एम0ओ0यूज0, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पावर परचेज एग्रीमेण्ट हुए हैं, अगर ये सब उजागर हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। ये प्रदेश की व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश के हिस्से थे ये सभी समाजवादी पार्टी सरकार के समय हुए थे।

(विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने सीट पर बैठे-बैठे यह कहा कि बेनकाब करिये, कार्रवाई करिये)

कार्रवाई हो रही है, फेज वाईज कार्रवाई होगी। अभी बहुत सारी कार्रवाई होने जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर असर नहीं पड़ा है, ये नोएडा में लूटा गया है। अभी हमने सी0ए0जी0 से नोएडा की 10 वर्ष की ऑडिट करायी है। 10 वर्ष में केवल नोएडा में 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला आया है (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)। जब मैं वर्ष 2002-2003 के बाद से प्रारम्भ करूंगा, तो क्या हाल होंगे। ग्रेटर नोएडा में भी यही स्थिति है, इसका भी करा रहे हैं। अगर करने शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे लोग यह बोलने लग जाएंगे कि देखिये साहब..। यह पैसा मेरा नहीं था, लेकिन प्रदेश की 23 करोड़

जनता का पैसा है और प्रदेश की 23 करोड़ जनता को उस पैसे को प्राप्त करने का अधिकारी बनना ही चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, इन सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन आपको दिखायी दे रहा है, इसी का परिणाम है। वर्षों की गन्दगी को एक झटके में साफ उसी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और ये एक्सप्रेस-वे का जाल भी प्रदेश के अंदर इसीलिये बिछाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन, देश का पहला वाटर-वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है, हल्दिया से वाराणसी के बीच (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। वाटर-वे का उपयोग हम कर सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बासमती चावल, गुड़, आलू, मकई भी हम यूरोप में भेज सकेंगे। एक-एक प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकें, इस दृष्टि से, इस प्रक्रिया से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके 60 फीसदी से अधिक हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताया है कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होने जा रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यह बोल सकते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है तो इससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होगा ? इसके अलावा और भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके बारे में भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है।

ऊर्जा क्षेत्र में भी कहीं सब-स्टेशन बनने हैं, कहीं फीडर के सेप्रेशन की कार्यवाही होनी है, कहीं अन्य छूटे हुए क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना है और भी अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने 34 हजार 5 सौ 43 करोड़ रुपये की व्यवस्था ऊर्जा विभाग के लिए इसमें की है।

लोक निर्माण विभाग में ग्रामीण सड़क हो, स्टेट हाइ-वे हो, इण्टर स्टेट कनेक्टीविटी का हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लाक/तहसील हेडक्वार्टर हों, इन सबको जोड़ने के लिए, पुलों के निर्माण के लिए डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर इस्टर्न, डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर वेस्टर्न में आर0ओ0बीज0 के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें 29 हजार 4 सौ 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था लोक निर्माण के मद में की है।

इसके अलावा सिंचाई विभाग की परियोजनाओं-बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और इससे संबंधित योजनाओं के लिए भी 17 हजार 121 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में करने की कार्रवाई की है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि पिछली बार हम लोगों ने जिन योजनाओं को पहले चरण में पूरा किया था बाण सागर, पहुंज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध, जमरार बांध इन परियोजनाओं को पूरा करके हमने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर लैंड को सिंचन की सुविधा दी है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा, जो सिंचाई की परियोजना है, अर्जुन सहायक नहर परियोजना है, इससे संबंधित जितनी भी अन्य

योजनाएं हैं इसमें चाहे वह कचनौदा बांध परियोजना है, भौरट बांध परियोजना है, उमरहट पम्प नहर परियोजना है, इन सभी योजनाओं को अगर लेंगे तो लगभग 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त लैंड को सिंचन की क्षमता हम इसके माध्यम से देने जा रहे है। और प्रदेश में एक अटल भू-जल योजना को भी इसके साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया है। महोदय, मेट्रो, हम लोग आये थे 2017 तक कोई भी मेट्रो की योजना उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं चल रही थी। कोई भी चालू नहीं हो पाई थी। हम लोग आये इसके बाद लखनऊ, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्यवाही हुई। आज कानपुर में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगरा में कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक परमीशन उसमें ली जा रही है। शेष अन्य शहरों में भी हम लोगों ने इस योजना को रखने की कार्यवाही की है। प्रदेश के अंदर मेरठ को आर0आर0टी0एस0 रैपिड रेल से जोड़ने के लिये, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ने की कार्यवाही के लिये धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र के विकास के लिये भी हम लोगों ने चाहे वह 10 सिटी हमारी स्मार्ट सिटी में चयन हुई थी। 7 अन्य को हम स्मार्ट सिटी में चयन कर रहे हैं। उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये लिक्विड वेस्ट के लिये हमारे यहां क्या कार्य योजना बन सकती है इसमें बनाने के साथ ही आवासीय योजना के लिये प्रधानमंत्री आवासीय योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, इन सबके लिये भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा में भी 77,599 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में इन सभी क्षेत्रों में की गई है। आपने देखा होगा इसमें हम लोग चाहे वह सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का हो, प्रयागराज में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हो, अटल आवासीय विद्यालयों के लिये भी 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिये और निराश्रित बच्चों के लिये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल के लिये हम लोगों ने बजट में व्यवस्था की है। प्रदेश में पुलिस एण्ड फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटी के साथ-साथ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक आयुष यूनिवर्सिटी के लिये भी हम लोगों ने बजट में इसकी व्यवस्था की है। मान्यवर, प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिये, पिछले तीन वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुआ। किसी भी किसान को अपने खेत में फसल जलाने की नौबत नहीं आई और प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान हुआ है। अब तक हम लोग 89 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में सफल हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) बंद चीनी मिलों के, मुझे याद है पिछले वर्ष में (व्यवधान) अभी 400 करोड़ के आस-पास बकाया है लेकिन 89 हजार करोड़ रुपये की तुलना में अगर आप देखेंगे और अपने कार्यकाल के समय को आप देखेंगे तो यह व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। (व्यवधान) और उसके लिये भी बजट में 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आपने अगर बजट पूरा पढ़ा होता तो आप यह प्रश्न मुझसे पूछते ही नहीं। मैं क्या कह

रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर यह हो रहा है लेकिन हमने इसके लिये व्यवस्था की है। गौ-आश्रय स्थल, मैं देखकर आश्चर्य करता हूं कि पिछले सत्र में मैंने कहा था बार-बार उसी प्रश्न को बार बार दोहराया जाता है कि निराश्रित गोवंश घूम रहा है, आवारा गोवंश घूम रहा है। सरकार ने उसके लिये पांलिसी बनाई है। सरकार ने उस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। निराश्रित गोवंश के लिये आश्रय स्थल बने। सरकार ने इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया। आज हमारे पास साढ़े चार लाख गोवंश निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार उनके लिए चारे की व्यवस्था कर रही है। हमने सभी जिलों को और सभी निकायों को इस बारे में कहा है कि जनपद स्तर पर मनरेगा की धनराशि का उपयोग गौवंश के लिए केयरटेकर के रूप में कर सकते हैं। हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि जो पराली खेत में आती है, उस पराली को किसान आग न लगायें, बल्कि मनरेगा के माध्यम से मजदूर लगा करके उस पराली को एकत्र करके इन सभी निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों पर पहुंचाने की व्यवस्था करवा लें, यह एक बड़ा कार्य होगा। यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि अगर कोई किसान या कोई नागरिक किसी निराश्रित गौवंश को अपने घर में रखकर पालना चाहता है तो हम उस किसान को 900 रु0 प्रति गौवंश प्रतिमाह देने की कार्यवाही करेंगे। 900 रु0 प्रति गौवंश हर महीने हम लोग दे रहे हैं और लगभग 50,000 गौवंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों से निकलकर उन किसान परिवारों के पास हैं, जो पशुपालन के रूप में उन गौवंश की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा निराश्रित गौवंश के साथ-साथ नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यवाही तेजी के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पराली की समस्या का समाधान भी होगा और इसको हम वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम सरकार का ही नहीं विपक्ष का और इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। जो लोग पहले गौवंश की तस्करी करवाते थे, गौवंश को कटवाते थे, जब हम गौ-आश्रय स्थल बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि प्रदेश में हम गौ-तस्करी भी नहीं होने देंगे, अवैध बूचड़खाने भी नहीं चलने देंगे और गौ माता को किसी कसाईखाने भी नहीं जाने देंगे। हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। यह सरकार उसके संवर्धन की दिशा में भी कदम उठायेगी और हमारी यह कार्यवाही प्रदेश के अन्दर चल रही है। चीनी मिलों की दिशा में भी कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। नई चीनी मिलें, रमाला चीनी मिल, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की मिल थी, एक्सपेंशन नहीं हो पा रही थी, नए सिरे से और नए सत्र में इस मिल को चलाया गया। 30 वर्षों से मांग हो रही थी, क्या कर रहे थे ? 10 वर्षों में 21 चीनी मिलें बेची गयीं। हमारी सरकार के समय चीनी मिलें बेची नहीं गयीं बल्कि बन्द चीनी मिलों को चलाया गया या उनके स्थान पर नयी चीनी मिलों को लगाया गया। खांडसारी उद्योग के लाइसेंस के नाम पर लोगों से जबरन वसूली होती थी, हम लोगों ने उनको लाइसेंस फ्री करके लाइसेंस दिया है। 6 चीनी मिलों के बराबर लोगों को रोजगार और चीनी मिलों के

बराबर वहां पर खांडसारी और अन्य उत्पाद बनने प्रारम्भ हुए हैं। यह चीजें वहां पर देने की कार्यवाही प्रारम्भ की है। प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने प्रक्यूरमेन्ट की अपनी नीति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही की है। धान, गेहं, दलहन, तिलहन, मकई, आलू इन सबको आगे बढ़ाने के साथ-साथ मंडियों के सुन्दरीकरण और E नाम के साथ मंडियों को जोड़ने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हुई है। प्रदेश के अन्दर किसानों की समृद्धि के लिए और भी जो कदम उठाए जा सकते हैं, इस दिशा में सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। अभी कल ही हमारी कैबिनेट ने 15000 करोड़ रुपये की लागत से बुंदेलखण्ड और बिन्ध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल की योजना को स्वीकृति दी है। बुंदेलखण्ड में सातों जनपदों में इसी मार्च महीने में हम लोग कार्य प्रारम्भ कर देंगे। हर घर नल की योजना को हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कार्यवाही भी हम लोग कर रहे हैं। बुंदेलखण्ड में और उसके साथ ही बिन्ध्य क्षेत्र में भी हम लोग मिर्जापुर और सोनभद्र में इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। 15000 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। इस बजट में भी हम लोगों ने 3300 करोड़ रुपये इस योजना के लिए उपलब्ध कराये हैं। 3000 करोड़ रुपये विगत वर्ष भी हम इसके लिए उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आजीविका के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भी जिसमें महिला स्वयं सेवी समूह गठित करके उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर किया जा सके इसके लिए भी एक हजार 672 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से करने की तैयारी की गई है। जिससे उन सभी लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए उन सभी का हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। महोदय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के माध्यम से 17, 821 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है चिकित्सा शिक्षा के लिए 6 हजार 916 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है यह व्यवस्था करने की तैयारी हुई है। इसमें बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 का एक सेटेलाइट सेंटर श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई जी की प्रथम कर्मभूमि थी बलरामपुर वहां पर हम इस कार्यक्रम को एक नए मेडिकल कालेज के रूप में विकसित करेंगे के0जी0एम0यू0 के सेटेलाइट सेंटर को उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्यवाही करने जा रहे हैं। यह कार्य प्रदेश के अन्दर हर एक क्षेत्र में हुआ है इसी दृष्टि से महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए भी 19,934 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है विभिन्न वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि छात्रों की छात्रवृत्ति के मद में धनराशि की कमी न पड़ने पाए इसके लिए सरकार ने पहले से ही विभिन्न विभागों को स्पष्ट हिदायत दी है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के सभी बच्चों के साथ-साथ जो एक पात्रता की प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया और पात्रता के अनुसार दो अक्टूबर और 26 जनवरी छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति की तिथि तय करते हुए। उनके खाते में हम इस धनराशि को पहुंचा सकें इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है और पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में उन सभी मदों के करने का कार्य भी किया गया है

जिसमें उन लोगों को यह सुविधा यहां पर प्राप्त हो सकती है मुझे लगता है कि हर एक विभाग के लिए अलग-अलग मदों के लिए व्यापक कार्य योजना के साथ इस बजट में प्राविधान करने का कार्य किया गया है। इसमें संस्कृत के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ 51 लाख रुपए, काशी विद्यापीठ के लिए 21 करोड़ रुपए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहां पर करने का कार्य बजट के माध्यम से करने का कार्य किया गया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि बजट में प्रत्येक तबके का पूरा ध्यान रखा गया है चाहे वह गांव हो, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हों, या फिर समाज के किसी भी तबके का हो उन सबके हितों को ध्यान में रखकर इस बजट को यहां पर वित्त मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बजट के माध्यम से प्रदेश की विकास की एक नई उड़ान हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। उस उड़ान में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग कभी भी इस बात को नहीं कहे कि सदन का मतलब सरकार को हम लोगों ने नहीं माना हमारा मानना है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे यह दोनों लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को, संवाद की भाषा को, जिसमें सहमति और असहमति होती है इन दोनों के बीच में संवाद बनाना और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करना यही सदन का कार्य है और सदन इसी कार्य को आगे बढ़ाता है। हमारी विभिन्न मुद्दों पर असहमति हो सकती है लेकिन उस असहमति का मतलब यह नहीं होता है कि हम लोग देश की संप्रभुता को चुनौती दें हम लोग नागरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने उठ जाएं हम कानून को बंधक बना लें यह चीजें नहीं हो सकती हैं मैं फिर आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। असहमति के स्वरों पर कहीं रोक नहीं है कहीं विराम नहीं है लेकिन संविधान के दायरे में रहकर हमें एक लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी और लक्ष्मण रेखा के अन्दर अगर हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी और यह बजट उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश को विकास की एक नयी ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने वाला बजट है जो 2024 तक वन ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकोनामी बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) उत्तर प्रदेश उस दिशा में एक लम्बी छलांग लगायेगा। याद करिये, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी, 2018 को यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के दौरान इस बात का एक लक्ष्य हमें दिया था कि क्या उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकोनामी को प्राप्त कर पायेगा। यह हमारे लिये एक अवसर है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देश को फाइव ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की दृष्टि से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महा ताकत के रूप में तेजी से उभरती हुयी एक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़े, यह केवल सत्तापक्ष का ही दायित्व नहीं है, यह आपका भी

दायित्व बनता है और यह बजट उसी वन ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकोनामी का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है जहां पर तीन लाख करोड़ से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ की सीमा पार कराने की दिशा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया गतिमान है और जिसमे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जनता की बुनियादी सुविधाएं, गांव के लिये, गरीब के लिये, किसान के लिये, नौजवान के लिये, महिलाओं के लिये और समाज के प्रत्येक तबके के लिये कार्य करने का कार्य किया गया है। हर एक के लिये कार्य हुआ है। कार्य की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। चाहे वह 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का हो, शौचालय का हो, 'सौभाग्य योजना' में बिजली के कनेक्शन का हो, 'आयुष्मान भारत' में या 'मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना' में पांच लाख रुपये का लाभ देने का हो, पशुपालन विभाग में नयी डेयरियों की स्थापना के साथ-साथ खुरपका और मुंहपका को पूरी तरह समाप्त करके दुग्ध उत्पाद को हम दुनिया के अन्दर भी भेज सकें और इस प्रक्रिया का हिस्सा बना सकें, यह सब उसी दिशा में किये जाने वाले प्रयास है और मैं चाहूंगा कि इस बजट में वित्त मंत्री जी को कम से कम आपकी सराहना तो मिलनी चाहिये। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) कम से कम एक बार आप लोग उनकी तारीफ तो कर दीजिये। दोनो चाहेंगे कि वित्त मंत्री आपके अनुरूप बजट भी बनायें और उसके बाद भी आप उनका विरोध करेंगे।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

अगर आज ही बोल देंगे तो फिर 28 को क्या बोलेंगे। फिर 28 को आयेंगे ही नहीं। इसलिये मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा नहीं तो अनावश्यक रूप से आप लोग इसको बहुत आगे बढ़ायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक संतुलित, विकासोन्मुख, समाज के प्रत्येक तबके के हितों का संवर्धन करने वाला और सबका साथ सबके विकास का प्रतिनिधित्व करके सबके विश्वास पर खरा उतरने वाले इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी को तथा उनके साथ प्रमुख सचिव के रूप में उस समय सचिव के रूप में कार्य करने वाले श्री भुवनेश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, वित्त विभाग की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा पूरे देश के अन्दर हुयी है, लोगों ने इसको सराहा है। मोना जी को भले ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ की थी और मैं विश्वास करूंगा कि यह लोग यहां सदन में दल से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में सही बात बोलने का साहस करेंगे। मैं एक बार फिर से उन सभी दलीय नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस बजट में भाग लिया और अपने सुझाव दिये हैं, उन सबका अभिनन्दन करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और विशेष तौर पर वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ बजट को बनाने और सदन में प्रस्तुत करने में योगदान दिया। आज बजट पर उनका अन्तिम भाषण यहां

पर होना भी है और उसके साथ ही बजट पास होगा, इसके लिये मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी इकोनामी बनाने में सफल होंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा 'जय श्रीराम-जय श्रीराम' बोला गया)

विधायकों की सैलरी, भत्तों व विधायक निधि को बढ़ाये जाने की मांग

***श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। सन्त तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है।

''जो बालक कछु अनुचित करहीं।
गुरु पितु मातु बोध अनुसरहीं।।''

अगर इधर से या उधर से कोई बात किसी ने कही हो तो मैं समझता हूँ कि मैं सबकी ओर से क्षमा चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में यह भी लिखा है।

''मोर मनोरथ जानऊँ नीके। बसहु सदा उर पुर सबही के।।
सो तुम्ह जानऊँ अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।।''

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के सारे सदस्य चाहे इधर हों, चाहे उधर हों बहुत आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहे हैं। पिछले तीन बजट आये ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाये हैं। किन्तु जो यह कहना चाहते हैं आज इनकी तरफ से मैं आपके सामने इनकी भावनायें रख रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप लोक सभा में सांसद थे आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सांसदों के वेतन भत्ते सुख सुविधा के लिए संस्तुति की थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपने 4 गुना बढ़ाने की बात कही थी। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) मैं चार गुना बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ यह आपकी मर्जी पर है। लेकिन मैं आपके सामने यह जरूर कहना चाहूँगा कि आपसे हमारा अनुरोध है कि विधायकों की सैलरी और सभी भत्तों को भारतीय संविधान प्रदत्त प्रोटोकाल के अनुरूप महंगाई इंडेक्स से जोड़ देना चाहिए। जिससे सदन को बार-बार इस बात से सांसदों को यातना न करनी पड़े अगर महंगाई इंडेक्स से जुड़ जायेगा तो वेतन भत्ता, सब अपने आप बढ़ जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी एक पीड़ा इन लोगों ने मुझसे और कही है कि जब इनको साढ़े चार लाख रुपये मिलता है रेलवे कूपन के रूप में उसमें तीन लाख रुपये डीजल के लिए कट जाते हैं सवा लाख के आस-पास शायद बचता है यात्रा करने के लिए। सवा लाख रुपये में इन लोगों को उस समय बड़ी हीन भावना का अनुभव होता है जब ये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हवाई जहाज में बैठते हैं और इकोनामिक क्लास में बैठते हैं और जब सचिवालय के अधिकारी इजीक्यूटिव क्लॉस में बैठते हैं तो इनको बड़ी शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है। मैं मांग करता हूँ कि जो रेलवे कूपन मिलता है उसको भी बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है हमारे प्रोटोकाल का अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हम किससे कहने जायेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि आप माता हैं, पिता हैं और गुरू हैं। इसलिए मैंने आपके सामने यह बात रखी है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोटोकाल अगर मुख्य सचिव के प्रोटोकाल के बराबर है या ऊपर है तो कम से कम हम लोगों के प्रोटोकाल की रक्षा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी उनसे वेतन चाहे मेरा एक रुपये ज्यादा हो लेकिन प्रोटोकाल की रक्षा होनी चाहिए। मैं बहुत आभारी रहूँगा। बहुत आशा के साथ सारे विधायकों ने मुझसे जब कहा तो मैं भी अपने आपको नहीं रोक पाया। हालांकि इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह कह नहीं सकते हैं। मैंने सबकी ओर से आपसे निवेदन किया है और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस छोटी सी मांग को जो सारे विधायकों की है पूरी की जाये।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मुझे बजट शायद पसन्द आया हो या न हो पर आलोचना करना मेरी मजबूरी है तो मैं इतना कहना चाहती हूं कि भले ही मैं सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत इस वित्त बजट की आलोचना करूं न करूं पर सुरेश जी की इस बात का पूरा समर्थन करती हूं और उसमें एक बात जोड़ भी देना चाहती हूं। वे बेचारे विधायक निधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव हम सब लोगों ने दिया था वह भूल गये, वह 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी आज मुस्कुरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश जी के समर्थन में आपको एक घाटा है, कल वह कहेंगे कि भाजपा में काम करो।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जब माहौल खुशनुमा होता है तो मुझे लगता है कि उसमें अपनी बात रखने का प्रतिफल भी अच्छा होगा। चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कैसे विकास होगा, उसकी रूप-रेखा उन्होंने रखी कि हम किन-किन सेक्टरों में किस-किस रूप में विकास करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह है कि जिस तरह से जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है या जब संविधान बना हुआ होगा और जब 403 विधान सभाओं की संरचना हुई, इसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि जब इस प्रदेश को 403 भागों में बांट कर विकास करेंगे। उसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य उद्देश्य यही था और यही नहीं हम लोगों को भी जो हमारे जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं किसी को चेक काटने का पावर नहीं है। हम अधिक से अधिक प्रस्ताव ही करते हैं और इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी बेहतर समझते हैं क्योंकि वे एक बहुत लम्बा कार्यकाल सांसद के रूप में व्यतीत कर चुके हैं और पूरे पूर्वान्चल में बहुत इनके दौरे हुआ करते थे। मान्यवर, जब हम क्षेत्र में जायेंगे वहां कोई न कोई पीड़ित अपनी दवा के लिए कहेगा लेकिन ज्यादा संख्या में लोग कहते हैं कि हमारे यहां मुहल्ले का पानी नहीं निकल पाता है हम लोगों के घरों के सामने गड्ढे बनाकर गन्दा पानी इकट्ठा करते हैं, नाली बनवा दीजिए या कोई यह कहता है कि सी0सी0 सड़क बनवा दीजिए लेकिन हमारे पास रुपया कितना है ? हम यह भी नहीं कहेंगे कि हम चेक काटेंगे हम केवल पी0डब्लू0डी0 को या सी0डी0ओ0 को प्रस्ताव लिखते हैं कार्यदायी संस्था से आगणन बनवाकर या इसका इस्टीमेट बनवाकर काम करवा लें। हम इतना ही कहते हैं कि काम आप करा दें। मुझे नहीं लगता है कि डेवलेपमेन्ट करने के लिए इन 403 क्षेत्रों से बेहतर कोई और भी सल्यूशन होगा। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा आप चाहे दिल्ली में देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप अन्य प्रदेशों में देख लीजिए, हमारी पापुलेशन देख लीजिए, हमारे एरिया देख लीजिए 10-10 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी जो विधायक निधि है, जोकि आज बिल्कुल न के बराबर है जो मेरा है भी नहीं है हम केवल सुझाव दे सकते हैं मैं आपके माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं कि प्रत्येक विधान सभा में 10-10 करोड़ की विधायक निधि कर दी जाये। यह मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

कोई वेतन पर तो चर्चा हो नहीं रही, सुविधाओं पर चर्चा नहीं हो रही है।

***श्री नितिन अग्रवाल-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, माननीय श्रीवास्तव जी ने और मोना जी ने विधायक निधि बढ़ाने की बात की इसका समर्थन सभी सदस्य करते हैं, लेकिन एक अनुरोध माननीय नेता सदन से और है। आज आप आये हुए हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और बजट भाषण के बाद मुख्य मंत्री जी विधायकों को हैण्डपम्प और सड़कों का भी तोहफा देते हैं। मैं मांग करता हूं और अनुरोध करता हूं माननीय नेता सदन से कि 10-10 करोड़ के प्रस्ताव सभी विधायकों की सड़कों का भी ले लें और अबकी बार हर विधायक को 100-100 बारात घर उनके विधान सभा क्षेत्र में दे दें।

श्री नितिन अग्रवाल-

क्योंकि देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमारी बहन-बेटियों की बारात आती है तो बारात के लिए जगह नहीं मिल पाती है, इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी प्रत्येक विधायक को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100-100 बारातघर उनके विधान सभा क्षेत्र के लिए दे दीजिये। सभी विधायकगणों की इच्छा है कि जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उनको एक-एक प्लाट लखनऊ में अवश्य दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दे दीजिये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को भी अपनी बात कह लेने दीजिये।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट हमारी बात पूरा सदन सुन ले। हमको निवेदन करना है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप हम सभी माननीय सदस्यों की ओर से बोल दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सबकी ओर से तो हम बोलते ही हैं, लेकिन हम अभी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से बोल रहे हैं। श्री सुरेश जी और कई मित्रों ने अपनी बातें कहीं। ऐसा लगता है कि उन बातों को लेकर यहां पर लोग ज्यादा गम्भीर नहीं हैं। हंस ज्यादा रहे हैं और बात कम कह रहे हैं। अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनको ध्यान से सुनने का प्रयास किया है, लेकिन सब लोग एक साथ चिल्ला रहे थे तो वह सुना नहीं जा सका। अगर आप सब शांतपूर्ण वातावरण में अपनी बात कहें तो हम सुन लें। अब देखते हैं कि क्या आप शांत रह पायेंगे।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सरकार से और मा0 मुख्य मंत्री जी से दो-तीन निवेदन करना चाहते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया उसमें समानता की तमाम बातें कही हैं। हम भी एम0एल0ए0 हैं और आप लोग भी सब एम0एल0ए0 हो। विगत दो वर्षों में विपक्ष के विधायकों के प्रस्ताव पर पांच-पांच करोड़ रुपये के प्रस्ताव नहीं लिये गये हैं। हमारा मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि सत्तापक्ष के विधायकों से जिस तरह पांच-पांच करोड़ रुपये के प्रस्ताव लिये गये हैं उसी तरह विपक्ष के विधायकों से भी प्रस्ताव लिये जायें। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि पिछले वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी भी मा0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक को हैण्डपम्प नहीं मिले हैं। हम चाहे सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों हमारे क्षेत्र में कहीं आग लगती है, कहीं वंचित परिवार बहुत दूर रहता है तो जहां नल नहीं है वहां हम उसे नल नहीं दे पाते हैं इसलिये सरकार प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में पांच-पांच सौ हैण्डपम्प देने का काम करे। हमारा तीसरा अनुरोध है कि हम आप शहर अथवा ग्रामीण क्षेत्र के एम0एल0ए0 हैं, छात्रावास में, स्कूल में, धर्मशाला में, मठ में, मन्दिर में हम अपनी क्षेत्रीय विधायक निधि से गीजर देना चाहते हैं लेकिन वहां नहीं दे पाते हैं। हम अपने क्षेत्र की सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 की ओ0टी0 में जाते हैं तो वहां ए0सी0 नहीं है। जनरल वार्ड में वहां ए0सी0 नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारी विधायक निधि से आप गीजर का प्राविधान और ए0सी0 का प्राविधान करवा दें।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, अब आप लोग समाप्त करिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

''कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।''

श्री लाल जी वर्मा-

आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी शेरो-शायरी के साथ यहां पर अपना भाषण दिया है तो उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक शेर और सुना दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने अभी एक शेर सुना तो दिया है। अब बाकी शेर वह आज शाम को पांच बजे सुनायेंगे। आप पांच बजे सुनायेंगे ना ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय सदन की भावना से मुख्य मंत्री अवगत हैं और आज आखिरी दिन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी मुस्कान से यह लोग मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है (सदन में हंसी के ठहाके)।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी जो भी चाहे उमाशंकर जी ने कहा हो, चाहे हमारे वर्मा जी ने कहा हो या अग्रवाल साहब ने कहा हो या कांग्रेस की नेता ने कहा हो अभी तक यह परम्परा रही है

कि जिस दिन हाउस का अंतिम दिन होता है उसी दिन इस परम्परा को विशेष रूप से देखा जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अवगत हो गये हैं और सभी की भावना से जानकारी भी मिल गयी है कि लोग क्या चाहते हैं और वह जिस अंदाज में यहां पेश किया गया है वह तो पूरे सदन की भावना है ? (सदन में हंसी) लेकिन जैसे कहते हैं न कि प्रतीक्षा में मजा ज्यादा रहता है। आज बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के सभी विषयों के ऊपर, कार्य योजना पर, प्रगति पर और भविष्य की योजना पर जिस अंदाज में प्रकाश डाला है, मैं विशेष रूप से नेता सदन को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने आज जो प्रस्तुत किया है उससे एक बात निश्चित है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का अपना कोई निजी एजेंडा नहीं है। माननीय मंत्री जी का सुबह उठने से ले करके रात को सोने तक केवल एक ही एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के हालात कैसे बदलें ? आम आदमी की पर-कैपिटा इनकम कैसे बढ़े ? प्रदेश तरक्की के मार्ग पर दिनों-दिन कैसे बढ़े ? यह उनके वक्तव्य से परिलक्षित होता है। मैं हृदय से माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं।

विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की सूची को समीक्षणोपरान्त नवीनीकृत किया जाना

श्री अध्यक्ष-

एक अनुरोध हमारा भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी सुन लेंगे तो सम्भवतः हो जाएगा। इस सदन में कई बार विषय आता है कि विधायक निधि से कराये जाने वाले कामों की सूची का। यह काम पहले कभी तय हुए होंगे कि इससे क्या-क्या हम लोग करा सकते हैं, तो परिस्थितियां बदली हैं इसलिए मेरा यह सुझाव है कि विधायक निधि से कराये जाने वाले कामों के बारे में एक बार पुरर्विचार किया जाना चाहिए कि कौन-कौन से काम बढ़ा सकते हैं और कौन-कौन से काम घटा सकते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, यह पूरा सदन इस बात का अधिकार रखता है कि विधान मण्डल से जुड़ी हुई जो यह निधि है, इस निधि का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें और अधिक से अधिक जरूरतमंद उन योजनाओं से लाभान्वित हो करके शासन के एक अच्छे परसेप्शन के साथ जुड़ सकें। मुझे लगता है कि पीठ के द्वारा जो भी इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी होंगे उस सम्बन्ध में मुझे लगता है कि यदि एक सर्वदलीय कमेटी गठित होती है तो उसकी सिफारिश ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल ठीक है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, और वह सिफारिश लेने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसमें सहमत होगी (सदन में मेजों की थपथपाहट)।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि एक सर्वदलीय कमेटी बन जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आ गया है और इससे बढ़िया क्या हो सकता है ? अब मद संख्या-14 से मद संख्या-48 तक जो याचिकाएं यहां उपस्थित की जानी थीं वह सभी याचिकाएं उपस्थित की हुयीं तथा सदन में पढ़ी हुई मानी गयीं।

श्री मो0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित चार याचिकाएं व जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित दस याचिकाएं†

श्री मो0 फहीम इरफान की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी अन्तर्गत प्रकेश्वर शिव मन्दिर ग्राम बेरनी से स्योंडारा बिजली घर डारनी बिलारी मार्ग तक नवीन डामर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी अन्तर्गत ग्राम मैनपुरी से पैगारफातपुर होते हुये जहाँगीरपुर तक नवीन डामर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री छन्नू मीणा पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम मैनपुरी पैगारफातपुर, तहसील चन्दौली जनपद सम्भल व अन्य की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम सिसौना के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुये गौरा शाहगवारा में बघवत बाबा का पोखरा का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम कूबरी मानक सम्पर्क मार्ग से पहाड़पुर डोहरी, श्याम सिंहपुर भंड़ी होते हुये जरगांव स्टेशन तक नवीन डामर मार्ग निर्माण सम्बन्धी श्री महबूब व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम चिड़ियाठेर से पीतपुर तक नवीन डामर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री खुर्शीद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बाछलभंड़, जनपद मुरादाबाद व अन्य की याचिका,

6-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के अन्तर्गत ग्राम गुलड़िया कला से हुलासननगर होते हुए खबड़िया जाहरवीर थान तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री यासीन व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम गौराशाहगढ़ से नया गांव होते हुए मंगूपुरा तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम मण्डवा सम्पर्क मार्ग से नमैनी उदैया होते हुए बेहटा सरथल तक नवीन डामर मार्ग के सम्बन्ध में श्री मो0 हसनैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम नगला कमाल मार्ग से सराय पंजू होते हुए ग्राम हरियाना तक नवीन डामर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुशाहिद खां व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

10-जनपद मुरादाबाद में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर शेष जिलों की भांति सम्भल की त्रिस्तरीय पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन कर विसंगतियाँ दूर करने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

11-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम ईसापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम मुडिया भीकम परिषदीय विद्यालय तक नवीन डामर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री मो0 रियाज व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

12-जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के 25 हजार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का बीते चार वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में श्री नफीस अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

13-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से परिषदीय विद्यालय मो0 इब्राहिमपुर होते हुए चन्दौसी मार्ग तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

14-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के अन्तर्गत ग्राम चैंचरी से ग्राम अटवा के सम्पर्क मार्ग तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री प्रतीक भूषण, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री प्रतीक भूषण की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के विकास खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा शहर के बाहर लखनऊ-गोण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग से गोण्डा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा गोण्डा-बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन रिंग रोड बनाकर जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अयोध्या शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के विकास खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोण्डा के सीवर लाइन को अण्डरग्राउण्ड किये जाने के सम्बन्ध में सुश्री नेहा त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद गोण्डा की तसहील गोण्डा के विकास खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोण्डा के सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत लाइन को अण्डरग्राउण्ड किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक अग्रवाल निवासी न0पा0प0 जनपद गोण्डा व अन्य की याचिका।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत तथागत गौतमबुद्ध के महानिर्वाण स्थली कुशीनगर में भव्य आडिटोरियम भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शक्ति पाठक व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ऐतिहासिक, पौराणिक व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कस्बा कुबेरस्थान व आस-पास के घनी आबादी वाले गांव को मिलकर नगर पंचायत सृजित करने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के थाना कसया के थाना प्रभारी का निवास थाना परिसर में उपलब्ध भंमि पर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुडवा उर्फ दिलीपनगर जो सब्जी उत्पादक बाहुल्य ग्राम सभा है, मण्डी समिति कसया तक आने के लिए सुगम पिच मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद कुशीनगर की विधान सभा कुशीनगर के ग्राम रामबर बुजुर्ग बाजार टोला पर पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री रजनीश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद कुशीनगर में महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों पर परिवहन निगम के बसों के संचालन के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद कुशीनगर में गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में किसानों की सुगमता हेतु मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 देश दीपक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका परिषद कुशीनगर के नगरपालिका प्रशासनिक/कार्यालय जर्जर जीर्ण-शीर्ण व परित्यक्त अनकूल भवन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री राजू मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

9-जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भटवलिया, न्याय पंचायत सखवनिया, तहसील कसया, ब्लाक पडरौना में पंचायत भवन का निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती रीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ सोनकर की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद वाराणसी में विकास खण्ड चोलापुर के ग्राम धौरहरा में सुरेश प्रसाद वाया जयराम सोनकर के घर से श्री मुस्ताक की दुकान तक लगभग 300 मी0 लम्बे सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट रोड पर आर0टी0ओ0 आफिस से ग्रामसभा रमईपट्टी तक जर्जर लगभग 1.5 कि0मी0 लम्बे सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद वाराणसी के ग्राम निहालापुर में राजकरन पटेल के मकान से लालचन्द सरोज के समाधी स्थल तक लगभग 1.0 कि0मी0 लम्बे सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकरन व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री पंकज सिंह की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के ग्राम आगाहपुर में शमशान घाट/मरघट की चहारदीवारी के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर-19 में पानी की समस्या के सम्बन्ध में श्री एस0एस0 राणा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के ग्राम नयागांव में बारातघर का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक भाटी निवासी ग्राम नयागांव सेक्टर-87 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर व अन्य की याचिका।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

जनपद बस्ती में एन0एच0-28 दुधौरा से चन्द्रभान के घर तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शत्रुहन प्रसाद मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सरवा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम कुमार यादव निवासी ग्राम सरवा, विकास खण्ड हुजूरपुर, जनपद बहराइच व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री सत्यवीर त्यागी की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जिसौरी से ग्राम शफियाबाद लौटी तक ब्लांक-खरखौदा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री बलराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम अल्लीपुर से ग्राम एतमादपुर तक ब्लांक-माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री किरण व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम खासपुर से ग्राम कैली तक ब्लाक खरखौदा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131-कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत जैतीपुर में राजकीय नलकूप की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्रीमती निर्मला संखवार की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम पंचायत सजावारपुर डामर रोड से सुन्दरलाल पांडेय के खेत तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलबाद के ग्राम सभा नोनारी बहादुर औनाहा में बारात घर बनाये जाने के संबंध में श्री अवधेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड झींझक के गाँव कुदौली से सबलपुर तक नवीन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री शीतल पाण्डेय की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित ही हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में ग्राम जिगिना विकास खण्ड सहजनवा से फरसाडाड पिच मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

2-जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में चडरावं ठाठेवारी होते हुए घघसरा तक मार्ग को पक्का बनवाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप सैनी व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री धनन्जय कन्नौजिया की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया की नगर पंचायत बलिया के अन्तर्गत जनता इण्टर कालेज के परिसर में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में श्री आलोक शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बलिया के अन्तर्गत ब्लाक सियर में चौकिया मोड़ से पिपरौली बड़ा गाँव होते हुए उभाव सिकन्दरपुर मुख्य मार्ग तक डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 दयानन्द वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद बलिया के अन्तर्गत ब्लाक सियर की ग्राम सभा बरौली में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बलिया के अन्तर्गत ब्लाक सियर में ग्राम सभा खन्दवा में सार्वजनिक विवाह भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद बलिया के अन्तर्गत ब्लाक नगरा तहसील बेल्थरा रोड में ग्राम सभा भीमपुरा में सार्वजनिक मंदिर एवं छठ पूजा हेतु पोखरे का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री सूर्यप्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

जनपद लखनऊ के एल्डिको-2 के अन्तर्गत रक्षाखण्ड, रायबरेली रोड में गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण एवं दोनों तरफ बनी हुई नालियों की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अन्नपूर्णा दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएं व जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री असलम अली की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम मसूरी से ग्राम नाहल तक टूटे पड़े मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फरियाद व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर में जिन्दल नगर के एन0एच0-09 से ग्राम मोहिउद्दीनपुर ढबारसी तक जर्जर टूटे पड़े मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इस्तेखार व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम पिपलेहड़ा से भंडगढ़ी तक के कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुलेमान भाटी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद हापुड़ के विकास खण्ड हापुड़ के ग्राम सरावा में शमशान घाट व कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर बने नाले पर पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अली व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में निकट मकदूम साहब मजार के पास में मेन रोड पर स्थित जर्जर नाले के पुल का नवनिर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी रफीक व अन्य की याचिका।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

डा0 डी0सी0 वर्मा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम अमौर से पंथरिया तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम पस्तौर से ग्राम पट्टी गन्ना सेन्टर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम कपूरपुर से मीरगंज सिरौली मार्ग तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम नगरिया कल्याण से वाया संजरपुर जौनेर तक रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जितेन्द्र गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम अब्दुल्लागंज से सलामतगंज होते हुए आजमतगंज तक रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चेतराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहिपुरा जागिर टीहर खेड़ा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बैरमनगर से सुकटिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम ओंध से बैकेनिया चम्मतपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चक्रवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मुहम्मदपुर में अजयपाल सिंह गुर्जर के घर से रामेश्वर बघेल के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम खंजापुर में फतेहाबाद रोड से हाकिम सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला चूरा में होली वाले चौक से भरत सिंह की ठार तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम तोतलपुर-सोफीपुर में गिरीश के घर से डा0 विजेन्द्र के घर तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण व दोनों तरफ नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम करकौली में हनुमान मंदिर से नरेन्द्र सिंह की ठार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

6-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम खंजापुर में नाथं सिंह के घर से पेमेश्वर गेट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री विजय कुमार राजभर की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा मूजडाढ़ में प्राइमरी विद्यालय से तिघरा होते हुए भीमलपुरा तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा सोमारी डीह में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थल का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद मऊ के तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के विकास खण्ड रानीपुर के अन्तर्गत शहीद फेकन सिंह चौहान के नाम स्मारक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल कुमार चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा मझवारा में बघवत बाबा का पोखरा का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा धवरियासा में इन्द्रदेव चौबे के घर से तालनरजा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रेनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अर्चना पाण्डेय की जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की मानी गयी।

श्री गंगा सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री गंगा सिंह कुशवाहा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा फाजिलनगर के विकास खण्ड फाजिलनगर, ग्राम दहारी पट्टी में अन्तेष्टि स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विवेक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मसूद अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ विल्सन बाग कालोनी में डा0 सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान तक नाला आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सत्तार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत विकास खण्ड कोंच के छानी से तहरपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम पंचायत सिलउआ जागीर के मजरा सिलउआ में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सेवक व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा के जगम्मनपुर से छौना मानपुरा वाया उदोतपुरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री कीर्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

4-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत कस्बा ऊमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री राम अचल राजभर की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा राजेपुर धावां के फौजदार सिंह के खेत से हौलदार सिंह के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा वल्लीपुर के प्राथमिक विद्यालय से सरदार बल्लभ भाई पटेल विद्यालय मुबारकपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचेत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा रामपुर मंगुरा डिला के टिक्कू यादव के आवास से राम सकल यादव स्कूल होते हुए दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसूरत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा बरौरा के राकेश के आवास से नरायनपुर पिच रोड तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सकलडीहा मार्ग से सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम अवध व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सकलडीहा कमालपुर अमड़ा मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत मोहनपुर-मुगलसराय भुपौली चहनियां मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भैया लाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

4-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सकलडीहा मार्ग से सढ़ान सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती संगीता यादव की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं व जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम दुधली से ग्राम बिरदोनंगली तक सम्पर्क मार्ग लो0नि0वि0 या पंचायती राज विभाग द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आबिद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना से राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में श्री रफी अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम किथौड़ा मदरसे से कादरपुर तैयब मार्ग तक लम्बाई सम्पर्क मार्ग एवं तालाब की दीवार 70 मी0 बनवाने के सम्बन्ध में श्री शहजाद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिल मेहरा व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर में मौजमपुर किरतपुर मार्ग के ग्राम पाड़ली से ग्राम अनवरपुर चतर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जिबरीश अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में श्री शारिक सुल्तान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर, गुनियापुर भरैकी मार्ग पर बान नदी का पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर-बडगरी मार्ग पर मालन नदी का पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री टीकम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना में सड़क मरम्मत करने के सम्बन्ध में श्री अशफाक व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर के ग्राम शिवदीनखेड़ा पो0 हरौनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पुष्पलता शर्मा निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव में विधान सभा पुरवा के विकास खण्ड असोहा एवं कालूखेड़ा मेन रोड से लगा हुआ कूटीवीर धाम ग्राम अजयपुर में पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद उन्नाव में विधान सभा पुरवा के विकास खण्ड असोहा में खेलकूद का मैदान/व्यायामशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम सादखेड़ा झूलूमऊ थाना विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी में श्री नन्हेलाल आदि द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अवैध निर्माण/कब्जे के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड असोहा नवीन राजकीय पद्धति विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड असोहा में निम्न विद्यालय/भवन निष्प्रभावी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में नया कृषि किसान कल्याण केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा ब्लाक मुख्यालय असोहा में किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मार्केटिंग हब बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

8-जनपद उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग में 2002 तक चल रही एलोपैथिक फार्मासिस्ट नियुक्ति प्रक्रिया में छूटे हुये फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

श्री रवेन्द्रपाल सिंह की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम टोडर डबबलपुर में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर राजपूत (पप्पू) व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम गंगीरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में श्रीमती गजमोतिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयी।

3-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

डा0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

डा0 अनीता लोधी राजपूत की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत डिबाई उमरारा रोड से पंचायत घर के सामने ओम पाल के मकान तक सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत कुढैनी से नगला बागी तक सड़क का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम वीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत नौदेई बांगर राजघाट नरौरा रोड पर तेजपाल सिंह के भट्ठे से गंगाघाट तक खड़ंजा निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत सतवरा गन्ना सेन्टर से डबका बगसरा तक सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत अकरवास गौशाला से प्राइमरी स्कूल तक काली सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्रीमती मनीषा अनुरागी की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयी :-

1-जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम सौरौ में पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री सूरज सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र स्थित चरखारी राठ मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री कृष्णकांत अनुरागी व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र स्थित चिकासी हरदुआ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामबाबू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

4-जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम चंदौरा भैसाय के मध्य पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार साहू व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बेल्रांवा से चन्दिका देवी तक का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन रावत, निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से आबादी भाग में ठाकुरद्वारा मंदिर तक सी0सी0 रोड तथा नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार गौड, निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बी0यू0ए0 मार्ग सफीपुर में गुलाब बिल्डिंग से जगदीश खेडा सम्पर्क मार्ग तत्काल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत निराश्रित बेसहारा गौ-आश्रम की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कुरसठ ग्रामीण के मजरा ताजूखेडा में बारातशाला की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू रावत निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं†

श्री गौरी शंकर की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के तहसील जालौन के अन्तर्गत जालौन बंगरा मार्ग से छिरिया सलेमपुर से दमा जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवराज सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद जालौन के तहसील जालौन के अन्तर्गत जालौन हरदोई मार्ग से छानी खास के जर्जर सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील जालौन के अन्तर्गत उरई जालौन फोर लेन के 7 मील से मकरन्दपुरा तक जर्जर सड़क की पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद जालौन के तहसील जालौन के अन्तर्गत जालौन हरदोई गुर्जर जालौन मार्ग से धनरौरा कला जाने वाली सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम वीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद जालौन के तहसील जालौन के अन्तर्गत जालौन कोंच मार्ग से खनुआ जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के उरई कोटरा मार्ग से सरसार जाने वाली डामर सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवीर राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद उरई में राठ रोड गल्ला मण्डी से कुईया रोड जाने वाली ओवरब्रिज के नीचे दोनों ओर सर्विस लेन को डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के हरदोई गुर्जर सोमई मार्ग से ग्राम पडुंआ तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद जालौन के तहसील उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम अजनारा गौशाला तक सड़क का नवनिर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद जालौन के तहसील कोंच के विकास खण्ड कोंच के अन्तर्गत पहाड़ गांव से कमतरी तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री टिंकू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री संजय प्रताप जायसवाल की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के ब्लाक साऊघाट के अन्तर्गत कठिनईया नाले के दोनों तटों पर बन्धा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलौट व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बस्ती में स्थित रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रुधौली के ग्राम भितेहरा में सहकारी समिति से राम बुझारत पाण्डेय के घर तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ में ग्राम जिनवा भिरिया प्रधानमंत्री सड़क से तीज नगर चौराहे से झलमहमियां होते हुए महादेवा घाट के पुल तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बस्ती में विकास खण्ड रूधौली के ग्राम भितेहरा में सहकारी समिति से राम बुझारत पाण्डेय के घर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बस्ती की तहसील रूधौली के ग्राम धरमपुरवा में हरिजन टोला से श्री जय बहादुर सिंह के मकान से होते हुए झकड़ी के मकान तक (लगभग 300 मीटर) सी0सी0 रोड और नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

6-जनपद बस्ती की तहसील रूधौली के ग्राम धरमपुरवा में माता काली जी के मंदिर पर सौन्दर्यीकरण, पेयजल और सोलर लाईट की व्यवस्था का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-46, 47, व 48 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-49

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

† दिनांक 31-08-2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं। मान्यवर, अब हम कल बोलेंगे।

कार्य-स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-02-2020 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है। मा0 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी गन्ना किसानों के बारे में बोल लें।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों की ओर जो लगभग 40 जिलों में गन्ना किसान हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रदेश में जब

---

†† दिनांक 06-03-2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नई सरकार आयी है गन्ना किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। वर्ष 2016-17 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में गन्ने का दाम 25 रुपये प्रति कुं0 बढ़ाया गया था। जिससे गन्ना किसान उत्साहित हुआ था। गन्ने की खेती में बढ़ोत्तरी हुयी थी। गन्ना का उत्पादन बढ़ा था। वर्ष 2017-18 में 120 लाख चीनी का उत्पादन हुआ था और वर्ष 2018-19 में चीनी का उत्पादन घटकर 118 लाख रह गया। सरकार किसानों से वादा करती है सपने दिखाती है किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है मगर किसानों की लागत का मूल्य नहीं दे पा रही है। आज महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैलाये हुये खड़ी है। बिजली, उर्वरक, डीजल, मजदूरी, कीटनाशक दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। गन्ना किसान अपनी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा करता है। जिससे चीनी के परता में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में चीनी का परता .03 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 15.57 हो गया। .54 प्रतिशत रिकवरी बढ़ी। इससे स्पष्ट होता है कि मिल वालों का लाभ बढ़ा है। डिस्टलरियां लग रही हैं। एथेनाल बन रहा है। मिल पावर प्लांट भी लगा रहे हैं। और मिलों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। चीनी के दाम में भी वृद्धि हुयी है। विगत तीन वर्षों में वर्तमान सरकार ने गन्ना के दाम में केवल 10 रुपये प्रति कुं0 वृद्धि की है। विगत दो वर्षों में गन्ना के दाम में एक पैसा की भी बढ़ोत्तरी वर्तमान सरकार ने नहीं की है। जो वर्ष 2019-20 की एस0ए0पी0 घोषित है वही दो वर्ष पुरानी है। वर्तमान सरकार से हमारी मांग है कि गन्ने का दाम कम से कम 400 रुपये प्रति कुं0 किया जाये। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद के मुताबिक 14 दिन में गन्ना भुगतान न होने पर 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का प्राविधान है। जिसका ब्याज भी नहीं दिया गया है। वर्ष 2017-18 में 45 सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान आज भी बाकी है। वर्ष 2018-19 में 500 सौ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है और वर्ष 2019-20 में आठ हजार एक सौ रुपया का गन्ना किसान का भुगतान बाकी है। कुल पैंतालिस सौ पचासी से छियासी करोड़ का गन्ना किसान का भुगतान बाकी है मिलों के ऊपर, किसान परेशान है।

मान्यवर, हाईकोर्ट लगातार भुगतान और ब्याज देने की बात कर रहा है। प्रदेश के गन्ना किसान जब धरना-प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उन पर लाठियां चलाती है। किसान पर पराली जलाने के नाम पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जुर्माना लगाया जा रहा है। आवारा पशुओं की वजह से गन्ना किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह है कि गन्ना किसानों को पर्ची मिलने में मुश्किल आ रही है इसलिए गन्ना किसान औने-पौने दाम पर गन्ना कोल्हू पर बेचने को तैयार है। अतः मैं इस अविलम्बनीय मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य और पूर्व गन्ना मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी ने कुछ विषय उठाये हैं, लेकिन मुझे यह बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य

मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज गन्ने के क्षेत्र में उनके कुशल निर्देशन के कारण और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मेहनत के कारण आज उत्तर प्रदेश देश में नम्बर-1 बना है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। हमारे साथी ने भुगतान की बात कही है। यदि मैं भुगतान के बारे में ही बात करूं तो भुगतान वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रदेश के अंदर कुल 18 हजार 3 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। वहीं हमने वर्ष 2016-17 में 25 हजार 364 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का भुगतान कराया है। वर्ष 2017-18 में 35 हजार 423 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का भुगतान कराया है। वर्ष 2018-19 में गन्ना किसानों का 32 हजार 614 करोड़ रुपये का भुगतान कराया है और इस सत्र में अब तक गन्ना किसानों का 10 हजार 535 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि आज तक किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी कालखण्ड में इतना भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना किसानों का योगी सरकार में 89 हजार 227 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। आज तक आजादी के बाद किसी भी सरकार में 03 वर्ष के कार्यकाल में इतना भुगतान नहीं हुआ है। यह योगी सरकार की गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूंकि मेरे कई साथी हैं जो गन्ना किसानों पर अध्ययन करते हैं और प्रश्न भी लगाते हैं, लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद गन्ना किसानों की समृद्धि, उनकी चिंता और तेजी के साथ गन्ना किसानों के विकास को केन्द्रित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फैसला किया है कि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार के द्वारा तय किया गया है। पहली बार चीनी का बिक्री मूल्य 2900 रुपये तय हुआ और फिर 200 रुपये बढ़ाकर उसे 3100 रुपये कर दिया गया। मैं कह सकता हूं कि यदि किसी को गन्ने की जरा सी समझ है तो यह बात स्पष्ट है कि यह फैसला गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 06 सालों से लगातार गन्ना किसान भुगतान का इंतजार कर रहा था। मैं उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि एक साथ पचपन सौ पैंतीस करोड़ का पैकेज देकर उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान का रास्ता सुगम किया है और लगातार गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किसान को जूझना न पड़े इसलिए केंद्र सरकार एवं योगी सरकार द्वारा जो एथनॉल की पॉलिसी लागू की गयी है कि गन्ने के जूस सीधे एथनॉल बनाना है। मुझे इस बात को सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश की मात्र दो शुगर मिलें बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बना रही थीं लेकिन इस साल 20 शुगर मिलें बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बना रही हैं जो गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सुगमता से चलने वाला रास्ता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिनके कार्यकाल में चार-चार साल तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, जिन लोगों ने शुगर मिलों को औने-पौने दाम पर बेच दिया, शुगर मिलों को बंदर बांट कर दिया, वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलों को बंद किया गया और वर्ष 2012 से

2017 तक उत्तर प्रदेश में 10 चीनी मिलों को बंद किया गया। दस साल में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलों को बंद किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी कुशल नीतियों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। मेरे विद्वान साथी बैठे हैं और सदन को जानकारी देना आवश्यक है ....

श्री अध्यक्ष-

बकाया के बारे में बता दीजिए, जिसके विषय में मा0 सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके विषय में भी ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। हमारे मित्रगण बैठे हैं और यह सवाल उत्तर प्रदेश के गौरव का सवाल है, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के स्वाभिमान का सवाल है इसलिए मैं आंकड़े जरूर दूंगा कि आज देश का चीनी मिलों को लेकर जो परिदृश्य है, यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में जहां पिछले साल 18 चीनी मिलें चली थीं, इस बार मात्र 16 मिलें चली हैं। कर्नाटक में पिछले साल 65 मिलें चली थीं, इस बार 62 मिलें चल रही हैं, महाराष्ट्र में पिछले साल 152 मिलें चली थीं, इस बार मात्र 140 मिलें चली हैं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन वर्मा जी केवल बकाया मूल्य पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश राणा-

लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पिछले साल 117 मिलें चली थी, इस बार 119 मिलों का संचालन हो रहा है, यह देश का अकेला राज्य है। वर्ष 2017-18 में हमने 35443.71 करोड़ में से 35423.17 करोड़ का भुगतान किया है जो 99.89 प्रतिशत बैठता है। वहीं हमने वर्ष 2018-19 में 3348.06 करोड़ में से 32614.67 करोड़ का भुगतान किया है जो कि 98.69 प्रतिशत बैठता है। 433 करोड़ रुपया पिछले सत्र का अभी मात्र 08 मिलों पर बकाया है, उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों में से 111 मिलों पर एक भी पैसा बकाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, उत्तर आ गया। यहीं आंकड़ा तो मुख्य मंत्री जी भी दिये थे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री सुरेश राणा-

यह अपने आप में ऐतिहासिक भुगतान है और लगातार जिन लोगों ने किसानों की मेहनत की कमाई से बनी चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेंच दिया, जिसकी जांच चल रही है, वह लोग गन्ना किसानों की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये जो पूछ रहे हैं, वह बता दीजिए।

श्री सुरेश राणा-

जिनकी सरकार में किसानों पर लाठियां बरसती थीं, जब वे गन्ना मूल्य की बात करते थे। मैं बधाई दूंगा आदरणीय योगी जी को, क्योंकि वर्ष 2015-16 के अंदर 64 करोड़ कुण्टल गन्ने की पेराई हुई थी, वहां आज 111 करोड़ कुण्टल गन्ने की पेराई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

उनकी जिज्ञासा केवल बकाया के संबंध में है, बाकी नहीं।

श्री सुरेश राणा-

जहां हमारा प्रोडेक्शन 120 लाख टन के साथ देश में नंबर एक है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि गन्ने के क्षेत्र में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शानदार काम किया है और अपने साथियों को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, पूरी तरह से काम कर रही है और जो भी आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाएगा। जैसे आवश्यकता हुई तो पचपन सौ पैंतीस करोड़ का पैकेज आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने दिया, हम गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने का काम करते रहेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान गन्ना मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। विगत 03 वर्षों में गन्ने के दाम में बढ़ोत्तरी केवल 10 रुपये प्रति कुन्तल की गयी है। जबकि गन्ने की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गयी है, बिजली बढ़ी, डीजल बढ़ा, खाद के दाम बढ़े।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो नोटिस है, उसमें भुगतान न करने की बात कही गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आज भी कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में 8546 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य, गन्ना मिलों पर बाकी है। न तो गन्ना मूल्य बकाया पर सरकार ब्याज दिला रही है, न गन्ना मूल्य बढ़ा रही है और ना खाद, ना बीज, ना डीजल के दाम घटा रही है, बल्कि कर्नाटक, जहां उनकी खुद की सरकार है, उसका मंत्री जी उदाहरण दे रहे हैं। यह सरकार किसान विरोधी है, गन्ना किसान की विरोधी है और सरकार ने जो जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसके विरोध में हम और हमारी समाजवादी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(समाजवादी पार्टी के श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष-

और किसको जाना है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी एक जिज्ञासा है।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि जिन लोगों ने 2012-13, 2013-14, 2014-15 के 1896 करोड़ रुपये का ब्याज गन्ना किसानों का शुगर मिल पर माफ किया था, वह किसानों की बात कर रहे हैं ? इनके पास आंख में आंख मिलाकर राजनीति करने का साहस नहीं है। वह साहस इसलिए नहीं है, चूंकि इन्होंने गन्ना किसानों के लिए कुछ किया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, वर्मा जी की बात सुन लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आंख में आंख मिलाने का सवाल नहीं है, किसान को लाभ दिलाने का सवाल है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी सूचना तो है नहीं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मेरी सूचना नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नियम-56 में जिज्ञासा नहीं चलती।

श्री लाल जी वर्मा-

होता है, होता है। यह सदन की प्रॉपर्टी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सदन की प्रॉपर्टी है, लेकिन यह नियम-56 में नहीं है। मान्यवर, नियम-56 में है कि जिसकी सूचना है, वही बोल सकता है।

श्री लाल जी वर्मा-

इसके लिए अध्यक्ष जी ने हमें परमीशन दी है, बिना परमीशन के मैं नहीं खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी ने परमीशन नहीं दी है, मैं देख रहा था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने परमीशन दी है। यदि अध्यक्ष जी कह दें, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप तो विद्वान हैं और हर वक्त किताब देखते हैं, इसमें भी किताब देख लें। जिसके सिगनेचर हैं, वही बोल सकते हैं, अन्यथा इसका कोई अन्त ही नहीं है, देखिए, 4:00 बज रहे हैं। मान्यवर, यह किस नियम से बोल रहे हैं, यह और बता दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, गन्ना मंत्री जी सिर्फ इतना ही बता दें कि आज तक कितना बकाया है ? पिछले वर्षों का और इस वर्ष का बकाया बता दें।

श्री अध्यक्ष-

राणा जी, क्या इतनी बात का आपके पास उत्तर है ?

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैंने 2017-18 से ले करके 2019-20 तक का बताया है। सारी जानकारी मैंने मा0 सदस्य को दी है और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं, चूंकि वर्मा जी लगातार जिज्ञासा रखते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

अब हमारी बात करेंगे तो हमें भी बोलने का आप अवसर दीजिए।

श्री सुरेश राणा-

आपने बोला तो मैं और किसकी बात करूं ?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यह है कि लगातार गन्ना किसानों के हित में सरकार ने जो काम किया है, उसकी झलक भी इन्हें सुननी चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए। आज गन्ना किसान, चाहे गन्ने का क्षेत्रफल हो, चाहे गन्ने का उत्पादन हो, चाहे रिकवरी हो, आज देश में उत्तर प्रदेश नम्बर-1 पर है, यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। वर्मा जी, अब आप अपनी सूचना पर बोलिए।

आपकी सूचना सेठ विशम्भर नाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, लखनऊ से बी0फार्मा कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के सवाल को रेज किया था। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बजट घटाने का काम हुआ है और उनके आवेदन करने में भी कठिनाई पैदा करते हैं, ताकि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति न मिल पाए उसका उदाहरण यह है कि सेठ विश्म्भर नाथ इंस्ट्टयूट आंफ फार्मास्यूटिकल साइंस खजूर गांव देवा रोड लखनऊ में है। यहां के बच्चों ने आंनलाइन आवेदन किया और इस तरह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में है। आन लाईन आवेदन के लिए छात्रों ने प्रयास किया कि कालेज से वह फारवर्ड होकर आ जाए, लेकिन समय से फारवर्ड नहीं हुआ, और जिसके कारण अनुसूचित छात्रों की यह जिम्मेदारी नहीं थी, छात्र ने आवेदन आंनलाइन कर दिया, लेकिन उसके कारण अनुसूचित जाति के छात्रों ने फीस देकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया, और यह समझ के लिया कि सरकार से फीस की प्रतिपूर्ति मिलेगी, हमारा भुगतान हो जाएगा, और जब भुगतान हो जाएगा तो हम फीस दे देंगे और अगले साल भी हम पढ़ लेंगे। चार साल का कोर्स है, लेकिन फारवर्ड न करने के कारण उनकी जो स्कॉलरशिप है, वह उनको नहीं मिल पाई, उसके कारण उनमें आक्रोश व्याप्त है। और यह पूरे प्रदेश की स्थिति है, इसलिए मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि यह पूरे अनुसूचित जाति के दोनों वर्गों के छात्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह नियम-56 में है कि कोई एक विषय की सुनिश्चित घटना आप ला सकते हैं, तो इसलिए एक सुनिश्चित विषय मैं लाया जो नियम-56 को उसके अनुसार पूरी तरह से उसको पूरा करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ है, और पूरे समाज के छात्रवृत्ति से जुड़ा है, बच्चों के छात्रवृत्ति से जुड़ा है। भविष्य में पहली साल की पढ़ाई के बाद दूसरी, तीसरी साल की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार कर लें, जिससे इस पर चर्चा हो जाए। चर्चा होने के बाद कोई एक प्रस्ताव पास हो जाए, जिससे कि इस तरह की जो समस्याएं हैं पूरे प्रदेश के छात्र की उसका समाधान हो जाए, और जो सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस की प्रतिपूर्ति देने का वह पूरा हा जाए, और उनकी पढ़ाई आगे चल सके। मैं चाहूंगा कि आप इसको ग्राह्य कर के इस पर चर्चा करा लें।

खाद्य प्रसंस्करण नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (डॉ0 जी0एस0 धर्मेश)-

मान्यवर, दी गई उक्त सूचना के संबंध में शासन के पत्र संख्या-06 नियम/26-3-2020, दिनांक 26-2-2020 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सूचना प्राप्त की जा रही है, सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सूचना प्राप्त की जा रही है। हमने एक सुनिश्चित विषय उठाया है, लखनऊ का मामला है, यह भी नहीं कि बाहर का है। अगर लखनऊ का मामला है और इसमें केवल

लखनऊ का ही विषय है, यह भी नहीं कि कहीं दूर का है, और सुनिश्चित मामला है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप यह आश्वस्त करिए कि उन छात्रों की छात्रावृत्ति मिलेगी, अगर वह पात्र हैं तो, इतना ही आप आश्वासन दे दें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक विद्यालय ने इतनी बदमाशी की, इसको संज्ञान में लाया जाए। अब उसकी सूचना पर फॉर्म फारवर्ड किया गया कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आ जाए, अभी सरकार का उत्तर नहीं आया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, कल तक मंगवा लें, लखनऊ का विश्वविद्यालय है फारवर्ड किया है, फॉर्म कि नहीं किया है ? आप आदेश का पालन करवा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 रमापति जी से कहा गया है कि यह सूचना जो है कल तक मंगवा लेंगे, कल सदन को उपलब्ध करा देंगे। आज सूचना नहीं आ पाई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगली सूचना मनोज कुमार पारस, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी जिन्होंने जनपद बजनौर में खनन माफियाओं द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों में अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप हो रही राजस्व क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। अगली सूचना श्री रफीक अंसारी द्वारा जिन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों को किसानों की भांति फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। मैं इस पूरे मूल पत्र को सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हं, निर्देशित करता हूं, सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मान्यवर, यह वाली सूचना मेरी तरफ की है। मा0 खन्ना जी के दफ्तर से मुझे मार्क कर दिया गया था क्योंकि बुनकर वाले विषय का सम्बन्ध मुझसे है। यदि ये उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना का जो भी विषय है, आप उस पर कार्यवाही करा दीजिएगा।

अगली सूचना श्री संजय गर्ग जी की प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरी सूचना राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सम्बन्ध में है। वहां बहुत बुरी हालत है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

मैं उस पर प्रातः काल ही ध्यानाकर्षण कर चुका था और आपसे बात भी हुई थी। अगली सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी जी की जनपद महाराजगंज के थाना सनौली, परसा मलिक एवं बरगदवा इत्यादि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम न लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(सदस्य श्री अमनमणि त्रिपाठी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इस पर शासन का ध्यानाकर्षण करता हूं और आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करता हूं।

(सदस्य श्री अमनमणि त्रिपाठी द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 त्रिपाठी जी, आपकी सूचना हो गई है, मैंने उस पर ध्यानाकर्षण कर दिया है। मैंने सरकार को ध्यानाकर्षण और आवश्यक कार्यवाही के लिए कह दिया है। अब आपका हो गया और अब मैं फिर से बजट चर्चा पर आता हूं। अब बीच में और तो कोई मद है नहीं, बजट चर्चा है न ? अब श्री संजय गर्ग जी शुरू करें। क्या आप बजट पर नहीं बोलेंगे ? ठीक है, अब श्री वीरेन्द्र यादव जी।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

(इस समय 03 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुये)

***श्री विरेन्द्र कुमार यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मा0 राम गोविन्द चौधरी जी के वक्तव्य से अपने को सम्बद्ध करते हुए वर्ष 2020-21 के बजट पर कहना चाहता हूं कि यह योगी सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, बेरोजगारी, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल, किसानों की खुशहाली, कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय पर पूर्ण रूप से गम्भीर नहीं है। इसके साथ ही निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनपद गाजीपुर में मा0 पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 300 बेड का हांस्पिटल देने का काम किया था और वह पूर्ण रूप से संचालित भी हो रहा है। पर उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें डायलिसिस नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, पैथोलॉजी के डॉक्टर नहीं हैं, कोई सर्जन नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है और नाक, कान, गले का डॉक्टर भी नहीं है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार वहां ये व्यवस्थाएं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का काम करे। पर्यटन के क्षेत्र में गाजीपुर जनपद लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, जहां धार्मिक आस्था का केन्द्र है। वहां पौहारी बाबा आश्रम पर स्वामी विवेकानन्द जी अमेरिका जाने से पहले जब वहां अपना गुरू बनाने के उद्देश्य से एक माह तक रुक कर आए थे, तब पौहारी बाबा ने कहा था कि तुम जाओ तुम्हारे गुरू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस स्थान के लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। इसके अलावा, महारधाम और सन्त श्री गंगादास आश्रम जहां वर्तमान मा0 मुख्य मंत्री और नेता सदन जी गए थे और वहां के महामण्डलेश्वर जी से यह कह कर आए थे कि हम पर्यटन हेतु आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार वहां पर पर्यटन की दृष्टि से कुछ व्यवस्था करने का काम करे। स्वच्छता के नाम पर वैसे तो गाजीपुर जनपद में ओ0डी0एफ0 हो चुका है लेकिन आज भी वहां शौचालय पूर्ण रूप से शौचालय नहीं बन पाए हैं, वह आज भी संतृप्त नहीं है और वहां सारा, सब कुछ पेपर पर ही है। इसका मतलब है कि गाजीपुर जनपद शौचालय की दृष्टि से पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं हो सका है क्योंकि यदि संतृप्त हो गया होता तो फिर उसके पैसे अभी तक अवशेष क्यों पड़े हुए हैं ? मान्यवर, जो गंगा किनारे के ओ0डी0एफ0 हो चुके गांव हैं, चूंकि हम भी गंगा किनारे रहते हैं और वहां निश्चित रूप से इन शौचालयों को कोई उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर मैं कहना चाहता हूं कि-

कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है

अंधी सत्ता के हाथों में किसानों, मजलूमों को जान गंवानी है।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार पुलिस के बल पर जनता को डराया-धमकाया जा रहा है और आज भी हालात ऐसे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिवर्तन चौक और जगह जगह पर पुलिस द्वारा बर्बरता और लाठीचार्ज करने के साथ महिलाओं पर घोर अत्याचार और उनका अपमान किया जा रहा है। बहुत ही हालात खराब हैं पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठी भांजी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इंटरनेट सेवायें बंद कर दी जा रही हैं। हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। वे घर पर सहमी हुई हैं और घर से भी नहीं निकल पा रही हैं। भ्रष्टाचार के आकंठ में यहां के तहसील, थाने से लेकर विभागीय कार्यालय तक सब लूट का अड्डा बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह भाजपा सरकार आई है मैं कहना चाहता हूं पहले वे भ्रष्टाचार न गुण्डाराज अबकी बार भाजपा सरकार का जो नारा दिया जाता था आज ठीक उसके उल्टे ये हो रहा है भ्रष्टाचार चारों तरफ से आकंठ भरा हुआ है। गुण्डाराज की बात तो कहनी ही नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ कब किसकी हत्या हो जायेगी इस योगी राज में कोई कुछ नहीं कह सकता है युवाओं की बात योगी सरकार ने कहने का काम किया

रोजगार देने की बात कही लेकिन आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का युवा निश्चित रूप से रोडों पर भटकने का काम कर रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि 12460 शिक्षकों की भर्ती मा0 अखिलेश यादव जी के समय में हुई थी लेकिन जब सरकार चली गई तो उसके बाद लगभग 7000 युवा शिक्षक आज बेरोजगार होकर रोडों पर टहल रहे हैं उनका प्रकरण महाधिवक्ता के स्तर पर न्यायालय के स्तर पर रूका हुआ है। आपके स्तर से मैं यह मांग करता हूं कि कहीं-न-कहीं सरकार अपना पक्ष रखकर उन युवाओं को रोजगार देने का काम करे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि गाजीपुर जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है मैं आपसे चाहता हूं कि सरकार वहां एक विश्वविद्यालय बनाये इसके लिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

''न मस्जिद को जानते हैं,
न शिवालयों को जानते हैं,
जो भूखे पेट हैं,
वो सिर्फ निवालों को जानते हैं।''

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी विधान सभा जंगीपुर चकताजुद्दीनपुर में एक लघु सेतु की जनहित में अति आवश्यकता है उसे बनवाया जाये। ग्राम सभा चौथी में भैसही नदी में एक लघु सेतु अति आवश्यक है। जंगीपुर विधान सभा में खेल प्रोत्साहन के संदर्भ में एक मिनी स्टेडियम की मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देने का काम करे। बिजली को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु ग्राम बौरी में जहां हम जमीन भी उपलब्ध करा चुके हैं वहां पर 33/11 के सब स्टेशन की मैं आपसे मांग करता हूं और उसके साथ ही हमारी विधान सभा चूंकि गंगा का किनारा है। गंगा के किनारे सटे होने के कारण बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता है वहां कालुपुर से युवराजपुर तक जो सड़क गई है मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस सड़क का उच्चीकरण और चौड़ीकरण करते हुए उसको बनवाने का काम करें। उसके साथ ही भरसण से जयरामपुर होते हुए इनवा मोड़ तक चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाये। बिन्दवलिया चट्टी से कदियापुर मदारपुर होते हुए मानपुर तक चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाये। जंगीपुर लावा मोड़ से जयन्ती दासपुर होते हुए रायपुर तक चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाये, कहोतरीचट्टी से मानपुर तक चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाये। गाजीपुर कासमाबाद मुख्य मार्ग बौरी से सर्वण्डी तक विशेष मरम्मत कार्य कराया जाये। ग्राम चौराबोज में नहर की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है उसको ना बनाया जाए एवं हमारे क्षेत्र में पंचायत भवन की काफी आवश्यकता है उसको बनवाया जाए। इस बजट पर चर्चा में मैं अपने नेता विरोधी दल की बातों से खुद का सम्बद्ध करते हुए एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा -

''मन्दिर मस्जिद के नामों पर
अपनों को ही काटा है,
खून में कोई फर्क नहीं,
बस बीजेपी ने बांटा है।''

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

आबकारी मंत्री एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री राम नरेश अग्निहोत्री)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, नये भारत के निर्माण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण हेतु देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक बजट हमारी सरकार द्वारा जनकल्याण की प्रतिज्ञा को साकार करने वाला है। यह बजट प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय को बिना किसी भेदभाव के सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, मकान आदि सुविधाओं को उनके द्वार तक पहुंचाने के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना मंत्री सतीश महाना जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 वर्षों के कार्यकाल में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस व डिफेन्स एक्सपो जैसा बड़ा आयोजन किया गया और प्रदेश के विकास हेतु भारी पूंजी निवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी और उसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 की तुलना में अपराधों पर बहुत भारी नियंत्रण का काम हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आयी है, डकैती में 53 प्रतिशत, हत्या में 14 प्रतिशत, लूट में 44 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 30 प्रतिशत की कमी आयी है। महिला सुरक्षा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने 'सुरक्षा कवच योजना' के अंतर्गत रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक मोबाइल से 112 नम्बर डायल कर सुरक्षा की मांग करने वाली मातृ शक्ति को उनके गन्तव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, सरकार 'युवा उद्यमिता विकास अभियान' के माध्यम से युवाओं को रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने की पहल कर रही है। प्रत्येक जनपद में 'युवा हब' की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों से प्रदेश के 8 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवायोजित भी कराया गया। हमारी सरकार की प्राथमिकता पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना रहा है। इस दिशा में किये जा रहे कार्यों हेतु माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर

में सर्वाधिक 30 प्रतिशत की गिरावट लाने के लिये उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से एम0एम0आर0 एवार्ड प्राप्त हुआ है। 108 एवं 102 एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकार द्वारा 'मुख्य मंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला' का आयोजन किया जा रहा है जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों के निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने, जिला चिकित्सालयों के नवीनीकरण हेतु 266 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे गृह जनपद मैनपुरी के समीप ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपये तक के कर्ज माफी का निर्णय लिया था। अब किसानों की आय को दोगुना करने हेतु गेहूं, धान तथा मक्का खरीद की नयी पॉलिसी लागू की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान करने वाला पहला राज्य बना है। इन ऐतिहासिक कार्यों के लिए माननीय कृषि मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये विगत दो वर्षों में रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकार्ड 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है, जो ऐतिहासिक है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, संक्षेप कर दीजिये। बहुत लम्बी सूची है, आज सबको बोलना है।

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में दुर्बल आय वर्ग हेतु सबके लिए आवास योजनान्तर्गत चार लाख भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गरीब, दुर्बल एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास का लाभ मिला है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वर्ष 2019-2020 में 6,796 क्रय केन्द्र स्थापित कर 37 लाख मैट्रिक टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की गयी। गेहूं तथा धान खरीद के कार्यों में पारदर्शिता लायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त कर दीजिये। बार-बार टोकना अच्छा मालूम नहीं होता है। समय काफी हो गया है और लोग भी बोलेंगे।

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

अन्त में जो मेरा विभाग है उसके बारे में सदन को बताने में मुझे बहुत प्रसनन्ता हो रही है कि आबकारी विभाग द्वारा राजस्व संग्रह समाजवादी पार्टी सरकार की तुलना में 200 प्रतिशत बढ़ा कर किया गया है तथा बसपा सरकार की तुलना में 600 प्रतिशत के राजस्व की बढ़ोत्तरी हुई है। यह परिवर्तन सरकार की मंशा ठीक होने के कारण हुआ है। सपा, बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों की भ्रष्ट वसूलीवादी मानसिकता के कारण प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ था। जो पैसा प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए था वह पैसा सपा और बसपा के नेताओं ने अपने भ्रष्ट आचरण से अपनी-अपनी जेबों में भर लिया।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, धन्यवाद। समाप्त करिये।

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

यह रिकार्ड बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन को संकल्पित है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट चर्चा के दौरान अधिकारियों की दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

एक व्यवस्था का सवाल है। सामान्य बजट पर चर्चा चल रही है और अधिकारियों की गैलरी में कोई भी महानुभाव अधिकारी नहीं है। पूरी गैलरी खाली पड़ी हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री लोग मौजूद है। अध्यक्ष जी, वहां से सब देख रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अगर आप व्यवस्था चाहते हैं। बजट पर चर्चा चल रही है और गैलरी में कोई भी अधिकारी नहीं है, यह परम्परा गलत है। आप मान लो भईया आप भी विधायक हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लिए कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

नरेन्द्र जी मैं इसके बारे में अध्यक्ष जी को सूचित किये दे रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आगामी वित्तीय वर्ष, 2020-21 के बजट चर्चा के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं

अपनी सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट में प्रदेश के समग्र विकास के लिए, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एवं विभिन्न सेवाओं के लिए इसमें व्यापक प्राविधान किये गये हैं इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ में विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और संचालन की व्यवस्था भी की है। मान्यवर, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां पर भी अभी हमारी सरकार ने एक युनिवर्सिटी देने का काम किया है। सहारनपुर को एक बहुत बड़ी युनिवर्सिटी मेरी सरकार के द्वारा दी गयी। मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार, शिक्षा व उनके विकास के लिए मुख्य मंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिले में स्थापित युवा हब के लिए 100 करोड़ एवं 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कांमन सर्विस सेन्टर के निर्माण हेतु रु0 29.40 करोड़ की व्यवस्था की है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके सुधार हेतु 7 लाख 83 करोड़ की व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 4 लाख 79 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी नरेन्द्र जी ने जो बात कही है, उसका संज्ञान ले लीजियेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

इससे हमारी सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को हमने आगे बढ़ाया है उसमें इसको शामिल किया है। चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी हमारी सरकार ने बड़े काम किये हैं। इसमें चिकित्सा सेवा में सुधार के लिये हमारी सरकार ने आठ जिलों में जो मेडिकल कालेज की घोषणा की है उसमें एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्वार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में नये मेडिकल कालेज की स्थापना और संचालन के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है। मैं इसके लिये सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने समुचित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये मेडिकल कालेजों को राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी अस्पतालों को रोगों के नियंत्रण के लिये भी बजट में 19-20 में 83.30 करोड़ का प्रावधान किया था इसके सापेक्ष इस बार 102.53 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो तुलना में 17.40 प्रतिशत अधिक है।

श्री अधिष्ठाता-

अपने क्षेत्र की समस्या रख दीजिये क्योंकि समय समाप्त हो रहा है।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

चूंकि प्रदूषण को लेकर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बात रखी है तो प्रदेश के महानगरों में प्रदूषणमुक्त परिवहन के लिये हमारी सरकार ने मेट्रो रेल तथा 09 महानगरों में 700 से अधिक इलेक्ट्रानिक बसों के संचालन की व्यवस्था की है इससे आमजन को अच्छा सफर मिलेगा। हमारे पश्चिम क्षेत्र मेरठ में गंगा एक्सप्रेस वे, जो 637 किमी0 लम्बा बनेगा उसके लिये भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या पराली को लेकर थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पराली को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें भी हमारी सरकार ने पराली के प्रबन्धन की योजना के लिये 300 करोड़ की व्यवस्था की है, मैं सरकार का उसके लिये भी धन्यवाद करता हूं और कृषि विकास के लिये भी सरकार ने बोरिंग की व्यवस्था की है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट लूंगा। मुख्य मंत्री सिंचाई योजना में 145 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास अन्तर्गत जो पंजीकरण 25 हजार का था, उसको भी घटाकर 05 हजार कर दिया है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी विधान सभा की दो-चार समस्यायें हैं वह रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वह तहसील भवन को लेकर है, पिछले 10 साल से मेरे यहां तहसील है लेकिन उसका भवन नहीं बना है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तहसील का जल्द से जल्द भवन निर्माण कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

हिन्डन नदी पर दो पुल निर्माण की और आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें पैरा मेडिकल स्टाफ और डाक्टरों की कमी है और हमारे यहां पर जो हास्पिटल है उसमें भी डाक्टरों की कमी है और एक ही डाक्टर पूरे अस्पताल को चलाता है। सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था कराई जाय। मेरे रामपुर क्षेत्र में नांगल में एक फायर स्टेशन का निर्माण कराया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

***श्री वीरेन्द्र-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जनपद एटा की विधान सभा क्षेत्र 105 महरेरा से पहली बार चुनकर आया हूं आपने मुझे लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है मैं इस पीठ को नमन करते हुये आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को प्रदेश के चहुमुखी विकास और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। बजट में महिलाओं का सम्मान प्रदेश के विकास में महिलाओं की सहभागिता और बराबरी का अधिकार देने के लिये प्रतिबद्धता दर्शाई गयी है। व्यापारियों का कल्याण, युवाओं का उत्थान, गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान सभी वर्गों का ध्यान रखते हुये जनकल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास में अच्छी सड़कों की भूमिका अहम होती है। बजट में अच्छे सम्पर्क मार्ग, एक्सप्रेस-वे, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य सेवायें देने की प्रतिबद्धता दर्शाई गयी है। माननीय उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए धन्यवाद् देता हूं। माननीय योगी सरकार का बजट माननीय मोदी जी के नये भारत की परिकल्पना की अवधारणा को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के परिणाम का प्रतिफल प्रतीत होता है। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अन्त्योदय की विचारधारा को माननीय मोदी सरकार ने सन् 2014 से पूरे देश में विकास गंगा के रूप में जो अभियान चलाया है। उसमें प्रदेश सरकार का बजट एक स्तम्भ और विकास में अहम भंमिका निभाकर मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को प्रमाणित करता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी एक तपस्वी और सन्त हैं और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी काफी अनुभवी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को अच्छे बजट के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी अनुमति से प्रदेश सरकार के बजट की दिशा को कविता की कुछ लाइन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इस कविता के लेखक इस सदन के कई बार नेता रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी हैं :-

दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है,
सज-धज कर आयें आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन,
होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल-संभल बढ़ता है,
अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उपसर्ग कामना,
जीवन का शास्वत व्रत लेकर साधक हंक कण-कण गलता है,
दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मोदी सरकार को और माननीय योगी सरकार को मन्दिर निर्माण और अयोध्या के विकास को बजट में व्यवस्था के सार्थक प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं। साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 100 करोड़ से भी अधिक हिन्दुओं की आस्था का सम्मान करते हुए निष्पक्ष और सम्मानजनक निर्णय दिया। मान्यवर, जब मन्दिर निर्माण की चर्चा हो तब इस सदन के महान नेता रहे हिन्दू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 1992 में 500 वर्ष पुराने मुस्लिम आक्रान्ताओं के कलंक को मिटाकर 100 करोड़ से भी अधिक हिन्दुओं की आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सरकार का बलिदान कर साहस और शौर्य का परिचय दिया था। जब-जब आने वाली पीढ़ी मन्दिर का इतिहास पढ़ेगी तब-तब माननीय कल्याण सिंह जी की शौर्यगाथा जरूर पढ़ी जायेगी। कार्यकर्ता ओर जनता के प्रति उनका समर्पण और कार्यशैली हमेशा याद रखी जायेगी। अयोध्या तो हमारी है, अब मथुरा, काशी की बारी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें। एक ही विषय को इतना लम्बा मत कीजिये।

श्री वीरेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। जब मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी जाये उस समय माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय आडवानी जी, माननीय उमा भारती जी, माननीय डा0 जोशी जी, माननीय विनय कटियार जी 1992 में मन्दिर निर्माण आन्दोलन में सहभागी थे इसलिए उनकी उपस्थिति एवं मन्दिर निर्माण समिति में सहभागिता रहेगी तो 1992 के लाखों राम भक्तों को आत्मिक सम्मान मिलेगा और अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा स्वच्छता का एक वीडियो टी0वी0 पर देखकर मुझे मेरे अच्छे कार्य के लिए फोन पर धन्यवाद दिया और आज मैं माननीय योगी जी के आशीर्वाद से देश का पहला विधायक बन गया जो भारत सरकार स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण और भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय की सरकारी साइड पर अपलोड हूं। मेरी विधान सभा में नगला अकोली में एक दिन में 100 शौचालय बनाकर वन-डे ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ और देश का पहला गांव बना।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के तपस्वी सन्त मा0 मुख्य मंत्री योगी जी को नमन करते हुए अपनी तरफ से और मारहरा विधान सभा की

जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि और विकास से पिछड़ी विधान सभा में एक मेडिकल कॉलेज, एक पॉलीटेक्निक कॉलेज, एक आई0टी0आई0, एक पर्यटक केन्द्र देकर विकास से अछूती मारहरा विधान सभा को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दीजिये, बहुत लम्बी सूची है।

श्री वीरेन्द्र-

मान्यवर, मेरी विधान सभा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी है, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा में एक महिला डिग्री कॉलेज और मिरहची को नगर पंचायत घोषित करने की कृपा करें। मान्यवर, मरथरा से मोहनपुरा वाया मिरहची, मारहरा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कराया जाय। मान्यवर, कासगंज सम्पर्क मार्ग से अनरंजीखेड़ा पर्यटन केन्द्र तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कराया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं एक बार पुनः इस सम्माननीय पीठ को नमन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, वन्देमातरम, जय श्री राम।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को अपने नेता माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी साहब से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित साथियों और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अभिभाषण पर चर्चा रामराज्य से शुरू की थी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष मा0 राम गोविन्द चौधरी साहब ने बहुत अच्छी तरह वास्तविक रामराज्य और इनके रामराज्य के बारे में समझाने का काम किया है, लेकिन मैं भी अपनी कुछ बातें चन्द लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि अजीब नशा है, अजीब खुमारी है। इन्हें कोई रोग नहीं, बस राम-राम बोलने की बीमारी है।। इन्हें मतलब नहीं राम के आदर्शों से, इन्हें बस राम नाम पर वोट लेने की खुमारी है।। वक्त रहते जाग जाओ ऐ हिन्द के शेरों। नहीं तो फिर गुलाम बनाने की तैयारी है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े आकार का 5 लाख 12 हजार 8 सौ 60 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है और प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की आय दुगुनी की जा रही है, किसान की आय दुगुनी हुई है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान की क्या हालात है यह किसी से छिपा नहीं है ? किसान वह अन्नदाता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है जो हमारा, आपका, प्रदेश, देश और पूरे विश्व का पेट भरने का काम करता है, लेकिन आज जहां तक किसान की बात है तो किसान दूसरों का पेट क्या भरेगा, जब अपना पेट भरने के लिए अपनी मेहनत और मजदूरी के पैसे उसे नहीं मिल रहे हैं। आलू किसान के हालात आप देख चुके हैं कि आलू किसानों ने अपना आलू सड़कों पर फेका। धान के किसानों का भी यही हाल है, बहुत मेहनत/मजदूरी करके उत्तर प्रदेश का किसान धान पैदा करता है, लेकिन जब धान बेचने का मौका आता है और जब वह सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने जाता है तो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वहां पर क्रय केन्द्र के बोर्ड व बैनर तो दिखायी देते हैं, लेकिन कोई क्रय केन्द्र नहीं होता है।

अगर हम गन्ना किसानों की बात करें, तो मैं पश्चिमी क्षेत्र के जनपद-बिजनौर विधान सभा क्षेत्र-नगीना से आता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे तो गन्ना क्षेत्र में अग्रणी है, गन्ना अधिक पैदा करता है। हमारे यहां करीब-करीब हर 20 कि0मी0 पर गन्ना चीनी मिलें हैं, लेकिन आज गन्ना किसान इस कदर परेशान/बेहाल है कि उसे पर्चियां नहीं मिल रही हैं और अगर पर्चियां मिल भी जाती हैं तो उनका क्षेत्रफल तो घटा है, लेकिन पैदावार बढ़ी है और पैदावार बढ़ने के बावजूद भी उनका बेसिक कोटा भी नहीं बढ़ाया गया है। मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव और सुझाव के साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि उन गन्ना किसानों का बेसिक कोटा बढ़ा दिया जाये, जिससे उनका गन्ना समय से बिक सके। मा0 अधिष्ठाता महोदया, हमारे जनपद बिजनौर में गन्ना अधिक पैदा होने की वजह से एक और चीनी मिल की आवश्यकता है, इसलिए अगर मेरे जनपद बिजनौर में एक और चीनी मिल की व्यवस्था हो जाती, तो कम से कम गन्ना किसानों को अपना गन्ना कोल्हू/कृषक वगैरा को नहीं बेचना पड़ता।

सरकार 'उज्ज्वला योजना' का बहुत प्रचार कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब ये 'उज्ज्वला योजना' को लेकर आये थे, तब गैस सिलेन्डर मात्र छः सौ रुपये का था और आज उस सिलेन्डर की कीमत बढ़कर लगभग रू0- 1100-1200 हो गयी है। जब ये कहते हैं कि हमने इतने हजार सिलेन्डर मुफ्त में बांट दिये, लेकिन उस बांटने से फायदा क्या हुआ कि आज जब सिलेन्डर एक बार मुफ्त में मिल जाता है। वह तो मुफ्त में वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो पैसा है उसमें हर बार सब्सिडी लगकर आता है, लेकिन अगर गैस सिलेन्डर मुफ्त में दे भी दिया जाता है, तो उन मां और बहनों का, जिनका पसीना पोंछने के लिए यह योजना लायी गयी। आज वह मजबूर हैं, जब अपनी कमाई को वह देखते हैं, तो सोचते हैं कि इतना महंगा सिलेन्डर कैसे भराएं ? इससे अच्छा लकड़ी से खाना बनाये, तो अच्छा होगा और आज वह लकड़ी से खाना बनाने के लिए मजबूर हो गये है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यही हाल बिजली का भी है। बिजली का मैं अभी देख रहा था कि इतने बड़े बजट में लाईन/ट्रांसफार्मर बदलने/रखने के लिए कोई भी पैसा किसी मद में स्वीकृत नहीं किया गया है। जहां-जहां नई बस्तियां/मजरे बस गये हैं, उनमें कई-कई जगह आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि बल्लियों के माध्यम से तार पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर खम्भे नहीं हैं, बिजली की लाइनें नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि हम 24 घण्टे प्रदेश में बिजली देने का काम कर रहे हैं।

मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर इन्फ्रास्क्ट्रचर में पिछली सरकार में वह इतना काम नहीं करते, इतने सारे पावर स्टेशन न बनवाते तो आज आप 17 घंटे 18 घंटे तो क्या 8-6 घंटे भी बिजली न दे पाते। यह अगर देन है तो माननीय अखिलेश यादव जी की है जिन्होंने इतने बड़े पावर स्टेशन बनवाये। मेरे अपने जनपद में मेरी अपनी विधान सभा में 9 बिजलीघर बनाने का काम किया गया था। लेकिन इस बार एक भी बिजलीघर का प्रस्ताव मेरे जनपद बिजनौर या मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना में नहीं किया गया। मान्यवर, कानून व्यवस्था के नाम पर कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की है और इसका सारा सीधा-सीधा उदाहरण आप रोज टी0वी0 चैनल पर देख सकते हैं और समाचार पत्रों में किस प्रकार से छपा होता है कि आज यहां लूट हुई, यहां चोरी हुई, यहां डकैती हुई। पुलिस को आप जब तक आधुनिक हथियारों से लैस नहीं करेंगें गाड़ियों से लैस नहीं करेंगे, तब तक कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, माननीय अखिलेश जी ने इसके लिये 100 नम्बर शुरू की थी लेकिन उस 100 नम्बर को बदल कर इन्होंने 112 कर दिया। कोई नई व्यवस्था इन्होंने नहीं की सिर्फ नाम बदलने का काम इन्होंने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैं दूसरा नाम पुकारने जा रहा हूं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा फिर समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं बहुत समय हो गया है। अब आप समाप्त करें। बहुत लम्बी सूची है। श्री बल्देव औलख जी, आप अपनी बात कहें।

श्री मनोज कुमार पारस-

आप से ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायं। आपका लिखा नहीं जायेगा।

***जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बल्देव सिंह औलख)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इतने बड़े बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सिंचाई व्यवस्था को प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के माध्यम से सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक) परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित जल शक्ति विभाग के अन्तर्गत रखा गया है। मान्यवर, मैं अपने विभाग के ही बजट को लेकर आ रहा हूं क्योंकि यह किसानों की आय को दोगुनी करना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाय और उस सपने को माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको साकार करने का 2017 से 2020 तक बीड़ा उठाया और इतना बड़ा बजट आज सिंचाई विभाग को उन्होंने दिया है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑपोजिशन वाले किसानों के बड़े हितैषी बनते हैं और अपना गला फाड़ फाड़ कर किसानों की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार में 30-30 साल से पुरानी योजनाएं पड़ी हुईं थीं कोई भी बजट उनको देने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि इनके और बहुत सारे ऐसे धन्धे थे जिनकी वजह से इनका किसानों की तरफ ध्यान नहीं था। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का बहुत बड़ा हितैषी होने के नाते उन्होंने बहुत बड़ी योजना जिससे बहुत बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते थे। बाण सागर योजना जो 1997-1998 में शुरू की गई थी। हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस परियोजना के लिये धन की व्यवस्था करते हुए वर्ष 2018 में इसको पूर्ण कराने का काम किया है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जुलाई 2018 में लोकार्पण किया गया। बाण सागर सिंचाई योजना से मिर्जापुर के लगभग 1 लाख 70 हजार किसानों को फायदा हुआ है और 1 लाख 50 हजार 132 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की यह योजना है। यह है किसानों की आय को दोगुना करने का। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं बुन्देलखंड में जो कि बहुत पुराने समय से पड़ी हुई थीं जिनको देखा नहीं गया जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया और 7 परियोजनाएं पूर्ण कराई गईं इस दो तीन साल के अंदर। जिसमें पहुज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, गुंटा बांध परियोजना और पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना है ऐसी बहुत सारी योजनाएं है जिनको पूरा करके 58 हजार किसानों को लाभांवित किया गया है। 2 लाख 66 हजार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हेक्टेयर भूमि के सिंचन का प्राविधान किया गया है। एक बहुत पुरानी योजना 1978 से 1979 के बीच सरयू नहर परियोजना आई थी बहुत सारी सरकारें आईं लेकिन इसकी ओर धन का कोई आवंटन नहीं किया गया जिसकी वजह से किसानों को बहुत प्रभाव पड़ा है।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी की सरकार बनते ही यह परियोजना लायी गयी थी 14 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित करने वाली यह योजना है, 1 लाख 26400 कृषक इससे लाभान्वित होंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी इस योजना के तहत 3445 करोड़ रुपये का आवंटन करके इसे इसी साल पूर्ण करने की स्थिति में हैं और इस परियोजना हेतु 1554 करोड़ का बजट रखा है यह सिर्फ किसानों को ध्यान में रखते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी अब आप समाप्त करें।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिम में मध्य गंगा जो कि 2007-2008 में इनकी सरकारों में लायी गयी थी मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस योजना को सिर्फ खोलने के लिए 66 करोड़ रुपये दिये गये। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में सिर्फ एक योजना बनाना, परियोजना को तैयार करना, उस पर ठेका पट्टा करना, उसके बाद पैसे का आवंटन न करना, ऐसे ही योजना को छोड़कर चले जाना यही होता था। गंगा, मध्य गंगा जो कि हरिद्वार से निकलकर पश्चिम में होते हुए जायेगी तो इससे हमारे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 2020-2021 के बजट में 1 हजार 736 करोड़ की परियोजना देकर इसे इसी साल पूर्ण करने का काम होगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी अब आप बैठ जायें।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों से जो बाढ़ का पानी बहुत सारी तबाही करता था मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछली सरकारों में जो बाढ़ का बजट होता था,

वह मई, जून में अलाट करते थे, वह बजट पिछली सरकारों और ठेकेदारों के मजे के लिए रहता था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी अब आप समाप्त करें, बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह बजट फरवरी, मार्च में देने का काम किया है, जिससे बाढ़ के कारण बहुत कम क्षति होने का काम हुआ है। 966 करोड़ रुपये बजट रखा गया है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नहरें किसानों की भाग्य रेखा हैं जो कि आपने देखा कि पिछली सरकारों में कहीं भी नहरों की सफाई नहीं होती थी, आज विपक्ष के साथी भी बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने यह काम किया है कि अगर टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और टेल तक पानी पहुंचाकर सार्टिफिकेट नहीं लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, दूसरे का समय ले रहे हैं।

श्री बल्देव सिंह औलख-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 वित्त मंत्री जी को, मा0 वित्त राज्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में एक बड़ा बजट देने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय कुमार राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2020-21 के इस बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 2020-21 का बजट बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला कल्याण हेतु सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ रोजगार, व्यापार, हुनर, शिक्षा, दवाई और बेटी की विदाई तक की बात कही गयी है। मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 का पहला बजट इस देश के किसानों और नौजवानों के लिए, वर्ष 2018-19 का दूसरा बजट प्रदेश में उद्यमियों के लिए और तीसरा बजट हमारी मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित इस प्रदेश की महिलाओं के लिए था। अभी आपके सामने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि यह जो बजट आया है, यह बजट प्रदेश में युवाओं को समर्पित बजट है। मैं इस प्रदेश के युवाओं की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार को, मा0 योगी आदित्यनाथ जी को, मा0 वित्त मंत्री जी को, मैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनायें और बधाई देता हूं। इस प्रदेश

में युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है, इस क्रम में हमारे जनपद में भी युवाओं की एक बड़ी फौज है। हमारा जिला मऊ जनपद है, जिसकी उपेक्षायें अन्य पूर्व की सरकारों द्वारा होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

गोरखपुर और बनारस के बीच एक छोटा सा जिला मऊ स्थित है। मैं आपके माध्यम से, अपने जनपद के लिए, एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज बनाये जाने की मांग करता हूं। हमारा विधान सभा क्षेत्र घोसी जहां दो बड़े-बड़े तालाब है एक पिहुआं ताल, दूसरा ताल नरजा जिसका क्षेत्रफल लगभग 100-100 एकड़ से भी अधिक है मैं मा0 जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं व आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन दोनों तालाबों का विस्तार करके इनको संरक्षित करके वहां के मछुवारा समाज जिनका जीवन यापन उन दो तालाबों से होता है मैं आग्रहपूर्वक मांग करता हूं कि जल संरक्षण की कोई योजना लाकर मछुवारों के जीवन को और सरल बनाया जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र घोसी में स्थित चीनी मिल, जहां पर आजमगढ़, मऊ, बलिया तीन जगहों से गन्ना भारी मात्रा में आता है, किसान लेकर आते हैं, मैं आग्रह करता हूं कि इस चीनी मिल का विस्तार कराया जाए व उसकी क्षमता वृद्धि कराई जाए एवं उसका कुछ अंश बकाया रह गया है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसका भुगतान कर दिया जाए। विधान सभा क्षेत्र घोसी में स्थित इंदारा रेलवे क्रासिंग जिस पर आए दिन 80 से 90 हजार वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि यहां पर एक आर0ओ0बी0 का निर्माण कराया जाए। जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरा- (ग्राम सभा) पिपरसात के गोलार घाट के पास तमसा नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं। जनपद मऊ की सदर तहसील में कूड़े के ढेर में पड़ी डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा, जो लम्बे समय से पूर्व की सरकारों द्वारा उपेक्षाओं का कारण बनी रही है मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको तहसील प्रांगण में शिव मंदिर के बगल में स्थापित कराया जाय। जनपद मऊ में बन्द पड़ी दो-दो काटन मिलें एक परदहा कताई मिल और दूसरी स्वदेशी काटन मिल को पुनः चालू कराए जाने की मैं मांग करता हूं, जनपद मऊ के पत्रकार बंधुओं के लिए जो लम्बे समय की मांग है मैं उनके लिए एक पत्रकार भवन का निर्माण मऊ में कराए जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विजय कुमार राजभर-

मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। जनपद मऊ में ब्लाक रानीपुर में स्थित अति प्राचीन धार्मिक स्थल जो देईया माई के स्थान के नाम से जाना जाता है उसकी भूमि को कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, मैं मांग करता हूं कि उस भूमि को संरक्षित कर, वहां का सौंदर्यीकरण कराया जाए। हमारे मऊ नगर पालिका क्षेत्र में जो लम्बे समय से विवादित

भूमि थी, जहां फुटपात के लोग अपना ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे वह जमीन अब नगर पालिका के पक्ष में चली गई है एवं ठेला, खुमचा हटवाया जा रहा है। लेकिन चालीस से पचास वर्षों तक वहां फुटपात के लोग अपना ठेला खुमचा लगाकर उस जमीन का संरक्षण करते थे वहां एक वेंडर कमेटी है जिसका अध्यक्ष मैं स्वयं हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विजय कुमार राजभर-

मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर वहां नगर पालिका द्वारा कोई दुकानों का निर्माण होता है तो, सबसे पहले वरीयता क्रम में फुटपात के लोगों को दिया जाय उ0प्र0 के समस्त राजभर समाज के लोगों के आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक व संस्कृतिक विकास सरकार द्वारा कराने पर विचार किये जाने की मांग करता हूं। अन्त में मैं इस बजट के पक्ष में अपने विचारों को इस बजट से जोड़ते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे 2020-21 के बजट भाषण में बोलने का मौका दिया मैं आपको हृदय की अनन्त गहराई से धन्यवाद देता हूं। सदन में उपस्थित सभी सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों को भी साथियों को भी पैर छूकर उनको बधाई देता हूं। सम्मानित साथियों वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं आठ बार के सदस्य हैं उन्होंने हर व्यक्ति की चिन्ता करके उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की चिन्ता करके बहुत बढ़िया बजट बनाने में पूरी ऊर्जा लगाने का काम किया है। अध्यक्ष जी पहले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी कुछ गांवों में विकास होता था कुछ गलियों में विकास होता था यह मैं बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी पांच लाख करोड़ से ऊपर का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का जो दिया है इसकी हम भूरि-भूरि प्रसंशा करते हैं। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सन्त मिलन को चालिए तजि माया अभिमान ज्यों-ज्यों पग आगे धरो सौ सौ यज्ञ समान। अध्यक्ष जी शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल संत। तैसे शीतल सन्त जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। धीरज शील सुभाव क्षमा न जाति बखानी कोमल अति मृदु बेन बज्र को करतें पानी। अध्यक्ष जी रहन चलन मुस्कान ज्ञान को तीन ताप मिट जाएं सन्त के दर्शन पावे। पलटूँ ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरन्त, शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल संत।' माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत कम समय लूंगा। मैं आपको अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं। परम् आदरणीय योगी जी ने हमारे फिरोजाबाद के लिये एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया। लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया। हमारे यहां पर 16 लाख श्रमिक भाई-बहन रहते हैं, उनका

उपचार उस मेडिकल कॉलेज में होगा। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद-फिरोजाबाद में 40 हजार आवास देने का काम किया है और एक आवास की कीमत ढाई लाख रुपये है, जिसमें से 20 हजार आवासों की तीनों किश्तें उन लाभार्थियों के खाते में पहुंच गयी हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं। इस बजट से पेट स्कैन, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड स्कैन और कैंसर की तमाम बीमारियों की बड़ी-बड़ी मशीनें उत्तर प्रदेश सरकार में आयेंगी और 23 करोड़ लोगों को उन मेडिसिन्स का, उन बड़ी-बड़ी मशीनों का लाभ मिलने का काम होगा। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के रामदासपुरा गांव में सोफीपुर, शंकरपुर, मालीपट्टी, उस्मानपुर, कटीनर बहुत से ऐसे गांव पड़ते हैं जहां पर आपके आशीर्वाद से अगर एक पुल नदी पर बन जायेगा तो 50-60 गांव यानी 50-60 हजार लोग जो कि मेरी विधान सभा के हैं उनको भी लाभ मिलेगा और जो फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र पड़ती है उसको भी पूरा लाभ मिलेगा और सरकार को भी लाभ मिलेगा कि उसका पेट्रोल बचेगा, क्योंकि इससे उसकी दूरी मात्र 02 किलोमीटर हो जायेगी। यह मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, सोफीपुर में एक गाटा संख्या-38 में ग्राम सभा की खाली पड़ी भूमि पर अगर एक अटल आवास अथवा जिला अस्पताल बन जायेगा तो उन गरीब श्रेणी के बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यह मेरी मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक मांग और है कि शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फरौल नगरिया जो कि परम् पूज्य अटल बिहारी जी का ग्राम था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका सपना था कि फरौल नगरिया में यमुना नदी के नीचे एक बहुत बड़ा बैराज अगर बन जायेगा तो फिरोजाबाद से लेकर आगरा तक के किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, अब आप समाप्त कर दीजिये। बहुजन समाज पार्टी से श्री आजाद अरिमर्दन जी।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा कि 'कभी गर्मी कभी सर्दी, यही कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वह भी रहते हैं, जो दरिया के किनारे हैं।' मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, आपको और सदन के सभी अपने भाइयों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। मैंने माननीय अरिमर्दन जी का नाम पुकार लिया है, अब आप बैठ जाईये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, यह बजट पूर्णतः काल्पनिक है, व्यवहारिकता से परे है, जनहित विरोधी है तथा प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ है। विशेष कर यह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, एस0सी0 विरोधी है, एस0टी0 विरोधी है, ओ0बी0सी0 विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और साथ में गरीब सवर्णों के भी विरोधी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में आय के स्रोतों का तो उल्लेख नहीं है, बल्कि व्यय को ज्यादा से ज्यादा अनुत्पादक कार्यों में दिखाया गया है जो बाह्य आडम्बर तथा अंधविश्वास से भरा पड़ा है। प्रदेश सरकार द्वारा नयी योजनाओं का तो जिक्र किया गया है जो जमीन से परे केवल एक कागजी पुलिन्दा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त, अपराधमुक्त बनाए जाने का नारा देती है जो 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' जैसा प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों, तहसील, थानों, ब्लॉकों में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है और बगैर रिश्वत दिये कोई काम नहीं हो रहा है, यहां तक कि जनप्रतिनिधियों की बात भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जहां तक सरकार ने पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का वायदा किया था तो आज पूरे प्रदेश में आये दिन लूट हत्या, छिनैती, डकैती आदि की घटनायें हो रही हैं। पुलिस जनता की बात नहीं सुन रही है आये दिन पुलिस और जनता के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। मान्यवर अभी हाल में सामंतियों द्वारा कानपुर में दलितों पर हमला एवं आजमगढ़ के कप्तानगंज के वाजिदपुर में सामंतियों ने एक जुट होकर दलितों की बस्ती पर लाठी, डण्डों, हथियार एवं असलहों से हमला किया और साथ में पूजनीय बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्तियां भी तोड़ी गयीं जिससे पूरे गांव में भय का वातावरण बना हुआ है निर्दोषों को फर्जी मुकदमें में फंसाया जा रहा है और दोषियों को बचाया जा रहा है। अभी हमारी विधान सभा क्षेत्र लालगंज बाजार में दिन में ही दूल्हे की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है और वहां का एस0एस0पी0 क्राइम की मीटिंग लेता है और उस मीटिंग से 500 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक और आदमी की हत्या कर दी जाती है। इससे और दुखद दिन क्या हो सकता है ? आजमगढ़ के बरदा थाना में दूबरा बाजार में जहां दिन दहाड़े 40 लाख की डकैती कर दी जाती है और आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और जिसको गोली मारी गयी है वह पी0जी0आई0 लखनऊ में अपने जीवन मरण की स्थिति में बना हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने इस बजट में अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा तमाम बातें किसानों के बारे में की गयीं। जहां तक किसानों की आय के बारे में इस बजट में

कहा गया है यह कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी। जब आप बिजली की दर बढ़ा दिये, खाद्य, बीज, यहां तक कीटनाशक दवाओं के दाम भी आपने दूना कर दिया। हमारे प्रदेश के किसान जो हमारी दलहने फसलें थीं उसको उगाना बन्द कर दिया है इन आवारा पशुओं की वजह से और यहां तक की हमारे धान, गेंहू फसलें नष्ट कर दे रहे हैं, कैसे आय दोगुनी होगी, यह विचारणीय प्रश्न है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश की बिजली की समस्या बहुत विकराल है आप विद्युत कनेक्शन तो दे रहे हैं लेकिन उन पर फर्जी बिल आ रहे हैं। उन गांव में खम्भे, तार, ट्रान्सफार्मर जर्जर की स्थिति में बने हुए हैं। यहां तक की आर0सी0 तक दी जा रही है। यह सरकार वादा कर रही है कि इस बजट में यह नौजवानों का बजट है, जहां तक नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था इस सरकार ने इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है कि नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जायेगा। रोजगार में तमाम जगह उनका निजीकरण करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन विभागों को भरा जा रहा है जिसमें एस0सी0एस0टी0/ओ0बी0सी0 का कोई आरक्षण नहीं है। यहां तक कि एस0सी0एस0टी0/ओ0बी0सी0 के सरकारी पदों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन उसे भरने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं इस बजट में मांग करता हूं कि बैकलाग के माध्यम से एक विशेष अभियान करके उन एस0सी0एस0टी0/ओ0बी0सी0 के अनुपात में उनके सरकारी पदों को भरा जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र लालगंज की तरफ रखना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में ठेकमा बाजार काफी वृहद् है, बड़ी जनसंख्या में है उसको टाउन एरिया घोषित किया जाये और साथ में ठेकमा बाजार को बाईपास के रूप में भी सड़क का निर्माण किया जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आजमगढ़ के लालगंज में राजकीय महाविद्यालय की भी मांग करता हूं साथ ही एक इंजीनियरिंग कालेज जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज था उसका नाम पुनः कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज कर दिया जाये। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड पल्हना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं साथ ही जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड लालगंज में ग्राम चेवार पूरब में मांगी नदी के पुल से ग्रा0-गोवर्धनपुर की ओर सड़क निर्माण की मांग करता हूं साथ ही जनपद आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज के बुढ़उबाबा केराकत सम्पर्क मार्ग से विधान सभा क्षेत्र केराकत की सीमा तक सड़क निर्माण की मांग करता हूं तथा मैं विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ठेकमा ब्लाक में महुआरी के पंचायत भवन से ग्राम-फेटी का सड़क निर्माण की मांग करता हूं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र लालगंज में जहां पर किसान फल, अनाज का उत्पादन करते हैं वहां मण्डी के निर्माण की मांग करता हूं। मैं विकास खण्ड पल्हना में चौकी को थाना बनाये जाने एवं उप फायर स्टेशन की भी मांग करता हूं। आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के सामुदायिक केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा एवं नियमित डाक्टर एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं

अपनी बात को सपा और बसपा नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी वर्मा जी की बातों से सम्बद्ध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री विजय कुमार कश्यप-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं बजट भाषण को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस जनहित के बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जबसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तबसे हमारी सरकार ने प्राथमिकता पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रशासन देने के साथ-साथ जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। जनता की शासन सत्ता में भागीदारी की पुनर्स्थापना सरकार का लक्ष्य रहा है। हमारी योगी सरकार ने शासन की नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम किया है। हमारी सरकार ने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है एवं भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का भी काम किया है। मेरे पास राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व है और मैं उस पर भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारी योगी सरकार ने राजस्व, आपदा राहत, बाढ़ तथा चकबन्दी के संबंध में जो उल्लेखनीय कार्य किये हैं उनमें राजस्व विभाग द्वारा मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, सम्पूर्ण समाधान दिवस, भू-अभिलेख/खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, भू-मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, खतौनी पुनरीक्षण एवं खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण, अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। हमारी सरकार के दौरान उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में काम किया गया है। प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 में प्रारम्भ की गई थी। इसका भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा संबंध है। चकबन्दी प्रक्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनायें पूर्ण की गईं, जिसमें 310 गांवों को सुरक्षित किया गया तथा वर्ष 2017-18 में 100 परियोजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 112 परियोजनायें पूर्ण कर 556 गांवों को सुरक्षित किया गया तथा 2018-19 में कुल चलित 246 परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2020 तक 149 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ व जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। योगी सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में बाढ़ की विभीषिका के कारण तटबन्धों के क्षतिग्रस्त होने में कमी तथा नदियों द्वारा अपना रास्ता बदलने

के उद्देश्य से पायलेट बेसिस पर घाघरा, गण्डक एवं राप्ती नदी में ड्रेजिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराया गया है तथा मा0 योगी जी ने बजट में इस वित्तीय वर्ष में बाढ़ से जनसामान्य को बचाने हेतु 966 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है इस हेतु मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके साथ-साथ अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र दूरदराज के गांवों की विधान सभा क्षेत्र है जिसमें विकास कराने की बहुत आवश्यकता है। मेरी विधान सभा में तहसील मुख्यालय नहीं है। मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र काफी दूर पड़ता है। आने-जाने में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से चरथावल नगर को तहसील बनाने की मांग करता हूं शामली जिले के थानाभवन नगर से मुजफ्फरनगर तक का मार्ग जो मेरी विधान सभा क्षेत्र चरथावल होकर जाता है, अत्याधिक व्यस्ततम मार्ग है तथा यह हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। मैं इस मार्ग को फोर लेन बनवाने का अनुरोध करता हूं। मुजफ्फरनगर में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है और यहां पर एक मेडिकल कालेज की अत्यन्त आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर शहर में एक गन्ना फार्म है जिसमें मेरी विधान सभा क्षेत्र का भी भाग लगता है उस भूमि पर इस मेडिकल कालेज को बनवाने की मैं मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में एक महिला इण्टर कालेज तथा एक महिला कालेज स्वीकृत किया गया है लेकिन अभी भी वहां पर एक महिला डिग्री कालेज तथा एक पालीटेक्निक कालेज भी बनाने की आवश्यकता है। यहां पर एक मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की भी जरूरत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के इस लोक लुभावन, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस सदन का बहुत-बहुत वन्दन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट के विरोध में बोल रहे विपक्ष के सम्मानित नेताओं और उनके वक्ताओं को सुन रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह हताशा से सराबोर हैं। क्योंकि यह जो बजट है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है। पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक कल्याण, महिलाओं के विकास का, युवाओं के रोजगार का और किसानों और श्रमिकों को समर्पित, सामान्य वर्ग के कल्याण का बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास का मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमान् सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुझे जहां तक जानकारी है कि हिन्दुस्तान की सभी स्टेट से सर्वाधिक बड़ा बजट जो पांच लाख 12 हजार करोड़ के लगभग प्रस्तुत किया है। इससे विपक्ष हतप्रभ और हैरान है। सरकार द्वारा सभी पहलुओं को, सभी वर्गों को छूने वाले इस बजट के लागू होने के बाद सभी

विपक्षी दलों की बोलती बन्द हो जायेगी। जो लोग दलित, पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंक कर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करते थे उनकी दुकानें बन्द करने वाला बजट है। मान्यवर, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास करने के लिए संकल्पित हैं और उसका विकास करके रहेंगे। इस बजट से निःसंदेह बेरोजगारी में कमी आयेगी। प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। यह बजट विकास एवं अवस्थापना के साथ-साथ प्रदेश में डिफेंस एक्सपो के माध्यम से 50 हजार करोड़ का निवेश करने का काम इस सरकार ने किया है और इनवेस्टर समिट के माध्यम से भी दो लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। जिससे हजारों, लाखों नौकरियों के अवसर इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलने वाले हैं। मान्यवर, हमारी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से प्रदेश का विकास करने के साथ-साथ इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने का काम करेगी। बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धों के लिए स्वाधार गृह योजना लागू करने का भी हमारा प्रस्ताव इस बजट में है। प्रत्येक जनपद में युवाओं के लिए युवा हब स्थापित करने का कार्य भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगभग 21 मेडिकल कालेजों का संचालन करना इस बजट की उपलब्धि है। मान्यवर, हमारी सरकार ने बन्द पड़ी चीनी मिलों को चलाकर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गन्ना किसानों का जो ऐतिहासिक भुगतान किया है यह भी इस सरकार का बहुत बड़ा कार्य है। चाहे हमने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना और सौभाग्य विद्युत कनेक्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का संकल्प लिया है। मान्यवर, यह बजट महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, किसानों, श्रमिकों के साथ-साथ सभी के विकास का बजट है। सामाजिक समरसता को और इस उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले बजट का मैं पुरजोर समर्थन करने के साथ-साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र 117, दाटागंज में एक चीनी मिल की स्थापना और एक स्टेडियम की स्थापना तथा एक कम्युनिटी सेंटर के साथ-साथ दो छोटे पुल और 20 किमी0 सड़क की मांग करता हूं जिससे मेरी विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य और अधिक हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री ज्ञानेन्द्र-

अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2020-2021 वित्त मंत्री मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का भारी भरकम

बजट गांव, गरीब, किसान, झुग्गी-झोपड़ी का इंसान, नारी का सम्मान, महिला का उत्थान यह सभी इससे प्रभावित होते हैं। यह सभी वर्गों के लिए और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ सम्मानित जनता का विश्वास इस बजट ने अर्जित किया है। मान्यवर, नमामि गंगे मिशन जो 27 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक गंगा यात्रा जो निकाला गया।

मान्यवर, हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है। मैंने पूर्व में भी सिंचाई मंत्रियों के कार्यों को देखा है। इस बार जल शक्ति मंत्री मा0 महेन्द्र सिंह जी ने व्यवस्था बनाई है। उसमें उत्तर प्रदेश की नहरों, माइनरों, एवं रजवाहों की एक साथ सफाई करा करके हेड से टेल तक पानी देने का काम किया है। जल जीवन मिशन का भी गठन हुआ है, जो हमारी सरकार की योजना है। सरकार की पाइप पेयजल से हर घर को जल देने की योजना है जिस तरह से हर घर को बिजली देने का काम किया गया है, हर परिवार को गैस कनेक्शन देने का काम किया गया है। उसी तरह से सरकार की हर घर को पानी उपलब्ध कराने की योजना है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस योजना के तहत बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लिंक से गोरखपुर को जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बात सपा एवं बसपा के लोग करते हैं। कानून-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमने सपा एवं बसपा के शासनकाल में देखा है कि थाने में सी0ओ0 को गोली मारी गई, दरोगा को पीटा जाता रहा है और थानों में बलात्कार की घटनाएं होती रही हैं। इस समय कानून-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। कदाचित यह सदन सहमत होगा कि केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज लिंगानुपात में अन्तर आ रहा है। यदि किसी के परिवार में बेटा जन्म लेता है तो पूरा परिवार खुशी मनाता है, किन्नरों को बुलाया जाता है, सोहर गवाये जाते हैं, लेकिन जब बेटी जन्म लेती है तो लगता है कि पूरे परिवार पर वज्रपात हो जाता है। इस योजना को फलीभूत करने के लिए माता-पिता को बेटी के पैदा होने पर कष्ट न हो, हमारी सरकार की योजना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार ने कक्षा-1 से लेकर परास्नातक तक बेटियों की शिक्षा को मुफ्त करने हेतु कन्या सुमंगला योजना चलाई है। हम पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी लोक सभा में हर साल इस विषय को उठाया करते थे। इंसेफेलाइटिस के कहर से छोटे-छोटे बच्चे असमय काल के गाल में समा जाया करते थे। उसमें 56 प्रतिशत की कमी आई है और सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में हर रविवार को मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगता है उस मेले में जनप्रतिनिधि जाते हैं, वहां पर मरीजों का चेकअप होता है और उनको दवाई भी उपलब्ध कराई जाती है। मेरे वहां मा0 मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ जी के द्वारा 30 बेड के महिला अस्पताल का उद्घाटन किया जा चुका है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण भी हो रहा है। हमारे क्षेत्र में तमाम सुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुना कैसे होगी ? हमारी सरकार ने 03 करोड़ किसानों के मृदा हेल्थ कार्ड

जारी किये हैं और मिट्टी की जांच कराई है। मिट्टी में उर्वरक की कमी होने पर बीज एवं खाद समय से उपलब्ध करायेंगे। स्वाभाविक है कि फसल अच्छी पैदा होगी और जब फसल अच्छी पैदा होगी तो हमारी सरकार खरीद करेगी। उसका उचित लाभ किसानों को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी। गन्ना किसानों की बात हो रही थी और मैं भी किसान हूं। अभी गन्ना किसानों को 89 हजार 700 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। हमने पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा है, इस सदन में कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। सपा एवं बसपा शासनकाल में मिलों को बेचा जाता था, बहुत-सी मिलों को बेच दिया गया। लेकिन हमारी सरकार ने बन्द चीनी मिलों को चलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने पिपराइच एवं मुण्डेरवा नयी चीनी मिल लगा कर गन्ना किसानों को उपहार के रूप में दिया है। गन्ने से गन्ना किसान को कैश प्राप्त होता है और इन चीनी मिलों से गन्ना किसान लाभ प्राप्त कर रहा है। मुख्य मंत्री आवास योजना में 50 हजार 740 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। वनटांगिया, मुसहर, कोल, भिल्ल आदि जो खाना-बदोश की जिदंगी जी रहे थे, हमारी सरकार ने उनको राजस्व का दर्ज दिया, आवास की सुविधा दी, बिजली दिया। सड़क दिया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, अभी ढाई मिनट ही तो हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उन सभी के लिए आवास की योजना बनाकर मकान उपलब्ध कराया। हमारी सरकार 18 घंटा, 20 घंटा और 24 घंटा बिजली दे रही है जबकि हमने पूर्ववर्ती सरकारों को देखा है जिनमें कुछ जिले वी0आई0पी0 जिले घोषित होते थे। सपा-बसपा के शासनकाल में वी0आई0पी0 जिले थे लेकिन योगी जी के शासन काल में कोई जिला वी0आई0पी0 नहीं है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से बिजली मिल रही है। हमारे क्षेत्र में दो सब-स्टेशनों का निर्माण हुआ है इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा एक विधान सभा क्षेत्र पनियरा था जहां एक भी टाउन एरिया नहीं था, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, पूर्व नगर विकास मंत्री मा0 श्री खन्ना जी और वर्तमान नगर विकास मंत्री मा0 टण्डन जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक साथ दो-दो टाउन एरिया उन्होंने दिया है। लोक निर्माण विभाग ने भी चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है, 99 प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त हो गयी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 42 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। एक बात बताना चाहूंगा कि जनपद महराजगंज में पंकज चौधरी चार बार सांसद हुए थे, एक भी चौड़ी सड़क हमारे जनपद में नहीं दिखाई पड़ती थी, केवल गोरखपुर से एक चौड़ी सड़क नौतनवां तक जाती थी। पांचवीं बार पंकज चौधरी सांसद हुए, केंद्र में भाजपा

की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्य मंत्री बने तथा केशव मौर्य जी लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने, आज हमारे जनपद महराजगंज में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसका चौड़ीकरण न हुआ हो। मेरे क्षेत्र में भी तीन सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुआ है, मेरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंदिर था, उस समय रीता बहुगुणा जोशी जी पर्यटन मंत्री थीं, वर्तमान में सांसद हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 30 लाख रुपया देकर उस मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री ज्ञानेन्द्र-

मेरी विधान सभा में तहसील नहीं है, परतावल और पनियरा के मध्य, मैं तहसील की आपके माध्यम से मांग करता हूं। भटहट-धोड़हवा एक मार्ग है जो गोरखपुर से चलकर बमनौली तक जाता है, बमनौली से महराजगंज जाता है, महराजगंज से नौतनवां और नौतनवा से नेपाल को जोड़ता है, उन सड़कों को बनवाने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत लंबी सूची है, अब आप समाप्त करिए। धन्यवाद।

श्री ज्ञानेन्द्र-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

समाजवादी पार्टी से श्री सुभाष राय जी हैं।

श्री सुभाष राय-

मान्यवर, आपने मुझे वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को क्रमशः किसानों, औद्योगिक विकास, नारी सशक्तीकरण का बजट बताया गया है लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। केवल बजट में हवा-हवाई बातें कही गयी हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के बजट में युवाओं को लाभ देने की बात की गयी है लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। आज यह सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन आज पूरे देश-प्रदेश की क्या स्थिति है, पहले दूरसंचार में जहां दो-दो लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज घटकर उनकी संख्या 30 हजार हो गयी है। एयर इंडिया बिकने जा रहा है, रेलवे बिकने जा रहा है, सारे कर्मचारी परेशान हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव को धन्यवाद देना

चाहूंगा जिन्होंने रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हुए इस प्रदेश के 18 लाख लड़के-लड़कियों को लैपटॉप देकर रोजगार का बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया था। इसके पीछे माननीय अखिलेश यादव जी की जो मंशा थी, वह यह थी, चूंकि पूरे देश में कर्नाटक और केरल सबसे अगड़ा प्रदेश माना जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को अगड़ा प्रदेश बनाने के लिए जो आज तकनीकी का दौर है, आज तमाम झोपड़ी में रहने वाले लड़के और लड़कियां, जिनके बाप पैसे के अभाव में अपने बेटे और बेटियों को लैपटॉप नहीं दे पाते थे, वह प्रतिभावान होते थे, इस सोच के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसे बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया था और रोजगार से जोड़ने का काम किया था। इसके साथ-साथ इस बजट में औद्योगिक विकास में इन्वेस्टर्स समिट के योगदान का जिक्र किया गया है। इस सन्दर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्वेस्टर्स समिट में काफी समय बीत गया है लेकिन इसमें कितना निवेश प्राप्त हुआ, इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात की गयी है। जब से प्रदेश के दो बड़े शहरों-लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर प्रणाली लागू की गयी है, आज दोनों शहरों में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है जो किसी से छिपा नहीं है। मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं, आज पुलिस भी काम के बोझ से अवसाद का शिकार हो गयी है। मेरा जो स्थानीय थाना जैदपुर है, उस थाने का इन्सपेक्टर रात के 2.00 बजे फांसी लगाकर मर जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आज रात की बात है। (विपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम कहा) यह तो यहां की कानून-व्यवस्था है। इसके साथ-साथ 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' की इसमें बढ़ावा देने की बात की गई है। आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। आज सत्ताधारी दल के विधायक किस तरह से बेटियों के साथ अपराध कर रहे हैं, यह भी जगजाहिर है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जो स्थिति है, मैं अपने जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अम्बेडकरनगर में 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये और बन करके 03-03 वर्षों से तैयार हैं लेकिन आज वह डाक्टर के अभाव में संचालित नहीं हो रहे हैं। दवाओं के सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कमेटी बनाकर जांच करा लीजिए, जनपद अम्बेडकर नगर में 03 दिन से जिला मुख्यालय सदर अस्पताल से लेकर के किसी भी सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर कुत्ता काटने का इन्जेक्शन और दवा नहीं है। इसके साथ-साथ इस बजट में किसान की आय दोगुनी करने की जो बात की गयी है, किसान मारे-मारे फिर रहा है, वह अपनी उपज का वाजिब मूल्य भी नहीं पा रहा है। आज शिक्षा में, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, आज अध्यापकों की संख्या घट करके 3/4 हो गयी है। अधिष्ठाता जी, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं। मेरे जिले से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रहा है, वहां किसानों की जमीन की रजिस्ट्री करा ली गयी है, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया है और जबरदस्ती उनकी फसल काट करके सड़क

बनायी जा रही है। किसान आन्दोलनरत है। इसके साथ-साथ मैं बजट के बारे में कहना चाहता हूं, इस बजट में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाये गए हैं, धरातल पर सफलता की इसमें कोई बात नहीं कही गयी है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे जनपद से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इसमें जलालपुर विधान सभा की पचासों गांवों की जमीन ली जा रही है, लेकिन वहां के लोगों को उस पर चलने की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, उस एक्सप्रेस वे पर अप्रोच मार्ग बनाया जाए। अधिष्ठाता जी, मेरे विधान सभा के मुंगराडिला-न्योरी मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाए। मालीपुर-जलालपुर-रामगढ़ मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाए। मेरे यहां जलालपुर और भियांव में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोला जाए, जलालपुर में बाईपास बनाया जाए, जलालपुर में उर्दू बाजार से मुंगराडिला जाने के लिए तमसा नदी पर पुल बनाया जाए, जलालपुर के विकास खण्ड भियांव में करमुलहा और उड़ारी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए तथा मालीपुर और नगपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार शर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2020-2021 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, 19 मार्च, 2017 को जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो विरासत में अर्थ-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था एक कूड़े के ढेर के रूप में मिली। प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि थानों को ठेकेदार चलाते थे, अपराधी थानों को चलाते थे। चारों तरफ भय, भ्रष्टाचार और गुण्डाराज व्याप्त था। मा0 योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज्य स्थापित हुआ है। आज गुण्डे भयभीत हैं, और अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं और कानून के द्वारा प्रदेश की सत्ता संचालित है। भ्रष्टाचारियों का भी सफाया हुआ है। महोदय, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में दो साइबर थानों का प्राविधान किया गया, जिससे कानून व्यवस्था साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में एक बहुत-बहुत महती भूमिका होगी। इसी संदर्भ में मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो थाना, एक थाना कौशाम्बी एक थाना श्रीराम रोड नया स्वीकृत किया और वह संचालित नया स्वीकृत किया और वह थाने संचालित होंगे इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो यह बजट नौजवानों को समर्पित है, लेकिन यह बजट नौजवानों के साथ-साथ किसान, खेत, खलिहान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और प्रदेश के पूर्ण और संपूर्ण विकास के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज प्रदेश में कैंप लगाकर के विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, विकलांगों और वृद्धों के

लिए पेंशन बनाने का कार्य किया जा रहा है। जहां गांव में बिजली के लिए पिछली सरकारों में कुछ जिले थे, जहां बिजली देखने को मिलती थी। आज गांव का छोटे से छोटा मजरा भी है वहां भी अधिष्ठाता महोदय हर घण्टे बिजली आ रही है, इसके लिए विद्युत मंत्री और मा0 मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हं, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, मा0 मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने एन0सी0आर0 क्षेत्र में भी विद्युत रैपिड ट्रांजेशन सिस्टम में दिल्ली से मेरठ तक के लिए रैपिड ट्रेन के लिए नौ सौ करोड़ रुपये का इस बजट में प्राविधान किया है, और इस रेल का अभी तक जो निर्माण हो रहा है, जिसमें पैसा लगना है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि वह पूरा का पूरा हिस्सा मेरी साहिबाबाद विधान सभा की क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का, और मा0 वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज की योजना बनाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ सात निगम नहीं आ पाए थे, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन सात नगर निगमों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्राविधान इस बजट में किया है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मेरा गाजियाबाद नगर निगम भी उन सात निगमों में आता है, मैं गाजियाबाद के नागरिकों की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेश में आज सड़के गढ्ढा मुक्त हो चुकी हैं, अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। ऐसा बजट जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सभी मा0 मंत्रीगण और वित्त मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा आभार व्यक्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, दो-तीन छोटी-छोटी बातें मेरी विधान सभा से संबंधित हैं उन्हें कहकर के ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सहिबाबाद विधान सभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधान सभा है और प्रदेश के सभी जनपदों के और देश के सभी प्रांतों के लोग वहां रहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ट्रांसहिडन एरिया का वहां एक सरकारी स्कूल, एक इण्टर स्कूल, एक सरकारी अस्पताल, और एक सरकारी डिग्री कालेज की बहुत आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस बजट में प्राविधान किया जाए और ट्रांसहिडन क्षेत्र में एक गवर्नमेण्ट स्कूल, गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज, एक गवर्नमेण्ट हांस्पिटल की व्यवस्था की जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक नगर पालिका परिषद खोड़ा मक्खनपुर है, और मेरी ही विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम का एक मोहन नगर जोन है, जहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूमिगत पानी खारा है, और पानी खोड़ा में तो बिल्कुल पानी की कोई सप्लाई है ही नहीं, और मोहन नगर जोन में थोड़ी सप्लाई है, लेकिन वह अपर्याप्त है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन दोनों स्थानों पर गंगा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें, बहुत ही कृपा होगी। साहिबाबाद ट्रांसहिडन क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम के नालों का नवीनीकरण होना, और नए नाले बनाया जाना और पुराने नालों की मरम्मत होना बहुत आवश्यक है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। लखनऊ और आगरा में और कानपुर में राज्य सरकार मैट्रों के लिए फण्डिंग कर रही है। महोदय, गाजियाबाद में मेट्रो चल रही है, लेकिन गाजियाबाद की जो मेट्रो है, उसके

लिए सरकार के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही वहां मेट्रों में जी0डी0ए0 नगर निगम और आवास विकास के द्वारा पैसा लिया गया और भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अब वहां के जी0बी0ए0 की और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो फेज-3 और फेज-2 की मेट्रों है उसकी डी0पी0आर0 शासन में जमा हो चुकी है। उसके लिए भी कृपा करें। लखनऊ और आगरा की तरह उसको भी राज्य सरकार से धन आवंटित किया जाए, मैं इसका आग्रह करता हूं। मेरी यह मांग है कि गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए। मेरा एक अनुरोध है, तमाम शहरी क्षेत्रों के लिए मांग है कि जो शहरी क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें लम्बे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। एक स्कूल में एक अध्यापक और 400-500 बच्चे हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसे भी विद्यालय हैं, मेरा अनुरोध है कि अब की बार जब नियुक्तियां हों तो शहरी क्षेत्र के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी अध्यापकों की तैनाती की जाए। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कृष्ण भार्गव-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मिश्रिख-नैमिषारण्य जो सीतापुर का विधान सभा क्षेत्र है वहां से चुनकर आता हूं। हमारा क्षेत्र नैमिषारण्य दधीचि की धरती है और आप भी जब वहां गए होंगे तो देखा होगा। उस धरती की तरफ से मैं सबका स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं। आपका भी बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं और मैं वर्ष 2020-21 के इस बजट के समर्थन में भी खड़ा हूं। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह सर्वसमाज का बजट है और इसमें सबके हित की बात है। जहां तक वर्ष 2019-20 की बात रही है तो उसमें भी हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सड़कों के मामले में हो, आज गड्ढामुक्त सड़कें की गई हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात आई है तो आज कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो गई है और अब तक जो लोग गड़बड़ करने वाले थे, उनको कानून व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही होगी। आज कानून व्यवस्था ठीक हुई है, सड़कें गड्ढामुक्त हुई हैं, बेसिक शिक्षा की समस्याएं दूर हुई हैं। आज जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लगता है कि वे किसी माण्टेसरी स्कूल में जा रहे हैं। अब अध्यापक भी समय से विद्यालय पहुंच रहे हैं क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूं, गांव से आता हूं और जब स्कूलों को जाता हूं तो देखता हूं कि वहां की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, पर और भी सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहां गरीब अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। आवास के मामले में हमारे सीतापुर में पिछले वर्ष 2019-20 में 80,000 प्रधान मंत्री आवास दिए गए थे। हमारी मिश्रिख-नैमिषारण्य नगर पालिका है वहां पर 700 शहरी आवास दिए गए हैं। आज लगभग सभी गरीबों के मकानों में कोई दिक्कत नहीं है, सबके मकान बन रहे हैं। ये मकान किसी एक वर्ग नहीं बल्कि सर्वसमाज के लोगों को दिए गए हैं। मिश्रिख-नैमिषारण्य में हमारे अल्प संख्यक लोग भी रहते हैं, मुस्लिम

भाई रहते हैं और वहां एक-एक व्यक्ति को आवास दिलाने का काम किया गया है। जो लोग केवल यहां बैठकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि आज आप गरीब के पास जाइए, मुस्लिम भाइयों और बहनों के पास जाइए, उनसे बात करिए, वे किसी सी0ए0ए0 की बात नहीं जानते हैं, न वे इस पर बात करना चाहते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और उसके साथ मा0 योगी जी ने करोड़ों रुपये दिए हैं। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में अपने फण्ड से एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये गरीबों का इलाज करने के लिए दिया है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी हैं। जहां तक हमारे यहां सिंचाई की समस्या थी तो इस बार ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मेरा गांव नदी का किनारा है और आज वहां 50 साल के बाद पहली बार नहरों में पानी गया है। इसके लिए मैं आदरणीय सिंचाई मंत्री और मा0 योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है क्योंकि आज से 50 साल पहले हमारे गांव की नहर में पानी गया था या फिर आज गया है। मान्यवर, सिंचाई के साथ-साथ हमारे वहां पर जहां भी पुलिया वगैरह की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए भी कहूंगा क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं कि वहां पर और ज्यादा व्यवस्था हो जिससे लोगों को दिक्कत न हो। मान्यवर, आज हमारे गांवों में नलकूपों के लिए बिजली में भी बहुत अभूतपूर्व सुविधा मिली है। आज जहां एक-एक मकान और घर है वहां भी ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली देने का काम किया गया है। पहले सिंचाई में 25-30 हजार रुपये नलकूप बनाने के लिए देने पड़ते थे लेकिन आज सोलर ट्यूबवेल बनने से केवल 1200 रुपये महीने देने पड़ते हैं। आज किसान खुशहाल हो रहा है लेकिन अभी उसको कुछ और भी सुविधा की आवश्यकता है क्योंकि हम सब लोग किसानों से ही जुड़े हैं। हम भी किसान हैं और गांव के रहने वाले हैं। अगर मैं लोक निर्माण विभाग की बात करूं तो बहुत कुछ काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग है वहां एक बरेठी के पुल की आवश्यकता है। एक हुसैनपुर पुल है उसकी आवश्यकता है। हमारे यहां बहराइच से लोग नैमिष को आते हैं। हर महीने में अमावस्या का मेला होता है उसमें कम से कम तीन-तीन, चार-चार लाख लोग आते हैं वहीं पर चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग है जो हमारे यहां परसो से निकली है और होली तक चलेगी। हरदोई होकर के फिर नैमिषारण्य में दधीचि जी के स्थान पर होली में समाप्त होती है। आज मुझे थोड़ा दुख है माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहूंगा कि नैमिष का नाम इसमें कहीं जोड़ा नहीं गया है। जहां मनु-शतरूपा और दधीचि जी ने अपनी हड्डियों को दान दिया है उस नैमिष का नाम इसमें जुड़ना चाहिये था। माननीय योगी जी ने भी घोषणा की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सीतापुर जाकर बखान किया है तो मैं माननीय योगी जी से और वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि नैमिष को इसमें जोड़कर वहां पर जो विकास की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाये। दूसरी बात उच्च शिक्षा के मामले में है नैमिष में एक डिग्री कालेज बन रहा था लेकिन उसमें दो सालों से कोई विशेष काम नहीं हुआ

है। एक कन्या डिग्री कालेज नैमिष में बना हुआ है अपनी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर पैसा देकर उसको बनवाया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे क्षेत्र में काम बहुत हुआ है, थाना भी बना है, फायर-बिग्रेड की व्यवस्था भी हुई है लेकिन एक सड़क जिसके माध्यम से बहराइच से खैराबाद होते हुए नैमिष को वह सड़क जाती हैं दो फैक्ट्रियों का गन्ना उसी सड़क से जाता है वह सड़क केवल 3 मीटर चौड़ी है मेरा प्रस्ताव है कि उस सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाये।* श्रीमन् आपने हमें इस बजट पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल आर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का विशाल बजट लोक कल्याणकारी बजट है। माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ बजट में किसानों, गरीबों, व्यापारियों, नौजवानों, युवाओं महिलाओं सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा है यह बजट प्रदेश की 23 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

''हमारी प्रगति के इरादों को समझिये-परखिये, अंधेरों में हमने नया सूरज उगाया है,
हमारे सामने आने से पहले अपना इतिहास तो जान लेते।''

आप लोगों को सरकार का विरोध ही करना है कि बजट अच्छा नहीं है और सरकार अच्छी नहीं है। जबकि हम तो अच्छा ही अच्छा काम कर रहे हैं। बुरे काम से तो दूर-दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप लोग अपने गिरेबां में झांक कर देखिये आपने तो बुरा ही बुरा किया है। अच्छे काम का तो वास्तव में कोई नामो-निशान ही नहीं है। आप लोगों ने प्रदेश में तानाशाही की सरकारें चलाईं। पूरे प्रदेश में लूट-खसोट, भय आतंक और गुण्डागर्दी का माहौल था, जंगलराज कायम था। अपनी कोई सही बात भी लोग नहीं कह पाते थे। कब किसका नम्बर आ जाये ये पता नहीं था। देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ था लेकिन हमको तो ऐसा लगता था कि हम फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ गये हैं। ऐसा माहौल आपने बना दिया था। इस माहौल को समाप्त करके प्रदेश में राम का राज कायम करेंगे हमने कहा था। गांव-गांव और नगर-नगर में आज बच्चा-बच्चा कह रहा है ये मोदी राज है, योगी राज है जहां इंसान रामराज की अनुभूति कर रहा है।

---

* नैमिष धाम व मिश्रिख में विकास परिषद् बनाया जाये जिससे नैमिष में देश-विदेश के पर्यटकों का आवागमन और बढ़ेगा, जिसका प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

''हुआ नहीं क्या आपको अब तक यह भी अहसास,

अपना तो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास।''

अभी तक आपको भरोसा नहीं हुआ। आप लोग यह समझ नहीं पाये कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर प्रदेश को प्रगति के सोपान पर हम ले जा रहे हैं।

''तीन साल में कर दिया 30 साल का काम,

आशीष हमको दे रहे कमलनयन श्रीराम,

राजनीति करिये मगर इतना रखिये बोध,

कौन बैठ सकता यहां करके राम का विरोध''।

राम जी का विरोध करके आप विधान सभा में बैठ सकते हैं लोक सभा में बैठ सकते हैं ? श्री राम हमारे अराध्य, हमारी संस्कृति हैं, हमारी सभ्यता हैं, हमारी आस्था का केन्द्र हैं। राम का विरोध मत करिए, आंख खोलकर देखिए, 'आंख खोलिए, देखिए, करिए सच पहचान, सबके हित में चल रहा नव विकास अभियान'। वास्तव में माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास ही दिखायी दे रहा है। पूरे प्रदेश में आज रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। पुल, पुलिया, ओवरब्रिज चारों तरफ दिखायी पड़ रहे हैं। घर-घर बिजली, घर-घर पानी, खेत-खेत पर पानी, अच्छी संस्कारिक शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रहने के लिए आवास, घर-घर शौचालय, किसान सम्मान निधि, घर-घर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, फसल बीमा योजना, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का चहुंमुखी विकास किये जाने का युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह से हम दृढ़ संकल्प थे। मोदी जी के और योगी जी के ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हम असंभव कार्य को संभव कर रहे हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। प्रदेश में बड़ी से बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। 'आयुष्मान भारत योजना', 'प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना' जिससे आधे भारत को लाभ हो रहा है। 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिये जाने का काम किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए, समय हो गया है।

श्री बिहारीलाल आर्य-

कश्मीर में धारा 370, 33 (ए) को हटाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 1 लाख 21 हजार 324 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। प्रदेश में 132/33 के0वी0, 33/11 के0वी0 के नये उपकेन्द्र बनाये गये हैं। सभी ग्रामों में जर्जर तारों को आज बदला जा

रहा है और देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गयी। आज शहरों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अब समाप्त करिए, धन्यवाद दे दीजिए।

श्री बिहारीलाल आर्य-

मान्यवर, तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे और गांव में अनवरत 18 घण्टे बिजली जा रही है। युगों-युगों तक हो गयी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए। श्री रफीक अंसारी जी।

श्री बिहारीलाल आर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। 'युगों-युगों तक अंकित यह तहरीर, सब के हित में खींच दी हमने बड़ी लकीर'। दोस्तों आप वर्तमान की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए, बहुत लम्बी लिस्ट बोलने वालों की है। आपकी सब बातें आ गयी हैं, अब आप बैठ जाइए। मैंने नाम बुला लिया है।

श्री बिहारीलाल आर्य-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने नाम बुला लिया है, आप बैठ जाइए। अब यह लिखा नहीं जायेगा।

(सदस्य का अपने स्थान से निरंतर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यदि समय के अंदर काम नहीं होगा तो कैसे सब लोगों को टाइम देंगे। आप बैठ जाइए, आपका भाषण समाप्त हो गया। समय के अंदर काम करना पड़ेगा, आप बैठ जाइए।

***श्री रफीक अंसारी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब यह बजट पेश हुआ था और आज हमारे मुख्य मंत्री जी इस बजट पर बोल रहे थे। मैं थोड़ी कड़वी बात जरूर करूंगा परंतु मैं जनहित की बात करूंगा। अधिष्ठाता महोदय, चूंकि आप राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं और आप मुझ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर विशेष कृपा करेंगे मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं। जब यह बजट पेश हो रहा था, आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के बाद, किसानों के बाद बुनकर समाज का नम्बर आता है। बड़ी-बड़ी लम्बी बात हमारे साथी भी किसानों के विषय पर कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप गांधी जी का चरखा चला रहे थे। उस चरखे से बुनकर समाज ने गांधी जी को कपड़े बुनकर पहनाएं हैं लेकिन इन बुनकरों का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों के बाद बुनकर समाज सबसे बड़ा है। वर्ष, 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को एक नई जिन्दगी दी थी। फ्लेट रेट पर बिजली देने का काम किया था। जब बुनकर समाज डूब रहा था, मर रहा था उस वक्त नई जिन्दगी देने का काम माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन इस बजट के अन्दर सरकार को यह भी तरस नहीं आया कि बुनकर समाज ने गांधी जी को कपड़े बनाकर पहनाया है, इन्होंने बुनकर समाज का एक मिनट के अन्दर गला घोटनें का काम कर दिया। फ्लेट रेट समाप्त कर दिया इस सरकार ने बुनकरों के लिए यह भी महसूस नहीं किया कि इनके बच्चों की शादी कैसे होगी, इनके बच्चे कैसे तालीम पायेंगे, इनके मां और बाप कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे बीमारी से दूर होंगे, सब रोजगार छिनने का काम कर दिया। बुनकर समाज जो पावनी कपड़ा बुनती है आज लोहे के दाम पर बिक रही है। तराजू में तोल कर लोहे के दाम पर बेचते हैं। औजार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि ''मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, अपनी प्यास की खातिर दरिया बहा रखा है।'' आज बुनकर समाज दो महीने से परेशान है। दर-दर भटक रहा है। कई मीटिंगें यहां पर हमारे हथकरघा मंत्री जी ने कर ली, कई मीटिंगें मुख्य मंत्री के साथ कर ली, बुनकर समाज को चश्में से देखा जा रहा है। बुनकर समाज को पारीख से नहीं देखा जाता। मैं पूछना चाहता हूं किसान, जाट, गुज्जर, मुसलमान, ठाकुर को जिस नजर से देखा जाता है वैसे बुनकर समाज को पारखी नजर से देखना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि ये कपड़ा मुसलमान बुनता है। उसके कार्य के नजर से देखना चाहिए कि काम क्या कर रहा है, उसका कितना उत्थान यह सरकार कर रही है लेकिन बुनकर समाज को इन्होंने कुचलने का काम कर दिया है। ''पहले यह तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बतायेगा तुम्हें कि गद्दार कौन है ?'' आजादी में सबसे ज्यादा योगदान बुनकर समाज का रहा है। बुनकर समाज के तमाम लोगों ने फांसी पर लटकने का काम किया है। अशफाक उल्ला से लेकर हमीद तक तमाम कुर्बानी देने का काम इस देश में बुनकर समाज ने किया है। आज ये सरकार बुनकर समाज को कुचलने और खत्म करने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र लखनऊ में भी बुनकर होंगे, कोई नहीं बोलता यहां पर बुनकर के लिए, किसानों के लिए बलिया से बोले हैं, गोरखपुर मुख्य मंत्री का क्षेत्र है, बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है लेकिन बुनकर समाज पर नहीं बोले। यह सरकार बुनकर समाज को खत्म करने का काम कर रही है। यह बुनकर समाज को खत्म नहीं कर रहे हैं, इस

प्रदेश को खत्म कर रहे हैं, इस देश को खत्म कर रहे हैं। अगर बुनकर समाज कमजोर होगा तो उत्तर प्रदेश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। अगर बुनकर समाज ताकतवर होगा तो पूरे देश को ताकत मिलेगी। आज जो हम कपड़ा पहने हैं वह बुनकर समाज की देन है। लेकिन बुनकर समाज के नाम पर जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये का बजट था वह भी खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चाहती है यह सरकार बुनकर समाज से। कौन-सा जुल्म किया है, बुनकर समाज ने। सब किसानों को दे दिया, गन्ने को दे दिया, सबको दे दिया, बुनकर समाज को क्या दिया, ये बताओ ? सबके क्षेत्र में बुनकर नहीं हैं। जो आज साईदे मसलत हैं कल नहीं होंगे, किरायेदार हैं, ज्याती मकान थोड़े है। कितना जुल्म करोगे, हम इस खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे। बुनकर समाज क्रांति लिख देगा। आप यकीन कीजिये कि ये बुनकर समाज सैकड़ों की तदाद में पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर, हर विधान सभा के अन्दर हैं। ये बुनकर समाज हर विधान सभा सदस्य से जवाब मांगेगा जो यहां बैठे हैं कि जब हम मर रहे थे, जब हमारे बच्चे जूझ रहे थे, जब हमारे बीवी बच्चे कमाकर हमको दे रहे थे, कौन विधायक बोला था, जवाब देना पड़ेगा इनको, जब चुनाव होगा। यह याद कर लें कि बुनकर समाज एक सच्चा ईमानदार है, जो इस देश का वफादार है। आज इन्होंने बुनकर समाज को कुचलने का काम किया है, आज बुनकर समाज को खत्म करने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज बेरोगारी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट न कीजिये, तो समय के अन्दर आपकी सब बात आ जायेगी।

श्री रफीक अन्सारी-

बुनकर समाज सबसे ज्यादा है, इसलिए कर रहा हूं। बुनकर समाज पर मुझे बोलना पड़ा, किसी ने नहीं बोला बुनकर समाज पर। मेरी आपसे मांग है कि बुनकर समाज को जिन्दा कर दीजिये। आपसे भी उम्मीद है कि आप इतने योग्य और पुराने लोग हैं, उन्हें बुनकर समाज याद कर रहा है, बुनकर समाज आपकी तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रहा है कि अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे लिए कोई नया एलान करेंगे और हमें राहत देने का काम करेंगे। अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज तमाम लोग परेशान हैं, हर क्षेत्र का बुनकर परेशान है लेकिन बुनकर समाज आपसे उम्मीद कर रहा है। एक गुजारिश और कर रहा हूं और अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं यह कहते हैं कि तमाम जगह विकास कार्य हो रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकिन यह बात सही नहीं है, यह सरासर गलतबयानी है। यह भेदभाव कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है वह सबके लिये काम कर रहे हैं। आप बताओ अधिष्ठाता जी, आप गवाह हैं ये सब गवाह हैं 5-5 करोड़ रुपये किसी भी विपक्ष के सदस्य को नहीं दिये गये। यह राजनीतिक मंदिर है और इस मंदिर में

खड़े होकर हमारे नेता मुख्य मंत्री झूठ बोलें इससे बड़ा क्या होगा। किसी को नहीं रुपये दिये, इतनी बड़ी गलतबयानी है जिससे उम्मीद करते हैं कि यह राजा है सबका, आज वह राजा झूठ बोल रहा है कि इनको दिये उनको दिये।

इनके मैखाने में कुछ उनके मैखाने में कुछ,
देख साकी तेरे मैखाने में न हो जाये कुछ।

अधिष्ठाता जी, एक बात और अर्ज कर रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों की एक मांग हाईकोर्ट बेंच की है। मैं कहना चाहता हूं कि इतने सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बेंच नहीं बन पायी। बीसियों साल से कितने आन्दोलन हुये। मेरठ के 6-6 एम0एल0ए0 हैं पूछ लो आप इनसे। आप अपने लोगों से पूछ लीजिये कि इनको हाईकोर्ट की बेंच चाहिये तो आपके लोग भी कहेंगे कि हां चाहिये। वोट लेने की खातिर तो हाईकोर्ट बननी चाहिये लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं हाईकोर्ट बेंच को। मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ के अंदर सरकार को हाईकोर्ट बेंच देनी चाहिये और मैं इसे देने की मांग करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की दो मांगे रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें, आप बार-बार एक ही बात कर रहे हैं। बिन्दु के साथ कहिये तो सारी बातें आ जायेंगी।

श्री रफीक अंसारी-

अधिष्ठाता जी, मेरे क्षेत्र के अंदर एक हास्पिटल पास हुआ था 50 बेड का। साढ़े चार साल हो गये, इसके लिये साढ़े 3 करोड़ रुपये माननीय अखिलेश यादव जी ने रिलीज किये थे। लेकिन आज इस सरकार ने इसको रोकने का काम किया और आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। यह कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे यहां जी0आई0सी0 इंटर कालेज है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी0आई0सी0 इंटर कालेज में इतने बच्चे नहीं पढ़ते जबकि हमारे यहां 2 हजार लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन शर्म की बात क्या है कि यह लड़कियां जमीन पर बैठकर पढ़ाई करती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री रफीक अंसारी-

अधिष्ठाता जी, यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है यह भेदभाव कर रही है जहां-जहां माइनारिटी के लोग हैं, जहां-जहां मुसलमान लोग हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है उन्हें कुचलने का काम कर रही है। मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि-

सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे,
मर्जी आपकी है जो तुम करोगे वही हम करेंगे।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं बजट के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बजट 5,12,860 करोड़ का है इतनी बड़ी राशि सुनकर पूरा विपक्ष अचेत हो गया। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि कभी इतना बड़ा बजट भी उत्तर प्रदेश में आ सकता है। कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हर वर्ग के लिये, हर तबके के लिये, हर एक के लिये इसमें कोई न कोई योजना है। मैं उन्हें याद कराना चाहता हूं कि 2017 के पूर्व योगी जी की सरकार से पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी। किसान ऋण से त्रस्त था, महिलायें असुरक्षित थीं, मां-बेटी के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा था, पूरे प्रदेश में अराजकता थी, जातिवाद और उन्माद पूरे चरम पर था। अभी कुछ मेरे भाई कह रहे थे और कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2017 के पूर्व पुलिस को थाने में घुसकर पीटा जाता था और अगर किसी को पढ़ना हो तो 08 मार्च को इस सरकार ने शपथ ली थी 08 मार्च से 15 मार्च तक के सारे अखबार उठाकर देख लें, 08 दिन तक लगातार बसपा के लोगों और पुलिस की पिटाई हुयी, क्योंकि बसपा पहले सत्ता में थी। हर एक दल उत्तर प्रदेश में अपने आपको बड़ा हितैषी दिखाना चाहता है। यह स्थिति थी कि खुद मैं एक वाकया बताऊं। मेरा भांजा जो इन्फोसिस में नौकरी करता है मुझसे आकर कहा कि मेरी कम्पनी यहां से जा रही है और आप कुछ प्रयास करो। हमने कहा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि कम्पनी यहां से जा रही है इसमें क्या करें, क्यों जा रही है क्योंकि सत्ता के लोग अनावश्यक दबाव बनाकर लोगों की भर्ती कराते थे। इसलिए कम्पनी घाटे में जा रही थी यह स्थिति थी 2017 के पूर्व और 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्ट हो रहा है। आज इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हमने 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया है। आज ग्यारहवां डिफेंस एक्सपो, जो उत्तर प्रदेश के बुन्दलेखण्ड क्षेत्र में मुख्य रूप से लग रहा है, वह बुन्देलखण्ड जो प्यासा मर गया, अनाज के लिए तड़प-तड़प कर मर रहे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर विपक्षी दल अपने आपको दलितों का, अल्पसंख्यकों का और पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी बताता है लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अन्दर गरीब लोगों को मकानों से वंचित कैसे रखा गया, सरकारी योजनाओं से वंचित कैसे रखा गया, इसका जवाब कौन देगा। इस बजट में जहां एक ओर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप दलितों के हितैषी हैं तो आपने जो आम बजट में आवास के लिए 6 हजार 404 करोड़ रुपए जारी हुए हैं पांच लाख आवास के लिए, 6 हजार के लगभग की संख्या वह है जो विपक्ष के नेता से

माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी है क्योंकि उन्होंने इतना पैसा मूर्तियों पर व्यय कर दिया। अगर मूर्ति न बनाकर गरीबों के लिए आवास बना दिये होते, दलितों के लिए शौचालय बना दिये होते, उनके घर में सिलेण्डर भेज दिये होते, उन्हें सौभाग्य योजना जैसी कोई योजना दे दी गई होती तो आज उनका जीवन स्तर कितना ऊपर होता। इससे कई गुना ज्यादा आवास बन सकते थे लेकिन ये लोग केवल बात करेंगे दलितों की और काम करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। दूसरी पार्टी सैकड़ों रुपया किस चीज पर खर्च करेंगे, यह कैसा समाजवादी है कि जन्मदिन मनाने के लिए नाचने-गाने में आप सात सौ करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। उसी वर्ष पूरे प्रदेश में भयंकर ओलावृष्टि और भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी, उन किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पैसा नहीं जा पाया लेकिन जन्मदिन पर सात सौ करोड़ रुपए नाचने-गाने पर खर्च कर दिये, यह था समाजवाद। आज विपक्षी माननीय सदस्यगण जिस हुनर की बात कर रहे हैं, उन हुनरमंद लोगों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है। हर जिले में ऐसे हुनरमंद लोग थे जो ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग से ही हैं लेकिन उनके हुनर को पहचाना नहीं जा रहा था उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था अब ओ0डी0ओ0पी0 के तहत् माननीय योगी जी की सरकार उनको अवसर मुहैया करा रही है और वह अपने प्रोडक्ट केवल देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेज पा रहे हैं। बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, मान्यवर, दोहरा आचरण देखिये, एक तरफ तो हमारे माननीय योगी जी की सरकार है जो अल्पसंख्यक बन्धुओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 479 करोड़ रुपए का बजट दे रही है ताकि उन्हें भी आधुनिक शिक्षा मिल सके, उनके बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सकें और वह भी प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। वहीं दूसरी तरफ मेरे बहुत सारे बन्धु उनको उकसा रहे हैं, चाहे वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हों, चाहे किसी अन्य संस्थान के, उनको कहा जाता है कि जाओ धरने पर बैठो और सी0ए0ए0 के विरोध में देश विरोधी नारे लगाओ। कितना अन्तर है सोच में, हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें लेकिन वे चाहते हैं कि वह लोग उनके लिए वोट बैंक बने रहें। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कल रात देश के गृह मंत्री जी को यह आदेश जारी करना पड़ गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाय और जिसने चुनाव में उनका लाभ लिया था आज वह गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं कि किसी तरह से रोको शाहीनबाग के मामले को। चुनाव में वोट तो ले ली लेकिन जो हालत उनकी हुई वही हालत आपकी भी होगी अगर आप इसी रास्ते पर चलोगे। कोई फायदा नहीं मिल पायेगा आपको, आप अपने हितों के लिए उस समाज को ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, आप कहते हैं कि जाओ बहनों धरने पर बैठो और दूसरी तरफ भाजपा कहती है, माननीय योगी जी कहते हैं कि नहीं, निराश्रित महिलाओं के लिए, तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए मैं फंड की व्यवस्था बजट में कर रहा हूं। हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप वोट बैंक के लिए उन्हें पीछे खींचना चाहते हैं। केवल पैसे की बात नहीं है, सोच की बात है। जब आपका समय

था, तीन जातियों, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनका जिक्र किया था, थारू, मुसहर, वनटांगिया। क्यों नहीं मिल पाई उन्हें मूलभूत सुविधाएं, क्या गलती थी उनकी। वनटांगिया वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया आजादी के आन्दोलन में। अंग्रेज तो उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि वह उनके विरुद्ध लड़े लेकिन विपक्ष उनसे किस लिए नाराज था कि देश की आजादी के इतने समय बाद भी उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलीं। क्यों आपकी नजरों से चूक गईं वह जातियां, जो बहुत छोटे-छोटे रूप में देश में रहती हैं और जिनकी संख्या बहुत कम है। क्या केवल इसलिए कि उनका वोट बैंक ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे पाये। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को देश से बाहर भेजेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम मुसलमानों को आवास, शौचालय, आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना दे रहे हैं, जो हिन्दुओं को मिल रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम उन्हें उजाड़ना नहीं चाहते, बल्कि बसाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सारी योजनाएं दे रहे हैं। आप जाने-अनजाने में वोट बैंक के लिए उन्हें और उनकी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों से राष्ट्र विरोधी नारे लगवा रहे हैं, ये अन्तर है हमारी और आपकी सोच में। ये बजट अपने आप में अभूतपूर्व बजट है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि पी.एफ.आई जैसी आतंकवादी संस्था भी यहां पिछली सरकार के कार्यकाल में ही सक्रिय हुई थी। मान्यवर, मैं जनपद शामली से विधायक हूं। इनकी सरकार में शामली में दंगा हुआ और जाट समाज खड़े-खड़े चिल्लाता रहा, सरकार से दुहाई देता रहा। सरकार के मुख्य मंत्री वहां गये और कांदला से घोषणा कर दी कि जिन किसानों के ट्रैक्टर जला दिये गये, जिनके ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन एक वर्ग के लोगों ने चिल्ला कर मना करना शुरू किया तो उस योजना को देने की मुख्य मंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई और वह अपने वादे से मुकर गये। उस योजना को इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि हम हिन्दू समाज के जाति विशेष से थे। सरकार के मुखिया का बयान आता है कि झगड़ा हिन्दू-मुस्लिम का नहीं था, बल्कि झगड़ा जाट-मुस्लिम का था।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिये। बहुत लम्बी सूची है। अपनी बात संक्षेप करिये।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलते हुए अपनी विधान सभा की दो योजनाओं की बात रखना चाहता हूं। जनपद-शामली में वर्ष 2017 में एक औद्योगिक पार्क मंजूर हुआ था। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वह औद्योगिक पार्क शामली क्षेत्र में, जो दंगा पीड़ित क्षेत्र है, उसमें नांक, लिसाड़ और पहावड़ी गांव आते हैं, जिनका जीवन कई सालों से रुका हुआ है और वहां दंगे के कारण हजारों युवक जेल में गये हैं। उस क्षेत्र में अगर यह औद्योगिक पार्क लगा दिया जाये, तो उस क्षेत्र/जिले की तरक्की होगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वह मेरठ-करनाल हाइवे पर स्थिति है। दूसरी मांग है कि मेरठ-करनाल रोड पर

शामली में बहुत जाम रहता है, शामली के पूरे शहर के ऊपर से बुधाना मोड़ से करनाल नहर तक एक बड़ा फ्लाईओवर बनाया जाये। मेरी एक और मांग है कि लाक गांव, जो दंगा पीड़ित गांव है, वहां पर एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मिल जाये, तो आपका बहुत-बहुत आभार है। चूंकि सभी जगह डिग्री कॉलेज दिये जा रहे हैं इसलिए जनपद-शामली के लिसार गांव में जमीन उपलब्ध है, इसलिए वहां पर एक डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार से मांग करता हूं। आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सत्यवीर त्यागी जी।

श्री सत्यवीर त्यागी-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। अभी मेरे से पहले हमारे मित्र बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक/बेमिसाल बजट प्रस्तुत करके एक इतिहास बनाने का काम किया है, इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। प्रस्तुत बजट का आकार पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ बहत्तर लाख रुपये का पहली बार इतना बड़ा बजट देश की सबसे बड़ी विधान सभा में पेश हुआ है, इसके लिए मैं अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, इसके लिए भी मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और अपने वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को और अपने उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बजट को बनवाने में अपना योगदान/राय देने का काम किया है। इसी तरह से अभी हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार की चर्चा हो रही थी।

(इस समय 06:00 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

समयाभाव के कारण मैं मोटे-मोटे तौर पर कुछ बिन्दुओं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं मान्यवर, पिछली सरकार के समय में ओलावृष्टि होने पर किसानों को जब वह मुआवजा की सरकार से मांग करते थे तो उनको लाठी डंडा मिलता था, और धरना-प्रदर्शन करने पर उनको जेल भेजने व उस पर मुकदमे लगाने का काम किया जाता था। एक संविदा विद्युत कर्मचारी का मामला मेरे किठौर विधान सभा क्षेत्र का था। उसके परिजन जब उसकी मृत्यु हो गई थी बिजली के खंम्भे से टकराने पर, जब अपनी मांग को ले करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसके परिवार पर मुकदमे लगा दिये गये और जब मैं भी उनके साथ धरने में शामिल हुआ तो तत्कालीन मंत्री स0पा0 सरकार के वहां मौजूद थे और उन्होंने मेरे ऊपर भी

मुकदमा लगा करके जो 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी व मुझे उसको मुआवजा देने के बजाय और उल्टा मुदकमा लगाने का काम उन परिजनों के ऊपर किया गया। मैं यह बात बताकर उस सरकार के चरित्र को उजागर करने का काम कर रहा हूं। इसी तरह से उस सरकार में एक गांव है हमारे विधान सभा क्षेत्र का राधना, रफीक भाई जानते होंगें। राधना गांव में उस वक्त कट्टों की फैक्ट्री और अवैध हथियारों, असलहों की फैक्ट्री चलाई जाती थी और तत्कालीन मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में शामिल थे और उन्होंने उनका संरक्षण करने का काम किया था। मैं मा0 योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इनकी सरकार आने के बाद एक हुआ था लाख का तस्कर जो हथियारों की तस्करी करता था उस पर छापा पड़ा और फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। अन्य कई अपराधियों को भी गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप करें।

श्री सत्यवीर त्यागी-

मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से योगी जी की सरकार ने फैसले लिये **'सबका साथ सबका विकास'** के सिद्धान्त को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई फैसले लिये हैं और इस बजट में सभी का जिक्र किया गया है। चाहे कृषि विभाग हो, चाहे ग्रामीण विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे दिव्यांग जन कल्याण योजना हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, कृषि उद्यान एवं सहकारिता विभाग हो सबको उचित और अच्छा बजट दिया है। इतना अच्छा बजट बनाने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय हो गया।

श्री सत्यवीर त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा समय हो गया है, लेकिन मैं सूक्ष्म में केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आ रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर जहां से मैं आता हूं तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने इतने जुल्म और ज्यादती की थी उसी के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि वहां पर कोई विकास का काम हुआ नहीं था और विकास के नाम पर केवल पशुओं की चोरी होती थी और अवैध कटान होते थे। विद्युत ट्यूबवेलों के स्टार्टर, मोटर और बिजली के ट्रांसफार्मरों की चोरी होती थी और यही धंधा वहां फल-फूलने का काम होता था। योगी जी की सरकार ने इस सब पर अंकुश लगाने का काम किया है, इसके लिये मैं आदरणीय

मुख्य मंत्री जी को और उ0प्र0 सरकार को बधाई देता हूं। किठौर शाहजहांपुर कस्बे में किठौर गढ़मार्ग में कई घंटे जाम रहता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यवीर त्यागी-

बस मान्यवर, दो तीन समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर जाम से बचने के लिये, जाम से निजात पाने के लिये ओवर ब्रिज बनवाकर बहुत ही उपकार करने का काम सरकार करेगी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं। माछरा व खरखौदा की जमीन व अन्य सुविधाएं हैं, तहसील बनाने की पात्रता के दायरे में आते हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मवाना और मेरठ तहसील दूर होने की वजह से 25 से 30 किमी0 लगभग उनकी दूरी है। लगभग 150 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, उन लोगों को जो असुविधा होती है उसके लिये खरखौदा और माछरा को तहसील बना करके वहां की जनता का उपकार करने का काम करेंगें। मान्यवर, पूर्वी काली नदी का मसला पहले भी मैं सदन में उठा चुका हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इसको सदन में दो बार उठा चुका हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 12-13 जिलों में मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़ आदि जिलों में पूर्वी काली नदी बहुत ही प्रदूषित है, जिससे आस-पास के गांव के सैकड़ों व्यक्ति कैंसर आदि बीमारियों से मौत के शिकार हो जाते हैं। काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने व शुद्ध पानी छोड़ने हेतु बजट में जो भी व्यवस्था हो, उसको कराने का कष्ट करें। मेरे क्षेत्र में दो-तीन पुलिस थाने राधना व सिसौली और पुलिस चौकियां बनवाने का कष्ट करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की आज की बैठक की सिफारिश पढ़ रहा हूं।

1- दिनांक 27 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण संबंधी मदें ले ली जायें।

2- दिनांक 27 फरवरी, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान संबंधी मदें ले ली जायें। शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि- ''कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत जो भी सूचनायें आयी थीं, उन सभी सूचनाओं को हमने स्वीकार कर लिया है।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में कतिपय राशन गोदामों को विस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महराजगंज के मुख्यालय पर के0एम0सी0 अस्पताल से हनुमान मन्दिर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री शीतल पाण्डेय की सेतु निर्माण निगम के उप परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अमर सिंह चौधरी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में नगर पंचायत द्वारा सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आई स्पर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग की समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वाले सॉफ्टवेयर में जबरदस्त तकनीकी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज में चानकी घाट का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा नवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक नाले से अतिक्रमण हटाये जाने एवं आधुनिक नाला बनवाये जाने के

सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी नौआबाद में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के ग्राम म्याऊ में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संशोधित अधिनियम-1999 में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा-शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री योगेश वर्मा की राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल डालीबाग में कतिपय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की कानपुर से हाबड़ा तक रेल कारीडोर निर्माण में वेन्डरों के साथ हुई धोखाधड़ी एवं भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत धान क्रय एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू) की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा में गन्ना विभाग के अन्तर्गत सड़क निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव की ललई जनपद जौनपुर में कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के कार्य-प्रणाली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री रफीक अन्सारी की जनपद मेरठ के जी0जी0आई0सी0 इण्टर कालेज में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा फर्नीचर आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना कुंवर माधवेन्द्र प्रताप की प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों का नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में है,

अट्ठारहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की कानपुर देहात में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर में हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर में कतिपय फैक्ट्रियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में कतिपय कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद मैनपुरी में शहरी नगरपालिका क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग आगरा की विद्युत इकाई द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत पुल के दोनों तरफ कैटल घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत सी0एच0सी0 धानापुर में श्रीमती सुजीता पत्नी राजेन्द्र की डिलीवरी के दौरान मृत्यु के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के नेवादा उपकेन्द्र के जर्जर तारों को बदलने एवं फीडर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के ग्राम धौरहरा में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ खण्ड शारदा नगर में स्वीकृत परियोजना को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के काले ब्लाक में अवैध खनन रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा एत्पादपुर में पाइप लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बलहा में सड़क का डामीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के परियोजना अधिकारी डूडा की कार्यशैली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने जनपद मथुरा के परियोजना

अधिकारी डूडा की कार्यशैली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री संजीव कुमार ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 12460 शिक्षकों की भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के तट पर घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के पंचायती राज विभाग में हुए कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुलतानपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में नालियों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में नई पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री राजकुमार अग्रवाल की जनपद बलिया में पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की गन्ना केन्द्रों पर घटतौली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में प्रदूषण की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद हापुड़ में फायर ब्रिगेड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री हरीराम की सोनभद्र के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जिलाधिकारी आगरा द्वारा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्रीमती निर्मला संखवार की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बांसठवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद अलीगढ़ में कतिपय नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तिरसठवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भगवंतनगर क्षेत्र के कस्बा बीघापुर में 100 शैय्या के अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भगवंतनगर क्षेत्र के कस्बा बीघापुर..

श्री अनिल सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अनिल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से दो तीन जानकारी चाहता हूं। यह जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, यह निर्माण संबंधी है। गलत जानकारी कर रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतना आशीर्वाद चाहता हूं कि यह टी0ए0सी0 से जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इस मामले में जो शिकायत है, वह इस बात की है कि निर्माण कार्य ठीक नहीं हो रहा है। आपकी तरफ से जांच महानिदेशक को जांच गयी है। महानिदेशक, स्वास्थ्य निर्माण कार्य की जांच नहीं कर सकते। इनका कहना है कि पी0डब्ल्यू0डी0 से जांच करा दी जाए। इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मान लिया गया कि रिपोर्ट में कमी है तो क्यों न टी0ए0सी0 से जांच करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, करा ली जाए।

श्री जय प्रताप सिंह-

[में 100 शैय्या अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है। उक्त निर्माण कार्य सी0एन0डी0एस0 द्वारा कराया जा रहा है। अस्पताल के निर्माण में सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मौरंग, बालू, गिट्टी, सीमेंट एवं सरिया का मानक के अनुरूप इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बहुत ही अधोमानक एवं घटिया निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल जैसा महत्वपूर्ण भवन जिसमें बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और चिकित्सक बैठते हैं, ऐसे भवनों को घटिया एवं अधोमानक रूप में निर्मित कराए जाने से क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर घटिया निर्माण किए जाने से सरकार की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

स्थानीय जनता द्वारा जांच की निरंतर मांग की जा रही है, परन्तु जांच की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। निर्माण कार्य निरंतर अधोमानक चल रहा है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे अधोमानक निर्माण के विरुद्ध उच्चस्तरीय टीम से जांच कराकर कार्यवाही कराए जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-नियम-14/पाँच-6-2020, दिनांक 20.02.2020 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रकरण के सम्बन्ध में जांच कर जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद लखनऊ स्थित टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी.....

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जब लखनऊ से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे उस समय पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजा टिकैत राय के द्वारा निर्मित तालाब जो पानी के अभाव में सूख गया था उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए अपनी सांसद निधि से एक संगीतमय फौव्वारे का निर्माण करवाया था और तालाब का सौन्दर्यीकरण भी कराया था। विगत वर्षों में भारतीय जनता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पार्टी की सरकार न होने के कारण यह तालाब उपेक्षित हो गया और इसमें लगा हुआ फौव्वारा और बिजली कट जाने के कारण अन्धकार में डूब गया। वर्तमान समय में वह अश्लीलता और अराजक तत्वों के लिए अपराध का केन्द्र बन गया। यहाँ पर सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में स्त्री और पुरूष टहलने के लिए आते हैं। इस तालाब का एक इतिहास है। इसे सुव्यवस्थित कराकर फौव्वारे को चलवाने और प्रातःकाल टहलने आने वाले लोगों के लिए 2 शेड बनाये जाने एवं एक छोटा शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के लिए दिनांक 24-07-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत मैने सूचना सदन में दी थी। जिसके लिखित उत्तर में मा0 नगर विकास मंत्री ने कहा था कि उपरोक्त सारी व्यवस्था कराये जाने के सम्बंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2019 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। मेरे द्वारा लगातार पत्र व्यवहार करने और व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी अभी तक उपरोक्त कोई कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-इस सम्बंध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 24-07-2019 को दी गयी सूचना के क्रम में नगर विकास अनुभाग-5 के पत्र दिनांक 25-07-2019 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि उक्त तालाब को सुव्यवस्थित कराकर फौव्वारे को चलवाने और प्रातःकाल टहलने वाले लोगों के लिए शेड बनाये जाने, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उक्त निर्देश के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24-10-2019 द्वारा टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण की परियोजना लागत रु0 1,10,24,960.00 (रु0 एक करोड़ दस लाख चौबीस हजार नौ सौ साठ मात्र) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध करायी गयी थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी परियोजना के परीक्षणोपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र दिनांक 06-02-2020 द्वारा परियोजना कतिपय संवीक्षण के साथ उपलब्ध करायी गयी है।

3-उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में शासनादेश दिनांक 06-06-2019 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी परियोजना का परीक्षण उक्त शासनादेश के आलोक में किया जा रहा है। परियोजना के प्रस्तावित कार्य उक्त शासनादेश में उल्लिखित कार्यों से आच्छादित होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कराया जायेगा।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज तो टी0वी0 की हेडलाइन्स में यही छाए है। ब्रेकिंग न्यूज में है।

श्री अध्यक्ष-

तो पुरस्कार रूप में आप सुरेश जी की बात मान जाइए। सुरेश जी संतुष्ट हो गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नगर पालिका में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेश चौबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री भूपेश चौबे जी उपस्थित नहीं है। फिर भी इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[श्री भूपेश चौबे, मा0 सदस्य, विधान सभा, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा दिनांक 19.02.2020 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नगरपालिका के पेयजल आपूर्ति हेतु चल रही परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है :-

''मेरे विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद-सोनभद्र के नगर पालिका राबर्ट्सगंज में पेयजलापूर्ति हेतु चल रही परियोजना को पूर्ण न होने से पेयजल की स्थिति बहुत खराब है। गर्मी का मौसम निकट है जिससे यह समस्या और बढ़ जायेगी। कई बार अधिकारियों से इस योजना को पूर्ण कराये जाने हेतु निवेदन किया गया परन्तु उदासीनता के चलते इस योजना को अभी तक पूर्ण नहीं कराया जा सकता है। जनहित में पेयजल की आपूर्ति योजना को पूर्ण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए राबर्ट्सगंज नगर पालिका के पेयजल आपूर्ति हेतु चल रही परियोजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।''

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि नगर पालिका परिषद, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र में वर्ष 1952 से पेयजलापूर्ति पाइप लाइन द्वारा की जा रही है। पूर्व में डाली गयी डिस्ट्रीब्यूशन की पाइप लाइन लगभग 30 वर्ष पुरानी है, जो कि सर्विस आयु पूर्ण कर चुकी है। कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपम्प का जल स्तर नीचा हो जाने के कारण टैंकर द्वारा जलापूर्ति करनी पड़ती है। नगर को जलापूर्ति का मुख्य स्रोत भिलाई बांध है, जो कि ग्रीष्म ऋतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में सूख जाता है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र में घंघरौल बांध, जिसमें वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, बांध से पेयजलापूर्ति किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30-12-2014 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र के लिए पुनर्गठन पेयजल योजना की अनुमोदित लागत रु0 9601.55 लाख स्वीकृत की गयी है। नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र पुनर्गठन पेयजल योजना की अनुमोदित लागत रु0 9601.55 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 4435.25 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री जय प्रताप सिंह-

[प्रधान सहायक द्वारा की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें स्टेशनरी इंचार्ज पद से हटाने एवं उनकी आय से अधिक की सम्पत्ति की उच्चस्तरीय जांच कराने हेतु नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव को निःशुल्क ट्रांजिट हास्टल आवंटित किये जाने तथा उनकी चल-अचल सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-4 के आदेश दिनांक 14-02-2020 द्वारा निदेशक (प्रशासन) को निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

(1) महानिदेशक द्वारा केयर टेकर को निःशुल्क आवास आवंटित किये जाने सम्बन्धी आदेश को तत्काल निरस्त किया जाय। केयर टेकर के पद पर जब श्री अविनाश श्रीवास्तव को निःशुल्क आवास आवंटित था, तो उन्हें एच0आर0ए0 का भुगतान कैसे किया गया, की विस्तृत जाँच कराकर शासन को जांच रिपोर्ट पृथक से प्रेषित की जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) श्री अविनाश श्रीवास्तव की चल-अचल सम्पत्ति की जांच भी की जाय तथा उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाय।

3-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 19-02-2020 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में चिकित्सा अनु0-4 के पत्र दिनांक 24-02-2020 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक (प्रशासन) को प्रकरण की जांच कराकर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।]

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह जो जाँच हो रही है यह बहुत गम्भीर मामला है। यह वित्तीय गबन का मामला है। स्वास्थ्य भवन के अधिकारी से इसकी जाँच कराई जा रही है जिस पर भरोसा नहीं है। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच शासन स्तर से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके।

श्री जय प्रताप सिंह-

श्री अविनाश श्रीवास्तव की चल-अचल सम्पत्ति की जांच भी कराई जा रही है मगर माननीय सदस्य जैसा कहे हैं यह मामला बहुत गम्भीर भी है इनकी और भी जाँचे कराना आवश्यक है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसकी जाँच शासन स्तर से करा दीजिए।

श्री जय प्रताप सिंह-

आपकी बात मान ली गई है।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में अधूरे निर्मित विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री रामचन्द्र यादव जी उपस्थित नहीं हैं फिर भी यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[श्री रामचन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-02-2020 को दी गयी सूचना में जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सुजागंज ग्राम पंचायत में अधूरे निर्मित विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

''जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सुजागंज ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान में जूनियर हाई स्कूल सुजागंज को अपग्रेड कर हाई स्कूल की स्थापना भारत सरकार के निर्देशानुसार की गयी। स्थापना के बाद कक्षायें संचालित हो रही हैं। वर्ष 2018-19 में यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया जो दो वर्ष बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। उपरोक्त हाई स्कूल में छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक होने के नाते पठन-पाठन में बड़ी कठिनाई हो रही है। आधे-अधूरे निर्मित भवन के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा बिल्डिंग को हैण्डओवर नहीं लिया गया। जिसके कारण अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में आधारभूत सुविधाओं के अभाव के नाते आक्रोश उत्पन्न हो गया है। क्षेत्र की जनता द्वारा उपरोक्त अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण कराये जाने की मांग लगातार की जा रही है परन्तु कार्यदायी संस्था की उदासीनता के नाते अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्ब विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समयबद्ध सीमा उक्त हाई स्कूल के निर्माणाधीन अधूरे भवन को पूर्ण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा अभियान (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रूदौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजागंज विकास खण्ड-रूदौली को उच्चीकरण कर हाई स्कूल की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 2015-16 से भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। विद्यालय निर्माण हेतु स्वीकृत इकाई लागत रु0 69.15 लाख है। जनपद स्तर पर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का चयन किया गया। प्रथम किश्त के रूप में रु0 20 लाख की धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 26-12-2017 को तथा द्वितीय किश्त के रूप में रुपये 20.00 लाख की धनराशि दिनांक 09-10-2018 को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक आर0एम0एस0ए0/GHS-554/1660-61/2019-20, दिनांक 24 फरवरी, 2020 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रु0 14 लाख जनपद को अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अनुमोदित लागत के सापेक्ष रु0 54.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद-अयोध्या की आख्यानुसार विद्यालय का निर्माण कार्य प्लास्टर स्तर पर है तथा अप्रैल, 2020 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर हैण्डओवर कराया जाना लक्षित है।]

जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

यह स्थगित है।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में डलमऊ पम्प कैनाल में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद रायबरेली के डलमऊ तहसील में चौधरी चरण सिंह...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[''ए'' पम्प नहर स्थित है, जो 02 चरणों में स्थापित है। डलमऊ ''ए'' पम्प नहर के प्रत्येक चरण के कुल 20-20 पम्प स्थापित हैं। प्रत्येक पम्प की क्षमता 60 क्यूसेक है। पम्प नहर की कुल क्षमता 14 पम्प (14X60=840 क्यूसेक) की है। शेष 06 पम्प स्टैण्डबाई के रूप में स्थापित हैं। पम्पों का संचालन गंगा नदी के जल स्तर एवं विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करता है। गंगा नदी में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर पम्पों का संचालन मांग के अनुरूप कराकर जल उपलब्ध कराना प्राविधानित किया गया है।

ग्राम कन्दरावां में सिंचाई हेतु राजबहा कन्दरावां का टेल भाग आता है, जो विगत कई वर्षों से किसानों द्वारा पाट दिया गया था, जिसे इस वर्ष पूर्ण रूप से कब्जा हटाते हुए साफ करा दिया गया है एवं पानी पहुंचा दिया गया है। ग्राम कोटरा बहादुरगंज में पड़ने वाली नहर कोटरा माइनर की सफाई विगत 03 वर्षों में पर्याप्त धन की उपलब्धता न होने के कारण नहीं करायी जा सकी थी, जिसकी इस वर्ष सफाई कराकर टेल भाग तक पानी पहुंचा दिया गया है।]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ यह हमारे विधान सभा क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में सिंचाई का एकमात्र साधन डलमऊ पम्प कैनाल है। मैंने अपने नियम-51 में यह लिखा था कि वहाँ पर 16 पम्प लगे हुए हैं जो चलने चाहिए लेकिन चल चार रहे हैं। दूसरा हमने कहा था कि जो इसका रोस्टर बनाया गया है कि हर एक सप्ताह ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र को पानी दिया जायेगा एक सप्ताह सदर विधान सभा क्षेत्र को दिया जाएगा। मैंने यह भी शिकायत की थी कि रोस्टर का अनुपालन नहीं हो रहा है। अधिकारी कितना गुमराह कर रहे हैं इसमें और किसानों की समस्या पर एक झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कि एक वर्ष से ज्यादा हो गया चार पम्प से ज्यादा वहाँ चले ही नहीं। चाहे गंगा का जलस्तर जितना रहा हो जब बाढ़ रही तब भी चार पम्प चले जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पम्प खराब है कभी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कहते हैं कि बिजली का तार शार्ट हो गया आज स्थिति यह है कि दो ब्लाकों में किसान धरने पर बैठे हैं नहरों में पानी नहीं जा रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि केवल तीन महीने में यह पम्प प्रतिदिन कितने चले हैं इसकी जाँच करा लीजिए इसकी रिपोर्ट मंगा लीजिए बिजली कितने घंटे रही पम्प कितने चले हैं इसकी जिलाधिकारी से जाँच करा लीजिए किसान बड़े संकट में है पानी नहीं मिल रहा है। पूरी ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र डलमऊ पम्प कैनाल से पानी जाता है केवल जिलाधिकारी से जाँच करा लेंगे तो सही स्थिति आपके सामने आ जाएगी और किसानों को पानी मिल जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है। मान्यवर।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ग्राम सभा इन्दारा मनकही सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल ...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(केवल वक्तव्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[लम्बाई 0.500 किमी0 है, मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है, मार्ग का विगत नवीनीकरण वर्ष मार्च, 2015 का है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की विशेष मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

उत्तर प्रदेश में विमुक्त घुमन्तू जनजातियों के विकास हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार डेविड द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं लेकिन इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विमुक्त जातियों के लिए 6 से 12 तक 490 की क्षमता के 09 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इन सभी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, स्कूल यूनीफार्म,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। इन विद्यालयों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

1-रामपुर, 2-फर्रुखाबाद, 3-सारनाथ (वाराणसी), 4-चन्दापुर (वाराणसी), 5-लखनऊ, 6-गोरखपुर, 7-गोण्डा, 8-दुद्धी (सोनभद्र), 9-हसनपुर (सुल्तानपुर)

योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक बजट प्राविधान रु0 10471.15 लाख के सापेक्ष रु0 7203.72 लाख व्यय किया गया।

(2) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज कल्याण विभाग से शत-प्रतिशत शासकीय अनुदान पर निम्न 03 आश्रम पद्धति विद्यालय उक्त वर्ग के बच्चों के लिए संचालित हैं इन विद्यालयों में भी निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, स्कूल यूनीफार्म, शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। इन विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

1-ईश्वर शरण आश्रम पद्धति विद्यालय, इलाहाबाद,

2-आश्रम पद्धति विद्यालय, सहारनपुर,

3-प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से बजट प्राविधान रु0 4004.69 लाख के सापेक्ष रुपये 2771.00 लाख व्यय किया गया।

(3) विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है, जिसमें 03 व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है :-

1-हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, 2-सिलाई एवं 3-हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से बजट प्राविधान रु0 277.25 लाख के सापेक्ष रु0 173.79 लाख व्यय किया गया।

(4) **राजकीय उन्नयन बस्ती**

ब्रिटिश राज्य में घोषित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से बजट प्राविधान रु0 1891.35 लाख के सापेक्ष रु0 1066.48 लाख व्यय किया गया।

उक्त वर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित उपरोक्त योजनाओं में आवंटित होने वाली धनराशि का व्यय विमुक्त जातियों के कल्याण के लिये नियमित रूप से किया जाता है। विमुक्त जातियों के कल्याण के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक बजट प्राविधान रु0 14753.09 लाख के सापेक्ष रु0 10148.51 लाख व्यय किया गया।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 26 फरवरी, 2020 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81-91 पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों का नगर निगम, लखनऊ एवं जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 05-10-2017 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के 06 विभिन्न खण्डों एवं सेक्टरों के हस्तानान्तरण हेतु दिनांक 06.09.2017 को मण्डलायुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में हुयी बैठक में हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि कालोनी हैण्ड ओवर के सम्बन्ध में आवास विभाग के शासनादेश संख्या-2337/9-अ-2-2001 दिनांक 27.07.2001 के परिपेक्ष्य में चेक लिस्ट तथा उक्त शासनादेश में वर्णित अभिलेख तथा उससे सम्बन्धित हस्तांतरण की प्रक्रिया का पालन लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम स्तर पर कर लिया जाय। नगर आयुक्त द्वारा अनुरोध किया गया कि हस्तांतरण किये जाने वाले खण्डों को विकसित किये जाने हेतु आस-पास के जिन गांव की जमीने अधिग्रहीत की गई है, उन गांवों का विकास जनहित में आवश्यक है। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे सभी गांवों का विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा चुका है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित कालोनियों के सम्बन्ध में याचिका संख्या-5371/2008 में दिनांक 04.09.2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि **"We further provide that in so far as the transfer of undeveloped colonies is concerned, as we have observed above, the L.D.A. can not be permitted to transfer colonies to any local authority without its full development wherein all civic amenities like roads, sewerage, water etc. as is usually provided by, it is provided**** को भी संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में नगर निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के भिन्न-भिन्न खण्डों को टेक ओवर किये जाने के सम्बन्ध में तैयार किये गये प्रस्ताव जिसका विवरण निम्नानुसार है, को प्रस्तुत किया गया :-

क0 सं0	जोन (नगर निगम, लखनऊ)	योजना का नाम	सिविल कार्य पर लागत	जलकल विभाग	पथ प्रकाश	औद्योनिक सौन्दर्यीकरण	कूड़ा प्रबन्धन	सफाई व्यवस्था	कुल योग
1	4	गोमती नगर योजना फेज-1 के विराज खण्ड-1 से 5 तक आवासीय एवं विराज खण्ड व्यवसायिक	610618021.00	68725000.00	10927470.00	31490210.00	25566291.00	11717640.00	759044632.00
2	2	गोमती नगर योजना फेज-2 के विकल्प खण्ड-1 से 4 आवासीय/व्यवसायिक	233757710.00	82773000.00	15334854.00		31475921.00	10119780.00	373461265.00
3	3	जानकीपुरम योजना सेक्टर-एच	275748000.00	पूर्व से हस्तान्तरित	पूर्व से हस्तान्तरित	9131250.00	31573581.00	9499490.00	325952321.00
4	6	शारदा नगर योजना रतन खण्ड	242994974.00	75324000.00	10655158.00	22484420.00	33512351.00	3886155.00	368857058.00
5	8	कानपुर रोड योजना सेक्टर- आई विस्तार	75540040.00	32155000.00	पूर्व से हस्तान्तरित	630000.00	31460431.00	1943077.00	141728548.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्व से	831160.00	35643761.00	2806668.00	837128869.00

नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. <u>अवस्थापना सम्बन्धी सिविल कार्य :–</u>

नगर निगम द्वारा सिविल कार्यों यथा नाला, नाली, सड़क एवं अन्य अवस्थापनाओं सुविधाओं के पुर्ननिर्माण/निर्माण हेतु रू0 144.98 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि नगर निगम के व्ययानुमानों में कुछ कार्य भविष्य की संभावनाओं के दृष्टिगत प्रस्तावित कर सम्मिलित किये गये हैं, जो समीचीन नहीं है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल के वर्तमान में वांछित कार्यों का सर्वेक्षण कर लिया जाए।

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खण्डों/सेक्टरों में जो भी सिविल कार्य अवशेष रह गये हैं तथा जहॉ पर सुधार की आवश्यकता है उन्हें विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं कराया जायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये कि सिविल सम्बन्धी ऐसे कार्यों की सूची नगर निगम द्वारा प्राधिकरण के साथ सर्वेक्षण कर संयुक्त रूप से तैयार कर ली जायेगी, उन्हें भी प्राधिकरण द्वारा शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा सम्बन्धित कार्य पूर्ण कर नगर निगम को सूचित कर दिया जायेगा। सिविल सम्बन्धी कार्यों के विकास के उपरान्त शासनादेश के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करके प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनियों का हस्तांतरण नगर निगम को किया जायेगा।

2. <u>जलापूर्ति एवं सीवरेज कार्य :–</u>

नगर निगम (जलकल द्वारा) जलापूर्ति एवं सीवरेज कार्य हेतु रू0 35.70 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा जलकल विभाग को उक्त कार्यों को कराने हेतु रू0 10.00 करोड की धनराशि उपलब्ध कराकर जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था को नगर निगम (जलकल) को हस्तांतरण करने की सहमति दी गयी। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा उक्त क्षेत्रों की सीवरेज एवं जलापूर्ति व्यवस्था को न्यूनतम मानक के अनुरूप करने में कुछ अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात कही गयी। उपाध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि यदि भविष्य में कोई कार्य महत्वपूर्ण होगा तो उसके लिये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करा दिया जायेगा। निर्णय लिया गया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था जलकल द्वारा टेकओवर किया जायेगा तथा प्राधिकरण रू0 10.00 करोड की धनराशि जलकल को उपलब्ध करायेगा।

3. <u>पथ प्रकाश का कार्य :–</u>

प्रश्नगत कालोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था के सुदृढीकरण, नियमित संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नगर निगम द्वारा रू0 6.99 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि धनराशि अधिक है, अतः प्राधिकरण स्वयं प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण करके भविष्य मे आवश्यकतानुसार प्रकाश की व्यवस्था करा देगा। आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रकाश की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को नगर निगम सूचीबद्ध कर प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा। किन्तु मार्ग प्रकाश व्यवस्था तत्काल प्रभाव से नगर निगम, लखनऊ के अधीन संचालित होगी। इस हेतु रु0 1.00 करोड (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि प्राधिकरण नगर निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराएगा। नगर निगम लखनऊ द्वारा सूचित आवश्यक अवशेष कार्यो को कराये जाने का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।

SE LDA

4. <u>औद्यानिक सौन्दर्यीकरण का कार्य :–</u>

प्रश्नगत 06 कालोनियों एवं उनके खण्डो में स्थित पार्कों/उद्यानों के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु नगर निगम द्वारा रू0 6.46 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय द्वारा यह कहा गया कि उक्त पार्कों के औद्यानिकीकरण हेतु नगर निगम को रू0 2.00 करोड विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और उक्त धनराशि से ही उक्त क्षेत्र के पार्कों का सौन्दर्यीकरण नगर निगम द्वारा करया जायेगा। पार्कों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये अभिमत पर प्राधिकरण एवं निगम द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। लखनऊ विकास प्राधिकरण 03 दिन में उक्त धनराशि रू0 2.00 करोड नगर निगम को उपलब्ध करायेगा। तदानुसार नगर निगम द्वारा सभी खण्डों/सेक्टरों के पार्कों को टेकओवर किया जाता है।

5. <u>कूडा प्रबन्धन का कार्य :–</u>

प्रश्नगत कालोनियों के सम्पूर्ण क्षेत्र में कूडा प्रबन्धन के कार्य हेतु नगर निगम द्वारा रू0 18.92 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि कूडा प्रबन्धन हेतु नगर निगम को रू0 10.00 करोड की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस कार्य को नगर निगम द्वारा टेकओवर किया जाय। नगर निगम द्वारा उपाध्यक्ष के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी एवं कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा रू0 10.00 करोड की धनराशि 03 दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। नगर निगम द्वारा उक्त कार्यों को तत्काल टेकओवर किया जाता है।

6. <u>सफाई व्यवस्था कार्य :–</u>

सामान्य सफाई व्यवस्था सम्बन्धी (स्वीपिंग) कार्यों हेतु नगर निगम द्वारा रू0 3.96 करोड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त आयुक्त महोदय द्वारा यह कहा गया कि प्रश्नगत कालोनियों में सामान्य सफाई हेतु प्राधिकरण द्वारा रू0 2.00 करोड की धनराशि तात्कालिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा सफाई सम्बन्धी समस्त कार्यों का हस्तांतरण नगर निगम को कर दिया जाय, जिस पर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

उक्त के अतिरिक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सामुदायित सुविधाएँ यथा कम्यूनिटी सेन्टर, बारात घर, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय, सब्जी मण्डी, पार्किंग, वेडिंग जोन आदि अन्य यथा उपलब्ध जन सुविधाएं नगर निगम को टेकओवर करा दी जाये और नगर निगम इन हस्तगत सुविधाओं को स्वीकार करेगा।

7. <u>अन्य बिन्दु :–</u>

कालोनियों के हस्तांतरण सम्बन्धी इस बैठक में विभूति खण्ड के सामान्य सफाई व्यवस्था (स्वीपिंग) पर भी चर्चा की गयी, जिसमें नगर निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि विभूति की सामान्य सफाई व्यवस्था (स्वीपिंग) पर लगभग रू0 12.00 लाख प्रतिमाह खर्च आयेगा और यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा भविष्य में प्रतिमाह यदि उपलब्ध करायी जाती रहेगी तो नगर निगम द्वारा विभूति खण्ड के आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों की समान्य सफाई व्यवस्था का कार्य करा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय

EE SE LDA

द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि प्राधिकरण द्वारा रू0 2.00 करोड की धनराशि एकमुश्त नगर निगम को उपलब्ध करा दी जाय तो नगर निगम द्वारा भविष्य में उक्त क्षेत्र की सामान्य सफाई व्यवस्था (नालो को छोडकर) सुनिश्चित की जायेगी।

(डा0 पी0के0 सिंह)
न0स्वा0अधि0, न0नि0, ल0

(चक्रेश जैन)
अधि0अभि0, जोन–1 ल0वि0प्रा0

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभि0, न0नि0,ल0

(आर0डी0 राय)
अधि0अभि0, जोन–2 ल0वि0प्रा0

(पी0एस0 मिश्रा)
अधि0अभि0, जोन–5 ल0वि0प्रा0

(मोहनजी पाण्डेय)
मुख्य अभि0 (वि0यॉ0), न0नि0,ल0

(एस0के0 वर्मा)
महाप्रबन्धक, जलकल, ल0

(पी0सी0 पाण्डेय)
अधी0 अभि0, ल0वि0प्रा0

(उदयराज सिंह)
नगर आयुक्त, न0नि0,ल0

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0

प्रतिहस्ताक्षरित

(अनिल गर्ग) 05/04/12
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषकः–	सेवा में:–
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
संख्याः– 5791/AA-5/सचिव/2018	नत्थीः– .....
दिनांकः– 17/11/2018	.....

:विषयः

जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–एच, लखनऊ में कराये गये अवस्थापना सम्बन्धी सिविल कार्य सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 05.10.2017 के कार्यवृत्त के अनुपालन में नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–एच के अन्तर्गत विभिन्न भागो में क्षतिग्रस्त कतिपय सड़को, नालियों एवं पार्को के सुधार का कार्य कराया गया है। सुदृढीकरण किये गये मार्गो एवं क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत तथा सुधार किये गये पार्को को संलग्न मानचित्र पर दर्शा दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त के अनुपालन में सेक्टर–एच, जानकीपुरम् योजना में अन्य हस्तान्तरित कालोनियों के अनुरूप आवश्यक रख–रखाव की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/11/18

(एम0पी0 सिंह)
नि0 सचिव

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

16/11/18

(एम0पी0 सिंह)
नि0 सचिव

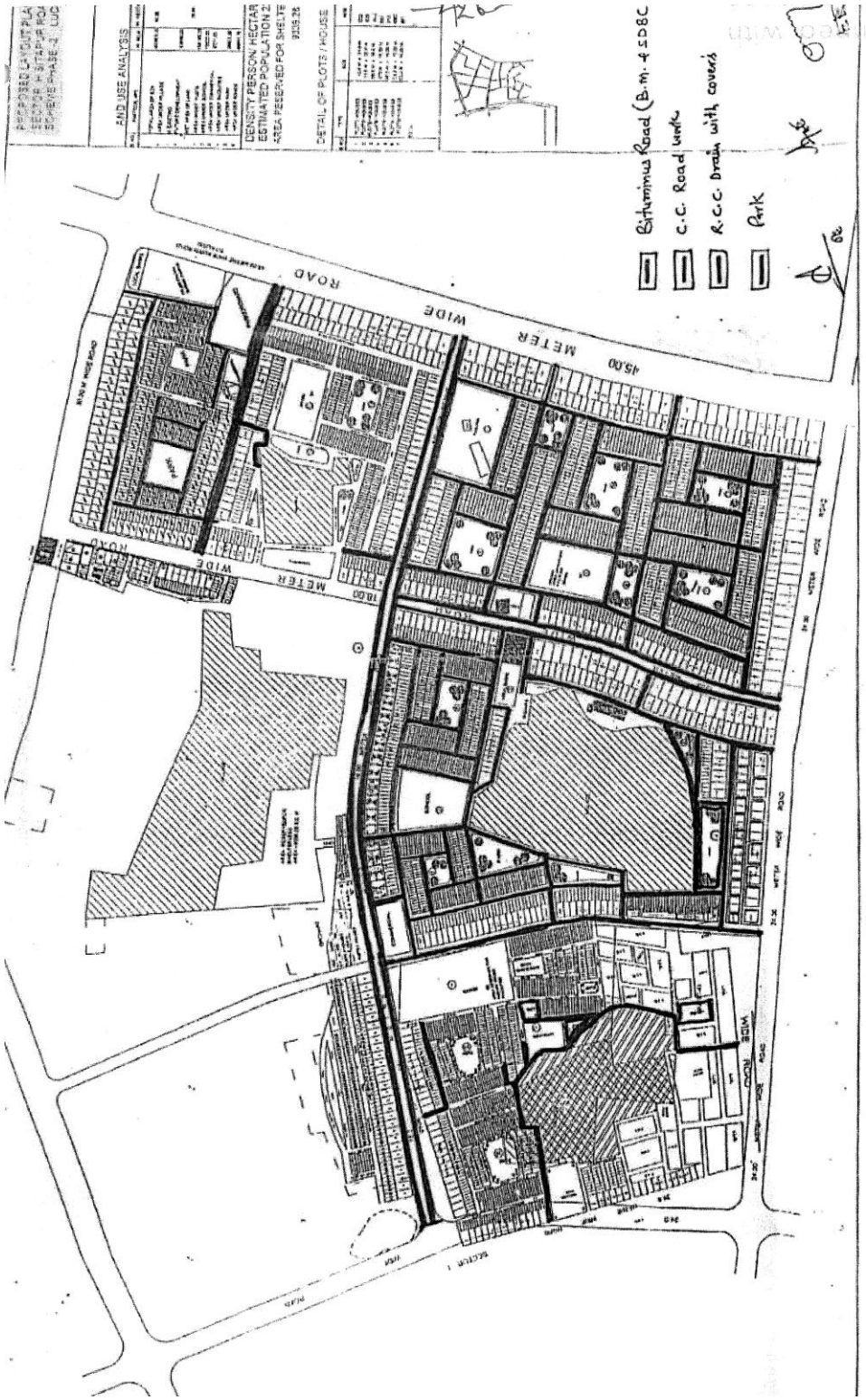
LAND USE ANALYSIS
DENSITY PERSON HECTAR
ESTIMATED POPULATION
AREA RESERVED FOR SHELTE
DETAIL OF PLOTS / HOUSE
Bituminus Road (B.M. & SDBC
C.C. Road work
R.C.C. Drain with covers
Park
45.00 METER WIDE ROAD
10.00 METER WIDE ROAD

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के 2-बुधवार के लिए निर्धारित श्री चेतराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-115 के उत्तरालेख का संलग्नक-1

.....

क्र0सं0	विभाग का नाम	समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ
01	एनेस्थेसियोलॉजी	00	100	02	02
02	एनॉटमी	00	02	03	07
03	बायोकमेस्ट्री	00	01	00	00
04	कार्डियोलोजी	00	52	34	57
05	कार्डियक एनेस्थीसिया	00	00	00	00
06	सी.टी.वी.एस	00	03	04	03
07	क्रिटिकल केयर	00	252	40	80
08	वैस्कुलर सर्जरी	00	00	00	00
09	क्लीनिकल हिमेटोलॉजी	00	02	04	12
10	कम्यूनिटी मेडिसिन	00	01	18	11
11	एडवांस रिसर्च लैब	00	05	00	10
12	डरमैटोलोजी, वेनरियोलोजी एण्ड लैप्रोसी	00	00	01	02
13	इमरजेन्सी मेडिसिन	00	00	00	00
14	ई.इन.टी.	00	00	02	17
15	इन्डोक्राइनोलाजी	00	00	00	00
16	इन्डोक्राइन सर्जरी	00	00	00	00
17	गाइनोकोलौजिकल आंकोलोजी	00	00	00	00
18	जिरियाट्रिक मैन्टल हैल्थ	00	01	05	11
19	न्यूरो एनेस्थिसिया	00	00	00	00
20	फारेन्सिक मेडिसिन	00	00	02	01
21	हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	00	00	00	00
22	हयूमन आर्गन ट्रान्सप्लानटेशन	00	00	00	00
23	मेडिसिन	00	03	07	43
24	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी	00	00	00	00
25	माइक्रोबायलोजी	00	05	04	11
26	मेडिकल ऑकोलोजी	00	00	00	00
27	पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक	00	00	00	00
28	न्यूरोसर्जरी	00	00	04	08
29	न्यूरोलॉजी	00	00	03	08
30	नियोनेटोलोजी	00	00	00	00
31	नैफ्रोलोजी	00	00	00	00
32	न्यूक्लियर मेडिसिन	00	00	00	00
33	ऑब्स एण्ड गायनोकोलोजी	00	11	06	131
34	आप्थैलमोलोजी	01	02	09	22
35	आर्थोपैडिक सर्जरी	00	01	00	15
36	पैथालोजी	00	10	06	19

क्र0सं0	विभाग का नाम	समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ
37	पिडियाट्रिक	00	01	06	11
38	पिडियाट्रिक ऑकोलोजी	00	00	00	00
39	पिडियाट्रिक सर्जरी	00	00	00	01
40	फार्माकॉलोजी	00	01	05	08
41	फिजियोलॉजी	00	01	03	03
42	प्लास्टिक सर्जरी विभाग एवं बर्न यूनिट	00	65	05	10
43	सायक्रैट्री	00	07	08	31
44	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	01	00	34	65
45	पल्मोनरी एण्ड क्रिटीकल केयर मेडिसिन	00	152	30	00
46	रेडियोडायग्नोसिस	00	00	05	01
47	रेडियोथेरेपी	00	05	11	12
48	रैस्पाइरेट्री मेडिसिन	00	00	04	19
49	रिहैमेटोलॉजी	00	02	07	00
50	सर्जिकल गैस्ट्रोइण्ट्रोलॉजी	00	01	00	44
51	सर्जरी (जनरल)	00	00	21	38
52	सर्जिकल ऑकोलोजी	00	03	12	18
53	स्पोर्ट मेडिसिन	00	00	00	00
54	थोरेसिक सर्जरी	00	00	00	00
55	ट्रॉन्सफ्यूजन मेडिसिन	00	00	15	18
56	ट्रामा सर्जरी	00	00	00	00
57	यूरोलोजी	00	10	09	01
58	कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री	00	00	00	00
59	कन्जरवेटिव डेन्ट्रिस्टी एण्ड इण्डोडौन्टिस	00	00	00	00
60	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलोजी	00	00	00	01
61	ओरल पैथालोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी	00	00	00	01
62	ओरल एण्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी	00	01	01	02
63	आर्थोडॉटिक्स विभाग (दंत संकाय)	00	00	00	01
64	पिडियाट्रिक्स एण्ड प्रिवेन्टिव डेन्ट्री	00	00	00	01
65	पेरियोडॉन्टोलोजी	00	00	01	01
66	प्रास्थोडान्टिक्स, क्राउन एण्ड ब्रिजस	00	00	01	01
67	कॉलेज आफ नर्सिंग	00	00	00	00
68	लेडी रेजीडेन्ट छात्रावास	00	00	00	02
69	न्यू सी0वी0 छात्रावास	00	00	00	02

क्र0सं0	विभाग का नाम	समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ
70	रेजीडेन्ट छात्रावास	00	00	01	22
71	डी0के0 छात्रावास	00	00	00	05
72	गौतम बुद्धा छात्रावास	00	00	00	00
73	नेहरू पी0जी0 छात्रावास	00	00	00	03
74	टी0जी0 छात्रावास	00	00	00	16
75	एस0पी0 छात्रावास	00	00	00	17
76	चक्रवर्ती छात्रावास	00	00	00	06
77	विजय लक्ष्मी छात्रावास	00	00	00	12
78	न्यू प्राइवेट वार्ड	00	00	00	12
79	वरिष्ठ मातृका कार्यालय	00	00	00	00
80	शाटिंग अनुभाग	00	00	00	00
81	लीनेन गोदाम	00	00	00	03
82	ड्यूटी रूम (अस्पताल पक्ष)	00	00	00	01
83	सेंट्रल ऑक्सीजन स्टोर	00	00	00	01
84	दंत संकाय	00	00	00	00
85	किचन विभाग	00	00	01	13
86	रिसर्च सेल	00	00	01	00
87	जन सम्पर्क कार्यालय	00	00	06	17
88	सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर	00	01	02	03
89	शव विच्छेदन गृह	00	00	00	03
90	आईसोलेशन वार्ड	00	00	00	01
91	कैज्यूल्टी रूम	00	00	00	01
92	इन्फेक्शन रूम	00	00	00	00
93	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी	00	06	03	44
94	विश्वविद्यालय हेतु	01	356	25	04
95	वित्त विभाग	00	00	10	02
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सरोजनीनगर)	00	00	06	08
97	विद्युत विभाग	00	00	02	18
98	केन्द्रीय पुस्तकालय	00	00	06	02
99	लाइब्रेरी दन्त संकाय	00	00	01	00
100	संक्रामक रोग चिकित्सालय	00	06	12	30
101	न्यू गेस्ट हाउस	00	00	00	00
102	शताब्दी चिकित्सालय	00	00	00	00
103	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय	00	00	00	03
104	प्राक्टर कार्यालय	00	00	00	00
105	कन्वेंशन सेंटर	00	00	01	00
106	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	00	00	01	01
107	ट्रामा सेन्टर	00	10	04	04

क्र0सं0	विभाग का नाम	समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ
108	अधीक्षक कार्यालय	00	07	18	16
109	डीन डेन्टल अधिष्ठाता दंत संकाय	00	00	02	04
110	कुलपति कार्यालय	00	00	02	01
111	निर्माण विभाग	00	03	03	30
112	कुलसचिव कार्यालय	00	05	05	08

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93-97 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के 2-बुधवार के लिए निर्धारित श्री चेतराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-116 के उत्तरालेख का संलग्नक-1

.....

क्र0सं0	विभाग/यूनिट का नाम
01	एनेस्थेसियोलॉजी
02	एनॉटमी
03	बायोकमेस्ट्री
04	कार्डियोलोजी
05	कार्डियक एनेस्थीसिया
06	कार्डियो वैस्कुलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी
07	क्रिटिकल केयर
08	वैस्कुलर सर्जरी
09	क्लीनिकल हिमेटोलॉजी
10	कम्यूनिटी मेडिसिन
11	एडवांस रिसर्च लैब
12	डरमैटोलोजी, वेनरियोलोजी एण्ड लैप्रोसी
13	इमरजेन्सी मेडिसिन
14	आटो-राइनो-लारिंगोलॉजी
15	इन्डोक्राइनोलाजी
16	इन्डोक्राइन सर्जरी
17	गाइनोकोलॉजिकल आंकोलोजी
18	जिरियाट्रिक मैन्टल हैल्थ
19	न्यूरो एनेस्थिसिया
20	फारेन्सिक मेडिसिन
21	हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
22	हयूमन आर्गन ट्रान्सप्लानटेशन
23	मेडिसिन
24	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी
25	माइक्रोबायलोजी
26	मेडिकल ऑकोलोजी
27	पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक
28	न्यूरोसर्जरी
29	न्यूरोलॉजी
30	नियोनेटोलोजी
31	नैफ्रोलोजी
32	न्यूक्लियर मेडिसिन
33	ऑब्स एण्ड गायलोकोलोजी
34	आप्थैलमोलोजी
35	आर्थोपैडिक सर्जरी
36	पैथालोजी

क्र0सं0	विभाग का नाम
37	पिडियाट्रिक
38	पिडियाट्रिक ऑकोलोजी
39	पिडियाट्रिक सर्जरी
40	फार्माकॉलोजी
41	फिजियोलॉजी
42	प्लास्टिक सर्जरी विभाग एवं बर्न यूनिट
43	सायक्रैट्री
44	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन
45	पल्मोनरी एण्ड क्रिटीकल केयर मेडिसिन
46	रेडियोडायग्नोसिस
47	रेडियोथेरेपी
48	रैस्पाइरेट्री मेडिसिन
49	रिहैमेटोलॉजी
50	सर्जिकल गैस्ट्रोइण्ट्रोलॉजी
51	सर्जरी (जनरल)
52	सर्जिकल ऑकोलोजी
53	स्पोर्ट मेडिसिन
54	थोरेसिक सर्जरी
55	ट्रॉन्सफ्यूजन मेडिसिन
56	ट्रामा सर्जरी
57	यूरोलोजी
58	कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री
59	कन्जरवेटिव डेन्ट्रिस्टी एण्ड इण्डोडौन्टिस
60	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलोजी
61	ओरल पैथालोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी
62	ओरल एण्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी
63	आर्थोडॉटिक्स विभाग (दंत संकाय)
64	पिडियाट्रिक्स एण्ड प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री
65	पेरियोडॉन्टोलोजी
66	प्रास्थोडान्टिक्स, क्राउन एण्ड ब्रिजस
67	कॉलेज आफ नर्सिंग
68	लेडी रेजीडेन्ट छात्रावास
69	न्यू सी0वी0 छात्रावास
70	रेजीडेन्ट छात्रावास
71	डी0के0 छात्रावास
72	गौतम बुद्धा छात्रावास
73	नेहरू पी0जी0 छात्रावास
74	टी0जी0 छात्रावास

क्र0सं0	विभाग का नाम
75	एस0पी0 छात्रावास
76	चक्रवर्ती छात्रावास
77	विजय लक्ष्मी छात्रावास
78	न्यू प्राइवेट वार्ड
79	वरिष्ठ मातृका कार्यालय
80	शाटिंग अनुभाग
81	लीनेन गोदाम
82	डयूटी रूम (अस्पताल पक्ष)
83	सेंट्रल ऑक्सीजन स्टोर
84	दंत संकाय
85	किचन विभाग
86	रिसर्च सेल
87	जन सम्पर्क कार्यालय
88	सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर
89	शव विच्छेदन गृह
90	आईसोलेशन वार्ड
91	कैज्यूल्टी रूम
92	इन्फेक्शन रूम
93	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी
94	विश्वविद्यालय हेतु
95	वित्त विभाग
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सरोजनीनगर)
97	विद्युत विभाग
98	केन्द्रीय पुस्तकालय
99	लाइब्रेरी दन्त संकाय
100	संक्रामक रोग चिकित्सालय
101	न्यू गेस्ट हाउस
102	शताब्दी चिकित्सालय
103	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय
104	प्राक्टर कार्यालय
105	कन्वेंशन सेंटर
106	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
107	ट्रामा सेन्टर
108	अधीक्षक कार्यालय
109	डीन डेन्टल अधिष्ठाता दंत संकाय
110	कुलपति कार्यालय
111	निर्माण विभाग
112	कुलसचिव कार्यालय

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के 2-बुधवार के लिए निर्धारित श्री चेतराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-116 के उत्तरालेख का संलग्नक-2

.....

क्र0सं0	विभाग का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	आर्थोपेडिक सर्जरी	2	0	0
2	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी	0	0	1
3	आप्थेल्मोलॉजी	0	0	1
4	इन्डोक्राइनोलॉजी	3	0	0
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	0	0
6	एनाटमी	0	0	2
7	एनेस्थीसियोलॉजी	3	0	4
8	ओटो-राइनो-लारिंगोलॉजी	1	0	1
9	ओरल पैथालोजी एण्ड माइक्रोबायोलॉजी	0	0	1
10	क्लीनिकल हिमैटोलॉजी	0	0	0
11	कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री एण्ड इन्डोडॉन्टिक्स	0	0	1
12	कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ	2	0	2
13	कार्डियेक एनेस्थीसिया	0	0	1
14	कार्डियोलॉजी	2	1	2
15	कार्डियो वैस्कुलर एण्ड थोरेंसिक सर्जरी	1	0	1
16	क्रिटिकल केयर मेडिसिन	2	0	3
17	गायनोकोलॉजीकल आंकोलॉजी	1	0	2
18	जनरल मेडिसिन	2	0	2
19	जनरल सर्जरी	0	0	1
20	जीरियाट्रिक मेण्टल हेल्थ	2	0	2
21	ट्यूबरक्लोसिस एण्ड रेस्पीरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	0	0	1
22	ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन	1	0	0
23	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	0	0	1
24	थोरेंसिक सर्जरी	1	0	1
25	न्यूक्लियर मेडिसिन	0	0	1
26	न्यूरो एनेस्थेसिया	1	0	1
27	न्यूरोलॉजी	0	0	0
28	न्यूरो सर्जरी	2	0	2

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।
1	2	3	4
1	बागपत	न0पा0परि0, बडौत	मो0 विजय नगर में सराय रोड से होते हुये नाले की पटरी से प्राईमरी स्कूल तक, इरफान के प्लाट से मोटा के प्लाट तक, आबिद के मकान से जाहिद के मकान से लियाकत के प्लाट तक, राजबीर के मकान से लियाकत के प्लाट तक, मोनू शर्मा के प्लाट से रवीता जैन के मकान तक सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 में आजाद नगर में गली नं0 07 के आखिर/(राममेहर) के मकान से मन्डी वाली रोड की ओर इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 आजाद नगर में गली नं0 07 के आखिर में मन्डी वाली रोड की ओर रमेश से जयपाल के मकान, बाबू से नरेश के मकान तक, अनिल से रोहताश के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 13 मो0 नयी रामनगर कालोनी में जलसिंह से नजीता से कौशल कश्यप तक व जितेन्द्र से हरेन्द्र पुत्र चरणसिंह के मकान तक 8 एम0एम0 इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 16 में हरपाल सिंह के मकान से तोमर के मकान तक, संजय बंसल के मकान से होते हुये अजय से संजय मास्टर के मकान होते हुये अजय से आखिर तक, धर्मवीर के मकान से प्राची एजेन्सी तक सी0सी0 इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।
6	तदैव	तदैव	नाला पटरी पर दिलीप विहार बड़ौत से शताब्दी नगर बड़ौत मनोज के मकान से अरविन्द के मकान तक सी0सी0 इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।

पी0एस0यू0पी0-एल0-17 विधान सभा (19)-09-05-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।